खण्ड-254, अंक-8
गुरूवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(4 मार्च, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 254 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७१५–७१९
मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव (अस्वीकृत)	७१९–८३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ४ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में १० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्ण चन्द, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव राम, श्री
केशव सिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री

गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद महरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गुँदादवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुजशर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री

जलील अब्बासी, काजी
जसराम सिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वाला प्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीत सिंह, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरसिंह नारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री

नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल श्री,
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती

बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री

यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, वर्मा श्री
रामकिंकर श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर, वर्मा श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभवन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती,
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
द्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखोसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बिक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री

आरदानन्द, श्री
आरदाभक्तसिंह श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
श्रुगनचन्द मजदूर, श्री
श्रुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सुबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह उपमंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त, तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)

आज की कार्य सूची के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, वह यह है कि कल जब हम लोग बैठे थे तब यह तय हुआ था कि प्रातः १० बजे से इस अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस होगी और वह ८ बजे रात्रि तक चलेगी। आज की कार्यसूची में आरम्भ होने का समय तो १० बजे दिन दिखाया गया है परन्तु समाप्त होने के समय ८ बजे तक का कहीं उल्लेख नहीं है। इसके अनुसार तो १० से ५ तक ही कार्यवाही चलेगी, ऐसा मालूम होता है। श्रीमन्, इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। श्रीमन्, आप कृपया अपनी व्यवस्था दें कि यह ८ बजे रात्रि तक छपने से रह गया है या ८ बजे रात्रि तक कार्यवाही चलेगी। नहीं तो श्रीमन्, ये जो कांग्रेस के लोग उधर बैठे हैं, जब हम उनके खिलाफ कहने लगेंगे तो.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने सुन लिया। जो घोषणा हो चुकी है, उसके अनुसार ही होगा। आप कहते हैं कि यह छपा नहीं। यह कहीं लिखा जाता है आपने कल का कार्यवृत्त मालूम होता है, पढ़ा नहीं है।

माननीय नेता विरोधी दल, २५ मिनट आप बोल लें। अन्य नेता विभिन्न दलों के १५-१५ मिनट बोल लें और शेष १० मिनट और जो मंत्रिगण उधर बोलेंगे सिवाय मुख्य मंत्री के, उनको भी उतना ही समय दिया जावेगा जो आपको दिया है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, हर पार्टी से एक माननीय सदस्य बोलेंगे। उनको आधा घंटा दे दें। और हर पार्टी से दो से ज्यादा न बोलें। एक माननीय नेता बोलें या कोई उनको रिप्रेजेन्ट करें या दो-दो माननीय सदस्य जो बोलना चाहें बोल लें। तो श्रीमन्, इस तरह से आप आधा घंटा और १५-१५ मिनट का समय रक्खें।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन वर्तमान मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।"

विरोधी दल की तरफ से यह अविश्वास का प्रस्ताव वर्तमान मंत्रिमंडल में बहुत सोच विचार कर पूरे उत्तरदायित्व के साथ हम लोग लाये हैं। समस्यायें, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, उन पर बहुत कुछ इस सदन में कहा जा चुका है, परन्तु सहने की भी कोई सीमा होती है। समस्यायें इतना विकराल रूप धारण कर रही है कि इस सदन के ही माननीय सदस्यों द्वारा ही नहीं परन्तु उत्तर प्रदेश के साढ़े सात करोड़ जनता की भी जो प्रतिक्रिया हो रही है, यह मंत्रिमंडल उदासीन होकर उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

एक सदस्य—

इसके जिम्मेदार आप हैं।

श्री अध्यक्ष—

सुन लीजिये।

श्री शारदाभक्तसिंह—

जिम्मेदार वे हैं जो बाहर कुछ कहते हैं और यहां कुछ कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, भाषण यहां हो रहा है और वहां हल्ला ज्यादा हो रहा है। हम लोग भी तैयार होकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष—

शांत रहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शारदाभक्तसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जब उधर से इस मंत्रिमंडल की प्रशंसा में और समर्थन में काफी उद्घोष हो रहा है तो मुझे केवल एक बात याद आती है कि जब भीष्म पितामह से यह प्रश्न किया गया कि धर्म करना तो ठीक ही है, लेकिन जो अधर्म उनके सामने हो रहा है, उसको सहना भी तो अधर्म है। तो उन्होंने एक बात महाभारत काल में कही थी कि मनुष्य पैसे का दास होता है। जहां से जो खाता है, उस नमक को वसूल जरूर करता है। इसलिये मुझे वह बात कहनी पड़ रही है। मेरे उस तरफ के बैठने वाले लोगों से कितनी ही बार बात हुई है, समस्याओं को वे स्वीकार करते हैं, उनकी विकरालता को स्वीकार करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि उत्तर प्रदेश ऐसी स्थिति में आता चला जा रहा है। जब प्रश्न आता है अनुशासन के नाम पर, या यों कहिये कि उनको आजकल के साथियों के कारण जो अनुचित लाभ दिलाया जा रहा है, वे बराबर उद्घोष करते हैं कि हालत बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जोर से उद्घोष किया जाय कि उत्तर प्रदेश की हालत बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश म कोई समस्या नहीं है। यहां की जनता बहुत सुखी है और आज उत्तर प्रदेश बहुत प्रगति कर रहा है। मैं चाहता हूं कि वे उद्घोष करें ताकि जनता सुने कि आपके क्या विचार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने उद्घोषों से वस्तुस्थिति को छिपा नहीं सकते हैं। आज जो गरीब लोग पीड़ित हैं जिनको सुबह भोजन मिलता है तो शाम के भोजन की समस्या बनी रहती है, जो इस महंगाई के कारण भरपेट भोजन भी नहीं पाते, उनका आपके उद्घोषों से पेट भरने वाला नहीं है।

जो समस्यायें पैदा हो रही हैं उनके संबंध में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन के इधर के लोगों ने ही नहीं बल्कि उधर के लोगों ने भी एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा प्रदेश है। श्रीमन्, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि १७ साल के कांग्रेस के शासन में इस प्रदेश को जो प्रगति करनी चाहिये, वह नहीं की। अगर प्रगति की है तो मैं जानता हूं कि दरिद्रता ने प्रगति की है और प्रदेश ने अपने भ्रष्टाचार में प्रगति की है। आपने महंगाई में प्रगति की है और अव्यवस्था में प्रगति की है। इसकी हम जरूर सराहना करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो परिस्थिति पैदा हुई है, आप और जो कहा रहे हैं कि देश पिछड़ गया है और इसकी चिन्ता व्यक्त करते हैं। इसलिये अगर उसका उत्तर-दायित्व आपके ऊपर है तो नैतिक कर्तव्य के आधार पर यह भी स्वीकार करना चाहिये कि इस प्रदेश के शासन में भविष्य में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। प्रदेश की ७१२ करोड़ जनता आपसे कहना चाहती है कि पिछले १७ सालों से हमने आपके कार्य को देखा, आपके शासन या दुःशासन को देखा और उसमें रहे और आपकी जितनी नीतियां हैं वे चलायी गयीं, परन्तु उसका जो दुष्परिणाम हुआ उनसे आप अपने को नहीं बचा सकते। शिक्षा मंत्री ने पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यह कहा कि हमारे यहां शिक्षा का अभाव है। हम शिक्षा में भी पिछड़ हुए हैं क्योंकि यहां की जनता सारे देश में शिक्षा की प्रगति में पीछे रह गयी और इसलिये हम अपनी योजनाओं को भी सफलतापूर्वक नहीं चला पाये। जनता के बीच में जो वातावरण बनाना चाहिये था वह नहीं बना पाये। योजना की सफलता के लिये हम उनके बीच में कोई उत्साह नहीं पैदा कर सके। जब आज हम शिक्षा के पिछड़ापन का अभिशाप भुगत रहे हैं तो हमें यह सोचना होगा कि शिक्षा का प्रसार कैसे किया जाय, प्रदेश में हम कैसे आगे बढ़ें और और प्रदेशों के बराबर जाकर हम कैसे खड़े हों। शिक्षा की प्रगति, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का स्तर तब तक नहीं उठाया जा सकता है जब तक कि आप शिक्षकों को सन्तुष्ट नहीं करते जब तक उनकी कठिनाइयों को आप अनुभव नहीं करते हैं, जब तक अध्यापकों की मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार नहीं करते हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हमें बड़ी सद्भावना है, और हमको सहानुभूति भी है। शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा है कि उनकी जो समान वेतन की मांग है, वह उचित मांग है। समान काम के लिये समान वेतन होना चाहिये। इस समाज-वादी सरकार से मैं पूछता हूं कि अगर आप समानता लाना चाहते हैं तो आपका पहला कर्तव्य यह है कि आप अपने कर्मचारियों और अध्यापकों के, जो समान काम करते हैं, उनको समान वेतन दें। यदि समान के लिये समान वेतन के औचित्य को आप स्वीकार करते हैं तो उनकी मांगों को

[श्री शारदाभक्तसिंह]

भी आपको स्वीकार करना चाहिये । आप यह भी कहते हैं कि अध्यापकों की दशा बड़ी शोचनीय है । वस्तुस्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के अध्यापक और कर्मचारी अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि धनाभाव की समस्या उनके सामने है । जब प्रदेश के अध्यापकों की दशा बड़ी शोचनीय और दयनीय है तो आपको उनकी कुछ सहायता करनी चाहिये, और उन्हें कुछ सुविधा देनी चाहिये । क्या आप औचित्य को स्वीकार करते हैं ? केन्द्रीय सरकार ने इस औचित्य को स्वीकार किया है । पिछले कई सालों से अध्यापकों ने इस मांग को दुहराया है और आपके सामने खड़े होकर अनुनय विनय किया, प्रदर्शन किया और उस पर क्या आप सोच नहीं सकते हैं और कहते हैं कि हमको धमकी दी जा रही है, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । गांव में एक कहावत है कि जो बात आप सोचते हैं वह बाद में सोचते हैं, समय निकल जाने पर । समय निकल जाता है और वातावरण आप ऐसा पैदा कर देते हैं जिसकी प्रतिक्रिया बहुत दिनों तक चला करती है और उसके अभिशाप हम भुगतते हैं । जब अध्यापकों की मांग उचित है, न्याय-संगत है तो उचित वातावरण आप क्यों नहीं बना रहे हैं ?

अध्यापकों और जनता के बीच में अगर आपको जाने का मौका होगा, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप देखेंगे कि आज जनता आन्दोलित है । हजारों अध्यापकों की दशा को देखकर जनता विस्मय में है । यह कैसी सरकार है कि जिसके हाथ में इस देश व प्रदेश का भविष्य है, जो इस प्रदेश को बढ़ाने में बराबर सहयोग देते हैं उनको इसने बेमौके पर चौराहे पर ले जा कर खड़ा कर दिया है और वहां खड़े हो कर वे रोटी मांग रहे हैं । मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप अपने लिए तो खतरा बुला ही रहे हैं, लेकिन साथ ही पार्टी को भी ले डूबेंगे । इसलिए आप वस्तुस्थिति को न भूलें । कल शिक्षा मन्त्री से पूछा गया कि आप डी० आई० आर० का भी इस्तेमाल करेंगे । आपके सामने उन्होंने कहा कि अभी कह नहीं सकता । इस प्रान्त का जो भाग्य होगा वह तो होगा, लेकिन हम इस अविश्वास के प्रस्ताव को इसीलिए लाये हैं कि वस्तुस्थिति जो है उस पर आप गम्भीरता से विचार कर रहे हैं या नहीं, कोई क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं या नहीं । अगर ऐसा आपने किया होता तो फिर इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने का मौका न होता । लेकिन आज आप समस्याओं पर हंसते हैं, उदासीन होकर वस्तुस्थिति को भूलते हैं इसलिए विरोधी दल के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अविश्वास का प्रस्ताव लावें और आपके नैतिक कर्तव्यों को जगावें । कुछ लोग उधर बैठे इस आतुरता में हैं कि मन्त्री जो कुछ कहें और वे हाथ उठा दें । इस हाथ उठाने पर यह सरकार आपको कुछ लाभ दे सकती है, लेकिन अन्त में जनता के प्रति आप उत्तरदायी हैं और उसी को आपको जवाब देना होगा इस सदन के बाहर । (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि आप शान्ति से मेरे विचार सुन लें । मैं आपकी बात भी सुनना चाहता हूं । मैं कह रहा था कि जब तक अध्यापकों को सन्तोष नहीं दिया जाता तब तक इस देश तथा इस प्रदेश के निर्माण में आप सफलता पा नहीं सकते ।

चरित्र निर्माण में जो उदासीनता आपने बरती, उसके प्रति जो दुर्लक्ष्य आपने किया है उसका फल आज राष्ट्र भोग रहा है । राष्ट्रीय चरित्र समाप्त हो गया है । व्यक्ति-व्यक्ति में भ्रष्टाचार है । प्रदेश भ्रष्टाचार से व्याप्त है और प्रदेश के मन्त्री उससे बाहर नहीं हैं । यह कम लज्जा की बात नहीं है । दूसरे देश जिनके सामने हम प्रगति का ढिंढोरा पीटते हैं उनके कानों में यह आवाज पड़ती होगी कि स्थान-स्थान पर आज मुख्य मन्त्री इस देश के भ्रष्टाचार में फंसे हैं । यहां के मन्त्री पर भी जज बैठाया जा रहा है । प्राइमा-फेसी केस बन रहा है । आपको तो शर्म नहीं आती लेकिन उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाते मेरा सर झुक जाता है । क्या यही प्रगति हम कर रहे हैं ? मुझसे कितने पढ़े लिखे आदमियों ने कहा कि अगर प्राइमा-फेसी केस किसी पर बनता है और उसकी जांच होती है तो वह मिनिस्टर कैसे रहता है ? इस प्रदेश का यह अजीब नमूना है । समय की मांग है कि अगर हम पर शंका की जाय तो हम कुर्सी को छोड़ कर अलग हो जायं और कहें कि हमारी जांच की जाय, लेकिन लीपा-पोती की जाती है । उससे काम

चलने वाला नहीं है। आप जनता को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं। इसलिए चुपके-चुपके जांच करते हैं। कभी सदन में बात होती है, कभी मुख्य मन्त्री जांच करती हैं, कभी कोई विजिलेंस कमीशन द्वारा जांच होती है, कभी जज बैठाया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष कुछ नहीं होता। मिनिस्टर मिनिस्टर बना रहता है और अपने पद का वह दुरुपयोग करता है। इस तरह से प्रदेश से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। हमारे गृह मन्त्री कितनी भी कड़ी बात कहें, लेकिन जब तक यहां से यह बात नहीं हटती भ्रष्टाचार फैलेगा और आपकी पुलिस उसे रोक नहीं सकती।

मेरा यह निवेदन है कि अध्यापकों की मांगें न्याय संगत हैं। इस प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख प्राइमरी अध्यापक, ४,१८५ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक विवश होकर परीक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं और इस प्रदेश की सरकार स्त्री हठ पर अड़ी है, मैं चाहता हूं कि जिद इस मामले में नहीं आनी चाहिए। यह जो सरकार ने तय किया कि परीक्षायें होंगी और प्रशासनिक ढंग से परीक्षायें होंगी, यह लोकतन्त्र के लिए लज्जा की बात है। उनकी मांग सही है। अगर उनको उचित वेतन नहीं मिलता है, उनकी दयनीय दशा है तो सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि अपने हठ को छोड़ कर उनकी मांगों के लिए हल निकाले। हमारी योजना है। हमारे पास धन नहीं है लेकिन योजना बनाने वाले हम हैं। कई बार इस सदन में कहा गया कि जनसंघ तो योजना का विरोधी है। जनसंघ योजना का विरोधी नहीं है। हमने कहा है कि इस योजना को बदलो। जिन कारणों से अव्यवस्था होती है, शिक्षा पीछे रहती है, जिसके कारण भीषण स्थिति पैदा होती है उन समस्याओं का पहले समाधान निकालो। योजना के नाम पर यह कह देना कि हमारे पास पैसा नहीं है केवल इसी से सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। सरकार ने शायद सोचा होगा कि अध्यापकों को धमकी दे कर, उनको वह डिमारेलाइज कर लेगी। तो यह कोई अच्छा काम नहीं है। सरकार ने नौकरशाही दृष्टिकोण से मैनेजरों को एक आर्डर निकाला है कि अगर उनकी बात टीचर्स नहीं मानते तो उनके खिलाफ अवज्ञा की कार्यवाही की जाय। इस तरह से टीचरों तथा मैनेजरों को आपस में लड़ा कर सरकार पंचायत करना चाहती है। सरकार प्रदेश की शिक्षा को आग लगाना चाहती है और इस प्रदेश को १० वर्ष पीछे फेंक देना चाहती है इस तरह से प्रशासनिक ढंग इस्तेमाल करके, डिप्टी कलेक्टर तथा कलेक्टर द्वारा परीक्षा का इन्तजाम करके।

आगरे के विद्यार्थियों ने कहा है कि उनको अध्यापकों से सहानुभूति है। मैं सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि यह चिंगारी कहीं विद्यार्थियों में लगी तो आपके डिप्टी कलेक्टर निकलते नजर आयेंगे। मेरा काम आपको आगाह कर देना है, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। विद्यार्थियों ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है उसे मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। मेरे पड़ोस के जिले में एक डिप्टी कलेक्टर गए स्कूल में तो लड़कों ने उनको घेर लिया और कहा कि आप परीक्षा लेने आए हैं। वह चुपके से चले गए। यह समस्या है और इसका समाधान आपको निकालना है। अगर शिक्षा में गड़बड़ी होती है, अव्यवस्था फैलती है तो आप इस प्रदेश का भला नहीं कर रहे हैं। इस समय शान्ति चाहिए। ऐसे कदम आप इस समय उठायें कि प्रदेश में अव्यवस्था न फैले। कहा गया कि केन्द्र ने कहा है कि हम सहानुभूति रखेंगे, लेकिन केन्द्र के द्वारा पैसा प्राप्त होगा या नहीं, यह कहना कठिन है।

मैं इस सरकार पर यह चार्ज लगाता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही कमजोर है। गल्ले का मामला लिया जाय। कहा जाता है कि केन्द्र हमको गल्ला नहीं देता, इसलिए भुखमरी है। हम केन्द्र से कहते हैं, लेकिन हमको आवश्यकतानुसार गल्ला नहीं मिलता। इसलिए यह खाद्य की समस्या बनी हुई है। अगर आपको केन्द्र से गल्ला नहीं मिलता, आपको अध्यापकों के लिए पैसा नहीं मिलता तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है या विरोधी दलों की जिम्मेदारी है? न्याय की मांग है अगर केन्द्र की सरकार आपको गल्ला नहीं देती और केन्द्रीय सरकार यदि आपके अध्यापकों की कठिनाइयों को हल करने के लिए पैसा न दे, तो क्या आपको नैतिक कर्तव्य

[श्री शारदाभक्तसिंह]

नहीं मालूम है कि आप गद्दी छोड़ कर अलग हो जायं कि हम प्रदेश में आग लगाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप शासन छोड़ेंगे नहीं और केन्द्र को बुराई देंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है।

आज अध्यापकों को धमकियां दी जा रही हैं। कल शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि हमें पता नहीं है कि डी० आई० आर० लगायेंगे या नहीं। क्या आपने डी० आई० आर० इसी लिए बनाया था? यह बड़ी विषम परिस्थिति है। यह इसलिए बनाया गया था कि देश की सुरक्षा का काम होगा। इस देश में कौन सा सुरक्षा का काम किया गया है? क्या आपने सिविल डिफेंस का काम किया है? आपने कौन-सा वातावरण पैदा किया है कि अगर आक्रमण होगा तो देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने को बलिदान करेगा? आप कैसे दुश्मन का सामना करेंगे? लेकिन आप तो डी० आई० आर० का इन्तजाम अध्यापकों पर कर रहे हैं।

आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि कच्छ की १३,००० एकड़ जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है उधर चीन पहले से हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है और काश्मीर के एक तिहाई भाग पर पहले से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। फिर भी आप कहते हैं कि अगर आक्रमण होगा तो इन्तजाम करेंगे। लेकिन अभी आक्रमण हुआ नहीं है। आज सुरक्षा के नाम पर जो तरह-तरह के खर्चे किए जा रहे हैं वे समाप्त होने चाहिए। देश की अखण्डता और स्वतन्त्रता सब से ऊपर होनी चाहिए, देश की अखण्डता के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे यहां के प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में यह बात आए कि देश पर खतरा है। इसका आभास तब तक नहीं होगा जब तक शासन के मन्त्री अनुभव नहीं करते हैं। कदम-कदम पर यह अनुभव होना चाहिए, फिजूलखर्ची खत्म होनी चाहिए और ऐसा वातावरण बनाया जाय कि अगर पुलिस मन्त्री या मुख्य मन्त्री बाजार से निकलें तो हजारों व्यक्ति अनुभव करें कि ये ही वे मन्त्री हैं जो दुश्मन से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आक्रमण नहीं होगा। सबसे पहली आपकी सुरक्षा यह है कि आक्रमण नहीं होगा, अगर न हो तो अच्छा है। लेकिन क्या आप अपने हृदय पर हाथ रख कर इसे कह सकते हैं? आप उस जमाने की याद कीजिए जब इंग्लैंड पर आक्रमण हुआ था उस समय क्या-क्या तैयारियां थीं? आप स्थिति को भुलाइए नहीं। मैं इसके कहने में कसर नहीं रखना चाहता हूं कि प्रदेश में जो तैयारियां आक्रमण के प्रतिशोध के लिए होनी चाहिए वे नहीं हो रही हैं। चीन ने एक तमाशा किया था कि आक्रमण करके वापस चला गया ताकि देश सो जाय और देश सो गया और हम उसके षड़यन्त्र में आ गए। हमने समझा चीन वापस चला गया इसलिए खतरा खत्म हो गया। प्रदेश में जो चहलपहल हुई थी वह खत्म हो गई।

आज आपके होम गार्डस् बन रहे हैं। मैंने कई आदमियों से पूछा कि तुम फौज में जाओगे तो उन्होंने कहा कि हम फौज में नहीं जायेंगे। इस भूमिका के साथ आप होम गार्डस् बनाना चाहते हैं। उनमें ऐसे लोग आते हैं जिन्हें पता तक नहीं है कि आक्रमण हुआ या नहीं, जिन्हें पता तक नहीं कि उनके क्या कर्तव्य हैं। आपको उस समय सन्तोष होना चाहिए जब होम गार्डस् में जितने पढ़े लिखे आदमी हैं, जिनका समाज में स्थान है, जो परिस्थितियों को समझते हैं, उस वर्ग के लोग अपने पुत्रों को भेजें या खुद जायं। इसकी परेड में ये लोग खड़े दिखाई दें उस समय आपको सन्तोष होना चाहिए कि देश में कुछ प्रतिध्वनि आ रही है कि हम देश की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन गांव के आदमियों को बुलाकर उनको वर्दी और जूता देकर अगर काम करायें तो वह चलने वाला नहीं है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप भी चाहे इसे अनुभव करते हों कि ऐसा लगता है कि हर समस्या सैचूरेशन प्वाइन्ट पर आ रही है। खाद्य समस्या के लिए कह दिया कि फसल अच्छी हो गई है। लेकिन प्रदेश के लोगों को इस महीने में बजाय ६ किलो गेहूं के ३ किलो दे रहे हैं। इस महंगाई में अगर आप राशन कम करते हैं तो जनता समझेगी कि आपकी बातों में कुछ खोखलापन है। इसका परिणाम यह हुआ है कि समाज के कुछ वर्ग के लोगों ने गल्ला समेटने के लिए

योजनायें बनानी शुरू कर दी हैं। इसलिए आपको इन सारी बातों पर विचार करना होगा। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि हम वास्तविक रूप से समझते हैं कि जो वास्तविक बातें हैं उनको आप अनुभव नहीं कर रहे हैं। आपको इस प्रदेश की खाद्य समस्या को सुलझाना होगा, भ्रष्टाचार को मिटाना होगा देश और प्रदेश में फैली विषमता को मिटाना होगा, समान काम के लिए समान वेतन देना होगा तथा एक त्याग और तपस्या का वातावरण आपको बनाना होगा। एक ऐसा वातावरण आपको निर्माण करना होगा जिसमें हर व्यक्ति अपने स्थान पर यह समझे कि हमारा प्रान्त पिछड़ा हुआ है और हमें इस पर कुरबानी देनी होगी। लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक कि आप अपना आदर्श जनता के सामने नहीं प्रस्तुत करेंगे। यह तब तक नहीं होगा जबतक कि आप गुटबाजी में पड़े रहेंगे। आप तो गुटबाजी में पड़े हुए हैं आपको देश और प्रदेश की क्या चिन्ता है। इस गुटबाजी के नाम पर उत्तर प्रदेश की कितनी हानि हुई है जो आपके अन्दर परोक्ष रूप में है वह अनेक वर्षों तक भी पूरी नहीं हो सकती है। आपके कैबिनेट में एकता नहीं है और रात-दिन इस तरह के षड़यन्त्र जिले-जिले में हो रहे हैं कि कौन गुट ऊपर हो जाय। इसके लिए आपको प्रायश्चित करना होगा। अगर आप अपनी गुटबन्दी से ऊपर नहीं उठ सकते, अगर आप कुर्सी के लिए लड़ना बन्द नहीं कर सकते, अगर एकता का वातावरण आप नहीं कायम कर सकते, अगर दलगत निहित स्वार्थों से ऊपर आप नहीं निकल सकते, एकता का भाव नहीं पैदा कर सकते तो कम से कम इतना तो करिए कि वह आसन छोड़िए ताकि दूसरे लोग आकर इस कमी को पूरा कर सकें। अगर आप नहीं करते तो एक ही बात मैं अन्त में आपसे कहना चाहता हूं कि जो भावात्मक एकता की बात आपने बहुत दिन तक कही, उसके लिए मुझे खतरा नजर आता है। भाषा के नाम पर परोक्ष रूप से कांग्रेस के अन्दर जो हुआ है वह खतरे की घंटी है। इसलिए स्वार्थों को छोड़कर देश की बात सोचकर तथा एकता का भाव पैदा करने के लिए आप प्रयत्न करें। जबतक एकता नहीं होगी, जो भारत की हमेशा खराबी और अभिशाप का कारण रहा है, हम अलग-अलग टुकड़ों में बंटे रहेंगे और अपने हितों को हानि पहुंचाते रहेंगे। कामराज कुछ कहते हैं, प्रधान मन्त्री कुछ कहते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की मुख्य मन्त्री को कि उन्होंने हिन्दी का पूरा समर्थन किया है। यह बड़े अभाग्य की बात होगी कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मन्त्री को इसके लिए लड़ना पड़े कि हिन्दी हो जो कि संविधान के अनुसार होना चाहिए और यहां के तमाम लेजिस्लेटर्स इसे चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो विश्वास की बात हो जायगी।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैं इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि अगर यह व्यवस्था करना चाहते हैं, अभी उधर से लोग खड़े होंगे और कहेंगे कि कांग्रेस आज सबसे ऊंची है, सबसे ज्यादा वोट पाती है। अगर इस कांग्रेस ने यह कहा तो अवश्य प्रदेश उसका फल भोगेगा। बांसी में जो चुनाव हुआ वहां क्या हुआ, उसे आप देखें। जो अब तक आप अंधेरे में रहे बांसी के चुनाव ने आपकी आंखें खोल दी हैं। वहां पर जो परिस्थितियां रहीं, उससे जनता में अविश्वास हो गया है और उसी का परिणाम बांसी के चुनाव में आया। इसलिए आज मैं आपसे मांग करता हूं कि इस प्रदेश के हित के लिए, इस देश के लिए, एकता के लिए, साढ़े सात करोड़ के हित और सुख सुविधा के लिए आज इस मुख्य मन्त्री और उनके मन्त्रि-मण्डल को खत्म होना चाहिए और इसे अब तक मिनट भी शासन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर आप अपने आप हट जायेंगे तो आप जनता के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे और देश पर उसका एक वातावरण बनेगा लेकिन अगर आप नहीं हटेंगे तो इस प्रदेश की जनता इस प्रदेश के चिन्तनशील व्यक्ति, वह चाहे इधर के हों या उधर के हों, अपना लाभ छोड़कर आपको हटने के लिए विवश कर देंगे। मैं समझता हूं कि उधर के सदस्य भी जो इस

[श्री शारदाभक्तसिंह]

प्रदेश का हित चाहते हैं, क्योंकि इस प्रदेश के बारे में आपका भी उत्तरदायित्व है इस प्रस्ताव को अपना समर्थन देकर, जो वक्त की मांग है, वक्त का तकाजा है, उसको पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि जनतन्त्र के अन्दर विरोधी पक्ष को यह अधिकार है कि वह सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उसको हटाने की चेष्टा करे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय अहमद बख्श, इस तरह से बीच में खड़े होकर बात करना अनुचित है ।

श्री नवलकिशोर—

अविश्वास का प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण हथियार है जिसका प्रयोग आमतौर से आखिरी तौर पर किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि यह अविश्वास का प्रस्ताव एक प्रकार से सालाना रस्म अदायगी की तरह हो गया है, वक्त नावक्त, मौके बेमौके वह रस्म अदायगी कर दी जाती है। मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं थी मगर जिस ढंग से भिन्न-भिन्न पार्टियों ने अपने प्रस्ताव पेश किए और बजट सेशन में वह दो बातों का सबूत देती है। एक तो यह कि या तो विरोधी पक्ष जिम्मेदारी से काम नहीं कर सकता, करना नहीं चाहता या दूसरे विरोधी पक्ष भानुमती का पिटारा है और उसके अन्दर कोई सामंजस्य नहीं है। मान्यवर, मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं । अगर थोड़ी देर के लिए यह मान भी लें कि विरोधी पक्ष अपनी शक्ति से सरकार को नहीं हटा सकते और सरकार यह सोचे भी कि इनकी सहानुभूति में हम स्वयं हुकूमत से हट जायं तो भी एक विषम समस्या सामने आ जाती है है कि हुकूमत की बागडोर किसके हाथ में दी जाय। बजट के मौके पर जनसंघ की तरफ से कम्युनिस्टों के लिए कहा गया कि इनको गोली मारनी चाहिए, कम्युनिस्टों ने कहा कि इनके पेट में अनाज ह निकाल लिया जाय। अगर हुकूमत इनके हाथ में दे दें तो ये एक दूसरे को गोली मारेंगे और पेट फाड़कर अनाज निकालेंगे। देश की क्या दशा होगी ? केवल कैओस और एनार्की हो जायगी। शारदाभक्त-सिंह जी के भाषण को सुनकर हमें एक शेर याद आ गया—

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरए खूं न निकला।"

मान्यवर, ढाई घंटे का समय अध्यापकों के सम्बन्ध में वादविवाद के लिए निश्चित हो चुका है, तो अगर इस अविश्वास के प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद को टीचर्स के सम्बन्ध में विवाद की संज्ञा दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उनके पूरे भाषण में रोष इसी बात पर था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अभी तो करारे हमले होंगे ।

"इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या,
आगे-आगे देखिए होता है क्या ।"

श्री अध्यक्ष—

अभी तो अपने करारे हमलों को अपने कोष में रखिए, वक्त पर निकालिएगा ।

श्री नवलकिशोर—

उग्रसेन जी, आपके हर हमले का यहां से जवाब दिया जायगा। मान्यवर, शारदाभक्त-सिंह जी ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में अध्यापकों की बात कही। मान्यवर, कौन नहीं जानता कि अध्यापक वह वर्ग है जिसका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है और भविष्य का समाज का निर्माता है। लेकिन साथ ही साथ हमारे मित्र ने यह भी माना है कि यह प्रदेश बहुत पिछड़ा है, आर्थिक बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनसमुदाय में टीचर्स नहीं हैं। अगर प्रदेश में पर कैपिटा इन्कम सबसे कम है तो फिर उसी हिसाब से टीचर्स भी स्थिति हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह—

लेकिन मिनिस्टरों की तनख्वाह तो बहुत बढ़ी है, कमी उसमें तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

शारदाभक्तसिंह जी, आपका पद ऐसा है कि आप बीच में न बोलें तो अच्छा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

विरोधी दल के नेता जब बोल रहे थे तब मन्त्री लोग बीच-बीच में टोक रहे थे तब यही बात आपने उनके लिए नहीं कही।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इशारा कर दिया, अगर आप ठीक समझते हैं और बोलना चाहते हैं, तो बोलें।

श्री नवलकिशोर—

मैं एक बात कहता हूं कि सरकारी पक्ष से कभी किसी ने इस बात का दावा नहीं किया कि उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की स्थिति अच्छी है। किसी ने यह बात नहीं कही। सबने इस बात को कहा कि उनकी मांग, जो भी वह अपनी मांग करते हैं, उनको करने का अधिकार है। यदि हमारी सरकार उनको सुविधा दे सके तो हमारे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। मौजूदा स्थिति ऐसी है कि उसमें वे सुविधा उनको नहीं दे सकते।

ग्रेड की बात कही गयी। जहां तक उनके ग्रेड की बात है और जहां तक प्राइमरी टीचर्स का सवाल है यह बात मानी हुई है कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन सरकार ने उनके लिए भी हमेशा कुछ न कुछ करने का प्रयत्न किया है। जहां तक सेकेन्डरी स्कूलों के टीचर्स का सवाल है, जिनकी तरफ से यह माध्यमिक शिक्षक संघ का आन्दोलन है उसके सम्बन्ध में मैं १, २ मिनट लेना चाहता हूं हमारे यहां और सारे देश में और प्रदेशों में ट्रेन्ड ग्रेजुएट का क्या ग्रेड है वह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं—

ट्रेन्ड ग्रेजुएट के स्केल विभिन्न स्थानों पर निम्न प्रकार हैं:—

	रु०
यू० पी० में	.. १२०—३००
केरल में	.. ८०—१६५
पंजाब में	.. ११०—२५०
राजस्थान में	.. १००—२२५
महाराष्ट्र में	.. १२०—३००
वेस्ट बंगाल में	.. १००—२२५
उड़ीसा में	.. १००—२१०
मैसूर में	.. १५०—२५०

[श्री नवलकिशोर]

मान्यवर, इसी प्रकार से ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट का स्केल हमारे यहां यू० पी० में और दूसरी जगहों पर क्या है वह मैं बतलाना चाहता हूं—

	रु०
यू० पी० में	७५–२००
केरल में	४०–१२०
पंजाब में	६०–१२०
राजस्थान में	७०–१४०
महाराष्ट्र में	७०–१५०
वेस्ट बंगाल में	७०–१५०
उड़ीसा में	६०–१००
मैसूर में	७५–१८०

तो जहां तक इन स्केल्स का सम्बन्ध है अगर और प्रान्तों के मुकाबले में ज्यादा नहीं तो कम भी इतने नहीं हैं कि जिसके आधार पर यह कहा जाय कि बहुत भारी अन्तर है। जहां तक महंगाई भत्ते का प्रश्न है मैं यह बतलाऊं कि सन् १९४७ में सबसे पहले हमारे यहां हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों का एक ग्रेड बनाया गया और उसको रिवाइज किया गया। १९६१ में इस बात की कोशिश की गई कि प्राइवेट स्कूलों को और गवर्नमेंट स्कूलों को एक स्तर पर ले आयें और उसमें सरकार ने लगभग ६० लाख रुपया खर्च किया। हमारे भाई यह जानते होंगे कि सन् १९६१ के पहले हमारे यहां जो महंगाई भत्ता था वह ७० रुपये तक १० रुपया मिलता था। अब उसके बाद उसको २० रुपया किया गया। इस वर्ष भी जो हमारे प्रिंसिपल और हेड मास्टर थे उनको भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। प्राइमरी वालों का भी ५ रुपया बढ़ाया गया और हमारे यहां जो डिग्री कालेज हैं उनके टीचरों को और नान टीचरों को, जो ३५० रुपये पाते हैं, उनके लिये महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इन तीन सालों में ५ करोड़ रुपया सरकार ने इस मद में खर्च किया है। एक बात यह भी कहना है कि जो विद्यार्थियों से पैसे लेते हैं १ रुपया डियरनेस की शक्ल में, उसके आंकड़े मैंने पहले भी यहां पर उपस्थित किये थे। वह पिछले तीन साल के यह हैं कि बावजूद उस फीस लेने के हमारी सरकार ने उसके लिये किसी साल २० लाख, किसी साल ३५ लाख और किसी साल ४९ लाख रुपये अपने पास से दिये हैं। इसलिये ऐसी बहुत-सी चीजें हैं कि जिन पर सरकार ने उनकी बात को माना है और उनको सुविधा पहुंचाने की कोशिश की है।

इसके अलावा हमारे यहां जो इंटरमीडियेट ऐक्ट बनाया गया है उसमें अध्यापकों की सर्विसेज की सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश की गई है। मैं टीचर्स की मांग के बारे में एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह सोचें कि अगर प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को ५० रुपया दें तो उसके लिये ४ करोड़ रुपया चाहिये। माध्यमिक शिक्षा के टीचरों के लिये भी सवा दो करोड़ रुपया चाहिये। सवा छः करोड़ रुपये तो यह हुए और डिग्री कालेजों के टीचरों को भी इस में शामिल कर लिया जाय तो साढ़े सात, आठ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जो उनको देने के लिये और चाहिये। श्रीमन्, सदन को याद होगा कि शारदा भक्त सिंह जी ने इस बात का अल्टीमेटम दिया था कि यदि टैक्स बढ़ाया गया तो जनसंघ आन्दोलन करेगा। एक तरफ तो आप ८ करोड़ रुपये देने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ टैक्स का विरोध करने की बात कहते हैं, यह न्यायसंगत नहीं है। टीचर्स के सम्बन्ध में आपने कहा कि उनका बड़ा गौरवपूर्ण स्थान है। सही बात है। मैं सौ फीसदी इत्तफाक करता हूं कि उनका एक ऊंचा स्थान है मौजूदा ढांचे में, लेकिन टीचर्स को आइसोलेशन में लेकर चलने से काम नहीं चलने वाला है। आपको राज्य के सारे कर्मचारियो में एक समन्वय करना होगा और बिना ऐसा किये सरकार कोई कदम उठाती है तो वह गलत होगा। आपको बैठ कर बतलाना चाहिये कि सरकार कैसे इन सबको एडजस्ट करे। इसके अलावा डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स हैं। उनकी भी अपनी समस्याएं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, दस मिनट हो गये ।

श्री नवलकिशोर—

अगर गवर्नमेंट सबको सब्सीडाइज करेगी तो नहीं मालूम बजट कितना बढ़ जायगा । इसके साथ ही आप कहते हैं कि टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है । यह ठीक है कि अध्यापकों को मांग करने का अधिकार है, लेकिन हम भी जितना दे सकते थे वह हमने दिया है। लेकिन आज अध्यापकों ने मांग उस समय की है जब विद्यार्थियों के इम्तिहान सिर पर हैं और इसलिये मैं उनका घोर विरोध करना चाहता हूं । आपने पेरेन्ट्स की बात कही, आप भी मां-बाप हैं, सैकड़ों रुपया खर्च करने के बाद आज अगर स्टूडेन्ट्स की जिन्दगी के साथ टीचर्स खेलना चाहते हैं और उसे ले कर हमें धौंस देना चाहते हैं तो यह बड़ी अशोभनीय बात है । शारदाभक्तसिंह जी ने कहा कि यह चिन्गारी विद्यार्थियों में भी फैल जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह आग फैली तो केवल सरकारी पक्ष ही नहीं, सारा प्रदेश इस में भष्म हो जायगा और इसकी जिम्मेदारी विरोधी पक्ष की होगी । (व्यवधान) शारदाभक्तसिंह जी ने कहा कि उनका शिर शर्म से झुक जाता है जब वे किसी मंत्री के विरुद्ध जांच की बात सुनते हैं । अगर सरकार किसी मंत्री की जांच के लिये किसी जज की नियुक्ति करती है तो उसमें तो आपका शिर शर्म से नहीं झुकना चाहिये । उसकी मांग तो आपने ही की थी, उस पर मंत्री महोदय ने भी कहा कि जांच जरूर की जाय । उसी को मुख्य मंत्री जी ने माना है । यह तो आपके लिये तारीफ करने लायक बात होनी चाहिये । मैंने पहले भी कहा है और फिर कहता हूं कि अगर यह तरीके विरोधी दल ने न छोड़े तो यहां की जनता में जनतंत्र के प्रति जो आस्था है वह उठ जायगी और ऐसा होने से देश में तानाशाही आयेगी और इसके जिम्मेदार आपके ये कारनामे होंगे । एक तरफ आपको इस तरह की बातों से शर्म आती है और दूसरी तरफ आपको हाउस में छूट है कि आप जो चाहें कहें, यह ठीक नहीं है । (व्यवधान) ।

मैं दो चार बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । यह बात कही गयी कि उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़ापन है । यह बात सही है । मैं आंकड़ों में ज्यादा जाना नहीं चाहता लेकिन पिछले तीनों प्लान आप देखें तो पता चलेगा कि यद्यपि हमारा पर कैपिटा इंवेस्टमेंट बढ़ता गया है, लेकिन आल इंडिया के मुकाबले में वह बहुत कम था । पंजाब के मुकाबले में तो वह बहुत ही कम था । यह सभी जानते हैं कि जब तक पर कैपिटा इंवेस्टमेंट हमारा नहीं बढ़ता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते । यह खुशी की बात है कि जो हमारा कैपिटल आउटले का टार्गेट था पहले और दूसरे प्लान का, उसमें कुछ लैकुना रह गया था उसे इस प्लान में पूरा करने की चेष्टा की गयी है और अगर हमको पूरा सहयोग मिला तो ५३२ करोड़ तक हम पहुंच जायंगे । इसके माने यह हैं कि हम चौथे प्लान की अच्छी बुनियाद डाल सकेंगे ।

मुझे एक बात यह निवेदन करनी है कि नेता विरोधी दल ने कोई एक भी बात ऐसी नहीं कही जिसके बल पर यह कहा जा सके कि इसलिये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये । यह मुहब्बत का आदान-प्रदान तो है नहीं कि आपने कहा हट जाओ और हम हट गये । गवर्नमेंट को तो हटाया जाता है और उसके लिये आपके पास शक्ति नहीं है । यह हमारे लिये भी दुर्भाग्य की बात है, आपके लिये भी ।

मान्यवर, इसमें चीन और पाकिस्तान की बात भी आ गयी । चीन के हमले की बात भी आ गयी । यद्यपि मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है और वह इस तरफ पूरी तरह से जागरूक है मगर फिर भी बताता हूं कि अगर चायना से हमले की बात आती तो उत्तर प्रदेश की सरकार और जनता चाहे निहत्थी हो, उसका डटकर मुकाबला करेगी । लेकिन शारदाभक्त सिंह जी अगर केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारियों के लिये हमें गालियां देना चाहें तो उचित यह होगा कि वह कोई दूसरा तरीका निकाल ले . . . (लाल बत्ती होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपका एक मिनट है ।

श्री नवलकिशोर—

मैं अभी समाप्त करता हूं । आपने सिविल डिफेंस की बात कही । मुझे भी बोर्डर पर जाने का मौका मिला है । जहां तक होमगार्ड का ताल्लुक है वह बहुत उत्तम है, पहाड़ में और बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में । सिविल डिफेन्स में यह जरूर है कि उतनी तैयारी नहीं है, यह सही है । एक महीने की ट्रेनिंग होती है और ५०, ६० हजार विद्यार्थी निकाल दिये हैं, मैं उस से बहुत संतुष्ट नहीं हूं । लेकिन जो बात आप लायें उसकी यहां जरूरत नहीं थी ।

कैबिनेट की जो बात आप कहते हैं, तो इतनी बड़ी पार्टी जहां होती है उनमें मतभेद होते हैं । मैं डिफेंड नहीं करता हूं । उग्रसेन जो बैठे हुये हैं । पी० एस पी० में और उनकी पार्टी में जो कांड हुए हैं वह भी आप जानते हैं । जो कम्युनिस्ट भाई हैं जो उनका भी जो नाच केरल में हो रहा है उसको चन्द्रजीत जी जानते हैं । तो अच्छी परम्परा यही है कि जो अन्दरखाने के डिफरेंसेज हैं उनको यहां बहुत ज्यादा इको न करें ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आप व्यवस्था करें कि कितना-कितना समय है ?

श्री अध्यक्ष—

१० मिनट और १५ मिनट, यह समय है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इनको १६–१७ किस प्रकार से मिले ?

श्री अध्यक्ष—

वह मेरे ऊपर छोड़िये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अविश्वास के प्रस्ताव का केवल अपनी ही ओर से नहीं, बल्कि इस प्रदेश की करोड़ों जनता की ओर से समर्थन प्रकट करता हूं । मैं उधर के बैठने वालों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से नवलकिशोर जी की बातों को गम्भीरता पूर्वक सुना है, इधर के लोगों की बात भी सुनिये । हल्ला करने से काम चलने वाला नहीं है । यह तो आत्म-चिन्तन करने का समय है । अगर हो-हल्ला हो तो आप अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं और जो कमियां हैं उनको दूर करना नहीं चाहते हैं ।

नवलकिशोर जी ने कहा कि विरोधी दल कई गुटों में बटा हुआ है, सरकार कैसे वह बना सकते हैं और यह राज सत्ता कैसे उनके हाथों में आ सकती है । तो मैं केवल एक ही वाक्य कहूंगा कि इस कांग्रेस दल की हालत क्या है ? १९५२ से १९६२ का सिंहावलोकन इसी हाउस का कर लीजिये, और को छोड़िये । १९५२ में आपको याद होगा कि इधर के बैठने वालों की तादाद ४० थी । १९५७ में वह ८० हुई और १९६२ में १८० हो गयी । तो आप फैसला कीजिये कि सरकार की हालत क्या हो रही है, कांग्रेस पार्टी की हालत क्या हो रही है । सारी दुनियां का इतिहास उठा कर देखिये, दुनियां में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कांग्रेस के मुकाबले में जिसका इतना महान पतन हुआ हो और जिसकी आस्था जनता के दिलों में लगातार तेजी से उठती चली जा रही हो ।

कहा जाता है कि सरकारी और गैरसरकारी अध्यापकों में कोई अन्तर नहीं है। अध्यापक संघ की मांग रही है कि आप प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कीजिये। और यदि नुक्स न सरकार को नहीं है तो राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती है? स्पष्ट है कि आप दोनों में अन्तर मानते हैं। कैलाश प्रकाश जी ने विधान परिषद् में कहा है कि हमने १९६२ में माध्यमिक शिक्षक संघ के आग्रह पर २० रुपया महंगाई भत्ता बढ़ाया है। उधर के बैठने वाले जरा अपना दिल टटोलें। महंगाई कितनी बढ़ गई है। २२ लाख रुपया बढ़ाया गया और आज उनकी संख्या में वृद्धि के कारण आपके शब्दों में वह ४९ लाख के करीब होता है। मैं जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी स्कूलों के छात्रों की महंगाई फीस दूनी क्यों कर दी गई? छात्रों से दूनी फीस ले कर सरकार ने भत्ता बढ़ाया है। जनता जानती है कि प्रत्येक अध्यापक को सरकार ५ रुपये से अधिक महंगाई नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आमदनी में क्या अन्तर है? सरकार गैर-सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से दूनी महंगाई लेती है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से नहीं लेती, यह क्या इन्तजाम है? मैं और भी कहना चाहता हूं कि सरकार छेड़े नहीं अध्यापकों को। जो अध्यापक शान्तिपूर्वक बोर्ड की परीक्षा का केवल बहिष्कार करना चाहता है उसको छेड़कर सरकार अपने प्रान्त की शान्ति भंग न करें। परीक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं, कीजिये, लेकिन अन्ततोगत्वा मैं कहूंगा कि सरकार सफल नहीं होगी। अगर सरकार ने छेड़खानी की और गैर-कानूनी बर्ताव किया तो हम सब लोग उसको चुपचाप बैठ कर देख नहीं सकते हैं। उस संघर्ष में इस प्रदेश की लाखों-लाखों जनता साथ देने के लिये तयार है। जब कि २ लाख माध्यमिक संघ के अध्यापक और साढ़े ५ लाख विद्यार्थी इस ज्वाला में फंसने वाले हैं तो मैं सरकार की इस नीति को अनुचित समझता हूं। आज सरकार के कर्मचारी लाखों-लाखों की तादाद में नाराज हैं फिर भी सरकार हुकूमत चलाना चाहती है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हुकूमत फेल है, सरकार नहीं चलाना चाहिये।

एक दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री परिषद् क्या होती है? उसका प्रत्येक सदस्य एक साथ मिलकर काम करने की शपथ लेता है और गोपनीयता की शपथ लेता है। मैं अदब के साथ सुचेता जी से पूछ ना चाहता हूं कि क्या आपकी मंत्री परिषद् में गोपनीयता है, एक साथ जुटकर काम करने की शक्ति है? आप याद रखिये, पाकिस्तान जिसकी आप निन्दा करते हैं वहां खुरो को सजा दे दी गयी। इसलिये दे दी गयी कि उसने गबन किया था। आज ख्रुश्चेव, जिस पार्टी के नेता, श्री झारखंडे राय यहां बैठे हुये हैं, वह क्यों हटा दिये गये? इसलिये हटा दिये गये कि उन्होंने खेती-बाड़ी में कम गल्ला पैदा किया। सरकार तो स्वयं कबूल कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में १९६१ से १९६४ तक लगातार गल्ले में कमी हुई है। जब सरकार ही स्वीकार करती है तो क्यों नहीं इस मंत्रिपरिषद् को भंग कर देती हैं? नेगी जी बैठे हुये हैं। मैं चार्ज करता हूं, उनको खुद इस्तीफा देना चाहिये। उन्होंने रबी की फसल के लिये कहा था कि हमारे प्रदेश में गल्ले की कमी नहीं है। हम विरोधी दल के लोगों ने कहा था कि रबी की फसल मारी गयी है। उन्होंने कहा था कि गल्ला इतना ज्यादा है कि १८ महीने तक खिलाऊंगा। आज क्या हालत है? आज सुचेता कृपलानी जी और नेगी जी कहते हैं कि सचमुच ४० लाख टन गल्ला कम हुआ है। आज मुख्य मंत्री और उनकी परिषद् के सदस्य इस तरह से सदन में गलत प्रचार करते हैं और करोड़ों जनता को भूख से मारने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। ऐसी सरकार को अपने आप अलग हो जाने का संकल्प करना चाहिये और नेगी जैसे मंत्री को हटा देना चाहिये।

इस मंत्रि-परिषद् में कुनबापरस्ती है, जाति-बिरादरी का बोल-बाला है, भ्रष्टाचार है। एक उदाहरण मैं माननीय हरगोविन्द सिंह जी के बारे में रखना चाहता हूं। माननीय काशीनाथ जी ने कहा था तो माननीय हरगोविन्द सिंह जी नाराज हो गये थे, रामसूरत सिंह के सम्बन्ध में जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, माननीय जज ने जो लिखा है उसको वे देखने की कृपा करें। मैं चाहूंगा कि उस जजमेंट की कापी छपवा कर अपनी ओर से मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को वितरित कराऊं। माननीय जज ने लिखा है "छठी परिस्थिति जिसको कि प्रार्थी ने आधार

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

माना है इस मामले में, अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह राम सूरत सिंह की रिहाई से सम्बन्धित है जिसको कि प्रार्थी ने डकैतियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। रिहाई तक जो तथ्य निर्विवाद हैं वे निम्नलिखित हैं—"२८ जनवरी, १९६४ को ठाकुर हरगोविन्द सिंह ने रामसूरतसिंह की तथाकथित गिरफ्तारी की जांच के लिये निर्देश दिया। यह जांच सर्किल अफसर, श्री एस० आई० शर्मा ने की और उन्होंने इसकी रिपोर्ट २९, जनवरी १९६४ को दी"। श्रीमन्, इसमें कहा गया है कि उनकी रिपोर्ट पर ३ दिन के अन्दर ही बिना किसी शिनाख्त हुये उसकी रिहाई कर दी गयी। माननीय न्यायाधीश ने यह माना है कि बिना शिनाख्त हुये इतनी जल्दी एक डकैती के मुल्जिम को रिहा कर देना एक महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार बताये कि क्या किसी और केस में कभी ऐसा हुआ है जब कि डकैती के जुर्म में किसी की गिरफ्तारी हुई हो, गवाह भी उसके लिये मौजूद हों, और बिना शिनाख्त किये हुये उसकी रिहाई ३ दिन के अन्दर हो गयी हो ? मान्यवर, उसी जजमेंट में यह भी लिखा है "यह रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासिक्यूटर द्वारा उसी दिन पेश की गयी और उसी दिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उनकी रिहाई के आदेश पारित करने का निदेश दिया।" इस तरह से मान्यवर, शासन नहीं चलता। मैं अनेकों उदाहरण इसी तरह के आजमगढ़, बलिया, जौनपुर आदि के दे सकता हूं। आज जाति-बिरादरीवाद का बोलबाला है। उससे हजारों आदमी त्रस्त हैं। मैं चाहता हूं कि आपके मंत्रिपरिषद् के सदस्य कम से कम ऐसा काम करें जिस से हमें आप पर विश्वास हो। मैं नाम नहीं लेता, मगर आपकी पार्टी के ही अनेकों माननीय सदस्यों ने कहा है, मंत्रिपरिषद् के पुराने सदस्यों ने कहा है कि सरकार के काम गलत हुये हैं और उन्होंने असंतोष प्रकट किया है। इसी सदन में माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा, माननीय गोविन्द सहाय, विधान परिषद् में माननीय अलगूराय शास्त्री ने जो कहा है उसे आप देखें। जिस प्रकार माननीय सम्पूर्णानन्द मंत्रिमंडल के समय ९८ माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्रकट किया था, उसी तरह से आज के मंत्रिमंडल के खिलाफ भी सरकार की पार्टी में बहुत बड़े तादाद में ऐसे माननीय सदस्य हैं जो चाहते हैं कि यह मंत्रिपरिषद् हटे। आज जो कुनबापरस्ती और जाति-वाद का बोल-बाला है उस से सभी नाराज हैं। इसलिये नैतिकता का तकाजा है कि आप दूसरों को मौका दीजिये, कुर्सी छोड़िये। यह मंत्रिपरिषद् आज बिलकुल कुंठित हो चुका है, लुन्ज-पुन्ज है और श्रीमन्, इस प्रदेश में सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कायम कर सकती है जिससे जन मानस में श्रद्धा का स्थान प्राप्त कर सके।

मैं जहां सरकार की नीतियों की बात करता हूं वहीं और निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को देखिये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखिये, तृतीय पंचवर्षीय योजना को देखिये, हमारे पास आंकड़े तो बहुत ज्यादा हैं और मैं चाहता था कि देर तक बोलूं, आप पांच मिनट और बढ़ा दें, तो मैं आपकी मदद कर सकूं। प्रदेश की बात करना चाहता हूं, श्रीमन्, जरा सा माननीया मुख्य मंत्री जी पढ़े कि दिल्ली की सरकार ने उनको क्या दिया है, नवलकिशोर जी ने कहा कि दिल्ली की बात हमारे ऊपर क्यों लादते हैं ? जब मैं चीनी के विरुद्ध गन्ने के दाम के खिलाफ, खाद्यान्न के भाव के खिलाफ आन्दोलन करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यवाही के खिलाफ हमें आन्दोलन करते हैं, तो नवलकिशोर जी आपकी पुलिस और आपकी सरकार जेलखाना भेज देती है। फिर मैं किस प्रकार सरकार की मदद कर सकता हूं ? मैं तो चाहता हूं कि ऐसे वक्त में हमारे अन्दर ऐसी शक्ति मिले कि इस प्रदेश की सरकार को हटादें। प्रदेश और दिल्ली की सरकार से मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं एक स्वस्थ विरोधी दल बनाना चाहता हूं। हमारी पार्टी स्वस्थ वातावरण चाहती है। सरकार क्यों नाराज है ? सरकार अपने पूर्व नेताओं का अनुकरण करे, जो स्वस्थ परम्परा चाहते थे।

समयाभाव के कारण अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगा। मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश की सरकार ने उन्नति में पीछे गिराया है। पूरे देश को सारे प्रदेशों की दशा सरकार देख ले। श्रीमन्, मेरे पास तालिका बहुत बड़ी है। उत्तर

प्रदेश की सरकार इतनी कमजोर सरकार है, जो और प्रदेशों के मुकाबले में, यहां की जनता को उद्योगधंधे भी दिलाने में असमर्थ है। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या मिला है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना में साढ़े सात करोड़ मिला है। जब कि बिहार में १०३ करोड़, मद्रास में ४६ करोड़, महाराष्ट्र में ३६ करोड़, आसाम में २० करोड़, उड़ीसा में ३७ करोड़, केरल में साढ़े सात करोड़, आंध्र प्रदेश में साढ़े सात करोड़, हमारे प्रदेश को केरल के मुकाबले में कम और आंध्र के मुकाबले में कम धनराशि मिली है। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान की आबादी का पांचवां हिस्सा है, इसको मिलना चाहिये पांचवां भाग और आज जो मिल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में १/४२ भाग। नये प्रोजेक्ट में जो आश्वासन मिला है बिहार में ३५ करोड़, मद्रास में ३१ करोड़, बंगाल में ७४ करोड़ और उत्तर प्रदेश में ४१ करोड़। इस प्रकार से १/१३ उत्तर प्रदेश का हिस्सा पड़ता है। इस प्रकार की सहायता सरकार को मिली है और सरकार हिमाकत करती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को खुशहाल करेंगे। आज इस सरकार में ताकत नहीं है, संगठन नहीं है, एक दिल नहीं है, हिम्मत नहीं है केन्द्रीय सरकार से लड़ने की। लाखों अध्यापक और सरकारी कर्मचारी सरकारी नीति से नाराज हैं।

श्रीमन्, मैं आखिरी निवेदन सरकार और माननीय सुचेता कृपालानी जी से करना चाहता हूं, जो अपने को कहती हैं कि मैं गांधी जी की वारिस हूं। (व्यवधान) गांधी जी के साथ में रहने वाली आप हैं . . .

मुख्यमंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं कभी क्लेम नहीं करती हूं कि मैं गांधी जी की वारिस हूं, यह मैं बड़ी माडेस्टी के साथ कहना चाहती हूं, हां, मैं उनके साथ रही हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

गांधी जी का नाम हर वक्त लिया जाता है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गांधी जी के नाम पर सारा काम किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं माननीय सुचेता कृपालानी जी से कि क्या गांधी जी ने ऐसे ही स्वराज्य की कल्पना की थी? गांधी जी ने स्वराज्य की कल्पना की थी और आप मंत्रिगण जो बैठे हुए हैं उस राज्य को बनाने का संकल्प कीजिए और नहीं तो म स्पष्ट कहना चाहता हूं और प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार खुद ईमानदारी और नैतिकता से आपके कार्यों को नहीं करती है, तकलीफों को दूर करने के लिए तैयार नहीं है, तो डट जाओ, जग जाओ, संगठन में आओ, ऐसी शक्ति पैदा करो कि सरकार को संघर्ष के जरिए यहां से ढकेल करके अलग कर दो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधीदल द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव इस सरकार के विरुद्ध लाया गया है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने जो मुख्य-मुख्य बातें रखी हैं, उनका कुछ थोड़ा सा जिक्र करना चाहता । एक खास बात के लिए यह अविश्सास का प्रस्ताव लाया गया है और वह है शिक्षकों की समस्या। मान्यवर, पहली बात तो यह है कि मैं शिक्षकों की समस्या को इतन महत्व की समस्या समझता ही नहीं कि जिसके लिए सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सके। मैं मानता हूं, हमारी सहानुभूति है इस बात के लिए कि हमारे शिक्षकों की तनख्वाह उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए जितनी कि हमारी सरकार चाहती है, परन्तु.....

श्री नेकराम शर्मा—

प्वाइंट आफ आर्डर। आपने यह व्यवस्था दे रखी है कि डाइस पर कोई माननीय सदस्य नहीं आयेंगे, लेकिन संसदीय मंत्री फिर पहुंच गये आपके पास।

श्री बृजभूषणशरण--

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि शिक्षकों की इस वक्त की हालत के साथ हम सबकी सहानुभूति है। मगर हम इस बात का घोर विरोध करते हैं कि जो तरीका शिक्षकों ने अख्तियार किया है वह बिलकुल ट्रेड यूनियन की तरह का तरीका है। यह वह वर्ग है जिसे हम गुरुजन कहते हैं और गुरुजनों का यह तरीका कि वह स्ट्राइक पर उतर आयें और बच्चों की एक साल की पढ़ाई का सत्यानाश कर दें, इस बात के लिए कि वह तनख्वाह की मांग करते हैं, यह उचित नहीं है। एक वक्त था कि जब गुरुजनों का आदर था, वह राष्ट्र के निर्माता कहे जाते थे, और वह भिक्षा मांगकर के अपनी गुजर किया करते थे, मगर आज यह एक तरह का प्रोफेशन है..

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

माननीय शरण जी, अध्यापक राज्य नहीं मांग रहे हैं आपसे। वह सिर्फ आपसे भिक्षा ही मांग रहे हैं।

श्री बृजभूषणशरण--

अगर अध्यापक सिर्फ भिक्षा ही मांग रहे हैं तो यह वक्त नहीं था, यह तरीका उचित नहीं था कि इम्तिहानों का बहिष्कार कर भिक्षा वह मांगते। सरकार ने अपनी जायज मांग रखने का हमेशा उनको मौका दिया है। सरकार कब कहती है कि अपनी जायज मांग वह उसके सामने न रखें ? परन्तु सरकार अपने सीमित साधनों को देखते हुए जो कुछ कर सकती है वह करेगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या आपके गुरुजन रिटायर हो गये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

जरा शांत रहें आप लोग।

श्री बृजभूषणशरण--

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि इस तरीके की मांग को तमाम विरोधी दलों ने प्रोत्साहन देकर इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम लिया है। मैं मानता हूं कि इस बात को कि किसी और बात के ऊपर सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता, कोई ऐसे तर्क हमारे सामने प्रस्तुत किये जाते तो हम भी जैसा कि रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा है उठते और साथ देते। कहा गया कि सुरक्षा का कौन सा प्रबंध किया है ? सुरक्षा का कौन सा प्रबंध नहीं किया, एक भी बात ऐसी नहीं बताई गई। बात क्या कही गई कि चीन सिक्किम पर हमला कर रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, यह उत्तर प्रदेश की सरकार भला इसमें सुरक्षा का क्या प्रबंध कर सकती थी ? जहां तक सिविल डिफेंस का संबंध है, माननीय नेता विरोधी दल ने केवल यह कहा है कि होम गार्ड्स में इधर उधर से लाकर लोग खड़े कर दिये जाते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने हरदोई की होम गार्ड्स को देखा है या नहीं, लेकिन मैं अपने जिले की कह सकता हूं कि वहां रैस्पेक्टेबिल लोग होम गार्ड्स में हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में जब आक्रमण हुआ था तो क्या हुआ था। क्या वहां यही हुआ था जो यहां हो रहा है ? वहां सरकार और विरोधी दल सब मिल कर एक हो गये थे ? वहां १ अंडा और आधी डबल रोटी एक हफ्ते में दी जाती थी। फिर भी वहां किसी ने आवाज नहीं उठाई।

श्री शारदाभक्तसिंह--

यहां गुलछर्रे उड़ाते हैं।

श्री बृजभूषणशरण—

उन्होंने कहा कि गुलछर्रे उड़ाये जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड में आक्रमण के समय किसी मिनिस्टर ने अपनी तनख्वाह नहीं घटाई।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

रवीन्द्रालय में कव्वालियां चलती हैं।

श्री बृजभूषणशरण—

मुझे अफसोस है कि हरीश कुमार जी ऐसा कहते हैं। मान्यवर, हम तो उठकर चले आये थे लेकिन हरीशकुमार जी वहीं बैठे रहे थे।

नेता विरोधी दल ने कहा कि राशन घटाया जा रहा है। क्या उनको मालूम नहीं है कि अमरीका में स्ट्राइक चल रहा है और यह हमारा लीन पीरियड है, तथा कुछ ही दिनों में नयी फसल आनेवाली है? हमारी यहां कोई राशनिंग नहीं है। जितना दिया जा रहा है वह केवल सब्सीडी है। बाकी आप बाजार से खरीद सकते ह, वह खुला है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसानों को पूरी कीमत मिलनी चाहिए और टीचरों की तनख्वाह भी बढ़वाना चाहते हैं, तो वह कौन से तरीके का बजट होगा? वह आज तक कभी पेश नहीं कर पाये।

कहा गया कि कांग्रेस में बड़ी गुटबन्दी है। रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी कमजोर है। अभी ८ घंटे में पता लग जायगा कि हमार अन्दर गुटबन्दी है या नहीं। नेता विरोधी दल ने कहा कि बांसी का चुनाव देखिए। क्या उनको अलीगढ़ का चुनाव दिखाई नहीं पड़ता है? ऐसा लगता है कि चहे को हल्दी की गांठ मिल गई तो पंसारी बन बैठा। रायबरेली में आपकी सीट हमने जीती और रिपब्लिकन की सीट हमने जीती। यह आप देखें।

रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा कि सारी मशीनरी सरकार के खिलाफ है। रोज तो कहते हैं कि ब्युरोक्रेसी सरकार के सिर पर चढ़ी बैठी है और सुचेता जी ब्यूरोक्रसी से गाइड होती हैं। अगर सारी मशीनरी हमारे खिलाफ है तो हम उससे कैसे गाइड होते हैं। जनता हमारे खिलाफ नहीं है, भले ही यह ब्युरोक्रेसी खिलाफ हो। उनके साथ सख्ती से काम लिया जायगा तो जरूर नाराज हो सकते हैं।

मुझे इस बात का अफसोस है, क्षोभ है और निराशा है कि आज इस अविश्वास के प्रस्ताव पर १० घंटे सदन के बरबाद किये जा रहे हैं। यह बिलकुल इनइफीशेंट कारणों से ह, जबकि वह कहते हैं कि एमजसी में बचत होनी चाहिये।

मं इस अविश्वास के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और इस मंत्रिडल को पूरी शक्ति से समर्थन देता हूं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्यों? इस प्रदेश में फैले हुए लाखों मजदूरों का, करोड़ों किसानों का आज इस सरकार में विश्वास नहीं रह गया है। इस प्रदेश के करोड़ों खेतिहर मजदूर और गरीब किसानों का इस सरकार में कतई विश्वास नहीं रह गया है। इस सरकार में प्रदेश के ३, १/२ लाख गुरुजनों, ३ लाख सरकारी कर्मचारियों का विश्वास नहीं है। इस मंत्रिमंडल के सदस्यों तक का विश्वास इस सरकार में नहीं है।

मान्यवर, लेनिन ने कहा है कि गवर्नमेंट रूलिंग क्लास की वर्किंग कमेटी होती है। मौजूदा सरकार पूंजीबादी सरकार है और यह सरकार उस वर्ग की वर्किंग कमेटी है। इसका पूरा दृष्टिकोण पूंजीवादी विकास का है और उसी से प्रेरित होकर यह सारे कार्य हर क्षेत्र में कर रही

[श्री झारखण्डेराय]

हैं। हम इस प्रदेश में मजदूर, किसान, निम्न मध्यम वर्ग और प्रदेश के सभी देशभक्तों की सरकार कायम करना चाहते हैं, इसीलिए इस सरकार में हमारा अविश्वास है और रहेगा।

१७ साल की स्वतंत्रता के बाद भी मौजूदा सरकार हर क्षेत्र में असफल सिद्ध हुई है, हर क्षेत्र में मूलतः और मुख्यतया भूमि संबंधी सुधार इसके अधूरे हैं। उसके कदम हिचकिचाहट से उठते हैं। देहातों में धनी किसानों को पैदा करने की इस सरकार की नीति रही है। मुआवजे के साथ जमींदारी प्रथा तोड़ी जबकि हम सब की मांग थी कि बिना मुआवज जमींदारी प्रथा तोड़ी जाय। इसका फल यह हुआ कि ५, १/२ अरब रुपये का अतिरिक्त बोझा किसानों पर पड़ा है। आज भी भूमि का विषम बंटवारा हमार प्रदेश में कायम है, जिसके समाधान के लिए विनोवा भावे ने भूदान आन्दोलन की शुरूआत की थी, लेकिन वह भी असफल होकर आश्रम में गड़ गये। आज ५०,००० एकड़ का फार्म बीकानेर की सरहद पर कानपुर के एक पूंजीपति को दिया जा रहा है। ५०० एकड़ का एक फार्म पंजाब चन्दीगढ़ में बिरला को दिया जा रहा है। थिमैया और करिअप्पा को मैसूर में दस-दस हजार एकड़ क फाम दिय गये हैं। जबकि ५७ प्रतिशत किसानों के पास २ एकड़ से भी कम औसतन जोत है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

बीकानेर और चन्डीगढ़ के फार्मों से उत्तर प्रदेश का क्या वास्ता है, यह सरकार इसमें क्या कर सकती है ?

श्री झारखण्डेराय---

रामायणराय जी को मालूम होना चाहिए कि इन प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी का ही राज्य है। हमारे ही प्रदेश की विषमता की बात वह देखना चाहते हैं तो देखें। वह किछ्छ की नवतोड़ जमीन में जाकर देखें। २०० स ५०० सौ और ५००० एकड़ तक के फार्म वहां है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत उनको मालूम है।

मान्यवर, एक धोखाधड़ी वाला कानून प्रदेश में हदबन्दी का बनाया गया। जिसमें कहा गया कि ३० लाख एकड़ जमीन इसस हमको मिलगी जिसको खेतिहर मजदूरों में बांट दिया जयगा। लेकिन आज सरकार कहती है कि डढ़ लाख एकड़ जमीन ही मिलगी। इसी तरह से कच्छप की गति से चलने वाला चकबंदी कानून है सन् १९५३ में माननीय कृषि मंत्री ने कहा था कि सारे प्रदेश में ५ साल में इसको पूरा कर दिया जायगा। आज १२ साल हो गये हैं लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और आगे आने वाले १० वर्षों में भी उसके पूरा होने की आशा नहीं है।

मान्यवर, बनारस, रामपुर और टेहरी में जो हमारे प्रदेश के रूलिंग प्रिंसेस हैं उनको प्रिवी पर्स विशेष अधिकार एवं सुविधाओं के नाम सें बहुत सा रुपया दिया जा रहा है। यह रुपया संविधान की भावना के विरुद्ध दिया गया है। सरकार अगर इस विषय में उसे खतम करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हो तो हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। इन बातों से इस सरकार में हमारा अविश्वास है। सामन्ती अवशेष सड़ी बदबूदार लाश की भांति इस सरकार की नीति के कारण प्रदेश भर में फैले पड़े हैं।

इस सरकार की उद्योग नीति को ही ले लीजिए। मौजूदा सरकार की नीति औद्योगीकरण के खिलाफ है। पब्लिक सेक्टर के विरोध में उसकी नीति है। यह तो पूंजीपतियों की सरकार है। उसी का यह नतीजा है कि १५-१६ साल में पब्लिक सेक्टर में २ कारखाने सरकार खोल पायी है---एक चुर्क सीमेंट फैक्ट्री और दूसरा अणुवीक्षण यंत्रों का कारखाना। इस सरकार की पूंजीवादी नीति के कारण ही प्राइवेट सेक्टर में खुलन वाले कारखानों को तरजीह दी जा रही है। जनता और पूंजीपतियों के साथ भेदभाव की नीति बरती जा रही है। यही इस कांग्रेस सरकार की असफलताओं का मूल कारण है। इसीलिए कृषि सुधारों में भी यह

सरकार असफल रही है और इसी कारण कांग्रेस कमेटियों में भी भूमि सुधार की बात बार-बार कही जाती है क्रांतिकारी भूमि सुधारों की बात कही जाती है, जमीन के बटवारे की बात कही जाती है, लेकिन अपनी कमेटियों के सुझावों पर भी यह सरकार ध्यान नहीं देती है। यह हमें नहीं भूलना चाहिये कि भारत संसार--विश्व के सभी गरीब देशों से भी पिछड़ा है। और उत्तर प्रदेश हमारे देश में सबसे पिछड़ा है। हमारा देश लंका और पाकिस्तान से भी पिछड़ा है।

बेकारी सारे देश में फैली हुई है। दूसरी योजना में बेकारों की संख्या ८० लाख थी तो तीसरी योजना के अन्त में वह १ करोड़ २० लाख हो जायगी और चौथी योजना के अन्त में वह १ करोड़ ८० लाख हो जायगी। यह इस सरकार की असफलताओं का चिह्न नहीं है तो क्या है ? इसी प्रकार प्रदेश में प्रत्येक योजना की समाप्ति के बाद बेकारों की संख्या बढ़ी है। यह पूंजीवादी रोग है।

मान्यवर, इस सरकार ने इस प्रदेश की जनता को महंगाई के भयंकर जाल में डाल रखा है। मुख्यतया यह टैक्सों के अत्यधिक बढ़ने के कारण है। टैक्स चौगुन हुए है। देश की विकास योजनाओं के नाम पर टैक्स लिया जाता है, देश की सुरक्षा के नाम पर टैक्स लिया जाता है। सुरक्षा जरूरी है, विकास जरूरी है। लेकिन उसके लिये आपको साधन जुटाने होंगे और वह राष्ट्रीयकरण से जुट सकते हैं। जब सरकार से हम राष्ट्रीयकरण की बात कहते हैं तो सरकार चुप हो जाती है। जब से अवाड़ी में इस सरकार ने अपना लक्ष्य समाजवाद की स्थापना का घोषित किया है तब से इसने किसी चीज का भी राष्ट्रीयकरण नहीं किया। रोडवेज का जो आंशिक राष्ट्रीयकरण हुआ है वह तो उसके पहले की बात है और वह भी अधूरा है। क्या अमेरिका से मिले हुए दूध का वितरण आप समाजवाद मानते हैं ? समाजवाद के मानी होते हैं उत्पादन और वितरण के साधनों का स्वामित्व। इस तरह की सरकार ने आज तक कौन सा कदम उठाया है ? इस पूंजीवादी नीति के कारण हमें इस सरकार में अविश्वास है।

पूंजीपति और जनता के बीच यह सरकार जो भेदभाव बरतती है उसका एक परिचय और लीजिए। देश के पैमाने पर देखें। १० करोड़ रुपया टैक्स सरकार का टाटा पर बाकी है, या २ अरब ७१ करोड़ और पूंजीपतियों पर आय कर बाकी है। देश के पूंजीपति २०० करोड़ टैक्स प्रतिवर्ष बचा जाते हैं। मैं अपने प्रदेश की बात अब करता हूं। इस सरकार का साहू जैन के ऊपर ४३ लाख रुपया सन् ५६ से बाकी है, सिंहानिया पर ४३ लाख बाकी है, राम रतन गुप्ता पर २९ लाख बाकी है और यह सन् ५६ से बाकी चला आ रहा है। लेकिन इसके विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही नहीं की जाती। किसान पर अगर २९ पैसा भी बकाया होता तो उसके चूतड़ों की चमड़ी उधड़वा ली जाती। यह पूंजीपतियों और साधारण लोगों के प्रति भेदभाव की नीति नहीं तो और क्या है ?

मजदूर, किसान और अन्य गरीब वर्ग के ऊपर सख्ती और इन पूंजीपतियों के ऊपर नर्मी, यह कौन सा समाजवाद की ओर बढ़ने का लक्षण है, फिर हम इस सरकार में क्यों न अविश्वास करें ? अल्युमिनियम फैक्ट्री के लिए बिड़ला को बिजली देने में और व्यवहार और जनता को बिजली देने में दूसरा व्यवहार, दूसरे पूंजीपतियों को भी बिजली देने में तीसरा व्यवहार, क्या यह भेदभाव की नीति नहीं है ? इस नीति से बिड़ला को सवा करोड़ दान दिया जाता है। इस सदन में बार-बार यह बात कही जा चुकी है। सरकार की यह कौन सी नीति है, बतलाये, यह सरकार की पूंजीवादी नीति नहीं है तो और क्या है ? फिर हम सरकार पर कैसे विश्वास करें यह सरकार पूंजीवाद को बढ़ा रही है और पूंजीपतियों को बढ़ने का मौका देती है। सरकार आज अपनी नीति से जनता और पूंजीपतियों के बीच की गहराई और दूरी को और बढ़ाती चली जा रही है। यहां 'समाजवाद' कायम हो रहा है लेकिन 'उल्टा समाजवाद' कायम हो रहा है। उसका एक नमूना मैं आपके सामने देता हूं।

इस प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसी का शासन आंध्र में भी है जिसने अपने यहां की ४ सरकारी फैक्टरियों को सीरपुर, सीर सिल्क और अलबोपन्स की मिलें पहले ही और

[श्री झारखण्डेराय]

अब राजमहेन की पेपर मिल भी प्राइवेट सेक्टर में बिड़ला को ट्रांसफर कर दिया। यह उल्टा समाजवाद चल रहा है। माननीया सुचेता जी इसको गौर से सुन लें। दूसरा उदाहरण मैं मिस्र के कर्नल नासिर का देता हूं। वहां के दिल्ली स्थित राजदूत श्री अहमद हसन ने दिल्ली में बतलाया कि "स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद से उनकी सरकार ने समाजवाद की दिशा में तेज कदम उठाये हैं। उनके देश में बैंकों, बीमा कम्पनियों, भारी उद्योगों, आयात निर्यात, व्यापार और यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। विश्वविद्यालय तक शिक्षा मुफ्त है। हर बालक बालिका को यह शिक्षा मिल सकती है। उद्योगों का २५ फीसदी मुनाफा मजदूरों को मिलता है। कम्पनियों के ७ संचालकों में ४ मजदूर होते हैं। सप्ताह में ४२ घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाता। कम से कम मजदूरी की हद तय कर दी गयी है।" यह समाजवाद की तरफ कुछ कदम कहा जा सकता है और है। इसको माननीया सुचेता जी और हमारे देश के प्रधान मंत्री जो समाजवाद की बात करते हैं, वहां के समाजवाद से नापें कि आपका कौन सा कदम समाजवाद की ओर उठा है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता चाहता हूं कि इसका जवाब हमें सरकार की तरफ से अवश्य मिलना चाहिए।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त संसदीय समिति ने भी यह विचार व्यक्त किया है कि "भारत की दो पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ केवल ४० प्रतिशत जनता तक पहुंचा है। इस देश और प्रदेश की ६० प्रतिशत जनता को आपकी योजनाओं ने स्पर्श तक नहीं किया है। मैं आंकड़े में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय खतम हो जायगा। महालनवीस कमेटी की रिपोर्ट क्या आंख खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है? वेतनभोगी कर्मचारियों का अन्तर भी बहुत ज्यादा है। प्रदेश का सबसे निम्नस्तर का कर्मचारी ढाई पैसे रोज पाता है मेरा आशय गांवपाल चौकीदार से है, जब कि इसी सरकार का ऊंचे स्तर का सर्वोच्च अधिकारी १६७ रु० रोज पाता है मेरा मतलब राज्यपाल से है। वह कोई पाल हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, किन्तु यह फर्क है। एक ओर ३ आने से लेकर ८ आने रोज तक पाने वाला हरिजन खेतिहर मजदूर है और दूसरी ओर ५० हजार रु० रोज कमाने वाला भारत का सबसे बड़ा आदमखोर बिड़ला है। आखिर यह सरकार की पूंजीवादपरस्त नीति नहीं है तो और क्या है? जो सरकार समाजवाद का नारा लगाती है, उसके प्रदेशीय सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह में अन्तर है, प्रदेशीय सरकार के कर्मचारी और स्वायत्त संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में अन्तर है, बड़े और छोटे का अन्तर है, विभाग विभाग में अन्तर है, अन्तर, सारे प्रदेश के जनजीवन में अन्तर व्याप्त है और वह अन्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। सोचें आप कि क्या यह समाजवाद की ओर प्रगति करने वाली नीति है? बलिया और पूर्वी जिलों में खेतिहर मजदूरों को आज भी ४ पैसे, और एक पाव गुड़ या सत्तू मिलता है। ८ पैसा और १ पाव महुआ या १ पाव गुड़ मिलता है। समाजवाद की ओर बढ़ने का और प्रगति करने का क्या यही मैजरिंग राड है? अगर ४ ही पैसा आज भी दिलवाना है तो यह सरकार डूब जाय या मर जाय। सबको मालूम है कि "द्वितीय खेतिहर मजदूर जांच कमेटी" के अनुसार देश भर में १६२ लाख खेत मजदूर परिवार हैं, जिनमें ५७ प्रतिशत पूर्ण भूमिहीन हैं। यही करें और क्या करें। आज खेतिहर मजदूर को एक पाव महुआ या एक पाव गुड़ दिया जाता हैं, यह हालत हैं। आजमगढ़ में भी यही हालत हैं वहां भी ४ आना से ज्यादा मजदूरी नहीं दी जाती है और ८ आने से तो कहीं भी ज्यादा नहीं हैं, पूर्वी क्षेत्र के किसी अंचल में भी ८ आने से अधिक मजदूरी आज उन्हें नहीं मिलती। खेतिहर मजदूरों की हालत के विषय में श्रीमन्नारायण कमेटी ने भी अपनी सिफारिश की थी लेकिन आजतक उनकी हालत में कोई तरक्की नहीं हुई, जब कि वह १६२ लाख परिवार हैं और ५७ प्रतिशत उनकी तादाद पूर्ण भूमिहीन है।

राष्ट्रीयकरण के बारे में मैं कह चुका हूं। क्यों नहीं यह सरकार बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करती? केवल रोडवेज में कुछ कदम उठाया गया है, माल ढोने वाली ट्रकों का बिजिनेस है, उसका राष्ट्रीयकरण सरकार क्यों नहीं करती। जी० एम० ओ० यू०, के एम० ओ० यू०

और पहाड़ी क्षेत्र की ट्रांसपोर्ट कम्पनियां एक जबरदस्त लूटखोरी की केन्द्र बनी हुई हैं। ऐसी अन्य बड़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनियां हैं। मैं सुचेता जी से मालूम करना चाहता हूं कि इनके राष्ट्रीयकरण करने में उनको कौन रोकता है इसका वे जवाब दें। जहां तक चीनी, जूट, सूती मिलों आदि के राष्ट्रीयकरण का सवाल है उनके विषय में यदि राष्ट्रीयकरण का कोई कदम उठाया जाय तो हम उनमें विश्वास की बात सोच सकते हैं।

घोषित समाजवादी लक्ष्य से भी यह सरकार और उसकी पार्टी बराबर पीछे हटी है। सोशलिस्ट कांग्रेसी फोरम ने स्वीकार किया है कि दुर्गापुर में ही कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के लक्ष्य से पीछे हट गई है, लगता है कि उन को मरे हुए १०० वर्ष बीत गये हैं। पूंजीपतियों के पैसे से चलनेवाली कांग्रेस पार्टी समाजवाद कैसे कायम कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ९८ लाख रुपया लेकर उन आदमखोरों से, उन मौत के सौदागरों से सांठगांठ करती है और चुनाव लड़ती है। जब द्रौपदी की चीर भरी सभा में हरी जाने लगा तो कृष्ण को रक्षा के लिए दौड़ना पड़ा लेकिन दुर्योधन के पाप के अन्न पर पड़ने वाला भीष्म पितामह चुप सिर झुकाये बैठा रहा, विरोध का साहस नहीं किया। पूंजीवाद के संरक्षण और पूंजीपतियों द्वारा मोनोपोलाइजेशन की ओर यह सरकार बढ़ रही है, इसलिए हमारा उसमें अविश्वास है।

जहां तक सरकार की नियंत्रण नीति का सवाल है, सरकार की पूरी नियंत्रण नीति असफल रही है। पूर्ण नियंत्रण किया जाय वर्ना आप प्रयोग के लिए पूरा नियंत्रण कर के १ साल देख लीजिए कि उसका क्या फल होता है। उससे जनता में विश्वास के भाव आयेंगे। आज साधारण धारणा है कि सारे खुराफात की जड़ कंट्रोल में है। इस तरह के भ्रम को दूर करना लाजमी है। हमारे प्रदेश का पूर्वी अंचल यहां का सबसे निर्धन इलाका है लेकिन वहां की दशा सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वहां का सबसे बड़ा अभिशाप बाढ़ है लेकिन कोई सफल कदम वहां के लिए नहीं उठाया गया है। घाघरा, राप्ती, नारायणी नदियों की रिवर घाटी योजना बनाकर क्यों नही इस समस्या को हल किया जाता? १३-१४ वर्ष से बराबर यह बात कही जाती है, लेकिन कुछ नहीं किया जाता।

जो आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं, जो जिंदगी के प्रयोग की जरूरी चीजें हैं उनमें मिलावट का काम सूबे के स्तर पर हो रहा है। जीरा और धनिया की जगह घास पीस कर मिलायी जाती है, मसालों में घोड़े की लीद, चावल में उसी रंग का पत्थर पीस कर मिलाया जाता है, तेल में भटकटैया के बीजों का तेल मिलाया जाता है, घी की जगह अजगर की चर्बी, चीनी में सस्ता चावल और हल्दी में पीली मिट्टी पीसे नमक में खड़िया मिट्टी मिलायी जाती है, लेकिन सरकार इन चीजों को रोकने में असमर्थ रही है।

सरकार की दमनकारी नीति की हालत यह है कि सुरक्षा कानून का प्रयोग प्रदेश और जनता की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस की सुरक्षा के लिए किया गया है। आज इस सूबे में उसके मातहत ८० राइवल कम्युनिस्ट दल के लोग जेल में बन्द हैं।

इनके बारे में मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके पास जो प्रमाण हैं, वह सदन के सामने रखें ताकि हम भी आश्वस्त हों कि हां उनकी बातें सही हैं। वरना केवल चुनाव और राजनीति के दांव पेंच हैं। इनकी सारी नीतियां विफल रही हैं इसलिए हमको सरकार में अविश्वास है और रहेगा जब तक जनता इनको उखाड़ न फेंकेगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

श्रीमन्, संसदीय प्रजातन्त्र की कुछ मान्यतायें होती ह...

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मालूम पड़ता है जैसे भेड़ों में भेड़िया आ जाय, वही हाल है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय बैजनाथ सिंह जी, अगर आप न बोलते, तो अच्छा रहता।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, माननीय गृह मन्त्री को अब भेड़िया ही कहा करेंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैं कह रहा था कि संसदीय प्रजातन्त्र की कुछ मान्यतायें होती हैं और यदि हम उनका पालन न करें और उधर से भी उसका पालन न हो तो एक विद्वान ने कहा है कि यों तो प्रजातन्त्र सबसे कमजोर शासन पद्धति है लेकिन अगर उस प्रजातन्त्र में कैआस हो जाय, कोई अनुशासनन रहे और सभी, चाहे इधर के बैठने वाले हों, या उधर के, यदि अनुशासनहीन हो जायं तो उन्होंने कहा कि तब उस प्रजातन्त्र से कोई तन्त्र अच्छा है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

जैसे मन्त्री जी की पुलिस अनुशासनहीन है।

श्री हरगोविन्दसिंह---

तो श्रीमन्, इस कारण...

श्री राधेश्याम शर्मा--

मन्त्री जी नाम बतायें कि किस विद्वान ने कहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, सुनें।

श्री हरगोविन्दसिंह---

आपके सामने उनका नाम लेना बेकार ही है, क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं होंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

यह भेड़िया विद्वान ने ही कहा है।

श्री राधेश्याम शर्मा---

यह किसी ने नहीं कहा। खुद कहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

हो सकता है बात सत्य हो, चाहे किसी ने न कहा हो।

श्री हरगोविन्दसिंह---

इसलिये मैं कह रहा था कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस हल्कपन से यदि विचार किया जायगा तो यह कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि शायद प्रजातन्त्र की जड़ में हम ऐसा तत्व डाल रहे हैं जिससे वह पनप न पावे।

मैं हमेशा श्रीमन्, यह मानता हूं, और कई दफा कह भी चुका हूं, लेकिन आपकी आज्ञा से फिर दोहराना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र के लिए यह बड़ा दुर्दिन होगा और उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता यदि इस तरफ के बैठने वाले यह सोचें कि हम सदैव ही इस तरफ रहेंगे और उस तरफ के बैठने वाले सोचें कि हम को कभी इधर बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की होती है कि संसदीय प्रजातन्त्र में, कि उधर का प्रत्येक वक्ता यह समझकर अपने विचारों को व्यक्त करे कि, हो सकता है, और जैसा मैं ने कहा कि प्रजातन्त्र

के लिए बड़ा लाभकर भी है वह, एक समय इधर से भी बोलने का उसे अवसर मिले, जैसा कि नेता, विरोधी दल के मुख से भी कहा गया, औरों ने भी कहा, परन्तु नेता विरोधी दल के मुख से ऐसा न कहा गया होता, और लोग कहते तो दूसरी बात थी। लेकिन जैसा, श्रीमन्, आपने स्वयं संकेत किया कि विरोधी दल को नहीं बोलना चाहिये, वही संकेत मैं फिर दोहराता हूं कि यदि उनकी ओर से उनके मुखारबिन्द से भी ऐसी बातें कही जायं, जो कि तराजू पर ठीक न उतरें, जिससे हलकापन जाहिर हो, तो उनको यह समझना चाहिये। आज उन्होंने प्रस्ताव पास किया है, यदि हम यहां से हट जाते हैं तो शायद गवर्नर साहब उन्हीं से कहेंगे कि आप यहां पर सुशोभित हों। उनके मुख से वही बातें निकलें जो बड़े वजन की होनी चाहियें। देश पर जब संकट होता है, वे शायद नहीं मानते हैं, हम अब भी मानते हैं कि यह देश संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है और देश में श्रीमन्, प्रजातन्त्र की यह पद्धति बन गयी है कि जब देश संकटकाल से गुजरता है तो विरोधी दल और इस दल में कोई अन्तर नहीं रहता।

श्री लखीसिंह--

अध्यक्ष जी, मन्त्री जी को...

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्दसिंह--

उसको ऐसी ही बात करनी चाहिये जो सचमुच में, जिसकी पूर्ति वह उस अवस्था में भी कर सकते हों, जब कि वे यहां बैठे हों। श्रीमन्, हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि अपने अध्यापकों की तनख्वाह बहुत बढ़नी चाहिये। कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये। तनख्वाह सबकी बढ़नी चाहिये इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन सवाल तो यह है कि तनख्वाह देने वाला, मैं ही कोई नहीं हूं, या उधर के बैठने वाले ही नहीं हैं। तनख्वाह देने की जिम्मेदारी उधर के बैठने वालों की भी उतनी ही है जितनी यहां के बैठने वालों की होती है। तनख्वाह सबकी बढ़नी चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ रही है उसमें यह सहज ही समझा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने जीवन रक्षा की कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी है। लेकिन आप यह बतावें कि तनख्वाह बढ़नी चाहिये, खर्च कम होना चाहिये। यह भी आप कहते हैं कि तनख्वाह भी बढ़नी चाहिये सबकी, फिजूलखर्ची कम होनी चाहिये। आपके सामने बजट उपस्थित हुआ है। आपकी दृष्टि में जो फिजूल खर्चा है, अभी माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि उनकी दृष्टि में वह उससे भी ज्यादा फिजूल खर्चा है। सवाल यह है कि वह आवे कहां से? जहां तक अध्यापकों का सवाल है, श्रीमन्, पहिले अध्यापकों को तनख्वाह दी जाय या स्कूल में जो बच्चा जाता है, इस बात का प्रबन्ध किया जाय कि उसके पेट में एक टुकड़ा रोटी हो। हमको और आपको सबको सोचना चाहिये, चाहे वे किसी तरफ भी बैठे हों। यह सोचना पड़ेगा। खर्चा जो आज सरकार पर ज्यादा से ज्यादा है वह अपनी योजनाओं का है। वे योजनाएं केवल इस लिए हैं कि इस देश की सम्पत्ति बढ़े। असफल हो, यह हो सकता है, लेकिन वे योजनायें हैं। आपका यह कहना कि हमें इन कुर्सियो का मोह है, शोभा नहीं देता और कम से कम नेता विरोधी दल से ये शब्द सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कोई जबरदस्ती इन कुर्सियों पर नहीं बैठा है। जनता ने विश्वास प्रकट किया और उस विश्वास के फलस्वरूप ही हम यहां पर बैठे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, अगर इन्हें मोह न होता, तो चोर दरवाजे से न आते।

श्री हरगोविन्दसिंह--

उस विश्वास के फलस्वरूप यदि आप यहां बैठे हैं या इधर के लोग बैठे हैं तो यह कोई लोभ या पाप के बस नहीं बैठे हैं। हम समझते हैं कि इधर के बैठने वाले लोग जनता के साथ विश्वासघात करेंगे यदि वे इन कुर्सियों को छोड़कर आप के हाथ में शासन की बागडोर दे देंगे।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

इससे बढ़कर और विश्वासघात नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे अफसोस हुआ, नेता विरोधी दल की बातों को सुन कर।

श्रीमन्, मैं एक बात और कह दूं। मैंने सोचा नहीं था कि इस भवन में बैठ-बैठ कर यह अवस्था आ जायेगी कि हमको बोलना पड़ेगा, लेकिन एक व्यक्तिगत आक्षेप का उत्तर मुझे स्वयं देना चाहिये, क्योंकि आपके दुर्भाग्य से और मेरे भाग्य से मैं इस प्रान्त का गृह मन्त्री हूं और इसलिए इसका उत्तर मुझे देना ही होगा। (हंसी)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अभी माननीय गृह मन्त्री ने कहा कि आपके दुर्भाग्य से मैं गृह मन्त्री हूं।

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, मैंने आपके दुर्भाग्य से नहीं कहा बल्कि (माननीय सदस्य की ओर इशारा करके) "आपके दुर्भाग्य" से कहा।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में आपकी आज्ञा जो चन्द दिन पहले भवन में हुई थी, वह मुझे याद है। जो आक्षेप आज लगाया गया, यही आक्षेप उस दिन भी लगाया गया था। उसी के सम्बन्ध में मैंने आग्रह किया था आक्षेप-कर्त्ता से, कि यदि आप कृपया इन आक्षेपों को इस भवन के बाहर दुहरावें तो आप बड़ी कृपा मुझ पर करेंगे, क्योंकि मुझको इस बात का अवसर देंगे कि मैं भी अपनी सफाई किसी के सम्मुख दे सकूं। लेकिन, श्रीमन्, आपकी आज्ञा हुई कि हमको ये शब्द नहीं कहने चाहिये थे। मैंने इन शब्दों को वापिस ले लिया। पता नहीं डर लगता है कि यदि आज भी इन्हीं शब्दों को दोहराऊं तो आप यही आज्ञा दे देंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, यह आपकी व्यवस्था पर कमेंटरी है।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण की प्रस्तावना है।

एक सदस्य--

सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो गयी है माननीय मन्त्री जी के बारे में।

श्री हरगोविन्दसिंह--

अरे आप (सदस्यगण) तो इतने ज्ञानवान हैं कि मेरी बात तो समझ गये हैं। घटना भी बता देना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो, लेकिन उसके पहले एक बात, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि यह सुनकर कि आप पुलिस के बड़े हिमायती हो गये और जो पुलिस कहती है उस पर माननीय सदस्य का पूरा विश्वास है। गृह मन्त्री होने के नाते मेरे लिए कोई यह बड़ी शोभा की बात नहीं है लेकिन फिर भी मजबूर हूं यह कहने के लिए कि मुझे पुलिस पर उतना विश्वास नहीं है जितना आज माननीय रामसुन्दर पांडेय ने जाहिर किया। जितना उनका विश्वास पुलिस पर है अगर उतना विश्वास मैं करूं, तो श्रीमन्, बड़ी नम्रतापूर्वक आपकी आज्ञा से उनको बताना चाहता हूं कि वह यहां बैठे नजर न आते।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, हाईकोर्ट के फैसले की बात हो रही है। पुलिस के विश्वास की बात यहां नहीं कही जा रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

श्रीमन्, आज वे गृह मन्त्री न होते तो वही पुलिस उनको भी कटघरे में बन्द किये होती।

श्री हरगोविन्द सिंह---

श्रीमन्, अब घटना की बात बताना चाहता हूं। २५ दिसम्बर की शाम को मैं जौनपुर पहुंचा। एक डेढ़ महीने पहले रामसूरत सिंह मेरे पास आया था। उसने मुझसे यह कहा कि हमारे ससुर से और वहां के दारोगा से मार पीट हो गयी और दारोगा जी ने हमारे ससुर पर एक मुकदमा चला दिया। उसमें मैं पैरवी कर रहा था। मुकदमे में हमारे ससुर छूट गये। दारोगा जी ने मुझ से कहा था कि तुमने इस मुकदमे में पैरवी की है और मैं तुमको देख लूंगा। बड़ी शोभा इस बात की है कि माननीय रामसुन्दर पांडेय को दारोगा जी की बात का ज्यादा विश्वास हो गया। रोज कहा भी करते हैं आज के अलावा और चिट्ठियां भी मेरे पास बहुत भेजा करते ह कि दरोगा ऐसा करता है, वैसा करता है। मैंने उससे कहा कि जब दरोगा तुम्हारे ऊपर कोई कार्यवाही करे तो मेरे पास आना। २५ दिसम्बर की शाम को पहुंचा। २६/२७ को कोई बात नहीं हुई। २८ तारीख को सुबह जब मैं मोटर में लखनऊ आने के लिए तैयार था, सुपरिन्टेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सी आफ के लिए आये हुये थे तो उस समय मेरे पास एक वहां का लड़का आया और उसने कहा कि २६ तारीख को जब रामसूरत सिंह स्वतन्त्रता दिवस का उत्सव देखने शाहगंज आया था। वहां के दरोगा की बात नहीं थी, वह आजमगढ़ का था। उस रोज दारोगा ने उसे पकड़ कर बन्द कर लिया और २६ को वहां रखकर और लोगों को बुलाकर उसे दिखाया और २७ तारीख को उसे जेल में बन्द कर दिया है। मुझे यह दुर्घटना याद आ गयी कि यह लड़का मेरे पास गया था और उसके १६ दिन बाद यह डाका पड़ा और उसमें उसका एक कन्फेशनल स्टेटमेंट लेकर उसको बन्द कर दिया।

(व्यवधान)।

तो श्रीमन्, मैं वकालत करता था फौजदारी का वकील भी था, कुछ हथकण्डे भी जानता था---

कुछ सदस्य---

और अब भी जानते हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह---

हम से ज्यादा रामसूरत सिंह जी क्रियात्मक रूप से जानते होंगे। लेकिन वैसे मुझे शक हो गया कि हो सकता है कि दाल में कुछ काला होगा। लिहाजा मैंने एस० पी० से कहा आप इसकी जांच कीजिये और जांच करके इसकी रिपोर्ट मेरे पास भेज दीजिये। वहां उन्होंने उसकी जांच की। हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, जो आपने पढ़ा होगा, उसमें यह लिखा है कि "किस प्रकार से वह छोड़ दिया गया और क्यों इतनी जल्दी छोड़ दिया गया, इसमें गृह मन्त्री का हाथ बिलकुल नहीं है और श्रीमन्, यह सभी जानते हैं, हालांकि आप विश्वास नहीं करेंगे....

श्री काशीनाथ मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह नहीं लिखा है, जजमेंट मेरे पास भी है। यदि आज्ञा दें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---

जरा शान्ति रखिये।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, यदि आप कहें, तो एक लाइन पढ़ दूं।

श्री हरगोविन्दसिंह---

उसमें, बाद में यह हुआ कि श्रीमन्, जब श्री रामसूरत सिंह को एक दफा यहां जेल में भेजने के पहले लाया गया तो उस डिप्टी ने, २७ तारीख को लिख दिया कि यह मुलजिम जब मेरे पास लाया गया तो वह बेपर्दा था। इस पर कोई पर्दा नहीं था। मैं २७ को जौनपुर में था, लकिन मुझे इसका कोई पता नहीं था, इसके बारे में मुझे कोई इत्तिला नहीं थी। मैं जौनपुर में २६ को था २७ को था और २८ को भी १० बजे तक था। तो पहले से जिस प्रकार से वह छूट गया, मैं नहीं जानता, लेकिन आपके कहने का आक्षेप मेरे ऊपर क्या है, वह अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है, शायद आक्षेप यह हो सकता है कि मैंने उसे छुड़वाया ऐसा मैं समझता हूं। कल मेरे पास कुछ लोग आये और उन्होंने कहा, और वे इस सदन के मेम्बर भी हैं, कि साहब, एक गलत मुकदमे में मेरा चालान किया जा रहा है या कुछ आदमियों का चालान किया जा रहा है, आप इसमें सी० आई० डी० से इन्क्वायरी कराइये। मैंने एस० पी० को फोन किया। इस पर एस० पी० ने कहा कि यह बात सही है कि यह मुकदमा झूठा है, इसमें १६९ की कार्यवाही करने का हम हुक्म देने जा रहे हैं। इसलिए इसमें सी० आई० डी० की जांच की जरूरत नहीं है। मैं गृह मन्त्री हूं, मुझ से कोई आकर कुछ कहे, मुझे उस पर पूरी तरह से विचार करके कुछ करना आवश्यक होता है। यदि उसमें अपनी विवेक बुद्धि से काम न लूं, उस की जांच न करूं, सही नतीजे पर पहुंचने का प्रयत्न न करूं, तो मैं गृह मन्त्री किस लिए हूं? यहां पर ऐसे लोग हैं, सी० आई० डी० की रिपोर्ट है कि दारोगा बेईमान है, लेकिन फिर भी हमारे दोस्त अपने लोगों को लेकर आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि इस दारोगा को न हटावें और अगर लोग कहें, तो मैं नाम भी बता दूं। यहां भी ऐसे लोग हैं और यहां पर बैठे हुये भी हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है। यह कहना कि यहां भी ऐसे लोग हैं बहुत आक्षेपात्मक है और माननीय गृह मन्त्री ऐसे शब्द को वापस लें। नहीं तो हम भी कहते हैं कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी बता चुके हैं कि उधर कैसे लोग बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठ जायं। मैं समझता हूं कि उन्होंने इधर और उधर के सभी लोगों के लिए कहा है।

श्री हरगोविन्दसिंह---

जिनके बारे में मैं कह रहा हूं वे तो उधर बैठे हैं, माननीय सदस्य भी हैं, नेता भी हैं, कोई साधारण नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा---

नाम बता दिया जाय, श्रीमन्, लीपापोती करने से क्या लाभ होगा?

श्री अध्यक्ष---

आप जब बोलियेगा, तो इस सम्बन्ध में कह लीजियेगा।

श्री हरगोविन्दसिंह---

मेरे में श्रीमन्, एक कमजोरी है और वह यह है कि जो बात मैं कहता हूं, कोशिश हर जगह करता हूं कि उसको हर जगह स्वीकार कर लूं और उसे इन्कार न करूं। मैं कसम तो नहीं खा सकता कि सत्य ही बोलता हूं, लेकिन यह कोशिश करता हूं कि वह बात स्वीकार कर लूं। इसलिए श्रीमन्, मैं ने यह स्वीकार कर लिया और यह कह दिया। माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे लेकिन समझदार आदमी को यह समझना चाहिये कि अंग्रेजों को कहावत कि हर आदमी

ठीक है कि जो शीशे के घर में रहते हों, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिये। शीशे के घर में तो अपने हों और दूसरों पर पत्थर फेंके यह शोभा नहीं देता और विशेष कर माननीय सदस्यों को कभी भी शोभा नहीं देता।

मुझे अफसोस है कि यहां पर टीचरों के आन्दोलन की बात उठायी गयी। यह पालिटिक्स है। ऐसा वातावरण आजकल हमारे देश में इसने पैदा कर दिया कि लोग विवेक से काम लेना भूल बैठे हैं। जहां तक टीचर्स की तनख्वाह की बात है कौन कहता है कि उनको नहीं देना चाहिये, लेकिन सवाल यह है कि आइये हम और आप बैठ कर के यह देखें कि कहां से पैसा लाना है। आप यह कहेंगे कि टैक्स एक पैसा नहीं लगना चाहिये, आप यह कहेंगे कि योजना सफल नहीं हो रही है, जितना सम्भव हो सकता है कि निर्माण और विकास के लिए वह सब होना चाहिये और यदि वह नहीं हो रहा है तो उस की कुल जिम्मेदारी इस तरफ के लोगों पर है और साथ ही यह भी है कि तनख्वाह सब की दुगुनी और तिगुनी होनी चाहिये। श्रीमन्, यह बात नेता विरोधी दल के मुख से सुनें यह दुखद है और संसदीय परम्परा और विश्वासों के प्रतिकूल है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मैं मन्त्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि राम सूरत सिंह जी से आपको क्या रिश्तेदारी है और वे किस दल से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री हरगोबिन्दसिंह--

कहिये तो बता दूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको एलाऊ नहीं करता। इस से बुरी परम्परा पड़ेगी। सीधी बात यह है कि चाहे सम्बन्धी हो या न हो। अगर गलत काम किया है तो सम्बन्धी न भी हों तो गलत है और अगर सही काम किया है उनके सम्बन्धी भी हों तो वह ठीक ही है।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय विरोधी दल के नेता ने, जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अकेला नहीं हूं जो इस विचार का हूं कि मौजूदा सरकार प्रान्त के दुख और दर्द की दवा ढूंढ़ने में असफल रही है, बल्कि उधर के बैठने वाले सदन के अन्दर कहें या न कहें क्योंकि वे पार्टी से बन्धे हुये हैं, परन्तु वे जो असन्तोष रात दिन एक दूसरे से बातचीत करके प्रकट करते हैं वह एक ऐसी दुखद कहानी है जिसके बारे में सही माने में हमें कोई न कोई हल तलाश करना पड़ेगा। उस हल के तलाश में जहां हमारी सरकार को और हमारे मुख्य मंत्री जी को कोशिश करनी चाहिये वहां उनके कहने के मुताबिक कुछ न कुछ हमारा भी उत्तरदायित्व है। यह बात सही है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कब कब कोशिश की कि वह हमारा सहयोग प्राप्त कर सकें ? श्रीमन्, यहां तो कहानी कुछ और है। कांग्रेस पार्टी यहां नहीं सारे देश के अन्दर जिस गिरावट के गड्ढे में पड़ती जा रही है उससे सारे देश को दुख है और सारे देश के अन्दर दर्द है कि उनका भविष्य इतना काला होता जा रहा है जिसमें जनता कोई भी ठिकाना अपना ढूंढ़ नहीं पाती है कि कल को क्या होगा। परन्तु श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक एक सरकार का हैड कच्चे कान रखेगा तब तक उनके कदम मजबूत नहीं होंगे और वह सरकार का काम काज चला नहीं सकेंगी, चाहे जिस तरह से उनको खुश कीजिये या निकाल दीजिये या जनता बाहर उनको कर दे और आज नहीं तो एलेक्शन के वक्त उनको बाहर कर दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

आज निकाल दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

हम यह चाहते हैं कि आपके जरिये से इस प्रान्त में ऐसा कार्य हो जो दूसरे लोग न कर पाये हों और एक मिसाल हो । आपके मंत्रिमंडल के जितने भी माननीय सदस्य हैं एक एक की कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । आप यह देखिये कि सब से अहम जो विभाग है वह गृह विभाग है, जिससे सारा कारोबार चलता है प्रान्त के अन्दर रक्षा और सुरक्षा का । इस हाउस के अन्दर कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिल पाया हो जो गृह विभाग को सम्भाल सकता हो । जनता ने उनके ऊपर विश्वास प्रकट नहीं किया । वह एलेक्शन के अन्दर हार गये तो उनको बैक डोर से लाकर यहां पर गृह विभाग सम्भालने को दे दिया ।

दूसरा विभाग अहम शिक्षा का है और तीसरा अहम फाइनेन्स का है, जो पैसे से सम्बन्ध रखता है, वह भी ऐसे ही व्यक्ति को दिया । माननीय शिक्षा मंत्री कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब तक जनता का विश्वास उनके अन्दर न हो, जनता उनको चुनकर नहीं भेजती है तो सदन के अन्दर इस पद पर रहना और माननीय मुख्य मंत्री को उन्हें उस पद पर स्वीकार करना कहां तक उचित हो सकता है यह विचार करने की बात है ।

श्रीमन्, आप देखिये कि इस सदन के अन्दर हमारे ला मिनिस्टर हैं, उनके बारे में सवाल उठाया गया और उस विषय में इन्क्वायरी चल रही है, लेकिन वह ज्यों के त्यों बने हुये हैं । उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया । उनको यह भी नहीं कहा गया कि वह त्यागपत्र दे दें । श्रीमन्, इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर महोदय के बारे में एक बहुत बड़ी फाइल तैयार हो गयी है । भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती आदि के आरोप उन पर हैं । आज एलान किया गया कि किसी हाईकोर्ट के जज उनका केस देखेंगे । हम लोग और जनता नहीं जानती कि कौन ऐसा हाईकोर्ट का जज होगा कि जो उन के केस पर अपने विचार प्रकट कर सकता है और मुख्य मंत्री जो क्यों अपने विचार उस केस पर जाहिर करने में असमर्थ रहीं । मुख्य मंत्री ने अपने विचार उस केस में जांच करने के बाद भी क्यों नहीं रखे । अगर उन्होंने अपने विचार जाहिर नहीं किये तो कम से कम इतना तो उनको करना ही चाहिये था कि उन मंत्री महोदय से वह विभाग ले लेती । उसकी कहानी बहुत लम्बी है, लेकिन उसमें मैं एक बात और रखना चाहता हूं । पिछले वर्ष मैंने खाद्य के बारे में सहारनपुर से चावल की गाड़ियां जाने के बारे में एक बात बयान की थी । उसमें जांच होने पर सिद्ध हुआ कि लाखों रुपये का भ्रष्टाचार हमारे फूड सेक्रेटरी ने किया, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि वे फूड सेक्रेटरी आज उस जगह से हटाये जा कर ऐसी जगह बैठाये गये हैं जहां वे उसकी चौगुनी और दसगुनी आमदनी करेंगे । क्या यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने के तरीके हैं ? हम से कभी पूछा नहीं जाता, हमारी बात सुनी नहीं जाती ।

श्रीमन्, मैं एक बात आप के सम्मुख रखना चाहता हूं । हमारे गृह मंत्री जी सामने बैठें हैं । मैं और दो एक सदस्य उनके पास हाजिर हुये, कहा कि सहारनपुर के डी० एम० और एस० पी० के विरुद्ध कुछ आरोप हमने मुख्य मंत्री जी के सामने रखे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ लोग उनमें इंटरेस्टेड हैं, जिनके साथ उनका चोली दामन का साथ है, वे उन अधिकारियों को वहां जमाये रखना चाहते हैं, हालांकि वहां का एस० पी० पिछले ४ महीनों से माघ मेले में गया हुआ है और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर आया नहीं । एक सज्जन की नियुक्ति वहां हुई, लेकिन उनको रोक दिया गया । श्रीमन्, यहां जिले-ब-जिले, तहसील-ब-तहसील, गांव दर गांव एक अलाहिदा हुकूमत कायम होती जा रही है और उसे ऊपर से प्रोसाहन. दिया जाता है । हमारे जिले में ९ एम० एल० ए० हैं उनमें एक भूतपूर्व मंत्री फूलसिंह जी भी हैं, दूसरे पुराने कांग्रेसी भी हैं और वहां गुटबन्दी का बोलबाला है । वे वहां के अधिकारियों पर रोब जमाया करते हैं कि अगर आपको जिले में रहना है तो फलां-फलां एम०एल० ए० से मिल-जुलकर

काम करो । यह ठीक तरीके नहीं हैं। हम लोग गृह मंत्री के यहां गये और उनसे कहा कि हमारे यहां किसी दूसरे आदमी को एस० पी० बना कर भेजिये । साढ़े तीन महीने से वह जगह खाली पड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह हमारी कापी में अच्छा आदमी है । श्रीमन्, अच्छाई और बुराई की नाप भी अलग अलग होती है । एक आदमी आप के लिये अच्छा हो सकता है जनता के लिये बुरा हो सकता है । आपने कहा कि शराब पीता होगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है । आप बतलायें कि बेईमान या रिश्वतखोर तो नहीं है । मैं कैसे कहूं ? कोई मुझ से पूछ कर रिश्वत नहीं देता, लेकिन वहां पिछले ४ महीनों से कोई नियुक्ति नहीं की गयी इसलिये कि वहां के कुछ सदस्य चाहते हैं कि वही शख्स वहां रहे । यह ठीक बात नहीं है ।

श्रीमन्, यही बात है । माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने यही प्रार्थना कहिये, शिकायत कहिये, की और कलेक्टर और एस० पी० के बारे में कहानी बतायी । उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । उससे अच्छा वातावरण पैदा नहीं होगा, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि तुम ने जाकर अखबारों में निकाल दिया और बयान निकाल दिया । अगर माननीय मुख्य मंत्री कोई ऐसी बात सिद्ध करें कि मेरे कहने से निकल गया एस० पी० या कलेक्टर तो मैं उसका नुकसान भुगतने को तैयार हूं । लेकिन अगर कोई कान का कच्चा हो तो इस प्रकार से यह सरकार नहीं चलेगी । आपको समझ से काम लेना पड़ेगा, अपनी आंखों और दिल व दिमाग से काम लेना पड़ेगा । हमारे यहां डी० पी० ओ० ६ दिसम्बर से जा चुके हैं । उसके बाद एक महाशय तशरीफ लाये । ८–७ दिन रहने के बाद कोशिश की गयी कि डी० पी० ओ० की पोस्ट खाली रहे । उनको हरिद्वार भिजवा दिया गया उनको मैजिस्ट्रेट बनवा कर, लेकिन तब से वह पोस्ट आज तक खाली है और कोशिश हो रही है कि श्री बी० एन० तिवारी जो सेक्रेटेरियेट में हैं वही जायेंगे, उनके अलावा दूसरा आदमी नहीं जायगा । मैं भी जानता हूं कि लाजमी वही जायेंगे । कल हम कुछ अधिकारियों से मिले तो वहां पता चला कि उन्हीं के लिये कोशिश हो रही है. . .

'(लाल बत्ती होने पर) अभी तो टाइम नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष––

१५ मिनट हो गये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर––

जो आपकी हुकूमत के घोड़े हैं जिनके कन्धों पर सवारी करके आप हुकूमत चला रहे हैं, आपको संतोष होना चाहिये उनके आचार विचार के बारे में । माननीया मुख्य मंत्री जी जिस समय पहले पहल तशरीफ लायी हैं वह रुड़की गयी थीं । आपके प्रोग्राम के बारे में जिस वक्त बातचीत हुई तो आपको उस वक्त कितनी नागवार गुजर रही थीं उन लोगों की वह बातें और उन्हीं की बातें सुनकर आप हमसे कहती हैं कि आपने अखबारों में प्रचार किया । बिना देखे-भाले आप अपने विचार बदल लेती हैं । मैं चैलेंज करता हूं उनको भी और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई आरोप किसी प्रकार का सिद्ध हो जाय तो मैं एक मिनट भी आपके सामने रहने को तैयार नहीं हूं । मुख्य मंत्री जी के ऊपर जितना विश्वास कम-अज-कम मुझ को था व्यक्तिगत रूप से और है, मैं तो चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को लाजमी तौर पर मजबूत होना चाहिये और हुकूमत की बागडोर को अपने हाथ में रखनी चाहिये । अगर ताकत बखेर कर अंग्रेजों की तरह से शासन चलाना चाहती है कि घोड़े पलेंगे कुछ राजाओं के यहां और आदमी पलेंगे दूसरे राजाओं के यहां और इस तरह से छोटी छोटी हुकूमतें कायम करेंगी तो आप माननीय पटेल के निर्धारित किये गये रास्ते के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी । हुकूमत के काम इस तरह से नहीं चला करते ।

श्रीमन्, एक और चीज पूछना चाहता हूं कि स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के एक महान् जगलर हुये, सही या गलत जो भी कदम वह उठाते थे और जो भी बात जनता के सामने रखते थे, जनता बिना दिमाग खोले हुये उनके साथ चलती थी और उन पर विश्वास करती थी । श्रीमन्, आप यह बताइये कि जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी यहां यू० पी० के अंदर

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

तशरीफ लायीं, जिस तरीके से भेजी गयीं वह सारी कहानी होते हुये भी, क्या यह वही कहानी दोहराई जा रही है जिस तरह से माननीय डाक्टर काटजू को मध्य प्रदेश के अन्दर भेजा गया ? जहां पर आप यह समझती हैं और जब तक आपको यह विश्वास नहीं है कि यहां की रहने वाली जनता आप पर विश्वास रखती है या आपसे उम्मीद लगा सकती है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होकर उनकी उम्मीदों को पूरा कर देंगी तब तक कोई ऐसी बात आप अपनी कुर्सी को मजबूत रखने के लिये न करें तो ज्यादा अच्छा होगा. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपका एक मिनट बाकी है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैं अर्ज करना चाहता हूं कुछ अपने खाद्य मंत्री से । खाद्य का मसला जहां तक है इसके बारे में बार बार कहना मुनासिब नहीं है । आज फसल अच्छी होने जा रही है, यह हम जानते हैं, आप जानते हैं । न तो उसका श्रेय माननीय चरणसिंह को है, न खाद्य मंत्री को है । लेकिन इस विभाग के अन्दर इनके कर्मचारी लोग जिस प्रकार से कार्य करते हैं, जिस प्रकार से मकानों के अलाट करने के और उनको कब्जे में रखने के केसेज चल रहे हैं हाईकोर्ट में और जिस प्रकार सें लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर, रेंट कंट्रोल आफिसर ने मकानात अलाट किये और यह सिद्ध हुआ कि आवश्यकता न होते हुये भी भ्रष्ट तरीके अख्तियार करके उन्होंने नाजायज फायदे उठाये हैं, सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ।

एक आखिरी बात आपके सामने कह दूं । कैबिनेट के अन्दर एक शपथ ली जाती है, जिस वक्त मंत्री नियुक्त होते हैं, गोपनीयता की । उसमें कांस्टीट्यूशन के मुताबिक यह है कि वह कोई बात दूसरे को नहीं बतायेंगे कैबिनेट की । आगरे का एक केस है । एक गाड़ी के नीचे एक लड़की आकर मर जाती है । केस चलता है । लड़की के रिश्तेदार मंत्री के पास आते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लड़की मर गयी है, पुलिस कुछ नहीं करती है । इसी मंत्रिमंडल के एक माननीय मंत्री गृह मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि फलां फलां व्यक्ति मेरे पास आये थे और चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो । यह चिट्ठी माननीय गृह मंत्री के पास भेजी जाती है । मैं नहीं जानता कि गृह मंत्री या स्टाफ में से और आदमी ने उस चिट्ठी को दूसरी पार्टी के हवाले कैसे कर दिया और हाईकोर्ट के अन्दर वह चिट्ठी पेश की जाती है और पेश होने में यह होता है कि यहां से केस ट्रांस्फर किया जाय, जो मैजिस्ट्रेट हैं हमें उससे उम्मीद नहीं है कि उससे इंसाफ होगा । एक चिट्ठी का इस तरह से कैबिनेट के मंत्री के यहां से चले जाने और दूसरी पार्टी के पास पहुंचना, यह कहां तक गोपनीयता है । उसकी कापी मेरे पास मौजूद है, मंत्री जी देखें । अगर गोपनीयता की शपथ का यही मतलब हैं तो उन्हें इसी समय इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जितना गम्भीर प्रश्न इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है, मैं तो बहुत कुछ आशा लगाये थी कि दोनों पक्षों से कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने उपस्थित होंगी जिसके महत्व पर हम अच्छी तरह से ध्यान देते, परन्तु बड़े दुःख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल ने जो आज तर्क दिये वह ज्यादा कनविंसिंग नहीं रहे, बल्कि मैं यह कहने को तैयार हूं कि उनके जैसे गम्भीर और विद्वान आदमी से मैं जितनी आशा लगाये थी कि कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनने को मिलेंगी, उनके तर्क में कुछ चमत्कार होगा, पर अफसोस की बात है

कि वह बहुत निर्जीव से रहे, सिवाय इसके कि अध्यापकगण में एक चिन्गारी सी फैलायी जाय और हमारे जितने बच्चे और विद्यार्थी हैं उनके बीच में अनुशासनहीनता का प्रचार हो, इसके अलावा कोई सामग्री मैंने नहीं पायी ।

जब हमारे सामने अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो वह कुछ उद्देश्य लेकर आना चाहिये। उसके पीछे या तो सरकार की नीति की आलोचना होनी चाहिये या कोई ऐसा विकल्प प्रस्तुत करना चाहिये, एक आल्टरनेट स्कीम सरकार के सामने आनी चाहिये या सरकार को हटा कर दूसरी एक सरकार बनानें की योजना होनी चाहिये ।

मान्यवर, हम एक सुदृढ़ लोकतंत्रीय प्रणाली के अनुसार काम कर रहे हैं । जब बजट अधिवेशन होता है तो अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आता । मद्रास में भी बजट अधिवेशन के समय अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, मगर वहां वह स्वीकार नहीं किया गया । यह उत्तर प्रदेश की सरकार की और हमारे स्पीकर महोदय की महानता है कि हमने हर तरह का विरोधी पक्ष को सहयोग दिया और बजट अधिवेशन में ही उसे स्वीकार किया और आपको अवसर दिया कि आप मैदान में आयें और अगर हिम्मत हो तो इस सरकार को हटायें ।

मान्यवर, मैं जानती हूं विरोधी पक्ष अभी इस योग्य हमारे प्रदेश में नहीं है कि वह सरकार बना सके । उनके पास कोई संयुक्त नीति नहीं है, कोई संयुक्त प्रोग्राम नहीं है । फिर कांग्रेस इतन बहुमत में है कि आप उसको हटा नहीं सकते । माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा कि एक समय था जब हम थोड़ स सदस्य विरोधी पक्ष में थे, आज बढ़ते बढ़ते इतने अधिक हो गये हैं । मैं सन् ६२ में आयी थी, और मैंने देखा कि उनकी पार्टी के ही १४ माननीय सदस्य उनकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं । इससे यह स्पष्ट है कि आपकी संख्या में कमी हुई है, हमारी संख्या में वृद्धि हुई है । माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का रोष और जोश देख कर मुझे शेक्सपियर की एक लाइन याद आयी—"आल साऊन्ड ऐन्ड फ्यूरी सिग्नीफाइंग नथिंग। वे इतना बोल गये, इतना रोश दिखाया, इतना जोश दिखाया मगर मेरी समझ में उनके भाषण में मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो अनुदानों के समय न कही जा सकती हो । मैं उनसे कहूंगी कि अगर वे अपनी पार्टी में इतनी गरमी, इतना गुस्सा न रखते, या भेदभाव न रखते, तो आज उनकी तादाद इतनी कम न होती और उधर के लोग इधर न चले आते ।

इसके अलावा, मान्यवर, अगर यह मान भी लिया जाय कि किसी प्रकार विरोधी पक्ष इस सरकार को हटाकर यहां बैठ सकता है, मगर मैं उस समय की कल्पना भी नहीं कर सकती कि उस वक्त क्या परिस्थिति इस प्रदेश में होगी। कम्युनिस्ट भाई कहेंगे बैंक का नेशनलाइजेशन हो, जन संघ के भाई कुछ दूसरी बात कहेंगे, कुछ कहेंगे स्टेट ट्रेडिंग हो, कोई पार्टी कुछ कहेगी, उस वक्त क्या परिस्थिति होगी यहां की। आप कौन सी भाषा में काम करेंगे ? किस नीति पर आपकी सरकार चलेगी ? योजनाओं पर भी एक मत आप है नहीं। कृषि के विषय में भी आपकी भिन्न भिन्न राय हैं। कम्युनिस्ट भाई कलेक्टिव फार्मिंग का मांग करते हैं, और अन्य सहकारी कें लिये भी तैयार नहीं हैं। मैं चाहूंगी कि जब माननीय नेता विरोधी दल जवाब दें तो वे इन बातों पर भी प्रकाश डालने को कृपा करें। लोकतंत्रीय प्रणाली में तथा हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश अगुआ रहा है। हमारे लिये यह गौरव की बात है कि अब तक हमारे ही प्रदेश का व्यक्ति भारत का सिरताज रहा है, प्रधान मंत्री रहा है। मान्यवर, हमारे भाई ने कहा कि समाजवादी सरकार है और समाजवाद से बहुत दूर है। मुझको खुद ही इस बात पर जरा सी हंसी आई। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी क्योंकि मैं वकील नहीं हूं, कानून तो मैंने पढ़ा नहीं है, परन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगी कि समाजवाद जो है, वह एक दिन में नहीं आ जाता है। समाजवाद एक ऐसी चीज है, जो एक आल-इंडिया पैटर्न हमने स्वीकार करा है कि समाजवाद हमारा लक्ष्य है और समाजवाद की ओर हम अग्रसर होंगे, मान्यवर, मैं कह रहीं हूं कि जब केरल में १९५८ में चुनाव हुआ और वहां पर कम्युनिस्ट सरकार आ गई और दो साल तक वहां पर कम्युनिस्ट सरकार विराजमान रही, तो क्या वहां पर कम्युनिज्म स्थापित कर दिया था।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

तो आल-इंडिया पैटर्न के अनुसार ही सोच सकते हैं। हमको उत्तर प्रदेश को ही नहीं देखना है, समाजवाद की तरफ हम लोग क्या कदम उठा रहे हैं ? एक मामूली तौर पर सारे देश का नक्शा देखना है । इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो । रोडवेज, रेलवेज, एअरवेज, तथा शिपिंग का राष्ट्रीय करण हो, इन्श्योरेन्स का राष्ट्रीय करण हो । हेवी इन्डस्ट्रीज के बारे में जैसा हमारे झारखंडेराय जी ने भी स्वीकार किया हम पब्लिक सेक्टर में भी लेने की कोशिश कर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश ऐसे प्रदेश को, जो कि एक पाइनियर रहा है, अगुआ रहा है और जमींदारी को अबालीशन कर दिया है, मान्यवर, ऐसे प्रदेश को कहना कि समाजवाद की तरफ नहीं जा रहा, कहां तक ठीक होगा ? वास्तविक बात मैं रखना चाहती हूं कि जब हमारी माननीया सुचेता जी यहां की मुख्य मंत्री बनी थीं, यह किसी से छिपा नहीं है कि एक चलेन्ज यहां पर छोड़ा गया । पहली बात बेचारी स्त्री है, क्या करेगी फिर कहा गया कि बाहर की है, और फिर कांग्रेस की गुटबंदी देखते हुए यह कहा गया कि ३ महीने से ज्यादा चल नही सकती, । मैं यह कह देना चाहती हूं कि जब से इन्होंने कार्य सम्भाला है और जो जो कार्य किया है, वह सराहनीय है । आंकड़े देखने से मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की पहले क्या कंडीशन थी और आज क्या है ? इन आंकड़ों को अगर देखा गया होता, तो शायद यह जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है, न लाया जाता । यह भी सही है कि हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है । मान्यवर. मैंने बजट स्पीच में भी कहा था और आज भी कहती हूं कि इसके पिछड़ेपन का कारण क्या है । तीनों प्लान के आंकड़े अगर हम देखें, तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है । प्लान आउटले पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम प्लान म उत्तर प्रदेश म २३, भारतवर्ष म ३६, सिकन्ड प्लान में उत्तर प्रदेश में ३४, भारतवर्ष में ५१, थर्ड प्लान में उत्तर प्रदेश में ६८ और भारतवर्ष में ९० । और प्रान्तों का मैं बता दूं, थर्ड प्लान में आन्ध्र का ८४·७२, आसाम का १००, ८४, बिहार का ७२·४८, गुजरात ११४·०८, केराला १००·५९, मध्य प्रदेश ९२·५९, मद्रास ८६·३१, मैसूर १०१·९३, महाराष्ट्र ९८·५४, उड़ीसा ९१·४३, पंजाब ११३·९८, राजस्थान ११६·८३, वेस्ट बंगाल ८४·००, और उत्तर प्रदेश ६८·०० । अगर इन सब चीजों के बावजूद उत्तर प्रदेश ने उन्नति की ह तो इसके लिए वह बधाई की पात्र ह । हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश तीसरी पंच वर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में सिर्फ ४८·५२ प्रतिशत था और अब आउट पुट में ५० प्रतिशत से बहुत ज्यादा इक्सीड किया है । इस वर्ष करीब १० करोड़ रुपया आउट ले से ज्यादा खर्च हुआ है और अगले वष करीब २३ करोड़ ज्यादा खच होन की आशा है । अगले साल आशा की जाती है कि हम और आगे बढ़ जायंगे । हमारी जो मशीनरी है वह मशीनरी तो हमेशा होती है, मशीनरी तो एक घोड़ा है, अगर सवार सतर्क है, तो उस मशीनरी से अच्छा काम ले सकता है । दो मिनट और दे दीजिए । मैं इतना ही कहूंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश की, अवध की तहजीब, यहां की अदा, यहां का कल्चर बहुत ऊंचा कहा जाता रहा है। उत्तर प्रदेश से यह सब चीजें लोग ले जाते थे । लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश में जब एक स्त्री रूल कर रही है और शान से रूल कर रही है तो आप लोग वह सारी शिवैलरी भूल गए हैं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप इस अविश्वास के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मेरे विचार वही हैं जो मैंने श्रीमन्, के सम्मुख जिस दिन अविश्वास के प्रस्ताव की स्वीकृति का प्रश्न उठा था उस दिन रखे थे कि आज इस देश पर और इस प्रदेश पर विशेषत: जो चीनी और पाकिस्तानी कसेन्ट्रेशन हो रहा है और जिस कंसेन्ट्रेशन के पीछे एकमेव लक्ष्य है कि इस देश को बलपूर्वक स्फेयर आफ इन्फलुएंस में बांटकर अपने अपने कब्जे में किया जाय । वह कुचक्र आज इस प्रान्त में और इस देश में चल रहा है । मैं देश की बात नहीं कहूंगा, केवल प्रान्त की ही बात तक सीमित रहूंगा । अभी लोक सभा

में २३ फरवरी को श्रीमान् चाव्हाण साहब जो हमारे सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उत्तर देते हुए स्वीकार किया, आप आज्ञा दें तो मैं अखबार से पढ़ दूं"

"He also informed the House that the Chinese were known to have deployed roughly 13 to 16 divisions on the northern border."

श्रीमन्, उन्होंने यह स्वीकार किया कि चीनी सेना १३ से १६ डिवीजन तक हमारे उत्तर की सीमा पर फैली हुई है। एक डिवीजन की संख्या कितनी होती है, क्या सरकार को इसकी जानकारी है? साधारणतः और सेनाओं के डिवीजन १२ हजार से १५ हजार सनिकों के होते हैं। परन्तु शायद इस सरकार को नहीं मालूम है कि चाइनीज डिवीजन २२ हजार का होता हैं। तो १३ या १६ से २२ हजार को गुणा कर दें, इतनी बड़ी संख्या में चाइनीज सैनिक फायर आर्म्स के साथ हमारे उत्तर की सीमा पर फले हैं और इनका मुकाबिला करन के लिये सरकार ने क्या किया? कहते ह पी० ए० सी० गयी। कितनी पी० ए० सी० गयी? और क्या उस पी० ए० सी० के पास आटोमेटिक आर्म्स और प्लेन थ्रोअर्स हैं? सरकार के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चाइनीज टैक्टिक्स बिलकुल सीधे मास अटैक की होती है (व्यवधान) हमारे मित्र यह नही जानते हैं कि यह जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं इससे कहीं ज्यादा डीटैल्स युद्ध काल में चर्चिल ने हाउस में दिये थे। अपनी अज्ञानता के कारण वह इस तरह की बात कर रहे ह। तो मास अटक्स की टक्टिक्स उनकी होती है और उस मास अटैक में उनको कितनी गोलियों से मारकर आप गिरा सकेंगे? आपकी राइफलों के बैरल गरम हो जायंगे, आपके सिपाही उनको रोक नहीं सकेंगे। इस मास अटैक के दो ही ऐन्टीडोट हैं —प्लेन थ्रोअर या न्यूक्लियर बाम्ब। (व्यवधान) सिविल डिफेंस अगर करगा तो फिर पी० ए० सी० को काहे खड़ा कर रखा है, क्या केवल नरसंहार कराने के लिये उसे खड़ा कर रखा है? जब आपका साधारण सैनिक यह जानगा कि उसके पास वह हथियार नहीं हैं जिससे वह उनका मुकाबिला कर सके तो उसका मारल वहीं गिर जायगा। इसलिये आप वहां उनकी संख्या बढ़ाइए और उनको वह शस्त्रास्त्र दीजिए, जिनसे कि उनका मुकाबिला वह कर सकें; अन्यथा केवल नरसंहार से कोई लाभ नहीं होगा।

सिविल डिफैन्स की बात की जाती है। डाइरेक्टर आफ सिविल डिफेन्स बनाए गए हैं। क्या सिविल डिफेंस की तयारी हो रही है? हम आप जानते हैं कि चाइना के पास एटोमिक बाम्ब है और वह दूसरा एक्सप्लोजन करने जा रहा है। यह अगर वह कहें कि बाम्ब को डेलीवर करने का साधन उसके पास नहीं है तो यह कैसे हम मानें? हमें यह मान कर चलना पड़ेगा कि हमारे विरुद्ध जो शस्त्र बनाये गये हैं उन शस्त्रों को डेलीवरेस का भी उसके पास साधन होगा। भल ही वह साधन ७००० मील दूरी से चलाने का न हो, २०० मील दूरी का हो।

इसके बाद सिविल डिफेन्स की तैयारी देखिये। क्या आपके यहां बाम्ब शेल्टर्स बनाये गये हैं? क्या सिविल डिफेन्स की ट्रेनिग दी जा रही है? इंगलैन्ड में लड़ाई शुरु होने से बहुत पहले ही सिविल डिफन्स की ट्रनिग द दी गयी थी। सिविल डिफेन्स के सारे साधन उनके पास पहल स थे। अगर आप यह मानत ह कि वह आक्रमण नहीं करेगा तो इमरजेन्सी की हालत क्यों है? और यदि इमरजेन्सी है तो उसके लिये क्या तैयारी हो रही ह? मुझे कहना पड़ेगा कि उसकी तैयारी कुछ हो नहीं रही है।

आपके यहां का जो बार्डर का एरिया है उसमें मिलिटरी का रिटायर्ड पर्सनेल बहुत सा है। क्या उनको फ्री आर्म्स के लाइसेन्स इश्यू किये गये हैं? जब आपकी सेना आगे लड़ती है तो सिविल पापूलेशन गुरीला वार फेयर का काम अच्छी तरह से कर सकती है। क्या आपने इसके लिये उनको तैयार किया है? एक ओर तो आप कह रहे हैं कि आप आर्म्स का इश्यू लिवरेलाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर दरोगा जी को सारे अधिकार दिये गए हैं। क्या यह लिबरेलाइजेशन आफ आर्म्स है? अगर कोई दरख्वास्त देता है तो वह

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

कलेक्टर के यहां से एस० पी० के पास और एस० पी० के पास से दरोगा के पास जाती है। क्या यह वही तरीका नहीं है जो अंग्रजों के जमाने में चालू किया गया था ?

आज आपके कारनामे ऐसे हैं कि आपके कृत्यों में जनता को विश्वास नहीं रह गया है। रोज आपकी तरफ में हल्ला किया जाता ह कि विकेन्द्रीयकरण किया जा रहा है। क्षेत्र समितियां बनायो जाती है, उनक अध्यक्ष बनाये जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती ह, टी० ए० मिलता है, लेकिन उनको अधिकार क्या होता ह ? एक तरह से वह बी० डी० ओ० के मातहत ही रहता है। क्या आपका यही विकेन्द्रीयकरण है ? कहा जाता है कि उनमें अभी पात्रता नहीं है, इसलिये यह शक्ति अपने पास रखी हुई है। कार्पोरेशन के मेयर बनाये गये हैं लेकिन उनको मुख्य नगर अधिकारी के बार में क्या पावर्स ह ? यही बात तो अंग्रज लोग कहा करते थे। और अंग्रेजों न तो कहीं विश्वास भी किया था लेकिन यह जो अपनी जनता की सरकार है, जन प्रतिनिधियों की सरकार ह, वह अपने कृत्यों के द्वारा जनता के प्रति अविश्वास दिखाती है और उसक कारण जनता को उसमें अविश्वास हो रहा है।

यह सारी चोर बाजारी क्यों हो रही है ? हालत यह है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि बम्पर क्राप हुई है। बड़े आनन्द की बात है। लेकिन चावल की वह बम्पर क्राप कहां गयी ? आप कहते हैं कि लोगों ने उसको दबा लिया क्योंकि वह सोचते हैं कि उनको बाद में ज्यादा मुनाफा मिलेगा क्योंकि ब्लैक करेंगे। यह किस वजह से है ? इसकी वजह आपकी इन्फ्लेशनरी पालिसी है। क्या अगली पंचवर्षीय योजना में जब आप २२ करोड़ रुपये के नोट देश की एकोनामिक्स में पंप करेंग तो क्या यही गहूं ३ रुपये सेर नहीं बिकेगा ? अपनी इस गड़बड़ पालिसी को दोष न देकर यह सरकार दुनिया को दोष देती फिरती ह। आप यह कहते है कि यह व्यापारी की गड़बड़ है, बड़े किसान की गड़बड़ है। लेकिन इस प्रदश में बड़े किसान ह कितन ? और मामूली किसान में रिटेंशन पावर कहां ह ? किसान बहुत दिनों तक गल्ले को रोक कर रख ही नहीं सकता। फिर आप सीधे सीधे यही क्यों नहीं कहत कि देश और प्रदेश में जो यह ब्लैक मार्केटिंग फैली हुई है उसका एक मात्र कारण आपकी इन्फ्लेशन की पालिसी है? अगर आपकी यही पालिसी रही तो ३ रुपया सेर तो क्या १०० रुपया सेर भी गेहूं बिक सकता है। अगर ऐसा हो गया तो भी किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। यही हालत जरमनी में हुई थी और चांगकाईशेक के चीन में हुई थी। क्यों आप दुनिया से सबक नहीं सीखते हैं ?

समाजवाद का बड़ा नारा लगाया जाता है। अभी भी बहुत सी स्पीचों में सुना गया समाजवाद, आपके समाजवाद की कोई परिभाषा नहीं है। आपका लचर समा-वाद है, कभी यह, कभी वह। हां, आपके समाजवाद की एक परिभाषा मेरी समझ में आयी और अगर म गलत कहता हूं तो उसे माननीय नेगी जी शुद्ध कर देंगे। श्रीमन्, पहले इस प्रदश में १५ दिन क लिये एक आदमी को ३ किलो गल्ला मिलता था जो घटकर अब डेढ किलो हो गया है। इस तरह से यह १५ दिन के लिये एक आदमी पर डेढ छटांक रोज पड़ा। अब आप सोचें कि डेढ़ छटांक में एक आदमी दिन भर में क्या खायेगा। मुर्गी के लिये आप ३ छटांक अनाज देते हैं। जेल में जो चोर है उसके लिये आप ज्यादा गल्ला देते हैं लेकिन हमारे प्रदेश का जो स्वतंत्र नागरिक ह उसकी स्वतंत्रता आपके समाजवादी राज्य में मुर्गा मुर्गी से भी बदतर हो गयी। क्या आपके समाजवाद के माने लोगों को भूखों रखना है और लोगों को दास बनाना है ? आज आपने इस प्रदेश की खाद्य-स्थिति यह कर रखी है और वह भी तब जबकि विधान सभा की अधिवेशन चल रहा है, यह गल्ले की मात्रा घटायी गयी है। क्या लोगों को मुर्गा मुर्गी से भी कम गल्ला देना, यही आपके समाजवाद की रूपरेखा है ? आपका समाजवाद तो भानुमति के कुनबे की तरह से जादूई पिटारा साबित हो रहा है।

हमारे मंत्रिमंडल के एक मंत्री महोदय ने बड़े जोरों से स्टेटमेन्ट दिया है और शायद कहीं भाषण दिया है कि हम तीन मंत्री काम करते-करते मरे जा रहे हैं ....

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह किसने कहा है ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—

शायद आपने ही कहीं भाषण दिया है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इट इज एब्सोल्युटली रांग । यह कतई गलत है ।

श्री उग्रसेन—

माननीया मुख्य मंत्री के अंग्रेजी बोलने पर मुझे आपत्ति है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

खैर, आपने यह कहा है कि आपके पास कार्यभार बहुत बढ़ गया है । इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास कई विभाग है । और दूसरी तरफ एक मंत्री ने कहा है कि उनके पास काम ही नहीं है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा है । इसके माने श्रीमन्, यह हुआ कि कुछ के पास काम है और कुछ बेकाम हैं । यह कौन सा समाजवाद है ? इसका स्पष्ट कारण यह है कि जब मंत्रिमंडल की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलटी है, तो आज उसके अन्दर कलेक्टिव रिस्पांसिबलिटी की भावना न रहकर एक गुटबाजी की भावना घर कर गयी है। क्या माननीया मुख्य मंत्री इस बात से इन्कार कर सकती हैं कि आज माननीय गुलजारीलाल नन्दा के पास से आधे दर्जन मंत्रियों की शिकायत इनक्वायरी के लिये पहुंची है? उस संबंध में अब तक क्या हुआ है और क्या हो रहा है ? मेरी जानकारी है कि उस आधे दर्जन में दोनों गुट के मंत्री लोग हैं जिसकी एक झलक इसी सदन में सवालों के सिलसिले में मिली थी । एक मंत्री के लिये कहा गया कि उन्होंने कारपोरेशन की जमीन पर कब्जा कर लिया । अगर यह ठीक है कि उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने गलत काम किया है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाया क्यों नहीं गया ? और अगर वे सही हैं, उनकी गलती नहीं है तो माननीया मुख्य मंत्री ने उनको डिफेन्ड क्यों नहीं किया ? यह वर्तमान मंत्रिमंडल के अन्दर गुटबाजी का ही प्रमाण है । एक मंत्री को पत्र लिखा गया कि चूंकि सदन में आपके संबंध में सवाल होने जा रहा है और उसका मुझे जबाब देना पड़ेगा इसलिये इस संबंध में आप उचित कार्यवाही करें । आखिर यह क्यों है, इसको माननीया सुचेता जी जबाब देते समय बतलावें । जब किसी एक गुट के मंत्री के संबंध में सवाल हुआ और फिर दूसरे गूट के मंत्री पर आरोप का सवाल उठा, ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में बड़ा हंगामा मचा, तो माननीया सुचेता जी को यह मुरव्वत कहूं या उनकी कृपा कहूं कि उन्होंने श्री मुसद्दी-लाल को जो विजिलेंन्स कमीशन के चेयरमैन थे उनको इस मामले को जांच के लिये दे दिया। जब विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन ने एविडेंस के लिये संबंधित मंत्री को कमीशन के सामने बुलाया तो बड़ा हंगामा हुआ कि नहीं, यह गलत है , मंत्री वहां नहीं जायेंगे । इस तरह से मंत्री को होली काउ समझ कर उसे छूट दे दी गयी कि वह जहां चाहें चरता फिरे उसे खुली छूट दे दी गयी , वह दगा सांड बनाकर रख दिया गया । इसका नतीजा यह हुआ कि श्री मुसद्दी लाल जी चिढ़ कर बोर्ड आफ रेवेन्यू में वापस चले गये । माननीया सुचेता जी इसका जबाब दें कि यह विजिलेंस कमीशन का मजाक है या क्या है । गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो विजिलेंस कमीशन बना है "इट इज नाट एकार्डिंग टु आवर पैटर्न ऐन्ड नाट एकार्डिग टु आवर सजेशंस ।" उसमें यह भी है कि आई० ए० एस० पर वह कुछ नहीं कर सकता ।

श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, यह जनसंघ के नेता की अंग्रेजी रोकिये, हम इसका विरोध करते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मैं अनुवाद किये दे रहा हूं। मेरा श्री उग्रसेन जी से नम्र निवेदन है कि वह जरा धैर्य रखें। स्पष्ट इस बात का उसमें संकेत है कि यह जो विजिलेंस कमीशन है वह न तो हमारी नीति और जरूरत के अनुरूप काम कर रहा है और न यह हमारे सुझावों के ही अनुरूप बना है। वह आई० ए० एस० को नहीं छू सकता, आई० पी० एस० को नहीं छू सकता, टाप ब्यूरोक्रेट आई० सी० एस० को नहीं छू सकता और मंत्रिगण तो अपरम्पार हैं। तो फिर यह क्या पटवारियों के लिये है, यह चपरासियों के लिये है, यह सरकार के पी० एज० के लिये है या मंत्री जी के स्टेनोग्राफर्स के लिये है? जब ऊपर यह अन्धेर-गर्दी है तो फिर क्या होगा और उसे कौन देखेगा?

सीक्योरिटी के नाम पर क्या नया रूप दिया गया? बड़ा हल्ला मचाया गया कि हमने लेफटिस्ट कमुनिस्टस को बन्द कर दिया, लेकिन क्या हमारी सीमाओं पर उस दल का जो दक्षिण विन्ग है जो कि उनका एक मजबूत हिस्सा है वह गड़बड़ी नहीं कर रहा है? क्या आपने उनको बन्द किया? नहीं किया। आज प्रदेश में कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि बिना परमिट और विसा के रह रहे हैं; उनकी संख्या ६,००० से कम नहीं है और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मंत्री जी मेरी बात को सही करें।

भाषा के विषय में भी हिन्दी को लाने का बड़ा हल्ला है। नवल किशोर जी बतायें और श्री कैलाश प्रकाश जी यहां नहीं हैं उन्होने कल एक प्रेस कांफ्रेस में कहा कि अभी हमने हिन्दी में काम शुरू नहीं किया है। तो काम कब शुरू होगा? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि यह बड़ी दुखद घटना देश के लिये है कि हम अंग्रेजी के लिये सिर फोड़ें। यह हमारी दासता का कलर मात्र है। क्यों न हम तीन भाषाओं के फारमूले को इस तरह से रखें कि हिन्दी हमारी अन्तरप्रदेशीय भाषा होगी और अहिन्दी प्रदेश सब मिलकर यह तय कर दें कि फलां अहिन्दी भाषा जैसे तामिल, तेलगू, मराठी, बंगला आदि में से एक एसोशियेट भाषा होगी और १ रीजनल भाषा रहे? तो इस तरह से ३ भाषा के फार्मूले के अन्तर्गत यह चीज आ जाती है और इससे देश में जो यह सिर फुड़ाई हो रही है वह बन्द हो सकती है और जो हमारा अपमान विदेशों में इस प्रश्न को लेकर ही रहा है वह बन्द हो जायगा।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

अध्यक्ष महोदय, बहुत देर से मैं बैठे-बैठे सुन रहा था। इस बीच में हमारे विरोधी दलों के कई नेताओं के भाषण भी हुए और मैं उनमें खोज कर रहा था कि उनमें कोई बातें ऐसी भी हैं कि जो जनता के लिये, उत्तर प्रदेश के लिये और जिनकी दोहाई दी जा रही है उनके लिये कोई बात उनकी लाभप्रद भी हैं लेकिन हमें उनमें कोई चीज ऐसी नहीं मिली सिवा इसके कि वही जो हमेशा से रिवाज हैं, रस्मी तौर पर जैसे बातें होती हैं उन्हीं को दोहरा दिया गया। हमें बड़ा दुख इस बात का है कि किसान जो हमारे विरोधियों के प्रचार में आ जाते थे और जो असर उनका उन पर पड़ता था उससे उनको कभी-कभी सफलता भी मिल जाती थी संसद या विधान सभा के चुनाव में लेकिन गुरुजनों का जो सूबे का एक पढ़ा लिखा तबका है और जो सोचता है, जिसमें बुद्धि है, समझने की शक्ति है आज उसके ऊपर जो उनका थोड़ा सा जादू चल रहा है उसका मुझे बड़ा दुख है। इससे उनको बड़ा असन्तोष है कि वह उनके बहकावे में आ गये और समझते हैं कि थोड़ी सफलता मिली है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वह भ्रमात्मक प्रचार कर के उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे लोगों को, अध्यापकों को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार के लिये ही नहीं बल्कि उनके लिये भी खतरनाक बात साबित होगी। जनता उनसे पूछेगी कि तुमने हमें गुमराह किया है जब कि हम प्रदेश को बना रहे थे, जब प्रदेश के चरित्र, शिक्षा और प्लानिंग को ठीक कर रहे थे, गरीबी को दूर करने के प्रयास कर रहे थे, उस समय तुमने हमें गुमराह और पथभ्रष्ट कर दिया। यह बात किसान एक दिन आपसे जरूर पूछेगा और आपको इसका जबाब देना पड़ेगा।

इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आजकल महंगाई के जमाने में २५० रु० से कम वेतन वाले का गुजारा नहीं है चाहे वह किसी श्रेणी का कर्मचारी हो। इससे कम किसी को नहीं मिलना चाहिये।

(इस समय १२ बजकर ५६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

लेकिन अगर २५० रु० प्रति कर्मचारी का हिसाब लगावें तो प्रदेश में जितने कर्मचारी हैं उनका वेतन २०० करोड़ रुपया होता है। अब अगर २५० रु० देकर सारे प्रदेशीय कर्मचारियों को इस लायक बना दें कि बाजार में अपनी आवश्यकता की चीजें खरीद सकें तो प्लानिंग सुरक्षा तथा अन्य योजनायें समाप्त करनी पड़ेंगी। जब साधन की बात पूंछते हैं कि कहां से इतना रुपया लाकर दें तो विरोधी दलों से कोई सुझाव नहीं आता है। जब सरकार की तरफ से संकेत होता है कि हम कुछ टैक्स के द्वारा थोड़ा पैसा किसानों से लेना चाहते हैं तो आप लोग विरोध करते हैं और विरोधी दलों के नेता ने तो कह दिया कि इसके विरुद्ध वह सत्याग्रह, प्रचार और क्रान्ति करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि कर्मचारियों को दो अरब रुपया वेतन के रूप में दो और दूसरी तरफ कहते हैं कि टैक्स न बढ़ाये जायं। तो यह जबरदस्ती की बात है। मैं आगाह करना चाहता हूं कि थोड़े दिनों में कलई खुल जायगी और जनता आपसे जगह-जगह पूछेगी और कहेगी कि आप हमको गुमराह न कीजिये क्योंकि प्रदेश की स्थिति खतरनाक है।

माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने सुरक्षा पर बड़ा बल दिया। क्या यह बात वाजिब है कि इस तरह से जनता के मनोबल को कमजोर किया जाय और सुरक्षा को मजबूत किया जाय? यह न्याय की बात नहीं है। २४ घंटे भ्रमात्मक बातें विरोधी लोग करते हैं और जो कुछ आजकल हो रहा है उसमें विश्वास नहीं पैदा होने देते और फिर कहते हैं कि सारी चीजें होनी चाहियें। इस प्रकार से जो प्रचार होता है वह हम सब के लिये बहुत ही हानिकारक है।

आजकल २, ३ बातों पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। महंगाई के बारे में कहा जाता है और सही भी है कि इसका असर सब पर है, सब को कष्ट है, लेकिन क्या विरोधी दल के किसी भाई ने महंगाई खत्म करने के लिये कोई तरीका बताया, किसी हल्के को लेकर अधिक अन्न उपजाओ स्कीम बतायी, किसी गांव को लेकर कोई आदर्श स्थापित किया जिस पर सरकार चलने की कोशिश करती? मैं कहता हूं कि केवल आलोचना से काम नहीं चलता। आलोचना से ही सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती। मैं जनता हूं कि उसके पीछे एक राजनीतिक षड़यंत्र है कि प्रदेश की जनता को गुमराह किया जाय और अपने चुनावों में कामयाबी होती रहें। वही मसल है कि अंधे के हाथ में बटेर लग जाय। अभी एक बस्ती का चुनाव जीता, जिस पर हमारे नेता विरोधी दल को बड़ा घमंड हो गया। मैं आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि उसमें सिर्फ हमारी जो जन्म भूमि अयोध्या का एक सैन्टीमेन्ट हिन्दू है, हिन्दू सैन्टीमैन्ट छिपा हुआ है, उसमें जनसंघ की देशभक्ति छिपी हुई नहीं है। जन्मभूमि पर इन्होंने कब्जा किया था। हिन्दुओं के दिमाग में यह डाल दिया गया कि ये हमने निकाल कर दिया है। श्रीमन्, यही चीज इसमें छिपी थी कि ये इलेक्शन जीत गये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरा चैलेन्ज है कि बस्ती से इलेक्शन जीतकर बतायें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और चीफ मिनिस्टर भी वहां से इलेक्शन लड़कर देख लें।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

आपको यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि जनसंघ का महत्व बहुत बढ़ रहा है। हिन्दू जाति, सेन्टीमैन्टल जाति है। सैन्टीमेन्टल विचारों ने यह काम कर दिया कि मियां-बीबी दोनों को यहां जिताकर बैठा दिया। इससे कहीं यह भ्रान्ति न हो जाय कि जनसंघ को देश भक्ति के बल पर वे दोनों यहां आ गये हैं। जनसंघ के इतिहास को देश का बच्चा-बच्चा जानता है। वह कलंक ऐसा है कि जो भाषणों के जरिये नहीं धोया जा सकता। वह ऐसा कलंक है कि जो भारतवर्ष के इतिहास में सदैव बना रहेगा। महात्मा-गांधी जिसको सारा देश देवता मानता है उनके मंदिर का उनकी हत्या का कलंक आप पर है, जनसंघ पर है।

श्री शारदाभक्तसिंह---

इन्हें बोलने से रोकिये, श्रीमन्, ये क्या कह रहे हैं? जो बात बैजनाथसिंह जी ने कही मैं समझता हूं

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

इनको बैठाइये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री राधेश्याम शर्मा---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इधर के और उधर के माननीय सदस्यों द्वारा आदरणीय गवर्नर के भाषण पर सामान्य विवाद और रोज-रोज के कटौती के प्रस्तावों के संबंध में दिये गये वक्तव्य मैंने सुने हैं और जो आज अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके संबंध में भी आलोचनायें और प्रत्यालोचनायें सुनी गई हैं परन्तु मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष तो साफ-साफ सब बातों को कहेगा ही परन्तु फिर भी मैं सरकारी लोगों से कहना चाहता हूं कि वे इस बात की ही सफाई या विरोधी पक्ष की आलोचना ही न करके यह बतायें कि सरकार किन मुद्दों से ठीक है। आज सारे प्रदेश के अन्दर अनेकों समस्यायें खड़ी हैं। किसी भी शासन में रोटी, रोजी, कपड़ा, बेकारी, भुखमरी, गरीबी, जाति, जुल्म, भ्रष्टाचार बढ़े, तो हमको इसकी परवाह नहीं है यह तो हर सामन्तवादी और साम्राज्यवादी देश में होता ही है। सब से बड़ी चीज यह हुई है, इस समय मैं, मैं एक मुख्य मंत्री की बात नहीं कहता मैं तो इस सरकार के सारे इतिहास को बता देना चाहता हूं कि इस कांग्रेस सरकार ने जो कुकर्म किया है, इतिहासकार उसको लिखेंगे कि जो इस सरकार में कहा गया वह किया नहीं गया। कथनी और करनी में एकता नहीं लाई गई। इसलिये कि आने वाली सरकार भी ऐसी न निकले, इस कथनी और करनी वाली बात को इतिहास बख्श नहीं सकता। आज मैंने यह नई बात सरकार को कही। इसके बाद मैं अपनी बात क्या कहूं? उधर के लोग तो अपनी बात कह गये। मैं तो मनीषियों, दार्शनिकों की बात को इस बारे में बताना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र की हुकूमत क्यों बदल देनी चाहिये। मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता। सब से पहिले, श्रीमन्, लेनिन की बात कहूंगा---उन्होंने कहा है---'दुनिया के जिस भूभाग में भूख से कलह मचेगी उसे दबाया नहीं जा सकता है। एक दो बार संशोधन वादी नकली प्रजातन्त्री हुकूमतें जनता की निगाह अवश्य हटा दें, अन्त में भूख की ज्वाला क्रान्ति के रूप में सूखी अंतड़ियों से विस्फोट का रूप धारण कर नई समाज की रचना करके ही शान्त हो जावेंगी।" उसके बाद में जो मार्क्स ने बात कही है उसको बतलाता हूं। प्रजातंत्र के अन्दर हकूमतें बदलती हैं, क्यों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बदलना जरूरी है; मार्क्स ने कहा है कि "इस प्राचीन संसार को अपनी आंखों के सामने नष्ट होता देख कर हम दिल में कितने दुःखी हों पर इतिहास की दृष्टि में हम गेटे के साथ यहीं कहेंगे। तो क्या हम इस जुल्म से दुःखी हों जब कि यह हमारे लिए नयी खुशियां ला रहा है? क्या तैमूर के शासन में अनगिनत प्राणी मौत के घाट नहीं उतारे गये थे?"

इसके बाद मैं गौतम बुद्ध की बात कहता हूं। उन्होंने कहा है कि "निर्धन, कमजोरों, दीन, दुःखी प्राणियों के उद्धार का कोई हल समझ में न आवे तो राज करना व्यर्थ समझता हूं, इससे अच्छा यही है कि जनता का कोप भाजन बनने की अपेक्षा जंगल की कांटों भरी राह लूं।"

इसके बाद गांधी जी ने जो कहा है उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि "राज देशी हो, या परदेशी, जो जनता की दैनिक जरूरत जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, सत्य, न्याय व रक्षा सुलभ नहीं कर सकता, उसे एक क्षण भी रहने का नैतिक अधिकार नहीं। अच्छा तो यह है कि ऐसा राज स्वयं हट जाये यदि कोई बर्बर हकूमत हटना ही पसन्द न करे तो उसे सभी शांतिमय उपायों से हटा कर जनता का मनोबल बढ़ाना निहायत जरूरी है। जिस मुल्क की जनता ऐसा नहीं कर पाती, वही कायर है।"

संविधान बनाने वाले डा० अम्बेदकर ने कहा है कि "सरकार बदलती रहेगी और दुनिया में इतिहास बताता है। सृष्टि के आरम्भ से अदलती-बदलती रही है, परन्तु जो सरकार अपने ही बनाये हुये नियम व कानूनों की स्वयं अवहेलना करे, उसे तो एक क्षण भी नहीं टिकने देना चाहिए" रोज कानून बनाते हैं, रोज तोड़ देते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कानून तोड़ दिया।

इसके बाद नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने कहा है कि "अंग्रेजी राज भारत से उखाड़ने के बाद अंग्रेजी साम्राज्यशाही के अवशेष जिनकी जड़ें भारत में भारी गड़ चुकी हैं, उनसे लड़ना मेरे जैसे आदमियों को अनिवार्य हो जायगा, क्योंकि देश की पवित्र मिट्टी में जनता के इन दुश्मनों की आत्मायें बैठी हुयी घर कर चुकी हैं"? यह उनका कलकत्ता में दिया हुआ भाषण था।

अरस्तू ने कहा है कि "प्रजातन्त्र में अधिक दिन तक रहने वाली सरकार यदि अच्छी भी हो तो भी हटा देना जनहित में निहायत जरूरी है क्योंकि अधिक दिन तक रहने वाली सरकारें अमूमन यह समझ लेती हैं कि अब हटाने के लिए जनता कमजोर है तब वे निडर होकर ग़लत काम करने पर उतारू हो जाती हैं और धीरे-धीरे तानाशाही की तरफ अग्रसर होकर जन जीवन त्रस्त कर देती हैं।"

श्रीमन्, ७--८ दुनिया के भिन्न-भिन्न विचारकों तथा दार्शनिकों के मत मेरे पास हैं जो उन्होंने व्यक्त किये हैं पर मैं उनकी जरूरत नहीं समझता कि उन्हें यहां पर कहां मैं समझता हूं कि इस बात से ही सरकार समझ जायगी। सरकार का प्रजातंत्र में क्या कर्तव्य है? प्रजातन्त्र में सबसे बड़ा कार्य रोटी, रोजी, कपड़ा, देना और भुखमरी, और भ्रष्टाचार आदि को दूर करना है। इससे ज्यादा अधिकार और मैं नहीं समझता। श्रीमन्, हो क्या रहा है? सरकारी पक्ष गल्ती पर गल्ती करता चला जाता है। कृषि के मामले में आंकड़े प्रस्तुत किये गये। मैं आंकड़ों की बात नहीं करना चाहता। किसी भी पैदावार के दृष्टिकोण से देख लीजिए। अनुपात से अच्छाई का रास्ता नजर नहीं आता है। माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि विरोधी पक्ष तो कई एक पार्टियों में विभक्त हैं इसके बारे में मेरा निवेदन है कि यदि ऐसा न होता तो आज आप सदन में नजर न आते। जिस तरह से यह सरकार जिम्मेदार है उसकी दूसरी जिम्मेदारी विरोधी पक्ष की भी है क्योंकि आज विरोधी पक्ष कमजोर है। विरोधी पक्ष सही ढंग से सारी चीजों को देख कर सरकार का ध्यान खींचता है पर जितना आज खींचना चाहिए नहीं खींच पाता है। मार्क्स ने कहा है कि "सामाजिक व्यवस्था के ये छोटे-छोटे पुराने रूप अब बहुत हद तक मिटाये जा चुके हैं और इनका लोप हो रहा है। यह ब्रिटिश कराधिकारियों तथा ब्रिटिश सैनिकों की क्रूर दस्तन्दाजी के कारण इतना नहीं हो रहा, जितना कि अंग्रेजी आप मशीनों के कारण और अंग्रेजी स्वतंत्र व्यापार के कारण। वह परिवार रूपी समुदाय घरेलू उद्योग पर खड़ा था; जिसके हाथ की बुनाई, हाथ की कताई तथा हाथ की खेती सम्मिलित थी। इससे उसे अपने पांव पर खड़ रहने की शक्ति मिलती थी। अंग्रेजों की दस्तन्दाजी से सूत कातने

[श्री राधेश्याम शर्मा]

वाला लंकाशायर में विराजने लगा और बुनकर बंगाल में, या भारतीय बुनकर और भारतीय सूत कातने वाले दोनों का सफाया करके उन छोटे-छोटे अर्द्ध बर्बर तथा अर्द्ध सभ्य समुदायों को उनका आर्थिक आधार तोड़ कर मिटा दिया गया। इस प्रकार सबसे बड़ी और सच कहें तो एकमात्र सामाजिक क्रान्ति, जो कभी भी एशिया में न हो पायी थी, क्रियान्वित कर दी गई।"

मैं सारी बात तर्कयुक्त ढंग से आपके समक्ष रख देना चाहता हूं। सारे कार्य सरकार गलत करती है, लेकिन विरोधी पक्ष के लिये क्या कहूं---अविश्वास का प्रस्ताव है सरकार को बधाई देने के लिये। कोई माननीय सदस्य, नन्दा जी को, कोई लालबहादुर शास्त्री को और कोई राष्ट्रपति को बधाई देता है लेकिन फलां आदमी ने खराब कह दिया तो वह राष्ट्रद्रोही हो जाता है। एक नीति विरोधी पक्ष की होनी चाहिये। आपस में एक तालमेल की नीति स्थापित करनी चाहिये। आचार्य कृपालानी ने भाषण देते हुए अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर अभी कहा था कि हम एक काम नहीं देखना चाहते---इस कांग्रेसी हुकूमत को जिसने जनता को भूखों मार दिया। मैं चाहता हूं कि सारे दल मिल कर इस सरकार को अपदस्थ करें। छोटे-छोटे यज्ञ हमने रचाये। अलग-अलग लड़ कर देख लिया। यह कांग्रेसी सरकार केवल ३३ परसेंट वोट पाये हुए हैं और ६७ परसेंट हम सबने मिल कर पाये हैं। इन ३३ प्रतिशत वोट वालों को अपदस्थ करने के लिये ६७ प्रतिशत वालों को मिल कर एक महायज्ञ रचाना जरूरी है और काग्रेसी सरकार के गलत कामों को स्वाहा करके, उसे अपदस्थ करके सही समाजवादी सरकार की स्थापना करनी चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिये। इससे ज्यादा मुझे इस अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर कुछ नहीं कहना था।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास का प्रस्ताव बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मेरी यह धारणा थी कि अभी हाल में इस प्रदेश की मुख्य मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्र भाषा की समस्या पर जिस दृढ़ता का परिचय दिया और प्रदेश के जन-जन की जो आकांक्षायें थीं उनका जितना सुन्दर प्रतिनिधित्व किया था उसके लिये सदन उनके प्रति आभार प्रकट करता। यही बात नहीं थी। बिहार तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने कमजोरी दिखाई और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के खून में बंगला भाषा रहते हुए भी जिस प्रकार उन्होंने प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया उसके लिये सदन को उनके प्रति आभार प्रकट करना अपेक्षित था। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है कि वह आभार प्रकट न करके उनकी सरकार के प्रति आज भर्त्सना का प्रस्ताव लाये हैं। युग के साथ लोकतंत्र की परम्पराओं में भी परिवर्तन हुआ करता है और सरकारें तथा विरोधी पक्ष किस तरह से आचरण तथा व्यवहार करें, उसमें भी परिवर्तन हुआ करता है। १६वीं, १७वीं सदी में विरोधी पक्ष का एक ही मोटो हुआ करता था सरकार की हर चीज का विरोध करना, किसी चीज का समर्थन न करना और सदैव सरकार को उलटने के चक्कर में रहना। लेकिन जैसे-जैसे युग बदला आज विश्व में जहां-जहां जनतंत्र प्रणाली है विरोधी पक्ष ने इस मोटो को बदल दिया है और यह मोटो बना लिया है कि छोटे से इलेक्शन के लाभ के लिये हमको संसदीय प्रणाली, जो कि रचनात्मक प्रणाली है, की हत्या नहीं करनी चाहिये और यही कारण है कि लोकतंत्र के इतिहास में आस्ट्रेलिया में मेकेन्जी की सरकार एक वोट के बहुमत पर बनी रही और इंगलैण्ड में ४ वोट के बहुमत पर लेबर गवर्नमेंट है और स्टील नेशनलाइजेशन जैसे कार्य को लेकर चल रही है लेकिन यहां अपार बहुमत की कांग्रेस की सरकार के लिये शारदाभक्त सिंह कहते हैं कि इस्तीफा दे दो और कारण यह देते हैं चूंकि अध्यापकों की समस्या का आप समाधान नहीं कर सके इसलिये हम क्रान्ति करा देंगे। मैं निवेदन कर दूं कि संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में आज इस विधान सभा में विरोधी दल के नेता ने एक बड़ा 'हस्यास्पद उदाहरण उपस्थित किया है इस अविश्वास के प्रस्ताव को पेश करके और वह भी इस बात पर कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पकों की समस्या का यह सरकार समाधान नहीं कर पा रही है और उनका कहना है कि केन्द्रीय सरकार जब अध्यापकों को ५० प्रतिशत महंगाई भत्ता देने को तैयार है तो उत्तर प्रदेश को अपना शेयर देने में क्या आपत्ति है। मैं चाहता था कि विरोधी दल के नेता आकर शिक्षा मंत्री से, मुख्य मंत्री से पूछ लेते कि क्या यह सही है कि छागला साहब ५० प्रतिशत अनुदान देने को तैयार हैं; २० रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार महंगाई भत्ता पहले ही दे चुकी है और अगर २५ रुपये केन्द्रीय सरकार देने को राजी है तो फिर मुख्य मंत्री को ५ रुपये देने में क्या एतराज हो सकता है। तो यह ऐसी घटना नहीं है जिसके लिये आप अविश्वास का प्रस्ताव लाते। लोकतंत्र में यह भी एक मान्यता है कि विरोधी पक्ष एक वैकल्पिक सरकार की भांति कार्य करती है और यह मुमकिन है कि एक दिन हमें हटना पड़े। जिस दिन शारदाभक्तसिंह हमें हटायेंगे तो उग्रसेन और आप हिन्दी के लिये तो चिल्लायेंगे लेकिन भानुप्रताप सिंह और चन्द्रजीत यादव इस मसले में आपका साथ नहीं देंगे। झारखंडे राय इस समय मौजूद नहीं हैं लेकिन जिस समय वह कहेंगे कि खेती का सामूहिकरण किया जाय तो भानुप्रताप सिंह खेती में यह सहकारिता करण भी नहीं होने देंगे। माननीय उग्रसेन और चन्द्रजीत सिंह कहेंगे कि योजना बनना चाहिये और योजना का भी ठोस होना चाहिये, तो माननीय शारदाभक्तसिंह कहेंगे हम योजना के विरुद्ध हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह---

गलत है। हमको योजना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैंने समाचार पत्र में एक दिन पढ़ा कानपुर में जनसंघ के एक साहब हैं उनका कहना था कि हम एक आन्दोलन करने जा रहे हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना न लागू की जाय, उत्तर प्रदेश की क्षमता के बाहर है।

श्री शारदाभक्तसिंह---

हमारा कहना है कि स्वरूप बदलो।

श्री कृष्णानन्द राय---

यदि आप योजना के समर्थन में हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं।

उत्तर प्रदेश में आर्थिक विषमता का एक कारण है, आंकड़ों से हम भाग नहीं सकते, तीन पंचवर्षीय योजना में देश के समस्त सूबों में अधिक रुपया खर्च किया गया है और हमारे प्रदेश में अधिक खर्च नहीं किया जा सका है। मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम ३ वर्ष में ७० करोड़, ७९ करोड़ रूपये तक खर्च हो पाया था, लेकिन योजना के चौथे वर्ष में १२० करोड़ रुपया खर्च हुआ है और जहां तक मेरा विश्वास है, १४४ करोड़ रुपया योजना के पांचवें वर्ष में हम खर्च करने जा रहे हैं। इससे यह साबित होगा कि ५०२ करोड़ रुपये का जो फायनेन्शियल टार्गेट था उसको उन्होंने पूरा ही नहीं किया बल्कि उसको एक्सीड किया है। इसके लिये हमें धन्यवाद देना चाहिये। इसके अलावा वह केन्द्र से बड़ा संघर्ष कर रही हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना हमारे प्रदेश के लिये १,४०० करोड़ रुपये की हो जिससे हम ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें और शिक्षा, स्वाथ्य तथा अन्य सुविधायें को हम पूरा कर सकें। विरोधी दलों का यह कर्त्तव्य होना चाहिये था कि वे सदन में या सदन के बाहर एक जगह बैठ कर विचार करते कि आज हमारा प्रदेश जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उसको दूर करने के लिये माननीया मुख्य मंत्री जी ज: १,४०० करोड़ रुपये की मांग कर रही हैं उसके संबंध में हम और आप सब लोग सोच समझ कर उसकी समीक्षा करते। लेकिन मुझे याद है कि जून और जुलाई के महीने में खाद्य समस्या बड़ी कठिन थी। हम लोग अपने जनपदों में थे और जनता कहती थी कि इसका समाधान करना चाहिये। उस समय हम लोगों ने समाचारपत्रों में पढ़ा कि

[श्री कृष्णानन्दराय]

मुख्य मंत्री ने सभी दलों के नेताओं को इस समस्या पर विचार करने के लिये बुलाया था। हम लोग बड़ी आशायें लेकर आये थे। लेकिन, श्रीमन्, सितम्बर का अधिवेशन बिता दिया गया यह कह कर कि यह सरकार इतनी निकम्मी है, हम इससे क्या बात करें और जो संयुक्त समिति बनी थी उसमें विरोधी दल के आदरणीय नेताओं ने सहयोग करना अस्वीकार कर दिया। मैं आप से कहता हूं कि विरोधी दलों की मान्यता समाप्त हो चुकी है और आप लोग कलंक लगा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं विश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हमारे मुख्य मंत्री ने इस सूबे का चार्ज लिया तो मैं भी उन लोगों में से था जिन्होंने उनको बधाई दी थी। लेकिन आज इतने दिनों के बाद मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद वह बात गलत थी और जो उन्होंने इत्मीनान दिलाया था कि मैं सूबे की हर मुमकिन तरीकों से बेहतर से बेहतर खिदमत करूंगी उसके ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। यह मैं ही नहीं कहता, विरोधी दल के लोग ही नहीं कहते, बल्कि आपके दल के लोग कहते हैं और वे लोग कहते हैं जो आपके मंत्रिमंडल में थे। जब से आप मुख्य मंत्री हुई हैं आप अपने साथियों में कोआर्डीनेशन और कोआपरेशन पैदा नहीं कर सकीं।

श्री कृष्णानन्द राय—

इससे आपका क्या मतलब है ?

श्री हलीमुद्दीन—

हमें कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद अपने घर में बैठे कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको शान्ति से एक दूसरे की बात सुननी चाहिये।

*श्री हलीमुद्दीन—

मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे साथ आवाज लगायें। अगर मुख्य मंत्री में कोई कमजोरी है, इख्तलाफ है कि एक जगह एक विचार से नहीं सोच सकती हैं, तो वे सूबे का भला नहीं कर सकती हैं, सिवाय इसके कि बर्बाद करें। इस सिलसिले में, मैं आप से कहता हूं कि हमारे दोस्त जो उधर बैठे हैं वे भी उस जनता के रिप्रेजटेटिव हैं जिसके हम हैं। "कभी यह सोचा भी तुमने चमन के गुल बूटो, तुम्हारे रहते हुये भी वीरान हुआ चमन कैसे"। आप लोग भी सोचिये कि आप मौजूद हैं और यह हाहाकार मचा हुआ है। आपका कोई समझ बूझ कर काम नहीं हो रहा है, लोग-अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। एक मंत्री कहता है कि मैं तुम्हारी मातहती नहीं कर सकता, दूसरा मंत्री कुछ कहता है....

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

यह बतलाइये कि रिपब्लीकन पार्टी क्या करती है ?

श्री हलीमुद्दीन—

पहले आप लोग इस्तीफा दे दीजिये फिर बताऊंगा कि हम क्या कहते हैं। हम नहीं कहते हैं बल्कि दीवारें कह रही हैं कि आपका क्या हश्र होने वाला है।

हमारे मुल्क में जो जुबान का मसला है उसके सिलसिले में, मैं आपको बताऊंगा कि जो उर्दू जुबान के साथ यू० पी० सरकार का क्या व्यवहार है। वह कम से कम उस तबके के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों क लिये ठीक नहीं है, जिसने एक अरसे से हिन्दी नहीं जानी है । जो लोग अब बुड्ढे होकर....

(व्यवधान)

इसमें आप गलत समझ रहे हैं। आप मंत्रिमंडल को छोड़ दीजिये। हिन्दी को आपकी सरकार उन तमाम लोगों पर लाद रही हैं और उनकी तहजीब को खत्म करना चाहती हैं। आपके शिक्षा मंत्री जो वहां हैं, प्रधान मंत्री जो हैं वह कह रहे हैं कि आपकी तकलीफ सुनी जायेंगी, लेकिन यहां के शिक्षा मंत्री फरमाते हैं कि उर्दू जबान का तो कोई इलाका ही नहीं है, उस को पढ़ाने और बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है—

कुछ सदस्य—

जो अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं, उन शारदाभक्तसिंह जी से तो जरा इस पर बात कीजिये ।

श्री हलीमुद्दीन—

वह भी यहां पर इस बात के लिये मजबूर हैं। वह जो भाषा यहां पर बोलते हैं, वह तो हिन्दुस्तानी भाषा है, जो हम समझते रहे हैं, लेकिन जो जबान आपकी किताबों में, आपकी गजट में और नोटिफिकेशन में आ रही है चाहे जो भाषा हो, लेकिन वह आम जनता की भाषा नहीं है। मैं समझता हूं कि यह वह जबान नहीं है जिससे गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान के लिये ऐसी जवान होनी चाहिये, जो देश में बोली और समझी जाती है । आज जो आप लोग गांधी जी का नाम लेते हैं, उनके उसूल यदि याद हों, तो देखें कि क्या गांधी जी ने यही कहा था जो आजकल आप हमारी जबान के साथ कर रहे हैं । गांधी जी ने यह कभी नहीं कहा था कि जो आज आप हमारी जबान, तहजीब, वगैरह के साथ कर रहे हैं ।

आज मैं एक सवाल आप से पूछना चाहता हूं। आप को दक्षिण के लोगों ने जिस जबान में समझाया, जैसे जैसे कारनामे किये आप उनसे मजबूर हो गये और उनके आगे अपने घुटने टेक दिये कि ठीक है जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, जब तक तुम नहीं चाहोगे हिन्दी वहां नहीं चलाई जावेगी, अंग्रेजी चलेगी। यह सब क्या है ? तो क्या आप चाहते हैं कि हम भी वही रवैया अख्तियार करें अपनी जायज मांग को उसी जबान में आपको समझायें ? यदि आप इतना तक गिर सकते हैं तो यदि हमें भी जरूरत हुई तो हम लोग भी अपनी कुरबानी करने के लिये तैयार हैं । हमारी मांग उनसे कम वजन नहीं रखती और हम भी उनसे ज्यादा कुरबानी और सब कुछ कर सकते हैं जो उन्होंने किया। अगर उर्दू को खत्म करने की कोशिश की जायेगी तो यकीनन हम वही तरीका अपनायेंगे जो दक्षिण भारत ने किया । उन्होंने ऐसा रास्ता आपके ऊपर लाद दिया कि आप मजबूर हो गये गैर प्रदेश की जबान कायम रखने के लिये, और अब आप ऐक्ट में तब्दीली करने की बात सोचते हैं और जो आपके प्रदेश की एक खास जबान है, जो यहां पर फली-फूली है, उसकी आप कोई परवाह नहीं कर रहे हैं ।

इसी सिलसिले में, मैं आप से एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने एक जरा जमीन के लिए गवर्नमेंट को लिखा। महानगर में एक उर्दू स्कूल खोलने के वास्ते जमीन के निस्बत लिखा कि हम एक वहां पर उर्दू स्कूल खोलना चाहते हैं। लेकिन डेढ़ २ वर्ष हो गये अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। यह है आप की उर्दू के साथ बुरे सुलूक की बात। रामकृष्ण वालों को बाग लगाने के लिए बीघों जमीन मिल जाती है, मन्दिरों के बनवाने के लिए जमीन हो जाती है, लेकिन उर्दू के लिए कोई बात नहीं हो सकती है।

एक बात की तरफ मैं आप की तवज्जह और दिलाना चाहता हूं जो हम लोगों की इस गवर्नमेंट में कठिनाई है, मुसलमानों के ऊपर किस तरह से कठिनाई है। उस पर आप की सरकार कोई ध्यान नहीं देती। मुलाजिमत में मुसलमान लगातार कम होते जा रहे हैं तथा उन के साथ वह व्यवहार भी नहीं होता जो कि होना चाहिये और जो सलूक दूसरे लोगों के साथ किया जाता है। एक मुसलमान यदि कोई खता करता है तो उस को सख्त से सख्त सजा दी जाती है, लेकिन वही सजा जब कोई दूसरा करता है

[श्री हलीमुद्दीन]

तो उस को बहुत कम सजा दी जाती है या उसे बिलकुल ही छोड़ दिया जाता है। इस तरह से आपने एक मुस्तकिल अन्देशा उन लोगों में पैदा कर दिया है और कुछ लोगों ने...

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

पाकिस्तान में क्या हो रहा है?

श्री हलीमुद्दीन---

जहां हो रहा है, वहां जाकर देखिये। यदि आप पाकिस्तान की ही बात करना चाहते हैं तो मुख्य मन्त्री व प्रधान मन्त्री सब हट जायें और वह यहां भी हो जो पाकिस्तान में हो रहा है, यहां भी अयूब बन जायें।

बारबार पाकिस्तान की बात आप कहते हैं तो फिर पाकिस्तान से सबक लीजिये; फिर चाहे डूबें, चाहे उछलें हम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपको मुल्क को जम्हूरियत पर ले चलना है, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे हमें क्या ताल्लुक है, हम से वहां से क्या मलतब है? आप हमारे जज्बात से मत खेलिये। हमने पाकिस्तान नहीं बनवाया। हम पाकिस्तान के साथ कभी नहीं रहे। हमने पाकिस्तान के लिए कभी वोट नहीं दिया। अगर आप का खयाल हो तो अपने दिलों से उसको निकालिये। हम हमेशा कांग्रेस में थे, देश की आजादी के लिए हमने जेलें झेलीं, डन्डे खाये, हमारे घरबार उजड़े, उन से हम निकाल दिये गये, हम इसी बुनियाद पर कांग्रेस के साथ थे। लेकिन आज क्या नतीजा है? आज कांग्रेस में नहीं हैं। जो पाकिस्तान के साथ थे वह उधर ही कांग्रेस में हैं, उधर कुर्सियों पर रूनुमायां हैं। आप यह समझते हों कि दाढ़ी है, नाम राहत मौलाई है, तो आप गाली के अलफाज में दाढ़ी की बात कहते हो। लेकिन आप को असलियत मालूम नहीं है। मेरी सूरत पर दाढ़ी है वह भी आप की ही रखी गयी है। यह मैंने मजबूरन रखी है, मुझे यह रखनी पड़ी है कि जब आपने फिरकापरस्त कहना शुरू कर दिया है तो हम भी दाढ़ी बढ़ायेंगे, देखें कि आप क्या करेंगे? बार बार पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम लेकर आप खुद फिरकापरस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान गलत बात करता है तो आप बराह करम उसकी मत तस्दीक कीजिये। जो पाकिस्तान बनाने वाले थे उन से आप कहिये। जो आप के साथ आज उधर बैठे हुये हैं। वे उस वक्त मुसलिम लीग में थे, हम से क्या कहते हैं? हम ने कभी मुसलिम लीग की हमनवाई नहीं की है। अगर कोई बदगुमानी आप के दिमागों में उस की वजह से है तो उसको दूर करना हमारा फर्ज है। लेकिन हमारी मजबूरी है; अगर हम आवाज लगाते हैं सही बात कहना चाहते हैं, जज़बात को आप के सामने आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं, तो आप फिरकापरस्त कहते हैं और सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। हम जानते हैं कि उस में मजहब की बात पर जोर नहीं दिया जाता। लेकिन क्या किसी ऐसे तबके को जिस में करोड़ों आदमियों की जिन्दगी वाबस्ता हों नजरन्दाज कर दिया जाय और फिर भी आप जम्हूरियत को कायम कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आप को कम से कम मुसलमानों का जो तबका है, चाहे उनको फिरकापरस्त समझकर, चाहे हिन्दुस्तान का बाशिन्दा समझकर जो कुछ करना है करना होगा।

एक सदस्य---

बैठ जाइये।

श्री हलीमुद्दीन---

जरूर बैठ जाऊंगा, आप के हुक्म की तामील जरूर की जायेगी। अभी हमारे शहर मुरादाबाद में एक एलान हुआ। एलेक्शन का नोटिफिकेशन हुआ। गजट हुआ। यह बात छिपी नहीं है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं। इत्तिफाक से, खुशकिस्मती से वे मुरादाबाद तशरीफ ले गयी थीं, जब यह एलेक्शन मुल्तवी कर दिया गया। वजह क्या बतायी गयी कि वहां पर चूंकि कम्युनल टेंशन है इसलिए वहां के एक अधि-

अधिकारी ने यह कह दिया कि हम अमनोअमां के जिम्मेदार नहीं हैं। यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट हुई। मुमकिन है कि वहां कोई कम्युनल टेन्शन उन को दिखाई दिया हो। दूसरे मन्त्री भी वहीं से मुताल्लिक ह, वह आज यहां हैं, कल वहां हैं, जरा बतायें तो वहां कहां कम्युनल टेन्शन था। वहां मेडिकल कान्फ्रेंस थी। वह हो गयी। तमाम प्रांविसेज से बड़े-बड़े आदमी जमा हुये, कोई उस पर कम्युनल टेन्शन का असर नहीं पड़ा, लेकिन मुरादाबाद में एलेक्शन्स को मुल्तवी कर दिया गया, क्यों? वहां मुमकिन था कि कांग्रेस हार जाय, इसलिए उसको मुल्तवी कर दिया गया।

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

क्या मुरादाबाद और संभल में आप जीते, जो वहां ही आप की जीत हो जाती?

श्री हलीमुद्दीन—

जी हां, सब जगह हुई है। यह क्या बात है कि आप दूसरे मुकामात का मुकाबला करने लगे? अगर दूसरी जगह लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं तो यहां भी डालेंगे, यह क्यों कहते हैं और समझते हैं। बराह करम उस बात को मत उठाइये। कहीं हारे कहीं जीते, आइन के तहत में हमें एक राइट है कि हम अपना बोर्ड कायम करें, लेकिन आपने महज एक हाकिम के कहने से आपने हमारे उस कांस्टीटचूशन राइट को खत्म कर दिया। संभल में हम हार गये, अमरोहे में हम हार गये, तो फिर जो चाहे आप करिये। क्या आप यह चाहते हैं कि आप डिक्टेटरशिप कायम कर लीजिये? अगर ऐसी बात नहीं है तो कहीं कोई जीते कोई हारे, इससे मतलब क्या है? वैसे तो संभल के एम० एल० ए० भी आप के नहीं हैं और अमरोहे के एम० एल० ए० भी आप के नहीं हैं, दोनों इस तरफ बैठे हुये हैं। यह बेमानी बात है और अगर बनारसीदास जी इस को उचित समझते हैं तो ताज्जुब है। यह वही इलाका है जहां आप के मुख्य मन्त्री जी जिस इलाके से जीत गये हैं। संभल और मुरादाबाद भी उस में शामिल हैं। तो आप ऐसी बात मत कहिये जो वाकये के खिलाफ हो। मैं तो एक दूसरी बात कह रहा था कि महज एक आफिसर की बेबुनियाद रिपोर्ट के ऊपर यह कह कर कि कम्यूनल टेन्शन है, आप एलेक्शन को मुल्तवी करते हैं, यह बात तकलीफदेह है।

मैं यह कह रहा हूं कि हमारी मुख्य मन्त्री जी कहती हैं कि मैं गांधी जी की चेली हूं **औ**र अफसरों के हाथ में नहीं खेलती हूं। मगर मेरी गुजारिश है कि आप अफसरों के हाथ में खेलती हैं और जो भी अफसर कहते हैं वही आप करती हैं। मैंने उनसे गुजारिश की कि कौन सा कम्युनल टेन्शन मुरादाबाद में है जिसकी वजह से आप वहां के एलेक्शन को मुल्तवी कराना चाहती हैं। मैंने उनसे पूछा कि यह बात मुझे बतलायी जाय कि ऐसी बात वह किस बिना पर कहती हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट इस तरह की है। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको गलत रिपोर्ट देता है तो क्या आप उस गलत काम को करने के लिए तैयार हो जायंगी? मैं यह समझता हूं कि अगर आप अफसरों की किसी रिपोर्ट पर ऐसा करती हैं तो आप जरूर अफसरों के हाथ में खेलती हैं। मैं तो यह कह सकता हूं कि यह बात बिलकुल सही है कि आप अफसरों के कहने के बगैर एक कदम भी उठाने के लिए तैयार नहीं होती हैं। मैंने पहले भी यहां पर गुजारिश की कि आई० जी० के पी० ए० जो हैं वह बी० ए०, एल-एल० बी० नहीं हैं। पता नहीं किस तरह से वह आई० जी० के यहां घुस गये! बंशीधर जी को यह जान कर हैरत होगी कि वह इन्टरमीडियेट पास नहीं हैं, लेकिन आई० जी० के पी० ए० के ओहदे पर बैठे हुये हैं। आप को यह पता नहीं चल पाया कि वह किस तरीके से वहां पहुंच गये। यहां पर जब इस सवाल को उठाया गया कि कैसे उन के नाम के आगे बी० ए०, एल-एल० बी० लिख दिया गया तो यहां पर जवाब दिया गया कि तहकीकात से मालूम हुआ कि वह बी० ए०, एल-एल० बी० उन के नाम के आगे गलती से लिख दिया गया था और अब उस रिकार्ड को ठीक कर दिया गया है। इस तरह की आप के यहां हरकत होती है, लेकिन सरकार को पता नहीं चल पाता है।

[श्री हलीमुद्दीन]

एक और वाकये का जिक्र करना चाहता हूं, जिस के बारे में यहां पर जबाब दे दिया गया कि वह बहुत मामूली बात थी और वह बहुत मामूली नकशा था। डिफेंस के इन्चार्ज एक डिप्टी ने और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने मिल कर १५ लाख रुपये में वह नक्शा पाकिस्तान के हाथ बेच दिया। यह कितने ताज्जुब की बात है कि इतना अहम नकशा जो हमारे मुल्क के डिफेंस से ताल्लुक रखता था उसको दो सरकारी अफसरों ने मिलकर दूसरे मुल्क के हाथ में दे दिया। पिथौरागढ़ के बार्डर का नकशा कितना इम्पार्टेन्ट हो सकता है यह आप अन्दाजा लगायें, लेकिन जब इस सवाल को उठाया जाता है तो जवाब दिया जाता है कि वह कोई इम्पार्टेन्ट नहीं था। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप की हुकूमत में इस तरह की चीजें चल रही हैं। अगर जनता ने आपके हाथ में हुकूमत दी है तो आप इसको ठीक तरह से अंजाम देने की कोशिश करें। सिर्फ यही बात नहीं है कि विरोधी दल का आप के ऊपर से विश्वास हट गया है, बल्कि जनता का भी आप के अन्दर कोई विश्वास नहीं रह गया है। वह यह आवाज लगा रही है कि उसको रोटी दो और कपड़ा दो। वह भूखी है खाना चाहती है। उसके पास खाने के लिए नहीं है। मैं आप को बतलाऊं कि १८ हजार रुपये के परदे हर साल हम गवर्नर साहब को देते हैं। पता नहीं वे हर साल कहां चले जाते हैं! जनता भूखी है, उस के पास खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की शान की चीजें खरीदने के लिए हर साल पैसा मांगा जाता है। इसी वजह से जनता का आप के ऊपर से विश्वास हटता जा रहा है। अगर जनता की आवाज को लेकर हम यहां पर इस तरह के प्रस्ताव को रखते हैं, तो आप कहते हैं कि इसमें कोई वजन नहीं है, यह फैशन हो गया है और यह भानुमती का पिटारा है। याद रखिये इस भानुमती के पिटारे में बहुत जहरीले सांप हैं और अगर हर एक सांप ने काटना शुरू किया तो आपकी हालत बहुत खराब हो जायेगी और फिर आप का इलाज भी नहीं हो सकेगा।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता ने इस आदरणीय सदन में जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और घोर विरोध करता हूं। अभी अभी इसी सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकार ने विश्वास प्राप्त किया था और जब विश्वास प्राप्त किया तो जहां तक मुझे मालूम है किसी भी विरोधी दल के नेता या सदस्य को सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन यह सरकार की उदारता है कि सरकार ने उसके बाद भी आपके प्रस्ताव को बहस के लिए स्वीकार कर लिया और यह इसलिए कि सरकार जानती है कि उस में कोई कमजोरी नहीं है। मैं आदरणीय नेता जी से एक बात पूछना चाहता हूं। जब सदन में शिक्षा का बजट पेश थां उस समय आपने अपनी बात कही और उस के बाद शिक्षा के अनुदान पारित हुये। मैं जानना चाहता हूं कि उस समय शिक्षा के मद में अध्यापकों की बात क्यों नहीं उठायी गयी। उस समय आपने क्यों नहीं रोका? जब वह निकल गया तो आप लकीर पीट रहे हैं। सर्प निकल गया, आप लकीर पीट रहे हैं। यहां तो 'कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। अविश्वास के प्रस्ताव में एक जनसंघी है, एक समाजवादी है, एक कम्युनिस्ट है। आप देखिये कि बस्ती में जनसंघ जीता, लेकिन समाजवादियों की पराजय हुई। यहां विजित और पराजित एक साथ हैं। कांग्रेस वाले नरम समाजवादी हैं, लेकिन आप तो जनसंघ से पराजित हो चुके हैं, और यहां वही नेता लोग जनसंघ की बात का समर्थन कर रहे हैं। यह ताज्जुब की बात है। ऐसा ही विरोधी दल हमारे प्रदेश में रहा तो प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। जनता यह उम्मीद नहीं कर सकती कि इससे उसकी रक्षा या उत्थान हो सकता है। जहां और जिस काम में उनका उल्लू सीधा होता है वही काम यह लोग करते हैं। जनसंघ कहता है कि कम्युनिस्ट पंचमांगी हैं और इसलिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनको जेल भेंजना चाहिये, उन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये, लेकिन यदि यह प्रस्ताव आपका पास हो जाय और सरकार हट जाय तो मैं आदरणीय नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि क्या वे समाजवादियों और कम्युनिस्टों को मिला कर सरकार बना सकेंगे और क्या इस प्रदेश का होम मिनिस्टर डा० जेड० ए० अहमद को बनायेंगे । वह नहीं बनायेंगे । आप लोग तो भाई-भाई म जूता चलवाने वाले हैं । कल आप ही कम्युनिस्टों को जेल भेज रहे थे, आज आप ही उन के साथ हैं । हम तो समझते थे कि उन्होंने रूस और चीन से हाथ मिलाया होगा, लेकिन यहां के कम्युनिस्टों का कुछ पता नहीं । आज वह जनसंघ को सपोर्ट कर रहे हैं । मैं झारखंडे राय जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे जनसंघ के नेता को मुख्य मन्त्री की हैसियत से स्वीकार करेंगे । क्या उन को वे अपना नेता मानेंगे ? क्या इस के लिए वे तैयार हैं ? यदि नहीं हैं तो मुझे दुख है कि जो गरीब किसान की बात करते हैं वह समाजवादी और कम्युनिस्ट कैसे जनसंघ की हां में हां मिलानें के लिये तैयार हुए ? इसी तरह से शासन चलाओगे प्रदेश का ? यह आप लोगों के बस की चीज नहीं है ।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, आप हिन्दी हिन्दी चिल्लाते हैं । उधर हमारे मौलाना साहब उर्दू की बात कर रहे हैं और मौलाना साहब के भी अविश्वास पर दस्तखत हैं । मौलाना साहब की मैं इज्जत करता हूं और शारदा भक्त सिंह तो नेता विरोधी दल होने के नाते हमारे नेता हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी इज्जत करें । यदि आपकी हुकूमत हो गयी तो शिक्षा के मंत्री मौलाना राहत मौलाई को आप बनायेंगे ? आप नहीं बनायेंगे । उनके जानी दुश्मन होकर उनकी बात आप कहते हैं । हम तो कई हजार बरस के भुक्तभोगी हैं आपके । आज कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा है । आज वही हालत है कि जब दुर्योधन पर चढ़ाई कर दी एक यक्ष ने तो धर्मराज युधिष्ठर ने कहा था कि हमारे विचार आपस के कटुता के हैं लेकिन तुम्हारे लिये हम १०५ हैं । तो हमारे मतभेद की बात आप न करें । हम तो १०५ हैं आपके लिये । कितने भी मतभेद हों, लेकिन तुम्हारे लिये तो जब भी हैं, १०५ ही हैं, आजमायश करके देख लो । तुम्हारी इस भानुमती के कुनबे वाली नीति से इस प्रान्त का शासन चलने वाला नहीं है, इस प्रान्त को जीने दो, प्रान्त का उद्धार करो ।

आज इस प्रदेश में ३-४ करोड़ हरिजन वर्ग पीड़ित और दुखित हैं । इस प्रदेश के अत्याचारों से और यह सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है और यह आवश्यक है कि आप भरसक उसमें सहयोग दें, अच्छे सुझाव दें ताकि हमारे प्रान्त का कत्याण हो, प्रान्त की उन्नति हो सके । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और ऐसा प्रस्ताव आपको नहीं लाना चाहिये, क्योंकि अभी आपका संगठन नहीं है, भानुमति का कुनबा है ।

श्री कुमारकरुणाकृष्ण नायर (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो अविश्वास का प्रस्ताव हुआ है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । आज देश भर में भाषा की एक भयंकर समस्या खड़ी है और इस सदन में भी मैं देखता हूं कि भाषा के ऊपर सदस्यगण बहुत क्षुब्ध होते हैं । चूंकि मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, अगर मेरे भाषण में कुछ अंग्रेजी शब्द निकल जायं तो उसकी मैं माफी पहले से चाहता हूं ।

आज का दिन ४ मार्च, १९६५ भारत के इतिहास में जनतन्त्र के लिये, मैं समझता हूं, एक महत्वपूर्ण दिन है । इस वास्ते नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव हो रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, वह इस वास्ते है कि आज केरल में एक मिडटर्म इलेक्शन हो रहा है । उसका इतिहास जो भी जानता है उसको जनतंत्र का परिचय हो जायगा । इस मिडटर्म इलेक्शन की जरूरत कैसे हुई ? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो काम कर रही थी उसको जनता ने गद्दी से उतार दिया कुशासन के कारण । उसके बाद एक कांग्रेस गवर्नमेंट को सदन में वोट से गिरा दिया जिसमें चन्द ईमानदार कांग्रेसियों ने उनकी आलोचना की थी । यह दिन आज हमारे शासन के लिये एक चेतावनी है । हमारे कांग्रेसी मित्रों को एक गर्व है कि हमने चुनाव जीत लिया है और ५ वर्ष के लिये हमारा शासन रहेगा । जरूर रहेगा । अगर आप चाहें तो

[श्री कुमारकरुणाकृष्ण नायर]

रहेगा, मगर जो आज अविश्वास का प्रस्ताव है यह जनता के अविश्वास का एक रूप है । भले ही हम विरोधीगण अपने मत से आपको गद्दी से न हटा पायें, मगर आपको अपने दिल से पूछना चाहिये कि हम जनता के विश्वास के पात्र हैं या अपात्र हैं । अगर अपात्र हों तो आपको खुद गद्दी छोड़नी चाहिये ।

यहां पर गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर हम शासन छोड़ते हैं और विरोधीगण को गद्दी पर बैठाते हैं तो हमारी तरफ से जनमत के साथ एक बिट्रेयल हो जायगा, घात हो जायगा । उसी रीति से चन्द और सज्जनों ने भाषण किये । मैं कहता हूं कि न तो जनसंघ और न कोई और दल शासन करने की वांछा रखता है । हम चाहते हैं कि आप गद्दी पर से हट जाइये, एक दूसरा इलेक्शन होने दीजिये और जनता के मत को जाहिर होने दीजिये । मैं जानता हूं कि आज विरोधी दल की गवर्नमेंट बन जायगी तो आपके वोट से वह दूसरे दिन गिर सकती है और उसके लिये हम वांछा नहीं रखते हैं और न तैयार हैं । हम चाहते हैं कि आप मंत्रिमंडल से हट जायं, दूसरा इलेक्शन हो जाय, उसके बाद जनता का मत जाहिर हो जाय । आप पूछेंगे कि जनता का मत कांग्रेस के साथ नहीं है, इसका क्या प्रमाण आप देते हैं । मैं तीन प्रमाण आपके सामने रखता हूं । तमाम उत्तर प्रदेश कृषि पर निर्भर है । इस देश की जनता कृषि से अपनी हुकूमत को चलाती है । आज इस देश का कृषि करने वाला वर्ग, टेनेन्ट्स, आपके साथ हैं या नहीं हैं ? आप कहेंगे कि हमारे साथ हैं । तो अभी हाल ही में इसका परिचय हो चुका था । आपने टेनेंन्ट्स के ऊपर एक अडीशनल लेवी रखी थी । उसके विरोध में बहुत से विरोधी दल के लोग जेल गये, उसके बाद आपने उसको वापस लिया । क्यों वापस लिया ? जब कृषक वर्ग की मदद आपके साथ थी तो क्यों वापस लिया ? आज दूसरे रूप में आप एक लेवी ला रहें हैं । क्या आपके लिये धर्म नहीं है, न्याय नहीं है, कि आप जनता का मत दोबारा ले लें ? जिस कदम को जनता के विरोध के कारण आपने वापस ले लिया उसको दूसरे रूप में लाने से पहले क्या जनता के मत को दोबारा लेने की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी ? एक तो यह है ।

दूसरा प्रमाण यह है कि आज इंटेलीजेंशिया, शिक्षित वर्ग, आपके खिलाफ है । प्रमाण यह है कि हाल ही में नगरों में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से कितने उम्मीदवार विजयी हुये ? कितने आदमी कांग्रेस के टिकट पर खड़े होने के लिये तैयार ही हुए थे ? शिक्षित वर्ग के सामने कांग्रेसी उम्मीदवार होकर जाने के लिए लोग तैयार ही नहीं थे, यह हालत थी । तो सिविक इलेक्शन के रिजल्ट से मालूम हो जाएगा कि इंटेलिजेंशिया की कांग्रेस के संबंध में क्या राय है । आप कहेंगे कि इन्टेलीजेन्शिया का इस मुल्क में कितना हिस्सा है । मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो भविष्य के लिये आपका अन्त हो जायगा । आपको सोचना चाहिये कि क्या कारण है कि आज इन्टेलीजेन्शिया आपसे विमुख है, उसको आपमें विश्वास नहीं है । आप न्याय नहीं करते हैं । अंग्रेजी में यह कहा जाता है कि जस्टिस इज ब्लाइन्ड, न्याय अन्धा है । मंत्री अगर कोई अपराध करे तो उसके लिये कोई अपराध नहीं होता, उसके ऊपर कोई अभियोग नहीं चलाया जाता, लेकिन उसके हुक्म से अगर कोई आफिसर कुछ काम करेगा तो उस पर मुकदमा चलाया जायगा । मालवीय जी के कहने पर जिन लोगों ने काम किया उन पर आज मुकदमा चलाया जा रहा है । प्रतापसिंह कैरों दिवंगत हो चुके हैं, उन पर अभियोग नहीं चलाया गया, लेकिन जिन आफिसरों ने उनके कहने के अनुसार काम किया उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है । आप न्याय नहीं करते हैं और जनता को इस कारण आपमें विश्वास नहीं रह गया है ।

जनता का आप में विश्वास नहीं है, इसके प्रमाण में मैं तीसरा कारण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । पहला कारण मैं अध्यापक वर्ग के रोष का रख रहा हूं । माननीय नेता विरोधी दल ही नहीं, आपके कांग्रेसी लोग भी यह मानते हैं कि अध्यापकों की मांगें सही हैं । उनके लिये आपने कुछ नहीं किया है । आज यह भी संभावना है कि आप शायद उन पर डी० आई० आर०

का प्रयोग करें। मैं पूछता हूं यदि आपने अध्यापक वर्ग के ऊपर डी० आई० आर० का प्रयोग किया, और अध्यापकों को पढ़ाने के लिये मजबूर भी किया, तो आप उनकी हाजरी तो करा लेंगे, मगर आप उनके मूंह से अच्छी शिक्षा भी निकलवा सकेंगे ? अगर यह नहीं कर पायेंगे तो क्या परिणाम होगा ? जैसा कि माननीय शारदाभक्त सिंह जी ने कहा, यह चिनगारी विद्यार्थियों में भी लग जायेगी और वह आग का रूप धारण कर लेगी। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हम लोग चिनगारी लगाते हैं, हमको चिनगारी लगाने की जरूरत नहीं है, यह चिनगारी लगी हुई है, और इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। आपने अगर सख्ती की तो चन्द दिनों के लिये मास्टरों को तकलीफ हो जायेगी, मगर इसका असर विद्यार्थियों पर क्या होगा, उनकी परीक्षा कैसे होगी, उनके कागजों की जांच कैसे होगी, नहीं ठीक होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, और उस सबके लिये जिम्मेदार आप होंगे। वह सब आखिर में आपके ऊपर ही आयेगा।

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं, बांसी से चुनकर आया हूं, मेरे बारे में चन्द शब्द कहे गये, कुछ मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। यह कहा गया कि धर्म के नाम पर, धर्म का नारा लगाकर मैं जीत कर आया हूं। मैं कहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को यह भ्रम हो, वे बांसी जाकर यह पता लगायें कि कितने मुसलमानों ने मुझे वोट दिया है। वहां पर काफी संख्या में मुसलमानों ने मेरा समर्थन किया है। आज मुझे यह भी कहना है कि शासन से मुझे इसलिये निकाला गया कि मैं शासन का बागी रहा हूं, आज इस मंत्रिमंडल के कुशासन का मैं बागी हूं। अंग्रेजी शासन में मैं उस शासन का बागी रहा हूं। आज इस मंत्रिमंडल के एक सज्जन जो इस समय यहां सुशोभित हैं, जिनके ऊपर डी० आई० आर० का अपराध था, जिनके ऊपर जुरमाना हुआ था, उनको मैंने छोड़ दिया था। उसके परिणाम स्वरूप मुझे जजी से हटाकर मजिस्ट्रेट कर दिया गया था। इस सब के कारण मुझे ५० हजार का नुकसान हुआ था। मैंने अपना कर्त्तव्य किया था, मैं हमेशा कुशासन का बागी रहा हूं। आज भी इस शासन का बागी हूं, मैं धर्म का नारा लेकर नहीं आया हूं और न जनता ने धर्म के नाम पर मुझे वोट दिया है। मैं इसको दूषित समझता हूं। मैं इतना आप से कहना चाहता हूं कि आपका धर्म है कि आप अपने दिल से पूछें कि आज जनता का विश्वास आप पर है ? नहीं है, तो आप छोड़ दीजिये शासन। हम यह नहीं कहते हैं कि आप विरोधी पार्टी वालों के हाथ में शासन दे दीजिये, बल्कि दूसरा एलेक्शन होने दीजिये, जिस तरह से केरल में हुआ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज का विवाद विशेष प्रकार से अध्यापकों की समस्या के ऊपर केन्द्रित है, और वास्तव में इस प्रदेश की गम्भीर समस्या इस समय अध्यापकों की है। इसके सम्बन्ध में मैं आंकड़े तो नहीं दूंगा, इसके विषय में माननीय शिक्षा मंत्री जी सब स्पष्ट कर चुके हैं। यहां पर माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसा कह दिया कि राष्ट्रीयकरण कर दीजिये। ठीक है, मैं भी सहमत हूं कि राष्ट्रीयकरण कर दीजिये, परन्तु हमें देखना यह है कि हमें देश में, प्रदेश में प्रजातंत्र रखना है या नहीं रखना है। इस सदन में, इस देश में एक दल है, जिसे हम कहते हैं कि प्रजातंत्र नहीं चाहते हैं और चाहते हैं, तो इनके सामने एक लक्ष्य है, वह दल साम्यवादी दल है वह प्रजातंत्र में केवल साम्यवाद लाने के लिये प्रयोग करना चाहते हैं। परन्तु यह ऐसे दल हैं जो वास्तव में प्रजातंत्र चाहते हैं। प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, उन्होंने भी अगर वह नीति अपनायी, तो वह दुर्भाग्य की बात है। मैं बहुत समय से इस बात का समर्थक रहा हूं और अब भी हूं कि अध्यापकों को सुविधायें दी जायं। उनकी मांग जहां तक वेतन का सम्बन्ध है, जो यथोचित हो पूरी करनी चाहिये। अध्यापकों को ऐसा जीवनयापन करने का प्रबन्ध करना चाहिये, जिससे वे खुशहाल रह सकें, वे समाज में ठीक प्रकार से रह सकें, परन्तु प्रजातंत्र में वह मांग किस प्रकार से पूरी हो ? प्रजातंत्र में यदि एक पार्टी पावर में आ जाय, एक पार्टी को जनता चुनकर भेज दे, तो ५ वर्ष तक हमें उसके सामने मांग करने का, प्रचार करने का, सब कुछ अधिकार है, परन्तु हमें यह नहीं करना चाहिये कि उस सरकार को चलना असंभव बना दें यह डेमोक्रेसी का नेगेशन है। यह प्रजातंत्र को खतम करने की बात है। आज यह कहना

[श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)]

किसी से कि तुम टैक्स मत दो, यह कहना कि यह तो साधारण बात है, आज ऐसा कहने से अधिक व्यक्तियों को अच्छा लगेगा और यह किसी दिन भी आन्दोलन बढ़ाया जा सकता है। उसका परिणाम क्या होगा, कि इस देश में प्रजातंत्र नहीं पनप सकेगा। एक दल, दूसरे दल के साथ अगर उत्पात करता है, अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो कैसे चलेगा? आज जो तरीका अपनाया है इस बात से दुख है, इस तरह का जो तरीका अध्यापकों ने अपनाया है कि परीक्षा में भाग नहीं लेंगे, वह उचित नहीं है।

इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का यह अधिकार है कि वह किसी भी वर्ग की मांग का समर्थन करे, उस पर जोर दे और सरकार यदि उनको न्यायोचित मांग है तो उसको पूरा करे परन्तु साथ-साथ यह भी हरएक माननीय सदस्य का कर्तव्य है कि वह यह भी कहे कि जो तरीका अध्यापकों ने अपनाया है वह अप्रजातांत्रिक है और देश के हित में नहीं है। जो समझते हैं कि यह तरीका देश के हित में है उनका हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि किसी न किसी प्रकार से असंतोष पैदा करके और क्रांति लाकर एक विशेष प्रकार की सरकार वह यहां कायम करें। श्रीमन्, अध्यापकों का यह निश्चय मांग के रूप में नहीं रह गया है। जो तरीका उन्होंने अपनाया है उस तरीके को राजनीति में हमारे देश में पूज्य महात्मा गांधी जी लाये थे। मुझे याद है कि सन् २०–२१ या २२ के आन्दोलन में एक परिस्थिति ऐसी आयी जिसमें उन्होंने देखा कि यह आन्दोलन अब हमारे हाथ से बाहर होता चला जा रहा है तो उन्होंने खड़े हो कर यह कहा कि मैं आन्दोलन को वापस लेता हूं। चौरी-चौरा याद है। तो इसी तरह आज के नेताओं का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह यह देखें कि आन्दोलन उनके हाथ के अन्दर है या नहीं। यह आन्दोलन जो उन्होंने आज चलाया है, और इसके पीछे जो विषैला प्रचार चारों ओर हो रहा है, मेरे पास उसकी दो एक कटिंग्स हैं, लेकिन मैं उनको पढ़ूंगा नहीं, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वह नकल करेंगे, वह उनसे रुकेंगे नहीं। अगर ऐसा-ऐसा प्रचार हो तो कैसे कहा जा सकता है कि आन्दोलन नेताओं के हाथ में रह सकता है? वह आन्दोलन किसी समय भी भयंकर रूप दिखा सकता है। इस आन्दोलन को चलाना मांग को प्रस्तुत करना नहीं है बल्कि सरकार को पैरालाइज करना है। दो ही परिस्थितियां इसके बाद सामने हैं, एक तो यह कि या तो आन्दोलन सफल हुआ या असफल हुआ। अगर आन्दोलन सफल हुआ और परीक्षायें नहीं हुईं, तो क्या होगा? कितने विद्यार्थियों की हानि होगी? कितने विद्यार्थी इंजीनियरिंग में जाते, डाक्टरी में जाते, उनका सबका समय नष्ट हो जायगा। और अगर आन्दोलन असफल हुआ तो टीचरों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यह आन्दोलन किसी प्रकार से प्रजातांत्रिक नहीं है। जहां तक रुपये का ताल्लुक है, यह समस्या इन्हीं तक सीमित नहीं है। आज ही आपने पढ़ा होगा अखबारों में डिग्री कालेजेज के बारे में। ४५ हजार टीचर तो यह थे, ४ हजार टीचर उनके और आ गये और सबसे ज्यादा जरूरत आज जिसको है वह है प्राइमरी अध्यापक, तो इस तरह यह समस्या समस्त अध्यापक वर्ग की एक साथ हमारे सामने पेश है। मैं नहीं समझता कि कितने करोड़ का यह पड़ेगा। बराबर यों ही शिकायत होती आयी है कि बड़ा टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। इस वर्ष और पिछले वर्ष के बजट में आप देखें इसमें लगभग २७ करोड़ का अन्तर है। जिसमें से १३ करोड़ ५० लाख रुपया केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन अभिनवीकरण के कारण वृद्धि व अन्य सुविधाओं से संबंधित हैं।

दूसरी बात गल्ले के बारे में कही गई। गल्ले के मामले में मैं तो यह समझता था कि अब वह समय आ गया है कि शायद हमारे माननीय सदस्य सरकार को उसके लिये बधाई देंगे कि उसने ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में भी प्रदेश की नैया को इस तरह से खेया कि कहीं कोई भूख से मरा नहीं। वास्तव में गल्ले की बहुत ही विषम परिस्थिति हमारे सामने आयी थी। लेकिन अब हम उस परिस्थिति को पार कर गये हैं और उम्मीद है कि उसको पार कर जायेंगे। भाव भी नीचे आने लगे हैं। मैं यह नहीं कहता कि बिलकुल सब ठीक हो गया है। जब तक गल्ले

का मूल्य हम इस तरह से निर्धारित नहीं करेंगे कि जिससे किसान दूसरी पैदावार के मुकाबिले में अनाज बो सके और जब तक नीचे से उत्पादन के लेवेल से वह ठीक नहीं की जायगी तब तक बिलकुल ठीक स्थिति नहीं आ सकती। लेकिन पहले से बहुत अच्छी हालत है और जो परिस्थिति आयी थी उसको सरकार ने इस तरह से हल किया कि देश को कोई हानि उससे नहीं हुई।

एक बात माननीय यादवेन्द्र दत्त जी ने कही। उन्होंने चीन की तरफ ध्यान आकर्षित किया। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। वास्तव में हमारे सामने वह एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कुछ आंकड़े दिये कि कितने डिवीजन हैं और एक डिवीजन में कितने होते हैं। मैं सदन के सदस्यों से और उनसे निवेदन करूंगा कि वह चन्द मिनट के लिये यह भूल जायं कि वे किस दल से संबंध रखते हैं और यह सोच लें कि चीन सिर पर खड़ा है, तो वैसी स्थिति में हमारा क्या फर्ज हो जाता है और क्या हम उसके लिये वातावरण तैयार कर रहें हैं? कहीं भाषा पर रायट, संपत्ति का विनास, कहीं अनाज पर और कहीं अध्यापकों का आन्दोलन, क्या यह देश की शक्ति को बढ़ायेगा, क्या यह देश के हित में है और इसे प्रोत्साहन देकर क्या यह देश का हित कर रहे हैं?

राहत मौलाई साहब ने कुछ फरमाया। पिछली बार उन्होंने कहा था कि "हमारे खून की लाली उभर आई तो क्या होगा।"

श्री उपाध्यक्ष---

आप माइक पर बोलिये।

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)---

उन्होंने कहा कि उर्दू के मसले को नहीं माना गया तो हम वही करेंगे जो साउथ में हुआ। और वह कर सकते हैं। उन्होंने दो एक शेर भी सुनाये। हमने प्रजातंत्र स्थापित किया है, वह कुछ भी कह सहते हैं, कहते ही नहीं, करते भी हैं। हमने उन्हें कहने की स्वतन्त्रता दी है परन्तु, श्रीमन्, मैं भी उन्हें सुनाता हूं कि "हम रहे इतना तेरी खिदमत में सरगरने नियाज, तुझको हमने आशनाये नाजे बेजा कर दिया।" वह मेरे जिले के साथी हैं, आप कहें, हम सुनेंगे। डेमोक्रेसी में आपको आजादी है। लेकिन जो तरीका साउथ में अपनाया गया वही अपनाना चीन के हाथ मजबूत करेगा, हिन्दुस्तान के नहीं। वह इस देश की सेवा नहीं, बल्कि देश के दुश्मनों की सेवा करना होगा।

श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच)---

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, न तो कांग्रेस के विचारों पर मुझे अविश्वास है, न किसी व्यक्ति विशेष पर अविश्वास है और न किसी के ऊपर अविश्वास करने का प्रश्न ही उठता है। लेकिन अविश्वास इस बात पर है कि जिस बात को यह सरकार कहती है उसे करती नहीं है, जिस काम को लक्ष्य बनाती है, उसे पूरा नहीं करती है। यही एक मूल आधार है। जैसा पंडित जी ने भी कहा था प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिये, इस युग में सिपाही तो सब हैं लेकिन जब सिपाही की तरह काम पूरा करे तब ही वह सिपाही है। सवाल इस बात का है कि अगर आपने काम पूरा नहीं किया है तो इन्सानियत का तकाजा है कि आप हट जावें, भले ही कानून से आप ५ साल तक बने रह सकते हैं और उसके बाद जनता जैसा निर्णय करेगी वैसा होगा।

अध्यापकों के संबंध में बड़ी थ्रेटनिंग हुई और माननीय शिक्षा मंत्री ने बजट के भाषण के समय आचरण संहिता की ओर भी संकेत किया। थ्रेटनिंग करना अच्छा नहीं है, जब कि उनको यह मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट ने पीसफुल डिमांस्ट्रेशन को इल्लीगल नहीं माना है। उनका पीस-

[श्री रामअधार कनौजिया]

फुल डिमांस्ट्रेन साबित करता है कि वह अपनी मांगों को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। कहा गया कि अध्यापकों की २० रुपये मंहगाई बढ़ाई गई है---हम समाजवाद में आर्थिक असमानता को दूर करना चाहते हैं। सन् ५९ में वेतनों में कुछ सुधार किया गया है, ठीक है। १९६२ में मंहगाई भत्ता ३० रुपये दिया गया। उस समय अन्तर केवल १५ रुपये का था। लेकिन अब वह अन्तर सरकारी व गैर सरकारी अध्यापको के भत्ते में ३७.५० हो गया। जिससे जरूरी हो गया है कि अध्यापकों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाय।

जनता आपकी जबान और कामों को देखती है। खाद्य संकट के समय माननीय खाद्य मंत्री ने एलान किया था कि ६ किलो गल्ला देहात में फी यूनिट देंगे। लेकिन इस वायदे को पूरा करने के लिये उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। नतीजा यह हुआ कि हजारों की तादाद में लोग एक वक्त खाकर रहे या भूखे रहे। सन् १९४५ में बंगाल फेमीन कमीशन रिपोर्ट ने सबसे बड़ी बात लिखी थी कि गवर्नमेंट के सप्लाई और डिमान्ड की व्यवस्था के ऐजेस्टमेन्ट से लाखों आदमियों की जानें जाने का मुख्य कारण था जो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मदारी थी। वर्तमान सरकार को ६ किलो गल्ला देहात में पहुंचाना ही मुश्किल हो गया। आज गांव का कोई आदमी इस सरकार की बातों पर विश्वास नहीं करता है। गालिब साहेब ने भी कहा है कि जब जबान और दिल में मेल नहीं रहता है तो जबान गोश्त का लोथड़ा रह जाती है। यह सही है कि आपके विचार बहुत अच्छे थे लेकिन आप असफल रहे। उसका मूल कारण चन्द शब्दों में बता देना चाहता हूं। जो हमारे राष्ट्रपति ने बताया है, वह आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में पढ़ देता हूं---

"We talk about democracy, but when it comes to any particular issue, we prefer a man belonging to our caste or community or religion. So long as we have that kind of temptation, it means that our democracy is a phoney kind of democracy. This fact of favouritism and nepotism has been responsible for too much discontent and ill-will in our country. And if any one asks us as to why we suffer, we need not allude to the stars above or say that God has punished us. We have to put to our own inequities, our own disloyalties or deviations from the ideals, which we profess."

सन् ४७ से लेकर आजतक सरकारी कर्मचारियों में डिसकंटेन्ट है। सारे देश में अशान्ति की भावना फैली हुई है और उसका मुख्य कारण यह है कि कुनबापरस्ती बड़ी हुई है। सन् ४८ में जब झा साहब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने लिखा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जब लोग चुनाव के लिये आते हैं तो हमारे सामने बहुत सी दिक्कतें आती हैं हमारे पास बहुत से लोगों की सिफारिश होती हैं। इसलिये यदि इस प्रकार की कुनबापरस्ती न होती तो देश में आज जो अशान्ति दिखाई देती है, वह न होती।

*माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिनों से इसकी चर्चा सुनता आया था। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप बराबर अविश्वास का नोटिस देता चला आया है। कल शाम तक मैं बड़ा परेशान था और सोचता था कि जब सब लोग नाराज हैं तो क्या दशा होगी। लेकिन जब सुबह उठा तो मेरे दो दोस्त दरख्वास्तें लेकर पहुंचे। मैंने उनसे डरते हुये कहा कि ८ बजे रात के बाद लेंगे, पता नहीं क्या हो। लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी सीरियस बात नहीं है तब मेरी जान में जान आई। तब मैं जरा संभला और सोचा कि जब उनके दल के लोग ही इतने सीरियस नहीं तो फिर मैं क्यों इतना सीरियस होऊं। रात तो परेशानी में गुजरी लेकिन यहां आकर जब भाई शारदा भक्त सिंह जी से निगाह मिलायी तो परेशानी दूर हो गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके पास बैठे त्रिपाठी जी भी मेरी तरफ देखकर मुसकरा रहे थे, उससे कभी उलझन भी हो जाती थी। लेकिन खैर उनकी तकरीर खत्म हुई। मैंने देखा कि उन्होंने कोई नयी बात नहीं कही। चाहे कोई विषय हो, चाहे गवर्नर का भाषण हो, चाहे बजट का डिसकसन हो, हमेशा एक ही तरह की तकरीर होती है। (एक सदस्य—और आपका उत्तर ?) जब बात हमेशा एक होगी तो उसका उत्तर भी एक ही होगा। यह बहुत बारीक बात है, शायद आप की समझ में आयेगी नहीं, श्रीमन्, मैं बहुत लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं दूगा, आपकी झंडी का भी इन्तजार नहीं करूंगा। जब शारदाभक्तसिंह जी अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं तो उन्होंने गवर्नमेंट बनाने का भी इन्तजाम जरूर किया होगा। क्योंकि गवर्नमेंट के हटने के बाद वैक्युअम तो रहता नहीं है। किंग इज डैड, लांग लिव दि किंग। नायर साहब केरल के से जनरल इलेक्शन का ख्वाब देख रहे थे। एक अंधा कंडे बीनने गया। उसके हाथ बटेर लग गयी। उसने दूसरे दिन कहा कि बटेर लेने जाऊं या कंडा। इसी तरह से माननीय मित्र का हाल है। वे फूलपुर की बात भूल गये, मनकापुर की बात भूल गये, अलीगढ़ की बात भूल गये। उनके एक खास बात हुई जिसको मैं कहना नहीं चाहता हूं। वह हमारे दोस्त है, गोंडा में कलेक्टर रह चुके हैं। हो गया। इत्तफाक की बात है। जनता का मूड ही तो है, जिधर चला गया उधर चला गया। एक मर्तबा आपको भी जिता दिया। वह तो इस तरह से बेवकूफ बनाया ही करती है। इससे कोई खास नतीजा बरामद नहीं किया जा सकता।

मैं माननीय शारदाभक्त सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी गवर्नमेंट में मुख्य मंत्री कौन होगा और उनकी मिनिस्टरी में कौन कौन होंगे ? मुख्य मंत्री शारदाभक्त सिंह जी होंगे या दूबे जी होंगे, जो इन्तजार किया करते हैं कि जगह खाली हो जाय तो बैठ जायं। उधर राम सुन्दर जी होंगे या उग्रसेन जी होंगे ? स्वतंत्र पार्टी के लिये क्या कहूं। वे झगड़ा तो नहीं करते हैं लेकिन वे उसमें खपेंगे नहीं। झारखंडेराय जी की क्या बात है। उनको न हममें विश्वास है और न हमको उनमें विश्वास है। हम उनका बुरा नहीं मानते, जब वे यह कहते हैं कि इस गवर्नमेंट में हमको विश्वास नहीं है। हम खुद उनमें विश्वास नहीं करते हैं कि न मालूम कौन मौके पर वे चीन की तरफ चले जांय। तो उनके सहारे पर रहेंगे तो गड़बड़ है। खासकर जनसंघ से मैं कहता हूं और कुंवर श्रीपाल सिंह जी से कहता हूं। अभी तीन चार रोज हुए जिस रोशनाई से स्पीच लिखी गयी होगी वह अभी सूखी भी न होगी कि गोली मार दी जायगी। तो उनके दिल में उनके प्रति क्या भावना है ? क्या इनमें कभी मेल हो सकता है ? वहां भी कैबिनेट के लिये लाठी चलेगी। अभी बनारस में माननीय उग्रसेन जी लाठी चला कर आये हैं और अभी तक बहुत से जख्मी अच्छे भी नहीं हुए हैं। ऐसी दशा में हम तो आज इस कुर्सी को छोड़ दें लेकिन पहले आप आपस में तय तो करें कि कौन कौन होगा आपके मंत्रिमंडल में। अब माननीय मेनेजर सिंह सोचें कि हमारा नाम ही मैनेजर या प्रबन्धक सिंह है इसलिये हमें ही माल मंत्री बना दिया जाय और इस तरह से आपके यहां तो ऐसे ऐसे एलिमेन्ट्स मौजूद हैं, चारों तरफ ७-८ पार्टीज हैं। माननीय नेकराम शर्मा की पार्टी में हर एक आदमी पार्टी का लीडर है, आप किसको चुनेंगे ? श्री मौलाई साहब की बिलकुल ही नवजात शिशु पार्टी है, इसलिये अभी उसका सहारा करना ठीक नहीं होगा। वे तो किसी दिन नारा लगा देंगे कि "जाटव मुस्लिम भाई भाई, हिन्दू जाति कहां से आयी।" जब कि जन संघ में सब हिन्दू ही हिन्दू हैं। और भी बहुत सी बातें कही गयीं जिनका यहां रोज जवाब देते आये हैं। अगर कोई नयी बात कही जाती तो उसका जवाब भी दिया जाता। जेनरल बजट के वक्त और गवर्नर के अभिभाषण के मौके पर भी इसी तरह की बहुत सी बातें कही गयीं जिनको मैं बैठ कर चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि कोई नई बात तो कही नहीं गयी जिसका जवाब देने के लिये मैं खड़ा होता। लेकिन आज जब मेरे इधर के बहुत से मित्रों ने कहा कि आप भी कुछ बोलिये, तो मैं उचक कर बोलने के लिये खड़ा हो गया।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

लेकिन आपने भी पुराना ही जवाब दिया।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जब कोई नयी बात कही ही नहीं गयी तो मैं नया जवाब किस बात का देता ? पुरानी बात कही गयी इसलिये जवाब भी वही पुरानी दिया गया । मालूम होता है कि आपकी समझ में भी यह बात नहीं आयी । अब मैं क्या बात बतलाऊं, कहां तक समझाऊं ? जब कोई नयी बात हो तो नया जवाब हो । पुरानी बात कही गयी और पुराना जवाब दिया गया ।

हमारे माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि सोशलिस्म का नारा यह सरकार बहुत लगा लगाती है लेकिन उस सम्बन्ध में कुछ हुआ नहीं । जमींदारी खात्मे के बाद कितने राजे महाराजे धराशायी हो गये, सोने की चिड़िया की जान गयी, और इनके लिये कुछ हुआ ही नहीं । जौनपुर के नवाब बेमुल्क जो यहां बैठते हैं उनके पास एक बिस्वा जमीन तक नहीं है, बलरामपुर राज्य तथा तमाम रूलिंग स्टेट्स खत्म हो गयीं और इनका कहना है कि समाजवाद की तरफ कोई कदम ही नहीं उठाया गया ।

कंसोलिडेशन की बात बहुत कही गयी । कंसोलिडेशन कोई छूमंतर तो है नहीं जो जरा देर में छड़ी घुमाते हो जाता । माननीय राजेन्द्र सिंह जी अक्सर मेरे यहां आकर कहते रहते हैं कि हमारे यहां कंसोलिडेशन जरा ठीक करा दीजिये और भी सदन के हमारे दोस्त इस सम्बन्ध में आकर कहते रहते हैं और हम हर तरह से उसके लिये प्रयास कर रहे हैं । हमारा जितना टार्गेट था उसको पूरा कर लिया है और उसके बाद भी आगे करने का प्रयास कर रहे हैं । लेकिन यह छूमंतर से नहीं होगा । एक तरफ तो कहा जाता है कि जुडिशियारी को एक्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाय और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि जुडिशियरी को बलायेताक रख कर हमारे यहां कंसोलिडेशन का यह काम करा दो । एक तरफ तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से हमें यह सर्टिफिकेट मिला है कि हमारे यहां कंसोलिडेशन का काम देश के अन्दर सबसे आगे है वहां आप कहते हैं कि यहां कुछ किया ही नहीं गया है ।

आप कहते हैं तो हम यहां से चले भी जायेंगे क्योंकि हमें तो यहां बीस साल से मुसलसल बैठते-बैठते मन ऊब-सा गया है । लेकिन जब आप चाहते हैं तो हम यहां रहेंगे और मैं आपको यह भी बतला दूं कि अगर आप नहीं भी चाहें तब भी हम रहेंगे क्योंकि यह इतना अहम मसला है जिसको इतनी लाइटली न लिया जाय, और इसका इस्तेमाल बेजा तरीके से न किया जाय। उसको कुछ सोच समझ कर विवेक के साथ इस्तेमाल किया जाय तो कारगर हो सकता है वर्ना अनाड़ी के हाथ में तलवार लग जाय तो वह अपना ही गला काट लेगा । आप तो रोज कहते हैं कि सरकार निकम्मी है हम तो कभी नहीं कहते कि अपोजीशन निकम्मा है, चाहे वह असलियत हो । हमने तो १७ साल काटे, आप १७ साल काटें, तो हम जानें । आप का तो आपस में संगठन भी नहीं हो सकता । हमें तो बड़ा दुख इस बात का है कि यह अविश्वास का प्रस्ताव लाने का एकतरफा औजार आपको ही दिया गया है हमें नहीं दिया गया और संविधान में यह नहीं है कि अगर अपोजीशन भी निकम्मा हो तो उसे भी सरकारी दल अविश्वास का प्रस्ताव लाकर निकाल दे । आपको हक दिया गया है हमें नहीं दिया गया वर्ना अपोजीशन इतना निकम्मा नहीं हो सकता था जिसकी अलग-अलग खंजरी और अपना-अपना राग है, कोई सुर मिलाकर नहीं गाता । वर्ना वह इस तरह से रोज-रोज बिना बात, बिना जरूरत इस तरह के प्रस्ताव लाकर सदन का समय बरबाद न करता इसमें आज सदन का खर्च १५ हजार का होगा, दस बजे से बेचारे बिना पानी बैठे हैं और ८ बजे रात तक बैठे रहेंगे, हमें उनसे बड़ी हमदर्दी है कि वह तकलीफ बरदाश्त करते हैं और नतीजा भी कुछ नहीं निकलता । हम बुड्ढे आदमी बैठे-बैठे मुरझा जाते हैं जरा सी बात में लेकिन किशोर कुमारों के चेहरे वैसे ही हैं जैसे सुबह दस बजे आए थे । मैनेजर सिंह जी पर अब भी रौनक है । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री ने अपनी रात की परेशानी बतायी । कि उन्हें नींद नहीं आई वह डरते थे कि आज सरकार उलट जायगी । लेकिन हमारे कुछ विरोधी

पक्ष के सदस्यों के आश्वासन पर आज वह हिम्मत बांधकर सदन में बैठे हैं और उन्होंने अभी तकरीर भी की। अब उनको विश्वास हो गया है कि उनकी सरकार उलटने वाली नहीं है। उनकी घबराहट के कुछ कारण जरूर थे, वैसे तो वे बड़े सौभाग्यशाली हैं, मधुरभाषी हैं और कभी भी उन्होंने किसी से बचपन से आजतक इन्कार नहीं किया। नौजवानी में उन्हें अवध के ताल्लुकेदारों ने रखा। (हंसी) और कांग्रेस हुकूमत बनी तो उन्हें सर्वप्रथम स्वर्गीय पंत जी ने रखा, उनके बाद उन्हें हमारे आदरणीय विद्वान भूतपूर्व मुख्य मन्त्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने रखा और उसके बाद हमारे ओजस्वी भूतपूर्व मुख्य मन्त्री गुप्ता जी ने रखा और आज भी वह यहां हैं। उन्हें भय है कि आपस की कशमकश में अगर सरकार उल्टी तो ये नहीं रहेंगे केन्द्र की सरकार भी आज उनके गुट के मुआफिक नहीं है, बलात् कांग्रेस संगठन के चुनाव में केन्द्र ने दस्तन्दाजी की और उलट-पुलट हुई वैसे ही यदि केन्द्र के कारण श्री कमलापति त्रिपाठी यहां विराजमान हो जायेंगे तो वे इनको नहीं रखेंगे यह मुझे भी विश्वास है। मैं उन्हें विरोधी दल की भावना से अवगत कराना चाहता हूं, हम कभी यह नहीं चाहते कि आदरणीया सुचेता जी की सरकार उलटे और उनकी जगह उस ग्रुप की हुकूमत आये जिसके मुख्य मन्त्री बनने का ख्वाब श्री कमलापति जी त्रिपाठी आदि अन्य लोग देखते हैं। वह बुरा दिन होगा प्रदेश के लिए और विरोधी दल के लिए भी। वह बुरा दिन होगा जब ऐसे लोग मुख्य मन्त्री के शासन को सम्भालेंगे। यदि कांग्रेस में कोई मुख्य मंत्री योग्य है तो निश्चय ही आदरणीया सुचेता जी ही हैं। मुख्य मन्त्री के पद पर जो आज विराजमान हैं सुचेता जी इनसे अच्छा कोई मुख्य मन्त्री कांग्रेस के अन्दर इस प्रदेश को मिल नहीं सकता और न भविष्य में ही आने वाला है।

हम तो यह अविश्वास का प्रस्ताव इस उद्देश्य से लाए हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार उलटे और उसके बाद जनता अपना निर्णय दे। सही कहा माननीय राजस्व मन्त्री जी ने तथा अन्य सदस्यों ने कि विरोधी पक्ष में इतनी अभी क्षमता नहीं कि वह सरकार को चलावे, हम एक मत नहीं हैं, हममें उतनी ताकत नहीं है, यह सही है। हालांकि आपको शायद याद भी होगा कि १९ की संख्या होने पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने १८ महीने केरल में सरकार चला कर भारत में एक इतिहास बनाया है। एक बेईमानी की मिसाल आपने नहीं दी उस शासन की। अल्पमत में होने पर भी सरकारें बन सकती हैं। लेकिन उसका कड़ुवा तजुर्बा हुआ कि सही काम करने के कारण तथा जनता की भावना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ बढ़ने के कारण आपकी पार्टी ने उस शासन को गिराया। इसलिए यह नतीजा निकाला कि अल्पमत में कभी सरकार नहीं बनानी चाहिए। तो हम तो नहीं हैं इस स्थिति में अभी, लेकिन यह भी निश्चित है कि जिस दिन यह सरकार उलटेगी आपके कांग्रेस पक्ष में ही वह लतियावल और लठियावल होगी कि लीडर का चुनाव नहीं होगा।

श्री हरीसिंह—

बनारस में आपकी पार्टी में क्या हुआ?

श्री मैनेजरसिंह—

बनारस से बदतर आपकी पार्टी में होगा। वहां तो सिद्धान्तों और कार्य-क्रम में मतभेद होने के कारण लोग अलग-अलग हो गए, लेकिन आपकी पार्टी में तो एक ही झंडे में रहते हुए रोज लतियावल करते हैं। और उसके बाद क्या हश्र होने वाला है? उसके बाद कोई विकल्प नहीं रहेगा प्रदेश के सामने। केवल एक ही विकल्प है कि मिड टर्म इलेक्शन (मध्यावधि चुनाव) हो और इस विश्वास के साथ विरोधी पक्ष के लोग यह अविश्वास का प्रस्ताव रखे हैं। क्योंकि सरकार किसी की नहीं बन पायेगी, कांग्रेस की भी नहीं बनेगी और मिड टर्म इलेक्शन में जनता कांग्रेस को बहुमत में नहीं आने देगी यह निश्चित है।

आज इस प्रदेश में शान्ति व्यवस्था नहीं है। जब से हमारे गृह मन्त्री ने इस विभाग को सम्भाला है प्रदेश में अमन चैन नहीं है। जालौन और उरई में पिछले महीने के अन्दर २ हफ्ते में १२ कत्ल हुए। एक कत्ल में कहा जाता है कि ७०,००० रु० बरामद हुआ और उस रुपये का पता नहीं। मैं चाहता हूं माननीया मुख्य मन्त्री सी०आई० डी० से जांच करायें, स्वयं उरई जायं

[श्री मैनेजरसिंह]

और वहां की हालत को देखें। एक वरिष्ठ सदस्य आपके मन्त्रि-मण्डल के हैं जिनकी वजह से उरई और जालौन में अराजकता है और गुंडों का राज्य है। बलिया में एक विकास खंड के अन्दर कांग्रेस का बहुत पुराना मुसलमान कार्यकर्ता था जिसे उस क्षेत्र के ९९ प्रतिशत हिन्दुओं का स्नेह प्राप्त था, वह अविश्वास का प्रस्ताव लाया प्रमुख के खिलाफ। उसका कत्ल कर दिया गया और मुलजिम को बचाने की साजिश माननीय गृह मन्त्री ने की। मैंने और माननीय काशीनाथ मिश्र ने लिख कर पत्र दिया माननीया मुख्य मन्त्री को कि डी०, आई० जी०, सी० आई० डी० को फोन पर गृह मन्त्री ने कहा कि श्री शिवमंगल सिंह जा रहे हैं उनसे बात करें। मुझे खुशी है कि माननीया मुख्य मन्त्री ने उस पर ध्यान दिया और वह मामला आज अदालत में है इसलिए उसके तथ्यों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, बरिया विकास खंड की बात मैं बताना चाहता हूं। वहां पर राम जी सिंह, प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार होने वाला था। जिलाधीश के यहां विकास समिति के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर से दरख्वास्त दी कि हमें सुरक्षित बैठक के स्थान तक पहुंचाया जाय। जिलाधीश ने एस० डी० एम० को आर्डर दिया कि आवेदन कर्त्ता सदस्यों के वक्तव्य की जांच की जाय। और सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की जाय उन्होंने जांच की और एस्कोर्ट दी। ६ सिपाही बन्दूकधारी सदस्यों के साथ मीटिंग स्थान तक गये। ज्यों ही विकास समिति के सदस्य बस से पहुंचे, वहां पर तैनात डी० एस० पी० ने इन्हें रोका और उसके रुकते ही हमारे पुलिस मंत्री के कृपा पात्र लोग ने समिति के एक सदस्य को टांग कर अरहर के खेत में ले गये। जो दुर्दशा उनकी वहां की गयी, वह कहीं नहीं जा सकती। एक मेम्बर को डिप्टी के सामने मारा। ३-३ एस० डी० एम० और एक डी० एस० पी० वहां पर मौजूद थे। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इसकी जांच करावें। मुझे शिकायत मिली कि गृह मंत्री माननीय हरगोविंद सिंह ने फोन किया था एस० पी० को कि मीटिंग न होने पाये। वहां पर जो क्रिमिनल्स हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बलिया, जौनपुर, गाजीपुर में एक-एक स्थानीय गृह मंत्री हैं। आप कहेंगे तो मैं उनके नाम भी बता दूंगा। थानेदार उस मंत्री के यहां जाते हैं और निदेश लेते हैं जितने क्रिमिनल्स हैं वे आज सफेद कुर्ता पहनकर कांग्रेसी बने हुए हैं।

कांग्रेस की आपसी पार्टीबाजी में भी पुलिस का दखल है। हमारे जिले के खरौनी के ही एकमात्र जमींदार ऐसे थे जो राष्ट्र भक्त थे और जिन्होंने कांग्रेस के आन्दोलनों में सहयोग दिया है। उस परिवार में विजय बहादुर सिंह जो कांग्रेस के जिला परिषद् के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे और जिनकी उम्मीदवारी माननीय गृह मंत्री के षडयंत्र के कारण आदेश से उलट दी गयी थी, उन पर दफा १०७ चलायी जा रही है। आपकी कांग्रेस की क्या हालत है? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जौनपुर के दरोगा का जो केस हाई कोर्ट में गया था, उसके फैसले में माननीय न्यायाधीश ने लिखा है कि रामसूरत सिंह को जो छोड़ा गया है, इसमें गलत काम हुआ है। इसमें जल्दबाजी की गयी है। मेरी राय में बगैर शिनाख्त कारवाई हुए छोड़ना उचित नहीं था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि डी० एस० पी० और गृह मंत्री इन दोनों में कौन जिम्मेदार हैं? इसका पता लगाना होगा। इसका पता तो माननीय मंत्री जी भी नहीं लगा सकते हैं। माननीय हाई स्कोर्ट ने गृह मंत्री और रामसूरत सिंह के सम्बन्ध के बारे में कहा था कि सम्बन्ध प्रमाणित नहीं हो सके। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि सम्बन्ध बिल्कुल निश्चित हैं। रामसूरत सिंह उनके चचा जात बहिन के नाती हैं। ये सब भिखारी सिंह के खानदान में आते हैं। इससे सम्बन्ध बिल्कुल स्पष्ट है।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विरोधी पक्ष के लोग पुलिस की वकालत करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि खुद पुलिस की वकालत नहीं करता पर मुझे शिकायत है कि गृह मंत्री ईमानदार पुलिस कर्मचारियों को परेशान करते हैं। जोगेन्द्र सिंह पहले बलिया में पुलिस विभाग में रह चुके हैं। वे मुगल सराय में थे। जो थानेदार मुगलसराय में रहते हैं, उसकी आमदनी हजारों रुपया प्रतिदिन की होती है। वह अफसरों को भी खिलाता है। श्री जोगेन्द्र सिंह ने अपने कार्यकाल

में रहकर मुगलसराय में रेलवे की चोरी बन्द करा दी थी पर ऐसे आदमी की उन्नति नहीं होती। आज बेईमान तरजीह पा रहे हैं। यह है माननीय हरगोविंद सिंह जी की पुलिस। माननीय सहकारिता मंत्री जी इतने निपुण हैं कि नाम किसी का नहीं लेंगे जहां पार्टी का नाम आयेगा, चाहे दस सवाल कीजिये। उपाध्यक्ष जी, आप डाटते नहीं हैं, यह जवाब नहीं देते हैं। कल सवाल आया था कि फेडरेशन में गड़बड़ी की और शिवमंगल सिंह जी के बारे में सवाल किया गया था लेकिन आपने टाल दिया। मैं बलिया जिला सहकारी बैंक से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। उसमें बड़ा गड़बड़ घोटाला है, मैं उसमें रहना नहीं चाहता हूं। वहां बहुत गड़बड़ी है। फेडरेशन की एक दुकान है, वहां कहा गया कि आग लग गई और सिल्क के कपड़े जल गये। टेबिल क्लाथ वगैरा अलमारी के अंदर रखे हुये थे। घनघोर वर्षा के समय रात को भी नौ बजे आग लगी और टेबिल क्लाथ वगैरह जले नहीं, कीमती सिल्क जल गया। वहां के फेडरेशन के अधिकारियों ने उनको इस्तेमाल किया था, पैसे न देने पड़ें, इसलिये यह फर्जी काम किया गया। एक बैंक की जीप है, यह कांग्रेस के चुनाव में जाती है, विकास खंडों के चुनावों में भी गयी है। क्या मंत्री जी इसको रोक नहीं सकते हैं।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि अगर सहकारिता विभाग से कुनबा परस्ती और भ्रष्टाचार मिटाना है तो रजिस्ट्रार को निकालिये। वह कुनबा परस्त और भ्रष्ट अधिकारी है। यदि आपने उसको जल्दी नहीं हटाया तो ६ महीन में आपके ऊपर भी उंगली उठने लगेंगी। वह खतरनाक है, उसको हटाइये, वह नवाब बना हुआ है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप कोआपरटिव बैंक और फेडरेशन की जांच कीजिये और जांच करके यदि आप उचित कार्यवाही करेंगे तो मैं आपको बधाई दूंगा। आप इसको छिपाइये नहीं।

पंचायत राज्य की कल्पना की गई कि प्लानिंग का काम हमारे प्रदेश में आगे चले। लेकिन आज क्या हालत है? मैं पंचायत का समर्थक हूं। लेकिन पूरे प्रदेश में पार्टीबाजी की वजह से नियोजन का काम चल नहीं रहा है और हमारे जिले में तो बिलकुल बन्द है। इसलिये मैं समझता हूं कि और जिलों की हालत भी अच्छी नहीं होगी। हमारे जिले में कोशिश की जा रही है कि नियोजन के अधिकारी पार्टीबाजी में आ जायं नियोजन अधिकारी यह कहता है कि खुदा मियां से मिल आओ। एक भ्रष्टाचार अधिकारी को नियोजन का अधिकारी बना दिया है। मैं कहता हूं कि नियोजन के काम के लिये सरकार सक्षम नहीं रही है इसलिये कि उसने आज जनता का विश्वास खो दिया है। इस सरकार से नियोजन का कार्य नहीं चलेगा। इस प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिये हम चाहते हैं कि यह सरकार उल्टे और नया चुनाव हो और जनता अपनी राय दे।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैं कुछ कहने से पहले पूर्व वक्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम हमारे दल के नेता को ऐसा समझा कि उनमें अपना विश्वास प्रगट किया। इस प्रस्ताव की मंशा को पूर्व वक्ता ने जाहिर कर दिया है कि बातचीत के सिलसिले में रख दिया गया। उसके पीछे कोई चीज उनके दिल में नहीं है। मैं इस सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रगट करना चाहता हूं इसलिये कि इस सरकार ने बे रोजगारी खत्म करने के लिये कदम बढ़ाया, सिंचाई को मीडियम, बड़ी और लघु योजनाओं को लागू करने इस सरकार ने अपना कदम उठाया है। श्रीमन्, मैं इसलिये इस सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करना चाहता हूं और खासतौर से मुख्य मंत्री जी के प्रति कि उनके लिये कोई जाति और प्रान्त का सवाल न होकर वह हमारे प्रान्त की मुख्य मंत्री हैं। मैं इसलिये इस बात को कहना चाहता हूं कि इस बात का जिक्र किया गया कि कुनबा परस्ती और भाई भतीजे और भाई चारे का चर्चा या जो और समाज में रोग हैं जिनकी तरफ माननीय नेता प्रसोपा ने संक्षेप में और कुछ दूसरे लोगों ने जिक्र किया तो मैं कहना चाहता हूं कि आज कोई भी सज्जन जो इस सदन में बैठे हुये हैं किसी न किसी ऐसी जाति से चुने हुये हैं जिनकी जाति के लोग हर पार्टी में शामिल हैं लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनार्थसिंह]

इनके लिये यह बात नहीं पैदा होती है। यह कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है कि जिसके नेता आज इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं जिनके लिये न कोई प्रांत का सवाल है और न कोई जाति का सवाल है। इसलिये उनकी बात अपने आप कट जाती है। मैं इस बात को समझने में असमर्थ रहा कि इस सरकार के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव में यह बात कैसे कही गई।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार ने जहां दूसरी तरफ अच्छे-अच्छे प्लानिंग के काम किये, लोगों की जिन्दगी की जरूरियात को पूरा करने की तरफ कदम उठाये वहां आज सरकार की तरफ से जो टेक्नीकल एजूकेशन की कोशिश की जा रही है यह कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। आज अपने प्रदेश में टेक्नीकल एजूकेशन का फैलाव बहुत हो रहा है। चौथी योजना में इसको और बढ़ाने का कार्य-क्रम है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज इस प्रकार से टेक्नीकल एजूकेशन की तरफ सरकार का रुझान है। इनसे इतने अच्छे-अच्छे टेक्नीशियन निकलेंगे जिससे हमारा विश्वास है कि आने वाले जमाने में जब टेक्नीशियन की कमी महसूस होने लगेगी उस समय इतने अधिक लड़के समाज में रहेंगे कि जो इस देश का उत्थान करने में कोशिश करेंगे।

मैं कुछ और बातों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता ने कहा कि रक्षा प्रतिरक्षा की तैयारी में चीनी आक्रमण के सिलसिले में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं माननीय नेता विरोधी दल से आपके माध्यम से यह अर्ज करूंगा कि करीब-करीब ४० हजार जवान राइफल की ट्रेनिंग इस प्रदेश में पाये हैं। अगर मेरी सूचना सही है, अगर गलत हो तो नेता विरोधी दल कह दें कि गलत है, तो इतने लड़कों ने राइफल की ट्रेनिंग पाई है। इसमें केवल जवान लड़के ही नहीं हैं बल्कि इस ट्रेनिंग में औरतें भी सम्मिलित रही हैं। मेरा ख्याल है कि १,३००; १४,०० के करीब औरतों ने इस दिशा में ट्रेनिंग पाई है। इस प्रकार से रक्षा प्रतिरक्षा की कार्यवाही में हमारी सरकार सचेत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एस० एस० पी० के नेता ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर लिया जाता। मैं उनके नेता से एक बात अर्ज करूंगा कि वह जरा मेरी बात को ध्यान से सुनें। अगर उनके चुनाव घोषणा पत्र में कहीं भी शिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रीयकरण करने की बात लिखी गई हो तो दूसरे वक्ता महोदय उसको पढ़कर सुना दें। इसलिये इस सदन में यह कह देना और फौरी मौके का फायदा उठाना और अपने घोषणा पत्र में इस तरह की बात करने की कोशिश करना मैं समझता हूं निहायत मौका परस्ती की नीति है।

श्रीमन्, अपने कम्युनिस्ट भाइयों से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उनका जो कार्यक्रम है, कम्युनिस्ट पार्टी का दिसम्बर, १९६४ का जो प्रोग्राम बना है और जैसा कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में लिखा है उसमें टेक्नीकल एजूकेशन या हेल्थ एजूकेशन का कहीं पर जिक्र नहीं है कि इन शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीय करण किया जाय। इस तरह से बेमौके नारा देने का क्या फायदा है? ऐसी बात कही जाय जो पार्टी मीटिंग में तय कर के कही गई हो। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं याद्दाश्त के लिये....

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

इतने महीनों में ही आपकी राय इतनी बदल गई ?

श्री कल्पनार्थसिंह--

आपसे भिन्न सदा मेरी राय थी। यही राय मेरी पहले भी रही है (व्यवधान)। श्रीमन्, इसमें हल्ला करने की बात नहीं है। आपकी थ्योरी की बात कर रहा हूं।

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां अध्यापकों के बारे में यह बातें कही जा रही हैं, वहीं मैंने कुछ अपने दोस्तों से निवेदन किया कि अगर उनकी थ्योरी में कहीं कोई ऐसी बात हो तो

बतावें। खासकर नेता प्रसोपा जो सोपा के टिकट पर चुनकर आये हैं, बतावें कि जब केरल में कम्युनिस्टों की सरकार थी और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने जब शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात को उठाया तो उनका क्या रुख था, उनकी पार्टी का क्या रुख था? ऐसे लोगों को जिनके ऊपर समाज का बोझ है, जिनके ऊपर समाज के उत्थान का भार है, उनको आप सरकार की मशीनरी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकारी नौकर की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाये। श्रीमन्, मैं यह निहायत गलत काम समझता हूं। जो लोग हमारे लिये आदर्श हैं, जिन लोगों पर हमारे समाज को ऊंचा उठाने का भार है, उनको हम राजनीति में हथियार कैसे बना सकते हैं? उनको हम सरकारी प्रतिबन्ध में कैसे रक्खेंगे? इसे मैं निहायत गलत काम समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, हमारे माननीय उपनेता कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और इसलिये है कि इनसे इसे धन मिलता है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, उनमें से किसी भी पार्टी का नाम अखबार में अभी पहले से अछूता नहीं है। फर्क केवल यह है कि किसी पार्टी को उनसे कम मिला है और किसी को ज्यादा। सब सन्यासी क्या यह बिना वस्त्र के हैं। यानी सब लोगों के अन्दर पूंजीपतियों का धन पहुंचा है। सब लोग पूंजीपतियों के दरवाजे पर गये हैं। यह भी पता नहीं है कि यह किस अखबार की खबर है। मैं यह अर्ज कर रहा था, इतना ही नहीं अभी बैंक आफ त्रायना के हिसाब-किताब की सफाई भी नहीं आई है और उसमें किसका कितना खाता है इस बात की भी सफाई हो जाये। इस तरह की सारी सफाई हो जाये तो मालूम हो सके कि किसका कितना हिसाब है और यह ज्यादा अच्छा हो। इतना ही नहीं मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फारेन एम्बेसी से किसका कितना ताल्लुक है, यह भी सामने आ जाये तो अच्छा है। क्या क्या किसका कैसा सम्बन्ध है कोई बातें हों तो वह भी सामने आ जायं। जो लोग आज स्वयं शीशे के महल में हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिये, उन्हें दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिये। यानी पूंजीपतियों के दरवाजे पर जाने से कोई बचा नहीं है।

दूसरी बात गुटबाजी के बारे में कही गई कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर बड़ी गुटबाजी है। है गुटबाजी, यह मैं मानता हूं। यह गुटबाजों की पार्टी है। यहां सिद्धान्तों पर, विचारों पर गुटबाजी होती है, हुकूमत चलाने पर मतभेद होता है, लेकिन ऐसा कोई डिक्टेटर यहां नहीं है, न यहां गुरू जी हैं कि वह जो कह दें हम उसे मान लें कि यह सही है। श्रीमन, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं। हम में मतभेद हैं, लेकिन वह मतभेद ऐसा नहीं है जिससे पार्टी का बिखराव हो। वह मतभेद इस प्रकार का है जिससे पार्टियां मजबूत बना करती हैं, जो स्वस्थ परम्परायें बनाती हैं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की क्या हालत है, सुनिये। अभी तक वह लेफ्ट राइट अन्दर ही करते रहे अब बाहर सड़क पर लेफ्ट राइट करते हैं। और संसोपा जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को देखा तो उन्होंने भी चौराहे और वाराणसी के चौराहे पर लेफ्ट राइट कर दिया। स्वतंत्र पार्टी पर तो मुझे उत्तर प्रदेश में दया आती है। रही जनसंघ की बात, सारे मतभेद के बावजूद हमारे सारे लोग ज्यों के त्यों जैसे आये थे मौजूद हैं, लेकिन वहां हर एक पदाधिकारी बदल गया। तो आज इस मुल्क में अगर अच्छा शासन चलाने की क्षमता रखने वाली कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस है और उसका मुख्य मंत्री जिस पर हमें विश्वास है और मैं समझता हूं कि एक-एक करके सारे लोग मुख्य मंत्री के साथ हो जायेंगे।

मैं माननीय रामसुन्दर जी से पूछता हूं कि ५२ में कितने आपके साथ थे, ५७ में कितने आपके साथ थे और कितने लोग आज उनके साथ हैं। मैं जनसंघ से ही पूछता हूं कि जितने लोग जनसंघ में सन् १९५७ में विश्वास करते थे आज क्या उतने उन पर विश्वास करते हैं। आज संसोपा से कितने लोग कांग्रेस में आ गये? जो उप-चुनाव हुये हैं उनमें जनता ने किसका साथ दिया है वह कांग्रेस में विश्वास का सच्चा और ज्वलन्त प्रमाण है। इन शब्दों के साथ मैं अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, आज इस प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता में किसी से पूछ देखिये कोई भी वर्ग चाहे वह मास्टर हो, चाहे रिक्शा खींचने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे मुलाजिम पेशा हो और चाहे छोटे मोटे तिजारत करने वाले हों सिवाय चन्द लाख आदमियों के, जो या तो ऊंची-ऊंची मुलाजिमतों में हैं या सरमायेदार हैं उनको छोड़ कर उनके अलावा साढ़े सात करोड़ जनता में से कोई भी आये, कोई भी यह कहने के लिये तैयार नहीं होगा कि हम कांग्रेस से संतुष्ट हैं। क्यों नहीं है यही तो हम कहना चाहते हैं। हर शख्स कहता है यहां कि पैदावार नहीं बढ़ी, महंगाई कम नहीं हुई, चोरी डकैती कम नहीं हुई, कुनबापरवरी में कोई घाटा नहीं आया, प्रदेश की सुरक्षा का भी सही इन्तजाम नहीं हुआ, जब यह सारी चीजें सभी कहते हैं तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि इस प्रदेश की जनता का इस सरकार में विश्वास है।

एक बात के लिये हमारे बहुत से मेहरबान दोस्तों ने कही कि अपोजीशन महज बहस के लिये यह प्रस्ताव लाया है। ठीक है, बहस के लिये तो है ही, अपोजीशन के नेता चाहे वे किसी दल में विश्वास रखते हों उन्होंने आपके सोचने के लिये एक मौका दिया है। आज क्या बात है कि आपके ही अन्दर कुछ लोग हैं जो रात को यह उम्मीद लगा कर सोते हैं कि सुबह उठकर वे अखबार में पढ़ेंगे कि हाई कमांड का पैगाम आया है और सुचेता कृपालानी जी की सरकार खत्म कर दी गयी है। इरादा यह है, चाहते यह हैं, वे अपोजीशन के नेता को, अपोजीशन के लोगों को भी चैन से नहीं बैठने देते, कहते हैं कि लाओ अविश्वास का प्रस्ताव और एक दिन कम से कम बहस करो ताकि हाई कमांड को दिखाने के लिये तो हो जाय, कम से कम एक मसाला हमारे पास हो जाय कि जनता सुचेता कृपालानी की सरकार के खिलाफ है और एक दिन उनकी सरकार के खिलाफ लगातार १० घंटे तक बहस हुई। उन्हें क्यों नहीं समझाया जाता? वह एक खास चीज है जिसकी वजह से यह नो कान्फीडेंस मोशन लाया गया। काश उनमें हिम्मत हो जाती अगर वह बात जो वह छिपकर कहते हैं खुलकर सामने आते और कहते कि प्रदेश की जनता तुमसे संतुष्ट नहीं है भले वह सुचेता कृपालानी की सरकार हो या किसी की हो तो आज यह सरकार एक मिनट के लिये भी ठहर नहीं सकती। वह खुलकर क्यों नहीं मैदान में आते? यह खुद गिर जायेंगे।

इसके बाद, मैं इस सरकार का ध्यान इस प्रदेश की १ करोड़ जनता की तरफ ले जाना चाहता हूं। वह एक करोड़ हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई जनता है। आज यह देखकर अफसोस होता है कि उनकी मादरी जबान के साथ इस प्रदेश में हो क्या रहा है? इस बात का अफसोस सबसे ज्यादा है कि जब इस प्रदेश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है, इस प्रदेश के विद्यार्थियों को दर्जा ३ से मजबूर किया जा रहा है कि तुम अंग्रेजी पढ़ो लेकिन इसका कोई इंतजाम नहीं है कि वे अपनी मादरी जबान में तालीम ले सकें। विदेशी भाषा पढ़ाने के लिये तो इंतजाम है लेकिन मादरी जबान, हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब की मादरी जबान को पढ़ाने के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। आज स्कूलों के अन्दर तरीका है कि अगर कोई अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाना भी चाहे तो ६ठे दरजे के बाद कोई दाखिला नहीं है। नतीजा यह है कि वह उर्दू पढ़ नहीं पाते। जब अंग्रेजी राज्य था तब अंग्रेजी सिर्फ उन स्कूलों में पढ़ाई जाती थी जो ऐंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल्स थे। देहातों में मिडिल स्कूलों में ८वें दरजे तक तालीम हिन्दी या उर्दू में जो मातृभाषा होती थी दी जाती थी। लेकिन इस सरकार के जमाने में अंग्रेजी तालीम दर्जा ३ से ही हो जाती है। इससे ज्यादा अफसोस की बात दूसरी नहीं हो सकती। आज जब दूसरे सूबों के अन्दर जबान के मसले को लेकर यह किया गया है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है लेकिन मादरी जबान जो है चाहे मद्रास हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे मैसूर, आंध्र या मध्य प्रदेश या राजस्थान, चाहे बंगाल हो या बिहार वहां मातृभाषा में तालीम का इंतजाम हिन्दी के साथ-साथ है लेकिन यह बदकिस्मत उत्तर प्रदेश ही है कि जहां हिन्दी जबान की नेशनल लैंग्वेज की हैसियत है, हर शख्स का फर्ज है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसे पढ़े, लेकिन उसके साथ-साथ मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी पढ़ने का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ तुर्रा यह है कि अंग्रेजी को खत्म किया जा रहा है और कर दिया जायगा। समझ में नहीं आता कि कैसे खत्म कर दिया जायगा। जब तीसरे दर्जे के बच्चे को अंग्रेजी पढ़ायेंगे उर्दू पढ़ायगे नहीं तब क्या हो जायगा ?

आप यह देखें कि उर्दू जबान फारस से, चीन से, जापान से नहीं आई। इतिहास उठाकर देखिये। दिल्ली के अन्दर पैदा हुई, लखनऊ में उसने तालीम और तरबियत पाई। क्यों बनायी गई ? उसके बनाये जाने की वजह है। उस समय तमाम हिन्दुस्तान में लोग, अलग अलग भाषाएं बोलते थे इसलिये एक जबान की जरूरत हुई जिसे सब लोग समझ सकें और इसीलिये उसका नाम भी उर्दू पड़ा। उर्दू का मतलब है रिसाला या फौज। आज उस उर्दू के साथ बेइंसाफी हो रही है। आज एक करोड़ जनता जिसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी सभी हैं, के दिलों में एक असंतोष की भावना पैदा होती जा रही है इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि उस जबान में भी दरख्वास्त लिये जाने के आदेश प्रदान किये जायं। मैं खुश होऊंगा अगर आप किसी एक फिरके की जबान मान कर उर्दू को खत्म कर दें। आप कहें तो यह एक फिरके की जबान है। उससे बात खत्म हो जाती, लेकिन यह बात नहीं है। आप उससे इंकार नहीं कर सकते कि उर्दू लिखने वालों में मुंशी प्रेमचन्द, चकबस्त, मुल्ला, सुन्दरलाल जी का नाम अमर है। उन्होंने उर्दू के लिये जितना काम किया है वह उस फिरके वालों ने नहीं किया जिनकी जबान आप उर्दू को मानते हैं। खासकर उर्दू को बोलने वाले उत्तर प्रदेश में ६,७ जिले हैं जहां उसे थोड़ा-सा स्थान दिया गया है, लेकिन वहां भी अदालतों में अर्जी उर्दू में नहीं ली जाती, यह कह कर फेंक दी जाती है कि इसे दूसरी जबान में लिख कर लाओ। चूंकि यहां साढ़े दस फीसदी लोगों की जबान उर्दू है इसलिये इसे यहां की रीजनल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिये। दूसरे प्रदेशों में जहां साढ़े ७ फीसदी की यह जबान है वहां इसे रीजनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इस बात का वहां भरोसा दिलाया गया है, यहां कहा जाता है कि चूंकि उर्दू पढ़ाने वाले मास्टर नहीं हैं इसलिये इसे न पढ़ो। अंग्रेजी पढ़ो जब कि उसे पढ़ाने वाले मास्टर भी नहीं हैं। इससे ज्यादा शर्म की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन जी की कुछ बातों से मैं इत्तफाक करता हूं। हिन्दी या हिन्दुस्तानी के नाम पर इस उर्दू को इस उत्तर प्रदेश में स्थान मिलना चाहिये। लेकिन श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं।

इस अविश्वास के प्रस्ताव पर मैं नेता विरोधी दल का ध्यान दो, तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि इसमें वह अध्यापकों को न घसीट लाते तो अच्छा करते इसलिये कि वह हारेंगे, लेकिन यदि हारे तो अध्यापकों के साथ हारेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि नेता विरोधी दल का एक ऊंचा स्थान है। (व्यवधान) मैं रह चुका हूं और इसलिये मैं उसकी महत्ता समझता हूं, विरोधी दल के लोगों का आदर करता हूं और आज भी कहता हूं कि नेता विरोधी दल का काम यह था कि इस गवर्नमेंट को इस अहम मसले पर समझाने की कोशिश करते और गवर्नमेंट की परेशानियों और उसके पक्ष को भी समझने की कोशिश करते। (व्यवधान) अगर नेता विरोधी दल कहते हैं कि यह काम उन्होंने किया है तो वह धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे जहां तक पता है, नेता विरोधी दल ने यह प्रयास नहीं किया और उन्होंने इसे एक पोलिटिकल स्टंट बनाने की चेष्टा की।

श्रीमन्, आज जो यह कहा जाता है कि अध्यापकों की यह आग विद्यार्थियों में भी भड़केगी, उसके लिये मैं एक अपील करना चाहता हूं। जो लोग हम से ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे मैं अपील कर सकता हूं और मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिये,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

कि वह इस मामले में राजनीतिक दूरदर्शिता से काम लें और मैं समझता हूं कि आज इधर के बैठने वालों की पूरी सहानुभूति अध्यापकों की मांगों से है....

श्री शारदाभक्त सिंह—

"पूरी" कहा या "कोरी"?

श्री गेंदासिंह—

मैं समझता हूं नेता विरोधी दल के कान इतने कमजोर नहीं हैं। मैं यह अपील करना चाहूंगा कि आज माननीय विरोधी दल के नेताओं का यह काम है कि यह जो संकट उनको दिखाई दे रहा है यह ५ लाख बच्चों का संकट है। मैं समझता हूं कि अभिभावकों का अरबों रुपया खर्च हुआ और उनकी जो परीक्षा होने वाली है उसको पूरा कराने की चेष्टा माननीय नेता विरोधी दल करें और मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के गिर जाने के बाद भी आपका यत्न जारी रहना चाहिये जिससे अध्यापकगण और विद्यार्थी आपस में झगड़ने न पायें और जो आग भड़कने की आप कल्पना करते हैं वह न भड़कने पाये।

श्री उग्रसेन—

यह अध्यापकों और विद्यार्थियों की लड़ाई नहीं है, यह सरकार से संघर्ष है।

श्री गेंदासिंह—

कुछ और बातों की चर्चा की गयी। अनाज की कमी की भी चर्चा की गयी। मैं विरोधी दल के भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि जरूर अनाज की कमी है जिसको भुगतकर हम यहां आये हैं। ऐसा मालूम होता था कि पानी में डूब रहे थे लेकिन अब उससे ऐसी जगह पर आये हैं जहां किनारा दिखाई देने लगा है। मैं समझता हूं कि आज विरोधी दल का यह काम है कि कम से कम इस काम में फिर यह भावना न उत्पन्न करें कि सारे देश में कमी है, सारा देश मरने जा रहा है। भाव गिर रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूं, साधारण गृहस्थ किसान हूं कि अगले दो महीनों में देखियेगा कि बाजार भाव कहां आता है। उसको आने दें। हम और आप दोनों मिलकर आने दें। आप महंगाई को दूर करने के लिये सचेष्ट रहिये। रूठ कर मत जाइये, बैठिये एक जगह और इस काम में बैठ कर ऐसी सलाह दीजिये जिससे असाढ़ की महंगाई न आने पाये। मैं समझता हूं कि आपकी सलाह कीमती होगी। अगर आप जान बचाकर भागते हैं तो मुसीबत बढ़ेगी। इससे आपको किनाराकशी नहीं करनी चाहिये। एक बात और निवेदन कर दूं....

श्री उग्रसेन—

गोरखपुर, बस्ती, देवरिया आदि में सस्ते-गल्ले की दूकानें बन्द कर दी गयीं, तो अब कहां बैठा जाय, आप बतायें? (व्यवधान)

श्री गेंदासिंह—

मुझे भी थोड़ी-सी जानकारी है, इसलिये मैं चाहता हूं कि हम और आप बैठ कर विचार करें और जब हम दोनों कोई रास्ता निकालेंगे तो उसको टालने का कोई साहस नहीं कर सकता। महंगाई जरूर है, मगर आज की अर्थ नियोजित व्यवस्था में यह जरूरी है। सन् १९१४–१८ की घटना आपको विदित है। उस लड़ाई के बाद सस्ते की क्या हालत हो गयी थी, सारा संसार उसमें फंस गया था, हिन्दुस्तान भी फंसा था। उस वक्त तक उससे छुटकारा नहीं मिला जब तक लड़ाई के बादल छा नहीं गये और वह छिड़ नहीं गयी। आज हिन्दुस्तान एक नियोजित अर्थ व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उसमें निश्चित ही महंगायी आयेगी और उसको हमें

बरदाश्त करना पड़ेगा । आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप नियोजित अर्थ व्यवस्था तथा अराजकता में किसको पसन्द करते हैं । (व्यवधान) थोड़े से मुल्क ऐसे होंगे जहां किसान घाटे में न रहा हो, मगर ज्यादातर किसान ही घाटे में रहता है, उसको घाटा होगा और उसका परिणाम हम सब को मिल कर भुगतना पड़ेगा । जब तक इस मुल्क का किसान घाटे में रहेगा यह मुल्क दरिद्र रहेगा, यह सही है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

माननीय गेंदासिंह जी पहले नियोजन का अर्थ समझा दें ।

श्री गेंदासिंह—

उसका वही अर्थ है जो मैंने १० साल तक आपके साथ रह कर आपको समझाया है । (व्यवधान) माननीय नायर साहब की बात को भी मैंने बड़े गौर से सुना । उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि मैं तो शासन का बागी रहा हूं । माननीय राजस्व मंत्री जी ने जिन शब्दों में उनकी बात का जवाब दे दिया, मैं उसमें नहीं दे सकता, मैं नायर साहब का खयाल भी करता हूं, लेकिन हां, किसी जमाने में उन्होंने बगावत की है, कुछ अच्छा काम किया है, किन्तु अलीगढ़, देवरिया, फूलपुर आदि के उदाहरण आपके सामने हैं और उनका परिणाम आपने देखा है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ।

यह आरोप लगाया गया कि यह शासन ब्यूरोक्रेसी के हाथों में है । मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं । पिछला नियोजन हमारा ५ अरब का था, आज वह १२ अरब का होने जा रहा है । अब बिना सिविल सर्विस की सहायता के हमारा नियोजन चल ही नहीं सकता, उनकी सहायता के बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती । उस सिविल सर्विस के ऊपर इस १४ अरब को खर्च करने का भार यह मंत्रि-मंडल डालने जा रहा है और उसमें अगले ५ वर्षों के भीतर इस १४ अरब को खर्च करना अपनी लियाकत का इम्तहान देना होगा । मैं समझता हूं कि जो सरकार १४ अरब अर्जित कर दे, वह ५ वर्ष तक अच्छी तरह से उस पर सवार हो कर के उससे काम लेने के लिये कटिबद्ध है, तो मैं समझता हूं कि आज ब्यूरोक्रेसी जो है, वह हमारे ऊपर सवार नहीं हो रही है । एक बात विरोधी दल के भाइयों से और कहना है कि ब्यूरोक्रेसी का हौआ ऐसा मचा देते हैं कि हमको भी डर लगने लगता है कि नौकरशाही क्या इतनी ताकतवर हो गई है कि वह इन ५०० आदमियों के ऊपर शासन करेगी ? एक शब्द इन्टेलिजेंसियां नैयर साहब ने..... (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

अंग्रेजी शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं ?

श्री गेंदासिंह—

एक शब्द भी अंग्रेजी मैंने इस्तेमाल किया हो, तो कहिये । ..... (व्यवधान)

भाई उग्रसेन जी, मैं आपको ईल्ड करता हूं, जब आप बोलते हैं, तभी मैं बैठ जाता हूं, इसलिये कि हम बहुत दिन तक साथ रहे हैं । अध्यापक का मामला आप और हम दोनों तरफ के लोग बैठकर सुलझायें और लड़कों का इम्तहान भी दिलवायें और नो कांफिडेंस का मोशन लाकर उनको हरायें नहीं । आप लोग नो कांफिडेंस का मोशन वापस लें । यह अगर हमारी अपील पसन्द आवे, तो फौरन नेता विरोधी दल और उग्रसेन जी खड़े होकर वापस लें ।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता द्वारा रखे गये अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मुझे यह कहना है कि जब अविश्वास का प्रस्ताव सदन में रखा गया, तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब.लोजी अग्रवाल]

सरकारी पक्ष द्वारा यह कहा गया कि यह समय अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये अस्वाभाविक है । माननीय महामहिम राज्यपाल के भाषण के समय और अनुदान के समय, तथा बजट के समय विरोधी पक्ष को सरकार की आलोचना करने का समय पर्याप्त मिला ।

(इस समय ३ बजकर ३१ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मद्रास का हमें पता नहीं कि सरकार की आलोचना की गई या नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के विरोधी पक्ष के लोगों से कहीं अधिक सरकारी पक्ष के विधायकों ने सरकार की नीतियों की आलोचना की । सरकारी पक्ष के विधायकों ने विरोधी पक्ष के विधायकों से कहीं अधिक कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना की है ।

मान्यवर, गोविन्द सहाय जी ने कहा कि यह सरकार कमजोर सरकार है । मान्यवर, यही विरोधी पक्ष भी कहता है । सरकारी पक्ष के लोग और विरोधी पक्ष के लोग भी यह कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार जोकि जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा चुनी हुई है, अच्छा शासन नहीं कर रही है, बिलकुल नौकरशाही का शासन है । यह गोविन्द सहाय जी भी कहते हैं । आज वह सदन में नहीं हैं । वह सरकार के जिस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके साथ विरोधीपक्ष का भी साथ है । मान्यवर, इस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हम सरकार पर प्रत्यक्ष आरोप लगाना चाहते हैं, उसको धोखे में नहीं रखना चाहते, चुनौती देकर सरकार के सामने सीधे-सीधे अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं, वह इसका मुकाबिला करें । मान्यवर, इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने उत्तर प्रदेश को मरघट के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है । देश की उन्नति के नक्शे में उत्तर प्रदेश क्या शिक्षा में, क्या न्याय में, क्या प्रशासन में, क्या चिकित्सा में सब में पिछड़ता चला जा रहा है । मान्यवर, इस प्रजातंत्र के तीन आधार स्तम्भ होते हैं—न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका । इस सरकार ने इन तीनों ही क्षेत्रों को भ्रष्ट कर दिया है । मैं पहले न्यायपालिका की बात कहता हूं । जजों को बढ़ाते जाते हैं लेकिन मुकदमें और काम सब पिछड़ता चला जा रहा है । जजों की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीति और दलबन्दी के आधार पर की जाती है । न्यायपालिका का आदर करते हुये मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि दलबन्दी के आधार पर एक जज का लखनऊ से इलाहाबाद उसने तबादला कर दिया जबकि यह नियम है अंग्रेजी जमाने में भी रहा और अब भी है कि किसी भी अधिकारी का उसके होम डिस्ट्रिक्ट में तबादला नहीं किया जाता । यह कहा जा सकता है कि उनका घर बनारस में है । लेकिन बनारस पहले भेजे गये तो कहा गया कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद है और अब इलाहाबाद में भेजे गये तो यह कहा जाय कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट बनारस है, जब इस प्रकार से न्यायपालिका के जजों का तबादला किया जायगा तो ऐसे केसेज में जिनमें सरकार स्वयं पार्टी होगी जनता को कैसे न्याय मिल सकता है, यह मैं दोष सरकार पर लगाता हूं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आपकी जानकारी के लिये मैं कह दूं कि जजेज का ट्रांसफर हाई कोर्ट करता है ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

मान्यवर, हाईकोर्ट से भी तबादले सरकार के और आपके इशारे पर ही होते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आर्डर, आर्डर । हाई कोर्ट पर आप इस तरह से आरोप न करें ।

श्री बालोजी अग्रवाल---

सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं करती । उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं ए०आई०आर० १९६२ के पेज नं० ४७१ पर जे० एस० वर्मा वर्सेज स्टेट के फैसले में हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ जजमेंट दिया है और जिस कर्मचारी को निकाल दिया गया था उसको रीइन्स्टेट करने का आदेश दिया गया है । इसी प्रकार से खाद्य और रसद विभाग के सात कर्मचारियों को दलबन्दी के आधार पर निकाल दिया गया था, हाईकोर्ट ने उनको रीइन्स्टेट करने के आदेश दिये हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है और उनको जो १ लाख ७ हजार रु० देना पड़ेगा उसकी भी व्यवस्था बजट में नहीं की गई है ।

श्री बनारसीदास---

आप तो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मजबूत है तो यह नियम बनाया गया कि किसी को भी सजा न दी जाय ।

श्री बालोजी अग्रवाल---

कार्यपालिका के संबंध में सरकारी और विरोधी दोनों पक्षों ने एक से विचार प्रकट किये हैं । मैं एक उदाहरण रखता हूं । अभी अभी खाद्य विभाग द्वारा गेहूं और चावल के दाम बढ़ाये गये, उसके लिये जो आदेश आर० एफ० सी० के पास भेजे गये वह चार दिन तक पड़े रहे और तब जिलाधीशों को भेजे गये । इससे ७ लाख रुपये का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि तब तक वहां वह सस्ता बेचते रहे ।

मान्यवर, सुरक्षा के संबंध में बात यह है कि ५० हजार पाकिस्तानी समय-समय पर पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान से आये लेकिन आज पासपोर्ट की म्याद खत्म होने पर भी, ८-८ साल बीत जाने पर भी उनको आप प्रदेश से बाहर करने में असमर्थ रहे हैं । उनके यहां रहने से देश और प्रदेश की आन्तरित सुरक्षा का बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया है । इस सरकार ने विधायकों को भी भ्रष्ट किया है । मैं माननीय गेंदा सिंह जी का बड़ा आदर करता हूं लेकिन उन्होंने और माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जब इधर से उधर को जाकर कांग्रेस ज्वाइन की तो यह उन्होंने अपने यहां की जनता के प्रति गद्दारी का काम किया है । उन्हें उधर जाने से पहले त्याग-पत्र देना था और कांग्रेस की टिकट पर चुन कर आना था ।

मान्यवर, अभी अभी केन्द्र के शिक्षा मंत्री, श्री छागला ने लखनऊ में एक भाषण दिया था । उन्होंने कहा कि इस मेडीकल कालेज को ओवर ग्रेड करके केंद्रीय सरकार लेना चाहती है और उसको पंजाब में जिस प्रकार से मेडिकल कालेज को कर दिया गया है उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना देना चाहती है लेकिन इस राज्य सरकार ने उसको नहीं दिया । चंडीगढ़ में ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया गया है, पंजाब सरकार ने उसको दे दिया लेकिन इस राज्य सरकार ने इसको नहीं दिया । इससे मेडिकल रिसर्च और इस प्रदेश को बड़ी भारी क्षति हुई है ।

मान्यवर, विधायकों को इस सरकार ने परमिट, कोटे और लाइसेंसेज देकर तथा और अन्य प्रकार के लालच देकर उनको भ्रष्ट कर दिया है । ऐसे ही माननीय सदस्य इस सरकार का बड़े जोरों से समर्थन करते हैं ।

अन्त में मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार ने अब तक कांस्टीट्यूशन में १७ अमेंडमेंट किये हैं । राज्य सरकार को मैं एक सुझाव देता हूं वह ऐसा सुझाव केंद्रीय सरकार को दे कि वह अठारहवां संशोधन राज्य सभा के चुनाव के बारे में नियम बदलने के लिये करे । चुनाव का जो इस समय तरीका है उससे हमारे यहां के सदस्य भी भ्रष्ट होते हैं । रुपया लेकर वोट देते हैं । इन चुनाव के तरीकों को बदला जाय जिससे विधायक लोग भ्रष्ट होने से बच जायं । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री केशभान (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं इसका समर्थन करता यदि मैं यह देखता कि इस प्रस्ताव के पीछे कोई बल है। किसी प्रस्ताव में कितना बल है इसके लिये एक नपना होता है। सही नपने से अगर हम नापते हैं तो सही नतीजा निकलता है लेकिन अगर गलत नपने से नापा जाता है तो गणित के ठीक होने पर भी नतीजा गलत ही निकलेगा। इस अविश्वास के प्रस्ताव में दो प्रकार का बल होना चाहिये। एक तो रेखागणित का बल और दूसरा अंकगणित का बल। मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा।

यदि यह देखा जाय कि जनता किसी सरकार के प्रति कितना विश्वास रखती है, उससे वह कितनी आकांक्षा और आशा रखती है तो उसके लिये जनता के उस स्वप्न के नापने के लिये सरकार जितना पीछे रहती है उसकी उपलब्धियों में, उतनी दूर तक अविश्वास की मात्रा मैं मानता हूं। यह ऐब्सोल्यूट मात्रा है। किन्तु एक और सापेक्ष मात्रा है। जब हम यह देखें कि जनता सरकार से जितनी आशा रखती है उससे जितना पीछे सचमुच वह उनकी उपलब्धियों में रहती है, उसके मुकाबले में विरोधी दल के लोगों में उसका यह विश्वास हो कि यदि विरोधी दल की सरकार होती तो हमारी आकांक्षाओं को वे इतने अंश तक पूरा करते, उन दोनों में जो अन्तर होता है, सचमुच वही अन्तर अविश्वास का बल होता है। जब हम ऐब्सोल्यूट मात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में यह सरकार बहुत पीछे है, बहुत पीछे है और इसीलिये आज कई वर्षों से हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा काफी परिश्रम करके यह कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम पीछे हैं उससे आगे बढ़ें और जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल उपलब्धियों को लावें। हम जितना काम करना चाहते हैं उसमें बहुत कठिनाई है और हमने कई बार पहले भी कहा है कि स्वराज्य को हासिल करना आसान होता है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार द्वारा जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये जो चार बातें कही जाती हैं वे हैं, समाजवादी व्यवस्था कायम करना, अशिक्षा को दूर करना, लोगों के लिये खाने व कपड़े लत्ते का प्रबन्ध करना और अन्य दूसरी तरह की सहूलियतें उसके लिये उपलब्ध करना। लेकिन लोकतंत्र में सरकार के लिये यह आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत ही कठिन काम है। इसीलिये हमने अपनी पंचवर्षीय योजनायें बनायीं और इसीलिये वित्त मंत्री ने कहा था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमको आगे बढ़ने के लिये बहुत त्याग करना होगा। जब हम त्याग करेंगे तभी इस देश और प्रदेश का विकास होगा और देश आगे बढ़ सकेगा। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष हमें यह संकेत देना चाहिये कि अगली चौथी पंचवर्षीय योजना में हमें कितना त्याग करना होगा। उसी मात्रा में हम आगे बढ़ सकेंगे। यह रेखागणितीय बल हुआ। इसके मुताबिक हमें देखना होगा कि जनता का विश्वास हमने कितना प्राप्त किया है। यदि जनता का विश्वास विरोधी दल के लोगों में हो, या विरोधी दल के किसी दल में हो कि अगर उसे शासन सत्ता सौंप दी जाय तो वह हमारी आकांक्षाओं को कहां तक पूरा करेगा और कहां तक हमें उपलब्धियां प्राप्त करायेगा तो वह आंक कर ही हिसाब लगायेगा।

अंकगणितीय बल के अनुसार जब हम यहां चुन कर आये हैं और कुछ खास वर्ष के लिये आये हैं तो आज कौन-सी बात हो गयी जो कहा जाता है कि सरकार को यहां से हट जाना चाहिये। यदि यह होता कि सरकारी पक्ष की संख्या विरोधी दल के मुकाबले में घट गयी होती, या पहले से भी उनकी संख्या घट गयी होती तो इस तरह की कोई बात कही जा सकती थी लेकिन आज क्यों इस तरह की बात कही जा रही है....

श्री उग्रसेन—

आप संख्यात्मक न कह कर गुणात्मक कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केशभान—

इसके दो ही रास्ते हैं। यदि विधायकों की संख्या जो सरकारी पक्ष को पहले थी उससे घट जाय तो भी आप कहते तो हम समझते कि आपके अविश्वास के प्रस्ताव में कुछ बल है। दूसरे यह कि जितने विरोधी दल हैं उन सबकी संख्या मिलाकर भी यदि सरकारी पक्ष के लोगों के बराबर न हो, तो भी यदि यह विश्वास होता कि एक विरोधी दल ऐसा है जिसके पास इतना मत है कि वह सरकार को कायम कर सकता है, तो भी कहा जा सकता था कि सरकार को उलट दिया जाय....।

श्री उग्रसेन—

माननीय सदस्य तो मास्टर हैं, अध्यापकों के मसले पर भी कुछ बोलें।

श्री केशभान—

आज किसी उधर के दल में या संयुक्त विरोधी दल में क्या इतनी क्षमता है कि वह नई सरकार का शासन कायम कर सके ? अंकगणित प्रणाली में भी एब्सोलूट ताकत है ? यह गवर्नमेंट न रहे और कोई दूसरी भी न बने तो यह भी एक बात हो सकती है कि कोई गवर्नमेंट न रहे, किसी में विश्वास न हो और राज्य चूल्हेभाड़ में जाय तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। मैं इसको मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास नहीं समझता, मैं तो इसे लोकतंत्र के विरुद्ध अविश्वास समझता हूं। रेखागणित और अंकगणित के अनुसार जनता को जो आशा है उसके मुकाबले में हम और आप दोनों में इस सरकार को हटा कर सरकार बनाने को क्षमता न हो और सचमुच अगर जनता का विश्वास न हो तो लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी और दोनों को सोचना होगा कि क्या किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि जनता हम में और आप में दोनों में विश्वास खो चुकी है (व्यवधान) हमारी आपके लिये चेतावनी है कि हम तो शासन भोग चुके आप अभी भोगने वाले हैं आपको भी अब और अधिक चिन्तित होना चाहिये। आपको मैं चेतावनी दूंगा कि आप मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के बजाय .... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

उग्रसेन जी, आप बहुत इन्टरफीयरेंस कर रहे हैं, आप शांत रहें।

श्री केशभान—

अब मैं श्रीमन्, थोड़ी सी गुणात्मक गणना की भी चर्चा करना चाहता हूं। लोग समझते हैं कि आज सरकार को शिक्षक गाली दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारी गाली दे रहे हैं, किसान गाली दे रहे हैं, व्यापारी गाली दे रहे हैं, जनसंघ वाले और कम्युनिस्ट वाले गाली दे रहे हैं, जितने भी यह लोग गाली देते हैं उनको गिनने लगें तो इस सरकार को एक दिन भी नहीं टिकना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबलीसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह कहना है....

श्री अधिष्ठाता—

वह बैठ नहीं रहे हैं, आप नहीं बोल सकते।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार को सब दलों के लोग गालियां देते हैं, हम लोग कोई गाली नहीं देते, हम आलोचना करते हैं। वह यह शब्द वापस लें।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, आप बैठें ।

श्री केशभान—

मेरा मतलब गाली देने से था आलोचना करते हैं, अगर वह ठीक नहीं है तो मैं वह शब्द वापस लिये लेता हूं । इन आलोचनाओं से वह समझते हैं कि बड़ी भारी कोई बात हो गई लेकिन आंकड़ों के हिसाब में संख्याओं की शक्ति होती है, धनात्मक शक्ति और ऋणात्मक शक्ति और जो आपस में कट कर बहुत कम रह जाती है । एक प्रतिक्रियावादी शक्तियों को प्रोत्साहन देना और दूसरी पुलकावा देने वाली शक्ति है जो प्रगतिवादियों को दिया जाता है । तो यह दोनों अलग-अलग शक्तियां हैं और बहुत बड़ी शक्तियां हैं लेकिन नतीजा निकालने में वह छोटी सी ही रह जाती हैं । आप उसका जो रेमिटेंट है वह देखें कि कितना रह जाता है । शिक्षकों के सम्बन्ध में.....

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या आप जामेटरी पढ़ा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

आप गम्भीर बातों को गम्भीरता के साथ सुनें । आप जामेटरी पढ़ लीजिये, क्या हर्ज है ।

श्री केशभान—

श्रीमन्, आदमी जब स्वस्थ रहता है तो उसका स्वास्थ्य चिल्लाता नहीं और जब बीमार रहता है तो स्वास्थ्य परेशान करता है । चुनाव के समय में बहुत गालियां सुनने को मिलती हैं लेकिन ऐसे लोग जो सरकार में विश्वास रखते हैं, एक पार्टी विशेष में हैं वह दौड़-दौड़ कर चारों तरफ उसकी प्रशंसा नहीं गाते इसलिये भी लोगों में भ्रम हो जाता है ।

अब शिक्षकों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । आज शिक्षकों से मुझे एक बात कहना है । उन्हें मांगों को पूरा कराने के लिये एक अस्त्र उठाना चाहिये, शिक्षकों के अनुकूल उठाना चाहिये और जो अस्त्र उन्होंने उठाया है उसके समर्थकों का कहना है कि यह अन्तिम अस्त्र है और इसके पहिले जितने अस्त्र उठाये जा सकते थे, उठाये जा चुके हैं । उनका कहना है कि हम परीक्षाओं में नहीं रहेंगे, देखें सरकार कैसे परीक्षा कराती है । अगर सचमुच सरकार परीक्षा नहीं ले पायी तो सरकार की चीं बोल जाती है और अगर परीक्षा ले पायी तो शिक्षकों की चीं बोल जाती है । लेकिन मेरे पास एक और अस्त्र है जिससे शिक्षकों की जीत हो सकती है आज मैं शिक्षक होता, उनका नेतृत्व मेरे हाथ में होता तो मैं उनसे कहता कि आप इनविजिलेटर हो सरकार से कहो कि यदि सरकार दरिद्र है, यदि वित्त मंत्री के पास उनको देने के लिये पैसा नहीं है तो हम कोई फीस नहीं लेंगे, इनविजिलेशन का कुछ चार्ज नहीं करेंगे, कापियां जांचने की फीस नहीं लेंगे और इस तरह से पैसा बचे उससे सरकार धनी बने । मेरा खयाल है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार पर बहुत बड़ा दबाव पड़ता और सरकार को अध्यापकों को पैसा देना पड़ता । मैं शिक्षकों से अपील करूंगा कि सरकार उनकी बात सुने या न सुने, उससे होड़ न मचाइये, उन्हें इम्तहान लेना चाहिये और शुल्क को छोड़ देना चाहिये । मंत्रियों से भी मुझे कहना है, मैं नहीं समझता कि मेरा ऐसा कहना अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी, लेकिन यह जरूर है कि जब पूरे दृष्टिकोण से हम कुछ नहीं कहते तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है । बहुत से जिम्मेदार लोगों ने कहा कि शिक्षकों की मांगें उचित हैं लेकिन हम असमर्थ हैं उसे पूरा करने में । मेरा कहना है कि यदि उनकी मांग आपके कथनानुसार न्यायोचित हैं तो उनकी मांग को पूरा करना चाहिये । और अगर न्यायोचित नहीं हैं तो कहना चाहिये कि शिक्षकों के तुल्य अन्य बहुत से लोग हैं जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और उनको भी जब नहीं

दे पाते हैं तो शिक्षकों को कहां से दें ? अतः उनकी मांग को न्यायोचित न कहें। लेकिन अगर न्यायोचित आप मानते हैं और कहते भी हैं तो उनको देना चाहिये, तभी न्यायोचित कहें अन्यथा चुप रहें। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे इस बात को सुनकर अफसोस हुआ और खासकर माननीय नवल किशोर जी जैसे लोगों के मुंह से कि यह अविश्वास का प्रस्ताव सामयिक नहीं है और एक रस्म की अदायगी के लिये विरोधी दल के नेताओं ने पेश किया है। मैं समझता हूं कि अगर शासक दल और उसके जिम्मेदार लोगों को इस बात का अहसास नहीं है कि आज हमारे प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर इस शासन के प्रति गहरी अविश्वास की भावना है लोगों के अन्दर तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलतफहमी के अन्दर यह सरकार कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार की मौजूदा शासन के खिलाफ न केवल हमारे प्रदेश की अविश्वास की भावना है बल्कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि शासन के खिलाफ सारे देश के अन्दर एक गहरी अविश्वास की भावना पैदा हो गयी है। आज दिल्ली में आप जाइये और मंत्रियों से मिलिये वहां पर आप पायेंगे कि एक-एक मंत्री का इस प्रदेश के शासन में अविश्वास उन है। जो रुपया योजनाओं के अन्तर्गत दिया जाता है, उसका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। आज लोगों का इस शासन के अन्दर बिल्कुल ही विश्वास नहीं रह गया है। अब वे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो कि देश भर में सबसे बड़ा प्रदेश है, आज हर उन्नति के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां पर देश भर के १८ प्रतिशत लोग रह रहे हैं, वहां पर अराजकता की भावना फैल रही है और जिसकी जिम्मेदार यह सरकार है। आज इस देश की गरीबी के लिये भी यह सरकार जिम्मेदार है, पिछड़ेपन के लिये यह सरकार जिम्मेदार है। यदि यह सरकार केन्द्र के पास जाती है तो केवल यह दलील दी जाती है कि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, आबादी भी सब प्रदेशों से ज्यादा है अतः आप इन्डस्ट्री, उद्योग, अनाज के मामलों में हमारे ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जह दीजिए।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है, गरीबी नहीं दी ? क्या इस शासन ने पिछड़ापन नहीं दिया ? क्या इस शासन ने निकम्मापन नहीं दिया ? क्या इस शासन ने शिक्षा के अन्दर एक अराजकता नहीं पैदा कर दी ? फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे प्रति अविश्वास की भावना न रखो, आस्था प्रकट करो और हमारी प्रशंसा करो तो किस मुंह से यह आप कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। माननीय गेंदा सिंह जो ने बेहद तारीफ की है कि ३ उप-चुनावों के अन्दर हुए नतीजे को देख कर आप कह सकते हैं कि सरकार को जनता का विश्वास है। इस नाजुकता के अन्दर आप मत जाइये। विश्वास रखिए कि आपके अन्दर इस प्रदेश की जनता का विश्वास नहीं है। आप यहां पर बैठ कर कहा करते हैं कि जनता को अविश्वास नहीं है पर मैं कहता हूं कि वर्तमान शासन में किसी को भी विश्वास नहीं है। आज इस सदन में भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरफ के बैठने वाले १७२ माननीय सदस्यों को तो अविश्वास है ही, मैं यह भी जानता हूं कि शासन दल के अन्दर भी १०० आदमी ऐसे हैं जिनको मौजूदा शासन में विश्वास नहीं है। आपके ऊपर और आपके मंत्रिमंडल के ऊपर विश्वास नहीं है। माननीय अलीजहीर साहब को आपके प्रति अविश्वास नहीं है। आप कहते है कि हमारे ऊपर विश्वास करो, आस्था रखो, किस बात लिये हम आस्था करें। हमारे प्रदेश के अन्दर आज निकम्मापन है। जिन्दगी के क्षेत्र में हम पिछड़े चले जा रहे हैं। हमारे शासन के अन्दर एक पौलिटिकल बैंकप्टसी आ गयी है जिसके कारण यहां पर हर प्रकार की अराजकता फैली हुयी है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी हालत क्या है। माननीया मुख्य मंत्री ऐसी टीम की कप्तान हैं, जो टीम उनकी नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

उस टीम के कप्तान माननीय चन्द्रभानु गुप्त हैं जिनको मजबूरन उसके अन्दर रख छोड़ा है। इस टीम की आप कप्तान तो हैं मगर आपको उस पर भरोसा नहीं है और उस टीम का आप पर भरोसा नहीं है। जब इतनी कमजोरी और बैंकप्टसी हो शासन में और इतनी समस्यायें हों तो इस शासन के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है और जब तक इस प्रकार के शासन की स्थिति प्रदेश में रहेगी यह प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिये ८ करोड़ जनता की भावना, अविश्वास की भावना आपके प्रति इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रकट की जा रही है। यह हो सकता है कि हम आपको हटा न सकें लेकिन क्या अविश्वास के प्रस्ताव का मतलब सरकार की नीतियों को सेंश्योर करना नहीं होता और उसके निकम्मेपन को रोकना नहीं होता। आज जो परिस्थिति है उससे आप आंख मूंद नहीं सकते। आप वास्तविकता को देखें।

उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। जो राष्ट्रीय नीतियां हैं जिनको केन्द्रीय सरकार और इस पार्टी की दूसरी सरकारें अन्य प्रदेशों में कामयाबी के साथ अपना रही है, यहां पर शासन में एक प्रतिक्रियावादी नेतृत्व होने के कारण जान बूझ कर षडयंत्र करके उन राष्ट्रीय नीतियों को पीछे ढकेला जा रहा है। माननीया कृपालानी जी के पीछे एक सिंडिकेट है जिसमें बनारसीदास जी, दाऊदयाल खन्ना, कैलाश प्रकाश और राममूर्ति हैं और जिनके हाथों में वह नाच रही हैं और वह अपना नेतृत्व नहीं कर पा रही हैं।

माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि अध्यापकों की लड़ाई आप हार जायेंगे। आप कहते हैं कि अध्यापकों के साथ आपको हमदर्दी है, उनकी मांगें न्यायसंगत हैं, लेकिन उनकी लड़ाई का तरीका गलत है। मैं उनको बतलाता हूं कि न्याय की पराजय नहीं होती। न्याय जीतता है। उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन इतिहास इस बात को बतलाता है, जिन्दगी का तजुर्बा इस बात को बतलाता है कि न्याय की पराजय नहीं हुआ करती। आप एक जिद से, हठ से एक अराजकता की स्थिति क्यों शिक्षा में पैदा कर रहे हैं? शिक्षा संस्थाओं पर रेड सरकारी अधिकारियों के जरिये क्यों किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाता है, ताले तुड़वाता है और कापियां निकलवाता है, प्रिंसिन्पलों को मजबूर करता है परीक्षा लेने के लिये। आज पुलिस स्कूलों के पवित्र प्रांगण में जा कर रेड करती है यह शासन के लिये कलंक की बात है और इसीलिये इस सरकार पर अविश्वास प्रकट किया जा रहा है क्योंकि आपकी यह हठवादिता समस्या का समाधान होने नहीं दे रही है। हमारे अध्यापकों की मांगे जो हैं उचित हैं न्यायसंगत हैं और ५ लाख बच्चों की जिन्दगी का सवाल है और प्रदेश की ८ करोड़ जनता इस बात को चिन्ता की नजर से देख रही है कि आप उनकी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और प्रदेश को इस नाजुक स्थिति से बचायें लेकिन खेद है कि आप उसको हल नहीं कर पा रहे हैं।

माननीया मुख्य मंत्री जी केन्द्र के अन्दर गयीं। जब प्रश्न आया आल इंडिया में कोटा सिस्टम का तो उन्होंने उसका विरोध किया। हमारे प्रदेश को उससे लाभ होता, कोटा सिस्टम से हमको ज्यादा हिस्सा मिलता। मुझसे एक सज्जन ने कहा कि माननीया मुख्य मंत्री के अन्दर भावात्मक एकता इस प्रदेश के प्रति नहीं हो पा रही है, इमोशनल इंटेग्रेशन नहीं हो रहा है, इसलिये उन्होंने इसको नहीं माना। मैं इस बात को नहीं मानता लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया वह प्रदेश के हित के खिलाफ जाता है। वह इस प्रदेश की समस्याओं को नहीं समझ पा रही हैं यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति को उनका नेतृत्व समझने में असमर्थ है। प्रदेश की समस्याओं का हल निकालने में उनका नेतृत्व असमर्थ है। प्रदेश की समस्याओं का हल निकालने में उनका नेतृत्व असमर्थ है। मौजूदा नेतृत्व प्रदेश को सही दिशा की ओर ले चलने में असमर्थ है और उनका ही नेतृत्व इस बात के लिये जिम्मेदार है कि आज प्रदेश में भुखमरी फैली हुई है नौकरशाही का आज बोलबाला है। उनका नेतृत्व ही इस बात के लिये जिम्मेदार है कि शासन के हर क्षेत्र में आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ३ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी यह प्रदेश पिछड़ा चला

जा रहा है। क्योंकि यह शासन निकम्मा है, राजनीतिक समझदारी की इसमें कमी है, एक दीवालियापन है इसीलिये इस शासन के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होना अनिवार्य है।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले नेता विरोधी दल और उनके साथ-साथ मैनेजर सिंह, रियासत हुसैन साहब को जिन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से हमारी पार्टी के नेता में विश्वास प्रकट किया है और उन्होंने पिछले दिनों हिन्दी के सम्बन्ध में जो कुछ किया है उस सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने आभार प्रकट किया है उसके लिये मैं उन महानुभावों को बधाई देता हूं। मैं नेता विरोधी दल से यह आग्रह करता हूं और विनम्र प्रार्थना करता हूं कि माननीय चन्द्रजीत यादव ने अपनी वक्तृता में जो अविश्वास प्रकट किया है और विभिन्न तर्कों के द्वारा अपने प्रदेश की जनता के मनोबल को कम करने का प्रयास किया है उसको सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज हमारे देश और प्रदेश की जो स्थिति है राजनीतिक उसमें देश के ऐसे लोग जो देश की स्वाधीनता को बुरी निगाह से देखते हैं और देश के उन लोगों को जो मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल में अपनी स्वाधीनता अर्जित करने के लिये अनेकानेक प्रयास किये और अपने नाना प्रकार के तर्कों से आज इस अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से जो विचार व्यक्त किये हैं उनके प्रति मुझे कुछ नहीं कहना है। आप स्वयं भी जानते हैं जिन लोगों का खूनी इतिहास जनतंत्र के विरोध से लिखा गया है, ट्राटस्की से लेकर बेरिया तक के सर जिनके हथोड़ों से कुचले गये हों वे इस देश में जनतंत्र के नाम पर इस तरह के तर्क देते हैं तो कोई आश्चर्य मुझे नहीं होता। मैं माननीय नेता विरोधी दल की सेवा में यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी कम्युनिस्ट चीन में नीचे की आमदनी और ऊपर की आमदनी में इतना भेद है कि नीचे की आमदनी वाला जो कुछ पाता है उसमें उसको भर पेट रोटी मिलना भी दूभर हो गया है। आपने स्वयं सुना होगा कि जिस वक्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पुराने नेता और संयुक्त समाजवादी पार्टी के नये नेता रामसुन्दर पांडेय जो बोल रहे थे उन्होंने इस बात को उद्धृत किया था कि माननीय ख्रुश्चेव को किसलिये हटाया गया। मैं इन बातों को दोहरा कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं इस बात को मानता हूं कि आपके दिल में इस देश को बनाने की व्यथा है, और लोगों की तरह किसी को देशद्रोही नहीं मानता, मैं समझता हूं कि हर एक के दिल में बेचैनी है, बेकरारी है इस देश को बनाने की। लेकिन क्या उस बेचैनी का हल यह अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है जो एक ऐसी सरकार के प्रति लाया गया है जो अपने टूटे-फूटे साधनों के जरिये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में प्रदेश को उठाने का प्रयत्न कर रही है? क्या इस अविश्वास के प्रस्ताव के जरिये आप अध्यापकों की समस्या को हल करना चाहते हैं? कदापि ऐसा होने वाला नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर यह प्रस्ताव किसी और अवसर पर लाया गया होता तो सदन के इधर बैठने वालों ने भी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया होता। (व्यवधान) आप घबराइये नहीं, हम जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम इस सिद्धान्त को मान कर चलते हैं कि जनतंत्र की सफलता के लिये स्वस्थ विरोधी दल का होना आवश्यक है। विरोधी दल के स्वस्थ होने के लिये जो उसके हथियार होते हैं और उसका जो आदर होता है उसको हम देने के लिये तैयार हैं, लेकिन उसकी सफलता के लिये जो आवश्यक शर्तें हैं उनको भी आप दृष्टि में लाने की कृपा कीजिये। जनतंत्र की सफलता के लिये विद्या धन सम्पन्न व्यक्तियों का बाहुल्य होना चाहिये। जो ऐसे स्कूल हैं, विद्या मंदिर, हैं, उनमें काम करने वाले अध्यापकों के माध्यम से जो कुछ लीला प्रस्तुत की जा रही है उससे क्या आप आशा करते हैं कि इस प्रदेश का सुन्दर भविष्य बन सकता है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर उनका उद्देश्य ठीक है, उनकी मांग ठीक है तो उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं ? प्रश्न मांग का नहीं है, प्रश्न यह है कि उनको किस माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, कौन से साधन उनको प्राप्त करने के लिये अख्तियार किये जा रहे हैं ? सरकार से अगर नाराजगी थी तो उसको प्रगट करने के लिये सरकार ने अनेक अवसर प्रदान कर रखे हैं। उन विद्यार्थियों के बारे में माननीय नेता विरोधी दल सोचें जो पी० एम० टी० में बैठने वाले हैं, जिस देश में डाक्टरों का अभाव है, उसकी पूर्ति के लिये जो सक्षम हैं उनके मन में कितना कोलाहल मच रहा होगा। ऐसे नाजुक प्रश्न को इतने हल्के ढंग से आप हल करना चाहते हैं, मुझे हैरानी होती है।

जो भारत को सुन्दर बनाने की चेष्टा करना चाहते हैं, उनके द्वारा विद्यार्थियों से यह कहा जाता है कि अगर अध्यापकों की मांगें पूरी नहीं होंगी तो विद्यार्थी परीक्षा में नहीं जायेंगे। अध्यापकों की मांग के बारे में उल्टे तर्क सुनाये जाते हैं। आप जानते हैं कि इस राज्य सरकार ने पिछले कई वर्षों में बिना किसी आंदोलन के बराबर अध्यापकों की मांग को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया है और हम जानते हैं कि राज्य सरकार इसको मानकर चलती है कि Primary Education is primary for any Society' और जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है उसका दायित्व राज्य सरकार का होता है उसको हम स्वीकार करते हैं और उसको अमली जामा पहनाने के लिये हम तैयार हैं। जो अवसर न रहते हुये भी अपने उन तर्कों को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिन तर्कों का संबंध जनतंत्र के मूल सिद्धान्त से है। जगत के सब से बड़े विद्वान और फिलासफर लास्की ने कहा है कि Bye-elections are the barometer of public opinion' उप चुनाव जनतंत्र की कौन सी दिशा है इसकी ओर संकेत करता है। पंजाब से लेकर बंगाल तक और काश्मीर से गुजरात तक जितने उप चुनाव हुये हैं उनमें कितनों में कांग्रेस की पराजय हुई है और कितनों में आपकी विजय हुई है ? मैं आंकड़े देकर समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं।

सदन के एक नये माननीय सदस्य ने कहा कि शहर में ऐसे लोग रहते हैं जो बुद्धिजीवी हैं जिनको उन्होंने इंटेलीजेंशिया की संधि दी। मैं जानता हूं कि आज जिन लोगों की ओर वे संकेत कर रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जन समाज की सब से कठिन और बड़ी समस्या के समय चोर बाजारी में लगे हुये हैं, ऐसे धंधों में लगे हुये हैं जिसके चलते राज्य सरकार के सामने सब से बड़ा संकट उपस्थित है, आज उन लोगों की वकालत की जाती है, उनकी तरफ इशारा किया जाता है जो सचमुच इस देश के पंच मांगी हैं जो देश की स्वाधीनता को आज खतरे में डालना चाहते हैं। इसलिये मान्यवर, मैं नेता विरोधीदल से यह आग्रह करना चाहता हूं बड़े आदर के साथ उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस गम्भीरता के साथ वह उत्तर प्रदेश का भाग्य बनाना चाहते हैं, वह गम्भीरता आज के समय में उपहास मालूम पड़ती है, जिस समय आपके साथ श्री झारखंडे राय और चन्द्रजीत यादव ऐसे लोगों के हस्ताक्षर भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि कुछ लोग रहते तो यहां हैं, लेकिन जब पानी मास्को में बरसता है तो वे छाता यहां लगाते हैं। चीन के हमले की बात आप करते हैं, इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे संकट के समय में उन लोगों का मनोबल तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, जो वीरता से उनका सामना करने के लिये आज तत्पर हैं। हमारे यहां कहा गया है, 'सशंयात्मा विनेश्यतीः' यानी नाश का विनाश का एक बड़ा कारण संशय है। तो आज कुछ लोग भोली जनता के मन में संशय पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रकार से विनाश का एक मार्ग तैयार कर रहे हैं। यदि यही संशय देश की एक प्रजातंत्रात्मक सरकार के प्रति पैदा हुआ तो हमारी क्षति हो सकती है, हमारा विनाश हो सकता है। इसलिये हमें अपनी सरकार के प्रति संशय नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वह अपना अविश्वास का प्रस्ताव वापस ले लें।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अधिष्ठाता महोदय, अभी अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। मैं तो यह सोचता था कि सरकारी पार्टी की वकालत पुराने धुरन्धर लोग करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो लोग नये पार्टी के मेम्बर बने हैं, उन्हीं पर यह भार सौपा गया है, माननीय रामायणराय और कल्पनार्थसिह ऐसे लोगों पर। हम तो यह अच्छी तरह जानते हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा कोई यह सरकार बदलने वाली नहीं है, लेकिन इस तरह के अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा इसके माध्यम से हम विरोधी पार्टी के लोग अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। यह कांग्रेस सरकार अकाल और भुखमरी की सरकार है, यह राष्ट्रीय क्षति की सरकार है। जब तक यह सरकार रहेगी भुखमरी और अकाल बने रहेंगे।

माननीय चरणसिह जी ने उस दिन कहा कि पैदावार किसलिये नहीं बढ़ी कि मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया। यह बात ठीक नहीं है। आज कांग्रेस के सदस्य और मंत्री तथा गेंदासिह ऐसे लोग मौसम और वातावरण का बहाना करके जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। 'सर्वस्यः कारणम् काल :' का अभी श्लोक पढ़ा गया, और उसके जरिये से मौसम के बहाने को बल दिया गया और काल और परिस्थिति के कारण सारे दोषों को छिपाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह श्लोक का आधा भाग ही याद है, उन्हें शायद दूसरा पार्ट नहीं याद है, श्लोक का दूसरा भाग है, 'राजा कालस्य कारणम्,' यानी काल और परिस्थिति राजा के कारण ही उत्पन्न होती है, यदि राजा उसे दूर करना चाहे तो वह समय नहीं आ सकता है। राजा काल को भी पराजित कर देता है। आप इस देश के शासक बनकर बैठे हो और समय को बदलने की क्षमता नहीं रखते तो क्या हक है आपको यहां पर बैठने का।

किस किस मंत्री के बारे में गिनाया जाये, आज सभी अपनी अपनी राह पर हैं। जैसा कि अभी चन्द्र गोत जी ने कहा कि माननीय सुचेता कृपालानी एक ऐसे दल की कप्तान हैं, जिसका हर खिलाड़ी अपनी अपनी गति से खेल रहा है। समय नहीं है इसलिये मैं संक्षेप में ही कहना चाहता हूं। माननीय हरगोविन्दसिह ने वकालत की सदन में। वह इस समय तो नहीं हैं, उनके बारे में माननीय न्यायाधीश माथुर ने कहा रिलीज़ उनकी अवैध थी, जिस जल्दी के साथ रिहाई की गई वह नहीं होनी चाहिये थी। माननीय हरगोविन्दसिह ने भी स्वयं कबूल किया कि मेरे कहने से जांच शुरू हुई। जज ने भी लिखा कि उनकी गैर कानूनी रिहाई का जिम्मेदार कौन है? माननीय हरगोविन्दसिह जी ऐसे भ्रष्ट मंत्री जब वह कृषि मंत्री थे तो उन्होंने ढ़ाई सौ एकड़ का फार्म बाराबंकी में बना लिया और न जाने उन पर ऐसे ही कितने भ्रष्टाचार के दोषारोपण लगाये गये। माननीय न्याय मंत्री अली जहीर साहब और पुलिस मंत्री माननीय हरगोविन्दसिह जी जैसे लोग हों तो इस प्रदेश में अमन चैन की व्यवस्था कैसे ठीक रह सकती है? जिस प्रदेश के न्याय मंत्री और पुलिस मंत्री भ्रष्ट हों वह शासन कहीं चल सकता है? उस मंत्रिमंडल में जहां ऐसे लोग हों, जनता का विश्वास नहीं रह सकता। श्री अली जहीर जो न्याय मंत्री हैं, उनके यहां फर्रुखाबाद का एक केस आया, जिसका जिक्र मैं पहले भी इस सदन में कर चुका हूं कि इसमें अपील करने की इजाजत दी जाये, वह स्टेट बनाम महराजसिह का केस था। लेकिन जब इन पर दबाव पड़ा, रिश्वत का या राजनीतिक दबाव पड़ा हो, दोनों प्रकार का भी हो सकता है, रिश्वत लेकर वह केस वापस ले लिया गया। दूसरा केस एक बुलन्दशहर का है, स्टेट बनाम बुद्धसेन का है। उसमें भी ऐसा ही हुआ, उसमें 'यस' और 'नो' दोनों आज्ञायें एक ही दिन की तारीख में लिखी हुई हैं। सुचेता जी, अगर आपके मंत्रिमंडल में इस तरह के लोग रहेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार कहां तक इस प्रदेश की शासन व्यवस्था को चला सकती है। जिस प्रदेश का न्याय मंत्री और पुलिस मंत्री इस तरह का भ्रष्ट आचरण करता हो, जहां का पुलिस मंत्री हर जिले का एस० पी० भी हो, यहां बैठकर गृहमंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

की हैसियत से टेलीफोन उठाता है और पुलिस कप्तान से कहता है कि फलाने को दफा ७ में चलान कर दो, फलां को बन्दूक का लाइसेंस दे दो, फलां को इस दफा में और फलां को उस दफा में बन्द कर दो, क्या यह काम गृहमंत्री का है ? अगर यह काम आपके गृह मंत्री का है और ऐसा ही काम आपके न्याय मंत्री का है तो मैं कहना चाहता हूं कि उसकी नाव डूबने में देर नहीं है ।

अभी तीन दिन पहले इस सदन में सवाल हुआ कि जब अली जहीर साहब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री थे उसी वक्त लखनऊ शहर में इन्होंने म्यूनिसिपल बोर्ड की जमीन पर नाजायज कब्जा करके उसको बेंच भी दिया और महाराजा बलरामपुर से ३५ हजार के स्थान पर ४ लाख रुपये लिये । मैं कहता हूं कि आप की हुकूमत चल इसलिये रही है कि हमारी कमजोरी है । मैं विरोधीपक्ष के लोगों से भी कहता हूं कि हमारे अन्दर एक कमजोरी है, मैं पूछता हूं सुचेता जी से कि क्या दुनिया में कोई भी ऐसी हुकूमत है जहां १७ साल तक योजना चलती रही हो और फिर भी उसके राज्य में खाने पीने का अभाव हो । १७ साल तक लगातार योजनायें चलती रहें ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० की फौज आप खड़ी करते रहें, फर्टिलाइजर्स और सिंचाई योजनाओं पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते रहें ग्रो मोर फूड कैम्पेन चलता रहे और उसके बाद पैदावार घटती रहे । आज दुनिया में कोई हुकूमत बताइये, नवल किशोर जी, जो दूसरी भाषा के माध्यम से अपनी हुकूमत चलाती हो, जो १७, १८ साल की हुकूमत में अपनी मातृभाषा को, अपने प्रदेश के अन्दर प्रचारित न कर सकी हो। हिन्दुस्तान के अन्दर ही कोई राज्य क्या ऐसा है जहा पर कैपिटा इन्कम, औसत आमदनी घटी हो। पंजाब ने बढ़ा ली, वहां साढ़े चार सौ रुपये फी आदमी है, बंगाल में ५ सौ रुपये फी आदमी महाराष्ट्र में और मद्रास के अन्दर साढ़े तीन सौ और सारे हिन्दुस्तान की औसत आमदनी प्रति व्यक्ति ३४० रुपया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की औसत आमदनी २५४ रुपया प्रति व्यक्ति है। जो २, ३ बातें मैं बता रहा हूं उनसे साफ जाहिर है कि आप की सारी दुनिया में एक अजीबो गरीब हुकमत है । आपकी हुकूमत चल नहीं सकती ।

अब मैं यह बताऊं कि यह हुकूमत चल कैसे रही है । जहां माननीय अली जहीर और हरगोविन्द सिंह जैसे लोग २–२ और ४–४ लाख रुपयों के लिये नाजायज़ काम करते हैं वहां हमारे विरोधी दलों के लोग १५ रुपये २० रुपये, परमिट, लाइसेंस के लालच में, किसी कमेटी के चेयरमैन बनने की लालच में, कहीं कुछ मिल जाने की लालच में इधर से उधर जा करके सीटों पर कब्जा करते हैं। (हंसी) यह हंसने की बात नहीं है, यह रोने की बात है, वास्तविकता है । माननीय गेंदासिंह, माननीय कल्पनाथसिंह और माननीय रामायणराय से मैं साफ कह देना चाहता हूं कि आज वकालत करते हो कर लो, लेकिन इतिहास तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता । जिस वक्त उत्तर प्रदेश का इतिहासकार इतिहास लिखेगा वह यह लिखेगा कि जिस वक्त इस सड़ी गली हुकूमत को ठोकर देने का काम था उस वक्त गेंदासिंह जैसे लोग विरोध से वोट ले कर हुकूमत की तरफ जा कर बैठ गये और सड़ी गली सरकार का ही समर्थन करने लग गये । आज ऐसे ही लोगों के बल पर यह सरकार चल रही है ।

श्री गेंदासिंह—

विरोधी दलों के बल पर यह सरकार नहीं चल रही है । न उसके कहने से जायगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हुकूमत तो जायगी, आपके जैसे लोगों के बचाने से भी वह बच नहीं सकती ।

अब मैं एक बात और कहता हूं कि विरोधी पक्ष के नेताओं को चाहिये कि अध्यापकों का जो संघर्ष चल रहा है उसमें उनकी जितनी ताकत हो सब इस मोर्चे पर लगा दो । अगर यह मोर्चा चल गया तो इसी मोर्चे पर सरकार जा सकती है । आज सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय

कर्मचारी और आपके सारे राज्य कर्मचारी भी क्या कर रहे हैं ? आपके राज्य कर्मचारी, केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिले इसके लिये संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज वे सरकारी कर्मचारी तनख्वाह नहीं ले रहे हैं और वह भी इस लड़ाई के साथ मिले हुये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज हर एक सरकारी कर्मचारी का कर्त्तव्य है कि आज वह अध्यापकों की लड़ाई के साथ अपनी लड़ाई को मिला दे और इस सरकार के एक एक काम को ठप्प कर दे। मैं इस बात को मानता हूं कि सुचेता जी ने इस देश की जंगे आजादी में बड़ी ईमानदारी के साथ देश का नेतृत्व किया, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि सुचेता जी इस हुकूमत की कुर्सी को ठोकर मारकर इस हुकूमत के खिलाफ देश के अन्दर बगावत का झंडा बुलन्द कर दें तभी आपकी नेकनीयती का सबूत मिल सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इस प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं और यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का हर आदमी आज जाग गया है और वह समझ गया है कि यह अध्यापकों की लड़ाई न्याय के ऊपर है मगर यह सरकार उनके ऊपर लान्छन लगाकर उनको डी० आई० आर० से डराना चाहती है। आज इस प्रदेश के अध्यापक का स्तर हरगोविन्दसिंह जी और अली जहीर साहब से कहीं ऊंचा स्तर है। आज यदि वह चाहें तो सारे परचों को आउट कर सकते हैं, लेकिन उनका बहुत ऊंचा स्तर है। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के जन समुदाय से यह कहना चाहता हूं कि अध्यापकों की हड़ताल के साथ मिलकर इस प्रदेश के अन्दर बगावत पैदा करें जिससे यह सरकार एक मिनट भी इस प्रदेश में न टिक सके तभी इस प्रदेश का कल्याण हो सकता है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

अधिष्ठाता महोदय, प्रजातन्त्र में विरोधीदल का यह अधिकार है कि जब समय देखे और अपनी दृष्टि से उपयुक्त समझे तो सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करके उसे हटाने का प्रयास करे किन्तु मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुये यह कहना चाहता हूं कि आज सुबह १० बजे से लगातार मैंने विरोधीदल के नेता और दूसरे लोगों के भाषण सुने, और उसके समर्थकों के भाषण भी सुने हैं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह प्रस्ताव जैसा कि विरोधी दल ने मन्त्रि परिषद के विरुद्ध रखा है ऐसा शब्दों में तो लिखा हुआ है, किन्तु उसके समर्थकों के जो भाषण हुये हैं, जैसे अभी काशीनाथ जी मिश्र का भी भाषण हुआ है, इन सबको सुना, किन्तु मुझे इससे बड़ा भ्रम पैदा हुआ। सुचेता जी से उन्होंने कहा कि वह इस कुर्सी को छोड़कर कांग्रेस के विरुद्ध कार्य करें। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह अविश्वास का प्रस्ताव कांग्रेस के प्रति है या मन्त्रि परिषद् के प्रति है या इधर के बैठने वालों के प्रति है ? मैं बड़े गौरव के साथ यह कहना चाहता हूं कि इधर जो विधायक हैं वे माननीय काशीनाथ जी या विरोधीदल के नेता के चुने हुये नहीं हैं। ये विधायक तो विरोधीदल के लोगों की इच्छाओं को कुचलकर आये हैं। विरोधीदल का इस सरकार को बनानें में न पहले विश्वास था और न आज ही है और इस सरकार को बनाने में उनके विश्वास की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। हमारे कांग्रेस के चुने हुये जो विधायक यहां पर आये हैं, जनता ने पूर्ण विश्वास उनके ऊपर करके उनको यहां पर भेजा है। उन्होंने जो अपने लीडर को चुना है वह लीडर गवर्नर द्वारा आमन्त्रित किया गया यहां सरकार बनाने के लिये। जहां तक मैं समझता हूं इस अविश्वास के प्रस्ताव को किसी भ्रमवश रखा गया है। बालोजी अग्रवाल और चन्द्रजीत यादव जी ने कहा है और दूसरे भाइयों ने भी उनके समर्थन में बोलते हुये हमारी आपसी गुटबन्दी और गोविन्दसहाय जी की स्पीच का संकेत किया। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं दही के भरोसे आप कपास न खालें। यह आज रात्रि में आपको मालूम हो जायगा कि हमारे अन्दर गुटबन्दी है, देखिये इस प्रस्ताव का परिणाम क्या होता है ?

मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि अध्यापकों के प्रति इतनी सहानुभूति और उनके ही विषय को लेकर अविश्वास के प्रस्ताव को आज ले आये क्योंकि नेता विरोधीदल के भाषण में जो कुछ कहा गया उसका लब्बोलुवाब यही था कि अध्यापकों के प्रति उनकी बड़ी सहानुभूति

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

है। जैसा गेंदासिंह जी ने कहा यदि आपको अध्यापकों के प्रति वास्तविक सहानुभूति थी तो आज अविश्वास का प्रस्ताव न लाकर अध्यापकों के मसले पर २ घंटे का यहां पर डिस्कशन करते और सरकार का ध्यान आकर्षित करते और सम्भवतः उससे उनको लाभ पहुंचता। लेकिन मैं तो यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल को कोई सहानुभूति अध्यापकों के साथ नहीं है। एक ऐसी प्रज्वलित अग्नि की लपटों में उसको आहुति बना कर डाल दिया गया है जो रामसुन्दर जी के शब्दों में स्वाहा होना ही है। उसमें सफलता नहीं मिलने वाली है।

अध्यापकों के विषय में, यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका स्थान एक ऊंचा स्थान है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हममें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर किसी न किसी गुरु का भार न हो। गुरू के बनाये हुये ही हम लोग यहां सब हैं। उन गुरुओं का एक एशोसियेशन है, उसमें हम सबों के गुरू हों अथवा न हों लेकिन बहुत से उसमें शालिम हैं। मुझे बड़ा असमंजस होता है नेता विरोधी दल की बात सुनकर जिन्होंने अध्यापकों के प्रति यह बनावटी सहानुभूति दिखलायी। माता के कुक्ष में मनुष्य आ कर पलता है, वह उसका पालन पोषण करती है, पिता उसे शिक्षा देता है, किन्तु आचार्य उसे मनुष्य बनाता है। यह हमारी संस्कृति रही है। भारत का इतिहास रहा है कि गुरू चुटकी चुटकी भीख मांग कर भी शिक्षा देता रहा है। आज उनको गुमराह करने के लिये जो प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिये मैं नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि उनका जिन्होंने घोर विरोध किया था वही साम्यवादी दल के लोग खुले दिल से आज उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने यहां तक कहा कि यह चिन्गारी विद्यार्थियों में लग कर सबको भस्म कर देगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस चिनगारी को पसंद करेंगे? क्या आप उस सर्वनाशकारी साम्यवादी प्रवृत्ति को पसंद करेंगे? यदि आप उसे पसंद करें तो मुझे खुशी है, लेकिन मुझे एक भ्रम हुआ और वह भ्रम सही है। माननीय चन्द्रजीत जी ने, जो प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे थे, अपने असली रूप को खोल कर रख दिया। उन्होंने स्पष्ट-शब्दों में कहा कि अध्यापकों की मांग पूरी हो कर रहेगी। जिस भावना और विश्वास के साथ उन्होंने अपनी बात कही है, मैं समझता हूं कि नेता विरोधीदल उससे सहमत नहीं होंगे। जिस भावना को वह प्रोत्साहन देना चाहते हैं नेता जनसंघ उसे कतई स्वीकार करेंगे नहीं, यह मेरा विश्वास है। यदि आप इस अविश्वास के प्रस्ताव में साम्यवादियों के साथ रह कर उस भावना को प्रोत्साहित करना चाहते हों तो मैं समझता हूं कि आपको अध्यापकों से कोई सहानुभूति नहीं है। माननीय चन्द्रजीत जी ने बड़े गर्व के साथ एक दलील दी। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के समर्थन में कोई नयी बात नहीं कही गयी। वही सब पिटीपिटायी बात है। माननीय ठाकुर साहब कहा करते हैं कि टेप रेकार्ड लगा दिया जाय और वह बार-बार बजा दिया जाया करे तो उठने बैठने का कष्ट न हो।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

यह तो समझ की बात है।

श्री बंसतलाल शर्मा---

माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा कि ५२ में कांग्रेस कितने प्रतिशत से जीती थी, ५७ में कितने से जीती, और ६२ मे कितने प्रतिशत से जीती इसे देखा जाय। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज भी इस भारी बहुमत का इधर कारण क्या है? इसका एक मात्र जवाब उनके पास यही हो सकता है कि विरोधीदल के अनेक लोग खड़े हो जाते हैं। मैं नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि पहले अपने घर को सम्हालिये और सब लोग मिलकर एक बार कोशिश कर लीजिये। लेकिन यह उनकी करनी में संभव नहीं है। आप हम लोगों को हटाना चाहते हैं, लेकिन "पिछले पांव उठाइये देख धरन की ओर" आप कौन से दल को ला कर बैठाना चाहते हैं? आपकी आशा में सामन्जस्य की नीति नहीं है और स्वप्न देखते हैं इस सरकार को हटाने के

बजट सेशन चल रहा है, मगर ऐसे समय में भी अविश्वास का प्रस्ताव लाकर व्यर्थ समय नष्ट करना चाहते हैं।

अध्यापकों के विषय में माननीय नेता विरोधीदल ने कहा कि अध्यापकों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिलना चाहिये, मैं भी इसका स्वागत करता हूं। अध्यापकों के साथ आप से ज्यादा सहानुभूति हमारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने हायरसेकेन्डरी स्कूल्स और इन्टर कालिज ऐसे हैं जिनका मैनेजमेंट आपके हाथों में है? मुश्किल से एक दो होंगे। बाकी हम लोगों के हाथों में हैं। तो हमको भी उनसे सहानुभूति है, मगर अगर कोई यह चाहेगा कि हम दबाव डालकर कुछ करवा लें तो यह नहीं होगा और जिस तरह से २८ हजार पटवारियों को उनके अनुचित कार्य के लिये हटाया गया, उनको सबक मिला, इन अध्यापकों को भी यदि वे किसी के कुचक्र में पड़े वही सबक मिलेगा। अगर उनको महंगायी के लिये अपनी मांग रखना है, तो उसके लिये जो सही रास्ता है उसको वे अपनायें, न कि इस तरह से आन्दोलन करके ५ लाख बच्चों का भविष्य नष्ट कर दें। इससे जन सहानुभूति वे प्राप्त न कर पायेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बार बार यह दुहाई दी जाती है कि यह अपोजीशन एक नहीं है, जन संघ को सत्ता मिलेगी, या कम्युनिस्टों को या एस० एस० पी० को। बार-बार लड़ाने की भी कोशिश की जाती है। मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आप पहले अपनी कुर्सी छोड़ कर भागिये, हम कम्युनिस्टों का, एस० एस० पी० का समझौता बाद में देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यह बात कहता हूं कि आपको हटाने के लिये हम सब अपोजीशन वाले एक हैं, और एक दिन सरकार बनायेंगे। आप जैसे लोगों से तो जनसंघ अच्छा है, सभी अच्छे हैं, क्योंकि आपके कौल-फेर का तो कोई एतबार नहीं है, समाजवाद का केवल ढोंग रच रखा है। मुझे दृश्य याद आता है कि जब अंग्रेजी सरकार ने हमसे यह कहा था कि पहले तुम एक हो जाओ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो जाय, तब हम आजादी देंगे, यहां से जायेंगे। उस स्थिति को दोहराने की जरूरत नहीं है, हमने उस समय यही उनसे कहा था कि पहले तुम यहां से हटो, हम लोग आपस मे निपट लेंगे। उसी तरह आज हमारी यही मांग है कि पहले आप कुर्सी छोड़िये, हम सम्भाल लेंगे, उसी नारे को मैं आज भी बुलन्द करता हूं।

चुनाव, जनता की भावनाओं का दिग्दर्शन होता है। आप किस तरह से चुनाव जीतते हैं। बांसी का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यदि कांग्रेसी व्यक्ति यहां से जीतता है तो उसकी बात मैं सुनूंगी, उसका काम जल्दी होगा, दूसरा और कोई जीतता है तो उसकी बात नहीं सुनी जायेगी। इस तरह के भाषण होते हैं, और फिर वहां के बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, एस० पी०, डी० वाई० एस० पी० वगैरह सब के सब चुनाव में उनकी तरफ से कार्य करते हैं, कोने कोने तक जीप दौड़ती है, ऐसी स्थिति में आप क्या नहीं करते होंगे, इस तरह से आप चुनाव अगर जीतते भी हैं तो वह जनता की भावनाओं का सही दिग्दर्शन नहीं है। अगर कहीं आप की जीत हो गयी तो उससे यह मत समझिये कि जनता आप के साथ है। मैं तो आपको चुनौती देता हूं कि आप अगले ६७ के एलेक्शन में इन सीटों पर दिखाई दे जायं तो जिम्मा मेरा रहे। आज हम लोगों को टीचर्स के लिए आप एक अध्यात्मवाद और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, कहते हैं कि अध्यात्मवाद की ओर जाना चाहिए, लेकिन आप ने सबको एक भंवर में डाल दिया, मंझधार में छोड़ दिया, टीचरों को मजबूर कर दिया कि वह इस हथियार को उठायें मैं कहता हूं कि यह सबसे मजबूत हथियार है और यह तो आप को फायदा करा रहा है। वह फायदा यह करा रहा है, न तो आपसे वह इनविजिलेशन का पैसा लेंगे और न कापियों के जांचने का पैसा लेंगे। आपका तो पैसा बच रहा है, आप क्यों परेशानी में पड़े हुए हैं? मैं कहना चाहता हूं कि आप इनविजीलेशन करवा लेंगे, गार्डी करवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे, लेकिन कापियां

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

कौन जाचेगा, क्या आप लोग बैठ कर जांचेंगे। अगर आप कापियां जांचेंगे, तो जैसे प्रदेश की जनता के साथ न्याय आप कर रहे हैं, वैसे छात्रों के साथ भी आप न्याय करेंगे,। दूसरी बात, मैथमेटिक्स की कापियां तो जांच लेंगे, केशभानराय जैसे आदमी, क्योंकि एलजबरा, ज्योमेटरी में बहुत तेज हैं, लेकिन गृह विज्ञान की कापियां क्या सुचेताजी जाचेंगी ?

यह अविश्वास का प्रस्ताव आपके खिलाफ बड़ी गम्भीर परिस्थितियों में लाया गया है। आपने हमको भूखों मार डाला। श्रीमन्, आप भी देख रहे हैं कि जिस तेजी के साथ हम लोग बोला करते थे, अब वह तेजी भी हमारे बोलने में नहीं रही, क्योंकि खाना मिलता नहीं। यह बात अलग है कि उधर के बैठने वालों की आवाज और तेज हो गई है। आप नैतिकता का पाठ उन्हें पढ़ाते हैं और हमसे कहते हैं कि अध्यापकों के साथ सहानुभूति न रखिये। आप अध्यापकों को जेल में डालने की और पटवारियों की तरह बरखवास्त करने को धमकी देते हैं, और हमसे कहते हैं कि आप चुपचाप सुनते रहें। मैं बता देना चाहता हूं, बुद्धिजीवी वर्ग के अन्दर इस ट्रेड यूनियन की मेंटलिटी का आ जाना यह आप के विनाश का लक्षण है, आपकी सरकार अब रह नही सकेगी ? जिस दिन शिक्षकों के साथ इस तरह का जुल्म करने का कदम आपने उठाया। नैतिकता की बात आप हमसे क्यों करते हैं ? जबकि आप खुद नैतिकता का पालन नहीं करते। आपने शासन में बैठ कर और इन कुर्सियों पर बैठ कर किस नैतिकता का पालन किया है ? दो मिनिस्टरों के बारे में तो अभी माननीय काशीनाथ जी ने बताया, अपने यहां के मिनिस्टर की बात बताता हू कि वह नैतिकता के कितने पुजारी हैं। श्रीमन्, पहले भी मैंने कहा था, फिर कह दूं राम मूर्तिजी के बारे में, पहली बात तो कुनबा परस्तो की हद उन्होंने कर दी है। कुनबा परस्त उनके जोड़ का कोई दूसरा मिनिस्टर आप की कैबिनेट में नहीं मिलेगा। उनके साढ़ू तथा ममेरे भाई.....

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

अधिष्ठाता महोदय, जो सदन में मौजूद न हो क्या उसके बारे में.....

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, उनको सदन में रहना चाहिए। आप कृपा करके बैठें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि माननीया सुचेता जी जांच करें, हम किस प्रकार से इस मंत्रिमंडल में विश्वास रखें, जबकि इस-इस प्रकार के भ्रष्टाचारी और कुनबापरस्त लोग आपके मंत्रिमंडल में मौजूद हैं। उन्होंने क्या किया कि जब से वे एम० एल० ए० बने, उस जमाने से उनके साढ़ जो ममेरे भाई भी होते हैं, वह स्पेशल मैजिस्ट्रेट बरेली में हैं, और बराबर चले आ रहे हैं। चौराहे पर खड़े हो कर आप पूछ लीजिए कि रिश्वत लेकर कौन मैजिस्ट्रेट खुले आम काम करता है, सभी कह देंगे कि श्री भुवन चंद्र स्पेशल मैजिस्ट्रेट ईमानदार इतने हैं कि दोनों ओर से रिश्वत लेकर, जिसका काम नहीं होता, उसका रुपया लौटा देते हैं।

एक सदस्य—

अधिष्ठाता महोदय, यह व्यक्तिगत आक्षेप है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, संसदीय प्रणाली में यह हो सकता है।

श्री हरीशकुमार गगवार—

श्रीमन्, अखबारों में आया था, जिस मैजिस्ट्रेट की अदालत में जिस मैजिस्ट्रेट के मुंह पर जूता फेंक कर मारा गया था वह यही मैजिस्ट्रट साहब थे। उसने इनके ऊपर चार्ज लगाया कि

मुझसे हजारों रुपया इन्होंने ले लिया। यह राममूर्ति जी के साढ़ू और ममेरे भाई लगते हैं, इनका नाम भुवनचंद है। आंवले में इनके सगे बहनोई राम औतार सेक्रेटरी हैं, पहले सुरेश साढ़ू के भाई थे, जिन्हें अब कैम्फर में साढ़े आठ सौ रुपये पर लगवा दिया। बहेड़ी में हरीश तीसरे साढ़ू के भाई और सगे मामा के लड़के इनके हैं। चौथे साढ़ू के भाई को चुर्क सीमेंट की एजेन्सी दिलाई है। पीलीभीत म्युनिसिपल बोर्ड में सबसे बड़ा घपला किया है, वहां राममूर्ति जी के सगे साले, जो हाई स्कूल पास हैं, उनको रखवा दिया। आवेदन-पत्र में दरबारी-लालजी के दामाद जो बी० ए० एल० एल० बी० हैं, वे भी बैठे थे, लेकिन उन्हें न लकर हाई स्कूल पास को रखा और मंत्री जी ने कहा कि इन्हें क्वालीफिकेशन से इक्जेम्प्ट कर दो। गौतमजी ने इक्जेम्प्ट नहीं किया, तो पंत जी के जाने के बाद गौतमजी को हटाया और दूसरे से इक्जेम्प्ट कराया। अपने दामाद को सिंचाई में सहायक इन्जीनियर बनाया और कई आदमियों का हक मारकर विदेश भेजा और लौटकर आने पर कई व्यक्तियों का हक मार कर प्रोमोट किया। फिर श्रीमन्, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम यह किया कि जब सीलिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो अपने ५०० एकड़ के फार्म में शांतिप्रपन्न जी का नाम और कृष्णलाल, भुवनचंद, और शिव-नारायण आदि अनेक व्यक्तियों के नाम तथा २५–३० व्यक्तियों के नाम डलवा दिये। शांति प्रपन्न जी ने पिछले साल अपना नाम कटाया है। अपने फार्म तक सड़क बनवाई और फिर ट्यूबवेल लगवाया और बिजली लगवाई, सब सरकारी खर्चे पर, अपना एक भी पैसा नहीं दिया।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि भावनायें बदलती रहती हैं। यह बात सही है। अभी इसी सदन में जबसे चुनाव हुआ उसके बाद यहां जो विधायक के रूप में आये और जो उनके साथ थे उनकी भावनायें, इनके कृत्यों को देख कर बदलीं और करीब २५ विधायक उधर से इधर को चले आये। तो यह विधायकों की भावनायें बदलीं और मत-दाताओं की भी भावनायें बदलीं। जिन क्षेत्रों से पहले यह चुनकर आये थे उन क्षेत्रों से अब हमारे साथी चुनकर आये। इस तरीके से इनके कृत्यों को देख कर भावनायें बदलीं और इसी तरह से बदलती रहेंगी।

बड़ा जिक्र हमारी गुटबन्दी का किया गया, लेकिन अपनी गुटबन्दी को नहीं देखा। हमसे कहते हैं कि हम चलें जायें, अरे, हमारे रहते तो यह हाल है कि एक दूसरे को कहते हो कि फांसी डलवा दो, गोली मार दो और जब हम चले जायेंगे तो क्या हाल होगा, भगवान जाने? हम ऐसे नादान नहीं हैं कि आपको इस दशा में छोड़ कर चले जायं। हम छोड़ कर चले जायं तो यह जनता के साथ विश्वासघात होगा। आप हमारी बात करते हैं, जरा अपनी बात को सोचें। आपके अपने दल में झंडे दो, नेता दो, नारे दो और उस झन्डे के डन्डे से एक दूसरे का सिर आप फोड़ते हैं, उस पर भी हमसे कहने का साहस करते हैं।

इस अविश्वास के प्रस्ताव का सारा लब्बोलवाब जो रहा वह अध्यापकों का मामला रहा। इशारा किया गया कि अगर आप अध्यापक के मसले को हल नहीं करते हैं तो विद्यार्थियों को भी इसमें उभारा जायगा कि इसमें शामिल हों। यह कहां तक उचित है? राहत मौलाई साहब ने भाषा की बात की। जब चीन ने हमारी जमीन पर अधिकार कर रखा है तो उसे उससे छुड़ाना है, और वह हमारे दरवाजे पर खड़ा है, उस समय आप ऐसी बात करते हैं कि हम दक्षिण जैसी हालत कर देंगे। इस संकट के अवसर पर आप सेक्रेटेरियेट के कर्मचारियों को उभार रहे हैं, अध्यापकों को उभार रहे हैं और जब इसमें कामयाबी नजर नहीं आई तो आप विद्यार्थियों को उभारने की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि राहत मौलाई साहब के लिये संकट का समय नहीं है, लेकिन वह इस देश के हर नागरिक के लिये है। अध्यापकों के प्रति हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

सबको हमदर्दी है। न केवल अध्यापकों लिये बल्कि हर उस कर्मचारी के लिये और नागरिक के लिए जिस की आय कम है।

आपके ही शब्दों में ३ आने से ८ आने तक रोजाना आज खेत पर काम करने वाले मजदूर को मिलता है। बहुत से किसान इस प्रदेश में २ एकड़ से भी कम के हैं। अब आप ही सोचिये कि उन लोगों की क्या स्थिति है? जो शिक्षा के नींव के पत्थर या हड्डी हैं, प्राइमरी के अध्यापक उनको जो वेतन हम दे रहे हैं, उससे उनकी क्या स्थिति है? आप इस पर विचार करें कि वह करदाता, वह नागरिक और श्रमिक जो अपने खून-पसीने को बहाकर अन्नोत्पादन में लगा है, वह क्या सोचता है? क्या वह इसे पसन्द करेगा कि हम अपने खून को गाढ़ी कमाई सेक्रेटेरियेट में चन्द काम करने वालों के लिये, जिन्हें पहले ही ३००, ४०० रुपये मिलते हैं, दे दें? मैं मानता हू कि अध्यापकों को हम उतना पारिश्रमिक नहीं दे पा रहे हैं जितना कि होना चाहिये। लेकिन कठिनाई तो यह है कि एक तरफ आप खर्च बढ़वाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं कि टैक्स भी नहीं लगाना चाहिये। आज जब विद्यार्थी की परीक्षा का समय आया, जिसने साल भर परिश्रम किया है, उस समय अध्यापकों का यह कहना कि हम परीक्षा नहीं लेंगे, कहां तक उचित है? आपको मालूम है कि हमारे मौजूदा शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों के लिये त्रि-सूत्री योजना मैनेजमेन्ट्स से मनवाई और उनको सारी सुविधायें देने की कोशिश की। लेकिन हमें ७०, ७५ फ़ीसदी खेतों पर काम करने वाले लोगों की हालत को भी देखना है। उसका बच्चा जब परीक्षा देने जाता है तो अध्यापक का यह कहना कि उसको पढ़ई जहन्नुम में जाय, तो वह क्या सोचेगा? यह बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना है। लेकिन यह उन्हीं की बात नहीं है। यह तो सारी इस अविश्वास के प्रस्ताव की भूमिका और योजना की तैयारी है।

समाजवाद आपका नारा है। लेकिन इधर कहते हैं कि २००, ३०० रुपये माहवार पाने वालों को मंहगाई भत्ता अधिक दो और उन लोगों की आपको चिन्ता नहीं है जो बेचारे ५०, ६० और १०० रुपये ही पा रहे हैं। इस प्रकार कैसे समाजवाद आवेगा जबकि ऊंचे को आप ऊंचा करना चाहते हैं और नीचे वालों की आपको चिन्ता नहीं है? अध्यापक हमारे बच्चों के निर्माता हैं। बच्चा मां-बाप के पास २, ४ घंटे ही रहता है। लेकिन स्कूल में अध्यापक के पास तो ६, ७ घंटे रहता है। परीक्षा निकट है। सरकार को परचों की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी? क्या यह बात गलत है कि इस प्रकार की योजना आपकी तरफ से है कि परचों और कापियों में आग लगा दी जाय? लेकिन यह सरकार सजग है। सरकार पुलिस के दम पर या किसी और शक्ति के आधार पर परीक्षा नहीं लेना चाहती है। हम अपील करते हैं कि गुरूजन अपनी जिम्मेदारी को सम्भालें और जो गलत काम वह किसी प्रभाव में आकर कर रहे हैं उसकी वे गम्भीरता को सोचें। वे गुरू हैं। वे मिल मजदूर और रेल मजदूर नहीं हैं। ऐसे मौके का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा उन्हें नहीं करनी चाहिये। वे कह सकते थे कि जुलाई में हम विद्यालयों में नहीं जावेंगे। लेकिन यह कहना कि परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, हमारे गुरुओं के लिये शोभा नहीं देता।

मैं विरोधपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि वे इस बात पर विचार करें कि जो इशारा आज उन्होंने किया है कि विद्यार्थियों तक को इसमें शामिल करेंगे या शामिल होने की प्रेरणा वे देने वाले हैं तो भविष्य को वे सोचें कि वे कहां इस प्रदेश को ले जा रहे हैं और कहां वे विद्यार्थियों को बहकाना चाहते हैं और इससे कितनी हानि विद्यार्थियों की और प्रदेश की होगी? मैं अध्यापकों से बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि वे ठंडे दिल से सोचें। हम लोग उनके दुश्मन नहीं हैं। उनकी परिस्थितियों को हम जानते हैं। प्रदेशीय सरकार अपने साधनों को इकट्ठा करके प्रयत्न कर रही है कि उनकी सहायता करे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप का समय समाप्त।

श्री उग्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता जी, अविश्वास के प्रस्ताव पर सरकारी पक्ष के लोगों के भाषण को सुनकर मेरे मन में बड़ी गहरी ठेस लगी। मुझे याद आगया वह दृश्य और श्रीमन्, मैं आपको भी याद दिलाता हूं और आपके जरिये से माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि जब सुकरात अदालत के सामने खड़ा था तो अदालत ने यह कहा कि अगर तुम सच बोलते हो तो यह जहर का प्याला पी लो। तब सुकरात ने कहा कि हम तो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हम मरने के लिये आये हैं इसलिये हमारा मरना ही अच्छा है और आप कदाचित बने रहने के लिये ही आये हैं तो आपका बना रहना ही अच्छा है। आज उसी जज की सी मनःस्थिति उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को मालूम पड़ती है। वे समझते हैं कि वे यहां बैठने के लिये ही आये हैं और हम यहां मरने के लिये आये हैं। मैं आप को यह कह देना चाहता हूं कि अगर महात्मा बुद्ध का दर्शन सही है और हिन्दुस्तान के अन्य दार्शनिकों का दर्शन अगर सही है तो मुबारिक हो तुम को यह कुर्सी और हमको मरना मुबारिक हो।

(इस समय ५ बज कर ६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं ठाकुर साहब को ३० साल से जानता हूं। हमने अंग्रेजों के डंडे खा। लेकिन अब एक तमन्ना और है कि माननीय हरगोविन्दसिंह जी के डंडे और गालियां और मिल जायं। कम से कम माननीय रामायणराय जी के जमाने की एक बात तो याद रहेगी। माननीय गेंदासिंह जी से यह कह देना चाहता हूं और माननीय झारखंडेराय जी को याद दिला देना चाहता हूं कि जब माननीय गेंदासिंह जी इधर बैठते थे तो १६ पाव का गेहूं बिकता था, लेकिन जब २ पाव का गेहूं बिक रहा है तो माननीय गेंदासिंह जी माननीया सुचेता जी की बगल में चले गये। बैलों की जोड़ी में चले गये हैं। आज देवरिया में, जहां के वे रहने वाले हैं घास भूसा का भी इन्तजाम नहीं है, ५ हजार बैल भूखों मर गये देवरिया में। और पशुपालन विभाग के माननीय डायरेक्टर महाजन महोदय पी०ए०सी० में बता रहे थे कि अंग्रेजी डायरेक्टर के जमाने में सरकारी फार्म से मुर्गा १३ रुपये जोड़ी का मिलता था। लेकिन १५ अगस्त, १९४७ को जब कांग्रेस राज्य हो गया तो हुक्म दिया गया कि ३ रुपये में मुर्गा दिया जाय और १० रुपया सरकार दे। मैंने पूछा कि अगर १३ रुपये में ही दिया जाता तो कितना रुपया सरकार को मिलता? तो मालूम हुआ कि ४५ लाख रुपया। पशुपालन विभाग ४५ लाख रुपये के मुर्गे खा गया और देवरिया में ५ हजार बैल बिना भूसा घास के मर गये और इसी देवरिया से माननीय गेंदासिंह जी आते हैं।

सारे हिन्दुस्तान की प्रति व्यक्ति आय है १९४ रुपया देवरिया की है १५६ रु० और जौनपुर की, जहां के माननीय हरगोविन्दसिंह जी हैं, १६६ है और माननीय अलीजहीर जी आपका कुत्ता तो ३–३ बार हलुआपूरी खाये और मेरा बच्चा अंठलो की रोटी के लिये भी तरसे। मैं विरोधी पक्ष से कह देना चाहता हूं कि आज स्थिति आ गयी है कि आप अपनी ताकत को अजमायें। आपके हाथ में वह ताकत है कि आप चुनावों में इस सरकार को लात मारकर निकल सकते हैं और जनता को बचा सकते हैं। आप तो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। अगर हमको इन कुर्सियों पर चिपके रहना होता तो आचार्य नरेन्द्र देव और सेठ दामोदर स्वरूप के साथ हम लोग भी कांटों से भरे जंगली रास्ते पर न निकल जाते।

आज कुरबानी करना हमने अपने परिश्रम से सीखा है। अगर आप भी दुनियां का मजा लेना चाहते हो तो कुरबानी करके देखो।

आज मंत्रियों के बारे में क्या कहूं। मुजफ्फर साहब के बारे में माननीया सुचेता जी ने कहा कि जज बैठाया जायगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन जज बैठा? कितने जज बैठेंगे? तमाम मन्त्रियों के लिये जज बैठा दीजिये। उनको आप एक मामला सास वाला ही देंगे या सब मामले देंगे और सब मंत्रियों के बारे में बैठायेंगे? आज आप सब मंत्रियों के खिलाफ जांच बैठा दें और यह जांच करायें कि जब वे एम० एल० ए० नहीं थे तो उनकी

[श्री उग्रसेन]

क्या हैसियत थी और आज उनकी क्या हैसियत है और जितने विरोधी दल के नेता हैं, उनमें छोटे नेता भी हैं और बड़े नेता भी हैं, उग्रसेन भी उसमें हैं, इसका फैसला करने के लिये किसी जज को दे दिया जाय और वह कह दे कि इनको गोली मार दी जाय तो सब को गोली मार दी जाय। चाहे हम मर जायं, लेकिन अपने साथ इन लोगों को लेकर तो जायेंगे, क्या यह कोई कम होगा ?

नौकरशाही की चर्चा आप करते हैं। आज आप ने हमारी भारत मां की जबान को काट लिया है। उत्तर प्रदेश की झोपड़ियों में रहने वाले और दिन-रात मेहनत करने-वालों की जबान को हुकूमत ने काट लिया। इसको इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। माननीय रामायणराय जी मेरे साथ पढ़े हैं और वे नवयुवक संघ में रहे हैं, यह बौद्ध धर्म दर्शन का इतिहास है जिसे हमारे गुरु आचार्य नरेन्द्र देव ने हिन्दी में लिखा है। तो अध्यापकों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हैं, उसे हिन्दुस्तानी दर्जा देना चाहते हैं, उर्दू साहित्य को स्थान देना चाहते हैं तो आप को वही करना पड़ेगा जो इसमें लिखा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी हिन्दी के प्रकांड विद्वान अपने को बतलाते हैं और यूनिवर्सिटी से बड़ी-बड़ी डिग्री ले कर आये हैं ये महाराज भारत माता की जबान को नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आप यह जो कहते हैं जनता का विश्वास आप के अन्दर है इसीलिये आप बर बर जीत कर चले आते हैं, वरना हार जाते, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यही उसके विभाग की कमजोरी है जिससे आप जीत कर चले आते हैं। एक पोलिश साहित्यकार डिजरेस्की ने लिखा है कि जार जब जनता द्वारा कैद था तो उस समय भी कुछ वह बैठा हुआ हुक्मनामा जारी कर रहा था। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि वह कैद है। उसी तरह से यह सरकार भी आज जनता जनार्दन की क्रान्तिकारी भावनाओं के अन्दर बन्दी है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही है।

अभी जो महाशय बोल रहे थे वे भी अध्यापक हैं और जब वे मंत्री थे तो उस समय का एक वाक्य मुझे याद आ गया जो उन्होंने कहा था—"और अंग्रेजी नहीं चलेगी तो हमारे लड़कों को नौकरी कैसे मिलेगी।" यह लार्ड मेकाले के मानस पुत्र जैसे आदमियों की भावना मालूम पड़ती है। जो अध्यापक हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि हे वशिष्ठ, हे विश्वामित्र, हे द्रोणाचार्य उठो और शंखनाद करो, तुम्हारे शंखनाद से इस देश और प्रदेश की जनता जागेगी। बंगाल जग गया, आंध्र जग गया, पंजाब जग गया, और अब तुम भी दूसरे महायज्ञ के लिये शंखनाद करो जिससे और करोड़ों-करोड़ों की आवाज दब न जाय, जिसे यह सरकार डी० आई० आर० के जरिये दबाना चाहती है। कहा गया है कि ये देश के दुश्मन हैं। मैं कहता हूं कि चीन, तकलाकोट और बद्रीनाथ के माना गांव तक किसके राज्य में आया ? कालीदास के कुमारसम्भव में एक श्लोक है जिसमें दिया हुआ है—

"अस्त्युत्तरएआं दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः,

पूर्वापरौ तोयनिधि नगाश्च स्थितः पृथिव्या इवमान दंडः"।

अर्थात्—"पहाड़ों के देवता, दिशाओं की आत्मा, हिमालय पूर्व पश्चिम समुद्र के बीच दुनिया को थाम रहा है"।

क्या इस तरह की कोई मिसाल किसी कवि की चीनी साहित्य में मिल सकती है ?

तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता कहना चाहती है कि आप ज्वाला-मुखी पर बैठे हुए हैं। श्रीमन्, आज ऊपर के लोगों में भी भ्रष्टाचार घर कर गया है। यह गंगोत्री और यमुनोत्री का कीचड़ नहीं है बल्कि गोमती का कीचड़ है जो यहां और दिल्ली की गद्दे में चिपकी हुई है, उसे साफ करना होगा।

आखिर सब्र की भी हद होती है। मजदूरों को बोनस देने की बात बोनस कमीशन द्वारा तय हुई थी, लेकिन विक्टोरिया मिल के मजदूरों को बोनस न देने की कोशिश की जा रही है।

अरे तुम तो टाटा, बिरला से भी गये गुजरे हो, तुम तो पूंजीपतियों की पूंजीपरस्त नीति को चलाने की जिम्मेदारी लिये हो। अंग्रेज तो एक प्रगतिशील पूंजीवादी था, लेकिन तुम तो भंदू किस्म का पूंजीवाद पैदा कर रहे हो। आप की खामखयाली है आज उसको छोड़ें, आज नये कांग्रेसी और पुराने कांग्रेसी जिस धरातल पर बैठे हैं वह कुर्सी नीचे से जल रही है, सुलग रही है लेकिन दिल बहलाने को गालिब खयाल अच्छा है। नौकरशाही की और चीफ सेक्रेटरी से नीचे तक के अफिसरों की दशा में क्या कहूं, एक शेर याद आता है कि

"एक शोर मचा है गुलशन में, बतलाओ मेहरबां क्या होगा
हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अन्जामे गुलिस्तां क्या होगा ।

जब यह हालत हो तो यह सरकार कैसे रह सकती है ? मैं आज जनता से कहना चाहता हूं, जनता के नेताओं से कहना चाहता हूं, बहुत जोर की आवाज से कहना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक उन में केवल असंतोष ही पैदा किया है अब आप इनके प्रति घृणा पैदा कीजिये और तभी बगावत सम्भव होगी और यह इन कुर्सियों से हटेंगे। यह जायं यहां से और बाद में पता नहीं कि अल्लामियां इन्हें माफ करेंगे या नहीं या कयामत के दिन इनको क्या क्या दंड देंगे? मैं अन्त में कहता हूं कि अब सरकार में रहने की, सरकार चलाने की आप में क्षमता नहीं रह गई है। आप जायं जल्द जायं, जितनी जल्दी जायेंगे उतना ही जनता का भला होगा।

*श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधीदल द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं। मैं यह विरोध इसलिये नहीं करता कि यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल के द्वारा लाया गया है, मैं इसलिये भी इस का विरोध नहीं करता कि मुझे मालूम है कि यह प्रस्ताव गिर जायगा, मैं इसलिये भी इसका विरोध नहीं करता कि उनको इसको लाने का अधिकार नहीं है बल्कि मैं इसका विरोध इसलिये करता हूं कि हमारे नेता विरोधीदल के पास जो एक आखिरी तीर था उसको उन्होंने इतना सस्ता बना दिया है कि वह जब चाहते हैं उसको चला देते हैं। प्रजातंत्र में कुछ मान्यतायें होती हैं, कुछ परम्परायें होती हैं और उनके अनुसार वह ऐसे समय में लाना चाहिये और लाया जाता है जबकि सभी अन्य तरीके खत्म हो जाते हैं और खास तरीके से सरकार में अविश्वास पैदा हो जाय लेकिन मौके बेमौके, आये दिन चाहे बजट चल रहा हो, चाहे गवर्नर के एड्रेस पर अभी बहस हो चुकी हो, सारी आलोचनायें की जा चुकी हों, लेकिन फिर भी उन्हीं पुरानी बातों को, पुरानी कहानियों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होता। . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

बातें बहुत हो रही हैं।

श्री जगवीरसिंह—

माननीय नेता विरोधीदल को इस सदन में मैं कई वर्ष से सुनता रहा हूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जितना खराब भाषण उनका हुआ है उसको सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई और नेता विरोधीदल का इस तरह का भाषण मैंने कभी नहीं सुना। बहुत सी बातें उधर से कही गईं। माननीय रामसुन्दर जी ने बहुत सी बातें कहीं और बहुत से तर्क उधर से दिये गये। एक खास बात यह कही गई कि सरकार इस्तीफा दे दे, हम चाहे गवर्नमेंट बना पायें या न बना पायें और जनता बाद में अपना फैसला करेगी। मैं अपने विरोधीपक्ष के दोस्तों से कहूंगा कि जनता तो हर पांचवें साल फैसला देती है और अब से डेढ़ साल बाद जनता फिर फैसला करेगी कि कांग्रेस सरकार कामयाब रही है या नाकामयाब रही है। हमने जनता की सेवा की है या नहीं की है, इसका फैसला डेढ़ साल बाद हो जायगा, लेकिन अगर आप को यहां बैठकर यह मुगालता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगवीरसिंह]

हो गया है कि जनता आप के साथ अब हो गई है तो पहले आप, इस्तीफा उधर वाले दें, और फिर चुनाव लड़ें और अगर फिर आप चुनकर आ जायेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, अगर आप में से ५० प्रतिशत भी लौट आयेंगे तो यह कांग्रेस सरकार भी इस्तीफा दे देगी। पहले आप इस्तीफा दीजिये। मैं समझता हूं कि हमारे दोस्तों की कहने की बातें और हैं करने के लिये बातें और हैं।

माननीय गंगवार जी ने कहा था कि आप इस्तीफा दे दें हम सब एक हो जायेंगे, हमारी गोली नहीं चलेगी, हम पेट नहीं फाड़ेंगे। मैं समझ पाया कि क्या होगा अगर इस प्रदेश की बागडोर आपके हाथ में होगी? माननीय राधेश्याम जी ने लेनिन से लेकर आज तक के विचारकों के कुछ वाक्य पढ़ें। लेकिन मैं गांधी जी के एक वाक्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था जनता को कि "जो उनकी बातें न कर सके उसको हटाना चाहिये।" ठीक है जनता अगर हमको हटाती है तो हमको एतराज नहीं है और न किसी को होना भी चाहिये। जब जनता का विश्वास हम में नहीं होगा तो हम नहीं होंगे और हमारी जगह आप होंगे। हो सकता है आपका बहुमत इतना हो कि हमको आने ही न दें। लेकिन इसको जनता पर ही छोड़िये और हमको मौका दीजिये कि हम काम करें। मैं सोक्रेटीज का एक वाक्य बताना चाहता हूं ("If wisemen give up ruling the world, unwisemen would come in.") अगर समझदार आदमी शासन करना छोड़ देंगे तो बेसमझ उनकी जगह आ जायेंगे। हम हुकूमत करते रहेंगे और उन नादान दोस्तों को जो प्रदेश को गड्ढे में ले जाना चाहते हैं या प्रतिक्रियावादी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं या माननीय चन्द्रजीत यादव जी के स्वप्न को पूरा करना चाहते हैं, हम उनके हाथ में नहीं छोड़ेंगे, जनता के हाथ में छोड़ेंगे।

उर्दू में एक कहावत है कि जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले। माननीय काशीनाथ जी ने जिक्र किया अध्यापकों का। मैं भी उसका जिक्र जरूरी समझता हूं। लेकिन उन्होंने एक बात कह दी जिससे मुझे चिन्ता है। उन्होंने कहा हमको इस मोर्चे को बल देना चाहिये ताकि हम सरकार को हटा सकें। इसके माने यह हुए कि उनका अध्यापकों से बहुत प्रेम नहीं है, वह उनको केवल एक टूल बनाना चाहते हैं और पोलिटिकल कैपिटल उससे निकालना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इससे पोलिटिकल कैपिटल न बनावें। वह सोचें कि जनता ने उनको चुनकर भेजा है। अतः वह ५ लाख बच्चों तथा अध्यापकों के साथ खिलवाड़ न करें। मैं यह कह देना आवश्यक समझता हूं कि मेरी नजर में मास्टरों की मांग न्यायोचित है, और एक बात जरूर समझता हूं, हो सकता है कुछ मेरे मित्रों को इधर के वह बात प्रिय न मालूम हो, मेरे विचार से अध्यापकों के मामले को जिस तरीके से टैकिल किया गया है उसमें कुछ भूल जरूर है। अगर यहां से प्रयत्न किये जाते तो कुछ फैसला हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को लिया गया है मेरा, अपना विचार है कि उसमें कुछ भूल जरूर रही है, अब कहीं रही हो यह मैं नहीं जानता कि किस तरफ से भूल हुई। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, माननीय नेता विरोधीदल ने किसलिये वह बात कही मैं नहीं जानता, इसके नतायज बुरे हो सकते हैं, लेकिन एक पैरेन्ट के नाते जिसका लड़का इम्तहान में बैठ रहा हो उस पेरेन्ट को, आज जिसके बच्चे इम्तहान में बैठ रहे हैं यह फीलिंग है कि हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। मुझे चिन्ता है कि मास्टरों से लड़ाई के बाद इम्तहान ठीक प्रकार से हो पायेंगे, या नहीं। आज उन बच्चों के लिए अध्यापकों से फैसला किया जाय। अगर कोई तरीका न हो तो मेरा विश्वास है कि अध्यापकों की लड़ाई के बाद हम इम्तहान नहीं करा सकते हैं। जिन बच्चों को अध्यापकों ने सालों साल पढ़ाया है तो क्या उनका यह कर्त्तव्य है कि उन बच्चों के इम्तहान के समय यह कहते हैं कि हम इंविजिलेशन नहीं करेंगे। लड़ाई जैसे चाहें लड़ें, लेकिन आज ५ लाख बच्चे हैं जिनसे वे आशा करते हैं, कि वे उनकी ज्यादा इज्जत करें अपने माता पिता से भी ज्यादा, तो अध्यापकों का कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें। सरकार उनकी बात माने मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन आज अध्यापकों का कर्त्तव्य हो जाता है कि वे भी इस मांग को और तरह से रखें, लेकिन बच्चों के इम्तहान जरूर होवें। किसी कारण से भी हम इम्तहान में उनके साथ

खिलवाड़ न करें। मेरा अपना विचार है कि अगर हमारे बच्चे इम्तहान देना चाहते हैं तो उनसे इम्तहान दिलाया जाय। माननीय काशीनाथ जी ने कहा कि हम इस मोर्चे पर अड़े रहना चाहते हैं। उनको चाहिये कि हम इस मोर्चे को समाप्त करें। हमें अध्यापकों और बच्चों को समझना होगा।

मैं इन शब्दों के साथ आपके इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं, अविश्वास का प्रस्ताव जो सरकार पर आया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभी-अभी इस समय आज के भाषण जो सदन में हुए उनमें मास्टरों के विषय में बहुत ज्यादा समय लिया गया श्रीमन्, यह सही है कि नालायक बच्चे से भी मां सबसे अधिक प्यार करती है बिलकुल स्पष्ट है लेकिन यह दुर्भाग्य है कि मां लायक बच्चे को भी प्यार न करे। तो श्रीमन्, दुर्भाग्य होगा इस प्रदेश का यदि ऐसा हुआ। ये अध्यापक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं। प्रधान मंत्री से लेकर, विधायक और बड़े और छोटे उनके ही जरिये आगे आते हैं लेकिन आज आप उनको कितनी तनख्वाह देते हैं। थानेदार की तनख्वाह १५० रुपये और महंगाई भत्ता अलग से, लेकिन जो हमारे मास्टर बी० ए०, बी० ए०बी०टी० या बी०ए०,एल०टी० होते हैं उनको आप कितना वेतन देते हैं? यह सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। ज्वालामुखी के मुंह में आप वर्तमान परिस्थिति में सूबे के विद्यार्थियों को ले जायेंगे। यह बड़ा दुःखदायी है। आसानी से आप इसको कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर वहां के और यहां के लोगों को लेकर और अध्यापकों से बातचीत करके कोई रास्ता निकालें जिसने प्रान्त के ५ लाख बच्चों का जीवन अन्धकारमय न बन जाय।

जहां तक और समस्याओं के प्रश्न हैं ७ साल के समय में दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में गल्ले की समस्या को भी हल नहीं कर सके। महंगाई की समस्या को भी हल नहीं कर सके। भुखमरी और बेकारी की समस्या को भी हल नहीं कर सके। उसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि आपके सामने बीस बीस हजार आदमी जो सरकारी कर्मचारी हैं, इस भवन के सामने आये दिन प्रदर्शन करते हैं। यह उसका जीता जागता सबूत है। आज हर आदमी महंगाई से पीड़ित है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप महंगायी भत्ते को नहीं बढ़ाते हैं तो महंगायी को न बढ़ने दें लेकिन कन्ट्रोल करें, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं।

आज जनता का यह भी दुर्भाग्य है कि आप डाकुओं की समस्या को भी हल नहीं कर सके और जनता की आप रक्षा नहीं कर सके। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि झांसी में कुछ पुलिस के कर्मचारी और मिलिटरी के कर्मचारी सिपाही पकड़े गये हैं और उन्होंने १३ या १४ मामलों में डाके डालना प्रदेश में स्वीकार किया है। इससे बढ़कर कि हमारे सिपाही सरकारी बन्दूकों से डाके डालें, और व्यवस्था का कौनसा जीता जागता सबूत दिया जा सकता है? आज जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं हम कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि यह शायद हमारे हाथ में एकदम आजायेगी। हम हुकूमत अपने हाथ में ले लेंगे। हम भी समझते हैं कि आपके हटने के बाद हम सत्ता नहीं चला सकते हैं चूंकि हम में आपस में बटे हैं और हुकूमत हमारे हाथ में आना सम्भव नहीं है। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारा कर्त्तव्य है, अगर आप भूले हैं तो आपको मार्ग दिखायें, अगर आप अंधकार में हैं तो आपको प्रकाश बतायें। इसीलिये अविश्वास का प्रस्ताव आता है कि आपको मार्ग दिखा सकें और सूबे की सही हालत आपको बता सकें। बड़े दुख की बात है कि आज मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगें। मैं मंत्रिमंडल को बता देना चाहता हूं कि अगर आपको हमसे खतरा है कि हम सत्ता लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे। अगर आपको खतरा है तो अपने लोगों से ही है। आपके ही लोग आपको हटाकर आपकी जगह आना चाहते हैं।

[श्री लखपतराम शर्मा]

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन में दो तीन खास चीजें रखना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले माननीय न्याय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है, आप जिस स्थान पर बैठे हैं, न्याय आपके हाथ में है, इसलिये अगर आपका कोई आदमी गलती करे तो उसको कड़ा दंड देना चाहिय, रियायत नहीं करनी चाहिये। मंत्री जी ने स्वीकार किया कि १०-१०-६४ को झांसी जिले में सन् १९६० से लेकर १९६३ तक ५ मुकदमें वापस लिये गये। इन मुकदमों की हालत देखिये। जिन से यह मुकदमे वापस लिये गये उनमें एक सरकारी कर्मचारी है और शेष कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित हैं। दूसरे एक मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। आपको ताज्जुब होगा कि धारायें १२०, २०१, ४०६, ४१७, ४२० और ४७१ आदि के मुकदमे वापस ले लिये गये। यह आपका जवाब है, मेरा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था कैसे कायम रहेगी जब भ्रष्टाचार के मामले इस तरह से उठा लिये जायं। आप पार्टीबंदी पर फैसला करते हैं और पार्टीबंदी के बजाय तो अब आप जाति पर भी फैसला करने लगे हैं।

आप न्याय व्यवस्था और कार्यपालिका को अलग अलग कर दें। मैं कोई आपसे रियायत नहीं चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने स्वयं इसको स्वीकार किया है कि कार्यपालिका और न्याय-पालिका को अलग-अलग कर दिया जाय। आपको शासन करते हुये १७ साल हो गये हैं लेकिन फिर भी आप इनको अलग-अलग नहीं कर पाये हैं, केन्द्रीय सरकार की आज भी इच्छा है लेकिन हमारी सरकार तैयार नहीं है।

श्रीमन्, आपको प्रदेश की मौजूदा हालत का सही ज्ञान नहीं है, अगर है तो आप उस पर परदा डाले हुये हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि की बात है। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। वही हालत आपकी है। मैं व्यतिगत आक्षेप करने का हिमायती नहीं हूं। आपने आज श्रमदान को शर्मदान कर दिया है। उसका सबूत यह है कि आप भूखी नंगी जनता की हालत को नहीं देख पा रहे हैं। आप शहरों के व अन्य वर्ग के अन्दर जहां दौरे पर जाते हैं अगर वहां आपने गरीब मजदूरों व अल्प आय वर्ग की दशा देखी होती तो आप भी हमारी तरह से इंसान हैं तो आपको भी उनकी दशा पर दुख होता।

माननीय नेगी जी, आप इस महंगाई के जमाने में देहात की जनता के एक रुपया प्रति परिवार गेहूं १५ रोज के लिये देते हैं? कैसे आदमी अपना पेट भर सकता है? आप कह सकते हैं कि बाजार से खरीदा जा सकता है। लेकिन में माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे सदस्य हैं जो ३०० रुपये में खुशहाल हैं। आप सदस्यों से पूछें कि उनके घर में लड़ाई होती है। उनकी बीबी कहती है कि आप स्वयं खर्चा चलाइये। मेरे बस का नहीं है। जब माननीय सदस्य इस हालत में नहीं हैं कि बाजार से गल्ला खरीद सकें तो कितने लोग ऐसे हैं जो एक सेर का या अठारह छटांक का गल्ला खरीद सकते हैं? आपने बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ कोई सख्ती नहीं की। उनके ऊपर आपका करोड़ों रुपया सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स आदि का बकाया है। लेकिन आप उसकी वसूली नहीं कर पा रहे हैं।

श्रीमन्, रोज-रोज अविश्वास के प्रस्ताव आना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यह इसलिये आते हैं जो कि लोग अपनी भावना को रख सकें। अगर आपको विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलिये। मैं लखनऊ की दुकानों पर दिखा सकता हूं कि जब आदमी खाना खाकर जूठा दोना फेंकते हैं तो उस पर कुत्ता और इंसान दोनों एक साथ टूटते हैं, इसलिये जूठन पहले कौन खाये? यह सूबे की हालत है। अगर आप भूखे नंगों को देखते तो आपका हृदय पुकार उठता। आज आपने सुनारों की हालत क्या कर दी है, मजदूरों और गरीबों की हालत क्या है? क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है? मैं झांसी की बात कहता हूं, वहां पर इंसान नहीं, तांगेवालों के घोड़े तक भूख से मर रहे हैं। इंसान नहीं जानवर तक जब भूख से मरने लगें तो यह कितने लज्जा की बात है और आप कहें कि इस प्रदेश के अन्दर भुखमरी नहीं। ठीक है आपकी दृष्टि में भुखमरी नहीं है, क्योंकि आप इसे कभी देखने का प्रयत्न नहीं करते, देखकर भी आंख मूंद

लेते हैं। लेकिन मत भूलिये बड़ों-बड़ों का नशा उतर गया है, यह मत समझिये कि आपके नाम कोई पट्टा लिखा हुआ है। जनता ने चुनाव में फैसला कर लिया तो एक बार नहीं हजारों बार सत्ता बदली जायगी और आपको आसन छोड़ना पड़ेगा। यह मत सोचिये कि अविश्वास के प्रस्ताव से आज आप पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है तो आप हमेशा यहां बने रहेंगे, समय आयगा और जनता आपको उतार कर फेंक देगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मुझे यह आशा थी क्योंकि मैंने जब अविश्वास के प्रस्ताव को पढ़ा तो हमें लगा कि मानों प्रदेश के अन्दर कोई ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण वह अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। लेकिन सुबह से अभी तक उन लोगों के सब भाषणों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह कोई नई बातें नहीं कह रहे हैं। जो बातें बजट भाषण के समय कही गई, जो राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के समय कहीं गई, उन्हीं सब घिसी पिटी बातों को दोहराया गया है। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि विरोधी लोगों ने अविश्वास के प्रस्ताव को एक दस्तूर बना लिया है और इसके द्वारा वे लोकप्रिय सरकार के प्रति जनता में अविश्वास पैदा करना चाहते हैं।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस विषय पर मुझे डाक्टर गोविल्स जो हिटलर का प्रोपोगेन्डा सेक्रेटरी था, की थ्योरी याद आती है, वह यह कहा करता था, "किसी गलत बात को १० मर्तबा दोहराओ तो वह सच हो जाती है।" ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे साथी उक्त कथन में विश्वास करते है और उस डाक्टर के कथन को चरितार्थ करना चाहते हैं। जो बात सच नहीं है उसे बार-बार दोहरा कर लोकप्रिय सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और सारहीन बात कह कर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, उस पर कीचड़ उछालना चाहते हैं कि यह जनता के बड़े हितैषी हैं, उनका भला चाहते हैं और हम लोग जनता के सेवा न करके उनको जनता की सेवा करने का मौका दें। आपने यहां पर जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है, मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई गम्भीरता नहीं है। इस पर फुस-फुस, हल्के-फुल्के ढंग से इस सदन में चर्चा हो रही है, इससे स्पष्ट है कि इसमें कोई गम्भीरता नहीं है। हमारे बस्ती से निर्वाचित एक माननीय सदस्य उधर से बोले, मुझे उनसे आशा थी कि वह कोई गम्भीर बात कहेंगे लेकिन उन्होंने आरम्भ से अन्त तक अपनी सफलता की डींग मारी और अपना गुबार जो उनके मन में बहुत दिनों से भरा हुआ था, उसे निकाला। इन उपायों से, इस तरीके से क्या जनता की सेवा हो सकती है? एक दिन नष्ट करके आपने प्रदेश का कितना धन दुरुपयोग किया है? यह तो स्पष्ट है कि इससे कोई फायदा होने का नहीं है। इसमें कोई २ रायें नहीं हैं कि कांग्रेस सरकार के १७ साल के क्रियाकलापों का यदि आप सिंहावलोकन करें तो आप एक ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि १७ साल में हमारे प्रदेश के अन्दर सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है। बहुत संतोषजनक प्रगति हुई और उस प्रगति की झलक चारों तरफ दिखलाई पड़ती है। आप प्रशासन को लीजिये। किन-किन विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हमारे माननीय मित्र हर प्रश्न को लेकर आन्दोलन खड़ा कर देते हैं। कमी थी गल्ले की, सरकार ने उस परिस्थिति को काबू करने की कोशिश की लेकिन मेरे इन माननीय मित्रों ने आन्दोलन चला करके उस परिस्थिति को और भी जटिल बना दिया। सरकार जो कुछ करना चाहती थी उसको करने देने में बाधक हुये। मुझे क्षमा किया जाय यह कहने के लिये कि इस खाद्य संकट को उत्पन्न करने के लिये विरोधी पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं यह सरकार नहीं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों को लीजिये। औद्योगिक क्षेत्र को लीजिये। उसमें कितना विकास हुआ है। आज सैकड़ों प्रकार की संस्थायें खुली हैं जहां लोगों को कार्य मिला हुआ है, जहां टेकनिकल शिक्षा दी जाती है, जो दस्तकारी सिखाती है, टेकनीशियन्स तैयार करती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य को ले लीजिये और चीजों को ले लीजिये, हमने हर तरफ तरक्की की है।

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

एक बात और। हमारे माननीय प्रस्तावक महोदय ने अपने पूरे भाषण को अध्यापकों की स्थिति वर्णन करने में खर्च कर दिया। उन्होंने सबसे अधिक बल इसी बात पर दिया और कहा कि इसके कारण प्रदेश के अन्दर ऐसी संकटमय स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। उन्होंने दूसरी बातों की चर्चा ही नहीं की। मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह गम्भीरतापूर्वक विचारने का विषय है। मैं उनकी शुभ भावनाओं में अविश्वास नहीं करता हूं और समझता हूं कि आप जिम्मेदारी के साथ सुझाव देते हैं लेकिन यह एक विकट प्रश्न है। क्या आपका कर्त्तव्य नहीं है कि आप सोचें कि जो कुछ आप सदन के सामने कह रहे हैं, वह व्यावहारिक है या नहीं? अगर उनकी तमाम योजनाओं को, श्रीमन्, कार्यान्वित किया जाय तो करोड़ों और अरबों रुपयों का व्यय आप बताते हैं। नौकरों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये। बात अच्छी लगती है, आप लोकप्रियता भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सोचे यह रुपया कहां से आवें? आज महंगाई की वजह से जो हमारा आर्थिक संतुलन है वह डावांडोल हो गया है। आज आवश्यक वस्तुओं के दाम छगुने, अठगुने और दसगुने से भी अधिक हो गये हैं लेकिन हमारी आमदनी बढ़ी नहीं है। जिस वक्त कर वृद्धि की बात होती है उस वक्त आन्दोलन होते हैं। बात ठीक है। लोगों को बुरा लगता है। जहां तक तनख्वाह बढ़ने का सवाल है, तनख्वाह बढ़नी चाहिये, सब की हमदर्दी उसके साथ है। जितने, पचास, सौ डेढ़ सौ पाने वाले कर्मचारी हैं जिनको इतनी तनख्वाह है उनकी बढ़नी चाहिये। हम जब क्लर्कों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा काम कैसे चलता है और वह जब बताता है तब उसकी दुर्दशा देखकर हृदय रोने लगता है। वे कहते हैं कि तनख्वाह सौ रुपये है, क्या बच्चों को खिलायें, कैसे उनको शिक्षा दें, इतने में खर्च चलाना मुश्किल है। बड़ी तनख्वाहें पाने वाले हैं उनसे बात करें तो पता चलता है कि लोगों को कष्ट है और वह मिटना चाहिये, लेकिन जब तक देश की और प्रदेश की आमदनी नहीं बढ़ती वह कैसे हो सकता है? अध्यापकों से ज्यादा सहानुभूति तो मुझे चपरासियों और पुलिस के कांस्टेबिलों से है। जब वे बेचारे ६० रुपये लेकर घर जाते है तो मैं जानता हूं कि कैसे वे अपना काम चलाते हैं, उन पर क्या बीतती होगी? लेकिन हो क्या? नये करों का विरोध होता है। जो बजट आज हमारा है वह नाकाफी है। एक बात पर बहुत बल दिया जाता है कि खर्च कम कर दिया जाय। बकिया टैक्स वसूल कर लिये जायं। मैं पूछता हूं कि कितना टैक्स बकिया है, कितना वसूल हो चुका है और अगर वह वसूल भी हो जाय तो उससे कितना बढ़ जायगा? अगर सारे उद्योगपतियों से जो कानपुर के हैं उनसे सब वसूल कर लें तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? मिलें बन्द हो जावेंगी, मजदूर बेकार हो जावेंगे, सड़कों पर आन्दोलन होने लगेंगे और देश की सुन्दर शान्ति व्यवस्था पर असर पड़ेगा। अपना तो वेलफेयर स्टेट है। इसलिये जो भी बात कहें वह ऐसी होनी चाहिये जो व्यावहारिक हो। ऐसी लगता है कि जितनी प्रगति हुई है यह इनको जंचती नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि जो प्रगति हुई है वह इनको नहीं जंचती है। जो कमियां हैं उनको ये बताया करते हैं। बड़ी बड़ी शान की बात किया करते हैं और इस तरह की बातें किया करते हैं जो बिलकुल अव्यवहारिक हैं। इसका उत्तर मैं केवल एक बिहारी के दोह से देना चाहता हूं--

शीतलता और सुवास की घटे न महिमा मूर।
पीनसवारों ज्यों तजै शोरा जान कपूर॥

बस यही मुझे आपकी सेवा में निवेदन करना था।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय विरोधी दल के नेता ने, जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में, मैं खड़ा हुआ हूं। उधर के माननीय सदस्यों ने कहा कि यह प्रस्ताव रस्म अदायगी के रूप में आया है या एक तरीके से बनावटी रूप में रखा गया है, ऐसी बात नहीं

है । आज प्रदेश की जनता में जो भुखभरी फैली है, आज प्रदेश में अध्यापक वर्ग द्वारा तथा राज्य कर्मचारियों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ग्रामीण किसान जो भुखमरी के मुंह में ग्रसित है, इन सब बातों से स्पष्ट है कि आज जनता की आवाज यह कह रही है कि आपके अन्दर उसका विश्वास नहीं रह गया है । मान्यवर, इस प्रकार से देखा जाय तो यह पता चलेगा कि सरकार के प्रति आज अविश्वास का प्रस्ताव एक अहम परिस्थिति में आया है। यह नित्य प्रति जो प्रदेश में भुखमरी बढ़ रही है, प्रत्येक चीज के भाव नित्य बढ़ते जाते हैं, उस सम्बन्ध में सरकार असफल हुई तथा सरकार की नीतियां फेल हुई हैं और इस प्रस्ताव को पेश करने का कारण भी यही है कि आपकी नीतियां असफल रही हैं और खाद्य नीति भी पूर्णतया असफल रही है । अध्यापक वर्ग के विषय में यहां पर चर्चा हुई । जिस तरह से आज उनका आन्दोलन चल रहा है इस तरह का पिछले इतिहास में कभी नहीं चला । इस तरह से इतना बड़ा प्रदर्शन उन्होंने पहले कभी इतिहास में नहीं किया । सरकार का ही एक मुख्य अंग सरकारी कर्मचारियों का समूह भी आज सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है इसका अर्थ सरकार के हाथ पैर ही जबाव दे बैठे हैं । यह अध्यापक वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आज संघर्ष के लिये तैयार है । अगर आज इन ३६ हजार अध्यापकों की सरकार उपेक्षा करती रही और ये अपनी मांग पर अड़ गये तो यह निश्चय समझिये कि आप कभी अपने प्रदेश में फिर दोबारा इन कुर्सियों पर आकर नहीं बैठ सकते हैं ।

मान्यवर, खाद्य वस्तुओं की प्राइस नित्यप्रति बढ़ते जाने से आज छोटे कर्मचारी ही नहीं बल्कि जो बड़े सरकारी कर्मचारी हैं इससे वे भी परेशान हैं परन्तु उनकी आवाज बन्द है । केन्द्र के भी एच० एम० पाटेल (Patel) एक रिटायर्ड सेक्रेटरी जनरल ने बतलाया कि इस तरह कीमतें बढ़ती चली जा रहीं हैं कि जिससे १ हजार रुपया माहवार पाने वाला हो या २ हजार रु० माहवार पाने वाला, वह अपना प्रथम मास में बजट बना नहीं पाते हैं और बहुत परेशान हैं क्योंकि कीमतें नित्य प्रति बढ़ती चली जाती है और आज का बजट कल मीट नहीं करने पाता---

(इस समय ५ बज कर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, आज की परिस्थिति जानबूझ कर पैदा की गई है और हमारी सरकार ही इसके लिये जिम्मेदार है । अभी पिछली दफा इस सदन में जिक्र आया कि हमारे यहां जितनी खाद्यान्न की कमी थी उसको यहीं से पूरा किया जा सकता था परन्तु इस विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों के ठीक रूप से वितरण न किये जाने के कारण आज प्रदेश में भुखमरी पैदा कर दी गई है । मान्यवर, यह सरकार समाजवाद का नारा बराबर लगाती रहती है । उसका ही स्पष्ट रूप यह हमारे सामने है कि किस प्रकार का वह समाजवाद यहां पर ला रही है । मान्यवर, अभी पिछले साल सरकार ने एन्टी होर्डिंग आर्डर निकाला लेकिन उसका फल देहात की जनता को भोगना पड़ा और किसानों को भोगना पड़ा । शहरों में बड़े बड़े होडर्स का यह सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकी, किसान को यातनायें भोगनी पड़ी पर हाथ कुछ न आया । मान्यवर, अभी अपनी इस पालिसी के संबंध में सरकार ने एक ऐन्टी होर्डिग आर्डर पास किया और उसका प्रतिफल किसानों को भुगतना पड़ा । शहर के बड़े कैपिटलिस्टों का सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकी । आज यह विषम परिस्थिति उसी कारण उत्पन्न हुई है और इसका मुख्य कारण है कि सरकार में आपस में मतभेद है । प्रदेश के मंत्रियों में आपस में और केन्द्र में भी मतभेद है । श्री सत्य-नारायण सिनहा कम्युनिकेशन मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि श्री सुब्रामनियम साहब केन्द्रीय खाद्य मंत्री कंट्रोल का समर्थन करते हैं और मैं उसका विरोध करता हुं । जैसा केन्द्र में है उसीके अनुरूप प्रदेश में भी मंत्रियों में आपस में मतभेद है और इससे जनता में आप के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गई है । सरकार को इस संबंध में एक सुनिश्चित तथा दृढ़ नीति की आवश्यकता है, जो आप में, आपस में गुटबन्दी के कारण संभव नहीं है । प्रदेश में अगर तरक्की हुई होती तो यहां का उत्पादन बढ़ा होता, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी होती और उद्योगों की उन्नति हुई होती । आपके आंकड़े बताते हैं कि आपके प्रदेश का उत्पादन घटा है और निरंतर घटता गया है, प्रति व्यक्ति आय घटती गयी । प्रदेश में बेरोजगारी का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है । और इस

[श्री विजयसिंह]

सब का मुख्य कारण है कि सरकार अपनी नीतियों में असफल रही है। इसलिये ही हमको सरकार के समक्ष अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ा। मान्यवर, बहुत समय से कहा जा रहा है कि प्रदेश में ८० प्रतिशत किसान हैं इसलिये कृषि को यहां बल दिया जायगा, लेकिन सरकार ने उसके लिये कुछ नहीं किया। लघु तथा कुटीर उद्योग को देहात में सरकार नहीं बढ़ा सकी। यह सरकार न किसी की बात सुन सकी और न किसी बात पर ध्यान दे सकी। जो पैसा था उसे बड़े प्लान्स तथा हैवी इंडस्ट्रीज में लगा कर अ प्रोडक्टिव चैनल्स में उसे खूब बहाया गया। आपको कृषि पर ध्यान देना इसलिये जरूरी था कि आपका प्रदेश कृषि पर निर्भर करता है। सरकार ने जो गेहूं के दाम निश्चित किये हैं उनसे पता लगता है कि सरकार की नीति क्या है? किसान आपको भोजन देता है, आप उस पर कर लादते, लादते उसे पंगु बना रहे हैं, उसे पैदावार का उचित दाम नहीं दे रहे हैं। सरकार ने लाल गेहूं की कीमत ४५.५० रु० प्रति क्विन्टल, सफेद गेहूं की कीमत ४९.५० रु० प्रति क्विन्टल और उत्तम गेहूं की कीमत ५३.०० रु० प्रति क्विन्टल तय की है। यह १८ रुपये से २१ रुपये प्रति मन के हिसाब से पड़ती है जबकि सरकार के हेमपुर फार्म पर ३५ रुपये से ६५ रुपये प्रति क्विन्टल प्रोडक्शन कास्ट है और अंदेश-नगर फार्म पर ५१ से १०३ रुपये प्रति क्विन्टल कास्ट आती है। अगर इसी हिसाब से आपने कीमतें निश्चित की होतीं तो भी समझ में आता कि कि सरकार किसानों का हित चाहती है। किसान जब अपनी उपज पर लागत लगाता है तो कैसे वह कम मूल्य पर अपनी उपज दे दे। लेकिन सरकार उससे कम दाम पर उसका माल छीनना चाहती है। मान्यवर, कैसे किसान को प्रोत्साहन मिलेगा, कैसे वह अपनी उपज बढ़ायेगा। (लालबत्ती होने पर) मान्यवर, मैं अपने नेता के स्थान पर बोल रहा हूं। मुझे कुछ अधिक समय दिया जाय। सरकार को कीमतें प्राइस पैरिटी के आधार पर निश्चित करनी चाहिये थीं, लेकिन सरकार उसमें असफल रही है। मैं मंत्रि परिषद की बात नहीं कहना चाहता कि उसके लोग कैसे भ्रष्ट कामों में लगे हुये हैं। राजनैतिक दांव पेच की चौकड़ी में छलांगे लगा रहे है और प्रदेशों में असन्तोष पैदा कर रहे है। मान्यवर, यह सरकार पैदावार न बढ़ने देने की जिम्मेदारी प्रकृति पर डालती है। यदि ऐसा है तो तो फिर करोड़ों रुपया प्लानिंग पर क्यों खर्च किया जा रहा है? सब लोग काम बन्द करके के प्रकृति के भरोसे बैठे रहें। फर्टीलाइजर के संबंध में भी सरकार की जो नीति है वह बेकार साबित हुई। इन्टरनेशनल प्राइस रासायनिक खाद की (बारह सौ पचास रुपया) १२.५० रु० प्रति टन है, जबकि सरकार उसको १८.०० प्रति टन के हिसाब से देती है। फिर भी यह सरकार किसानों का भला चाहने वाली बनती है।

पूंजीपतियों की तरफ कितनी हमदर्दी की निगाह इस सरकार की रहती है, उसका भी उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रिहन्द की बिजली बिड़ला को १.९९ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाती है, और वही बिजली अगर किसान अपने नलकूप के लिये लेता है तो उसको ३७ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाती है। सरकार की नीति ऐसी है जिसके कारण आज जनता को इनमें विश्वास नहीं रह गया है।

उत्पादन के आंकड़े भी मैं इस सदन के सामने देना चाहता हूं। औसत उत्पादन प्रथम पंचवर्षीय योजना में १२१.८८ रहा था। दूसरी योजना में वह घट कर १२१.०५ रह गया और तीसरी में भी निरन्तर घटता गया। तृतीय योजना में १९६०–६१ में १४४.६०, १९६१–६२ में १४०.८०, १९६२–६३ में १३४.९६, १९६३–६४ में ११८.०७ रह गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है किसान, जिसके बल पर आज आप यहां आये है, उसका कोई भला नहीं हुआ है और इसी कारण आज आप में विश्वास नहीं है।

मान्यवर, सरकार की असफल नीति का एक और नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। १२०० करोड़ रुपया की लागत लगा कर सरकार ने हैवी इन्डस्ट्री खोली। सरकार का यह अनुमान था कि इससे साढ़े चार करोड़ का लाभ होगा, किन्तु आज १२ करोड़ का उससे नुकसान हो रहा है। अगर इस १२०० करोड़ की रकम को हम खेती के काम में लगाते तो

बहुत बड़ा फायदा होता। ५०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अगर किसान को देते तो ढाई करोड़ एकड़ भूमि काम में आती और करीब ४० लाख परिवारों को लाभ होता। इस हैवी इन्डस्ट्री में २०० करोड़ की लागत का अगर कोई उद्योग खोला जाय तो उसमें केवल ८ हजार मजदूर काम कर सकते हैं। ४८ हजार मजदूरों को रोजी मिलती, जब यह १२०० करोड़ रु० की इन्डस्ट्री खुली। पर खेती पर कितने लाख परिवार पल जाते यह आंकड़ा सिद्ध करता है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अदम एतमाद के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह उम्मीद कर रहा था कि कुछ ऐसी बातें कहीं जायेंगी कि उनका जवाब सोचना पड़ेगा, बहुत सी बातों का जवाब इस तरफ से दिया भी गया है, कोई प्रश्न ऐसा नहीं बचा जिसका जवाब बाकी हो। अभी कुछ बातें ऐसी कही गयीं, उन सवालात का जवाब दूंगा।

मैंने बड़े गौर से सुना, हमारे माननीय पांडेय जी यह बोल रहे थे। उन्होंने गृह मंत्री जी के विरुद्ध एक मसला उठाया था जिसका जवाब उन्होंने मुफस्सिल दे दिया। हमारे पांडेय जी यह सवाल उठा रहे थे कि किसी आदमी ने मंत्री जी से जाकर सही बात कही और मंत्री जी ने उनके कहने को सही मान लिया। लेकिन फिर भी माननीय पांडेय जी को संतोष नहीं हुआ। अगर माननीय पांडेय जी ऐसा एटीट्यूड लेंगे तो हमारे लिये बड़ी मुश्किल हो जायगी। एक तरफ तो लोग पुलिस की शिकायत करते हैं, पुलिस की गलतियां बताते हैं, दूसरी तरफ यहां उल्टा ही देखने में आ रहा है कि पांडेय जी पुलिस आफिसर की मुखालिफत में खड़े हैं और कहते हैं कि मिनिस्टर साहब ने दखल दिया और जो दरोगा कर रहा था वह सही था। मुझे यह सुन कर बहुत दुख हुआ। आम तौर पर ऐसी बात कांग्रेस दल की ओर से कही जाती है और विरोधीदल हमेशा से दारोगा को गलत ही समझता है और उसकी शिकायत करता है। लेकिन इस मामले में उन्होंने बिलकुल उल्टी बात कही। इस मामले में मैं पांडेय जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे ऐसी कोई मिसाल कायम न करें कि आगे चल कर खुद उनको ही कठिनाई पैदा हो जाय।

इसके बाद मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि कुछ लोगों की तरफ से यह भी कहा गया कि बहुत से लोग पाकिस्तान से पासपोर्ट लेकर आये हुये हैं, उनके पासपोर्ट का वक्त भी खत्म हो गया है लेकिन वे यहीं घूम रहे हैं। कई बार ऐसी चीज सदन में दुहराई गयी है। मैं जहां तक समझता हूं पाकिस्तान हमारे सर पर एक मुखालिफ की हैसियत से खड़ा है और हमारी सरकार कभी भी पाकिस्तान के साथ कोई रियायत करने को तैयार नहीं हो सकती। इस पर भी मुखालिफ दल के माननीय सदस्यों ने जो इल्जाम लगाया है उसमें उन लोगों का नाम बतायें जिससे हम भी सरकार से कह सकें और आपका साथ दे सकें और उसको रोक हो। लेकिन हजारों आदमियों पर इल्जाम लगा देना कि यहां बिना पासपोर्ट के घूम रहे हैं और नाम एक का भी न लेना, यह उन लोगों के लिये इंसाफ की बात नहीं है। यह उस कौम के साथ भी बेइंसाफी है जो आपके साथ इसी देश में भाईचारे से रहती है। यह बात ऐसे फिरके से ताल्लुक रखती है कि जिस की वजह से पाकिस्तान बना। इसलिये उस फिरके की तरफ से खामख्वाह लोगों के दिलों में भ्रम पैदा हो जाता है कि उस फिरके के हर आदमी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं विरोधी दल के माननीय नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस तरह से गैर जिम्मेदारी से बात न करें। आपको याद होगा कि पहले एक ऐसा मसला उठाया गया था, और मैंने जब उसके बाद उस बारे में कहा तो श्रीमन् को उस मामले को खत्म करना पड़ा और कार्यवाही में से उन चीजों को निकालना पड़ा। ऐसे इल्जामात के लगाने से और उनके अखबारात में शाया होने से काफी भ्रम लोगों में फैल जाता है।

रियासत हुसैन साहब ने उर्दू का सवाल उठाया। मैं उस मामले में उनका साथ देता हूं। लेकिन पहले वे जनसंघ के भाइयों और अपने दल के सदस्यों से यह जान लें कि

[काजी जलील अब्बासी]

उर्दू के बारे में उनके क्या खयालात हैं, जरा उनके दिल को टटोल लें। मैं अपने दल की तरफ से उनको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस दल कभी भी इस मामले में उनसे पीछे न रहेगा।

इसके बाद लखपतराम जी ने इस बात का रोना रोया कि कांग्रेस दल में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को खतरा है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, उन्होंने हमें अपने घर का हाल बता दिया, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि इस मुख्तलिफ से दल को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस हमारी एक बड़ी जमात है, इसमें कुछ उसूली मामलों पर इख्तिलाफ रहते हैं, जो हमेशा रह सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि विरोधीदल यह समझे कि इन लोगों में इख्तिलाफ है, इसलिये उसका फायदा मिलेगा। हम बहुत सफाई के साथ यह कहना चाहते हैं कि हम विरोधी दल के मुकाबले में एक रहे हैं और एक रहेंगे जैसा कि हमारे दोस्त बोल चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहां पर बस्ती के एलेक्शन का जो तस्किरा किया गया मुझे दुख है, हम हार गये, हम बधाई देते हैं कि आप जीत गये, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप जीत गये, तो जनता से आपका बड़ा लगाव हो गया। इसी जिले में जो साहब चुनकर आये हैं, हम उनको दो बार ५७,००० और ५०,००० वोटों से हरा चुके हैं। इस बार ऐसा आतंक फैलाया गया कि कोई मुसलमान या हरिजन वोट देने न जाने पावे। मैं समझता हूं कि इस हालत में हम लोगों को निहायत सब्र व सकून के साथ एलेक्शन लड़ना पड़ा और मैं समझता हूं कि यह जीत कोई जीत नहीं है। हमारे जनसंघ के बहुत से नेता गये थे और हकीकत है कि गांव-गांव में फैलकर किस-किस तरह से जनता में भ्रम फैलाते थे और हमें मजबूरी थी, हम ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वरना जब कि चीफ मिनिस्टर बस्ती से है, उसमें दिलचस्पी चीफ मिस्टिर की हैसियत से वे लेतीं, तो कोई वजह नहीं थी कि हम एलेक्शन न जीत जाते। वह एक कार्यकर्त्ता की हैसियत से जब वहां गईं, तो उसी प्रकार से उन्होंने सलाह दी कि एलेक्शन की हार और जीत से कुछ नहीं बनता, लेकिन हम लोगों को अपने उसूलों को नहीं कुरबान करना है, इसकी खुशी मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।

दो बातें और मुझे अर्ज करनी हैं कि हमारे भाई दर्शिह जी और रामायण राय जी के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आखिर यह १४-१४ आदमी उधर से इधर क्यों चले आये? क्या उन्हें मिला? बल्कि २५ आदमी उस पार से इस पार आ गये हैं। एलेक्शन भी हर जगह आप हार रहे हैं, क्यों, इसलिये श्रीमन् कि आज यह सोचना ही बेकार है कि कांग्रेस के अलावा कोई संस्था ऐसी है, जोकि जनता के साथ इंसाफ कर सके। जनता जानती है कि कांग्रेसी जमात ऐसी है जिसके हाथ मजबूत हैं और उसके अन्दर हम सुरक्षित ह। मुझे बड़े अदब के साथ माननीय झारखंडेराय जी और चन्द्रजीत यादव जी से कहना है कि जनसंघ के साथ आप कैसे मिल गये, आपके खयालात अलग, जमीन और आसमान का फर्क है, उनका नारा साम्राज्य है, आप सोशलिज्म चाहते हैं और वह कोआपरेटिव खेती के खिलाफ हैं, आप कोआपरेटिव खेती चाहते हैं, वह फ्री ट्रेड चाहते हैं, आप स्टेट ट्रेडिंग चाहते हैं। वह एक मुट्ठी भर लोगों की ताकतों को लेकर साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। आपके खयालात हमारे करीब है, उनके नहीं। फिर आपका, उनका क्या संबंध, फिर आपका उनका क्या ताल्लुक मेरी समझ में बात नहीं आई। अगर बोलने के लिये ही यह प्रस्ताव आया है, तो मैं तो देखता हूं कि माननीय झारखंडेराय, और माननीय चन्द्रजीत यादव बराबर बोलते रहते हैं। बोलने का हर वक्त आपको मौका हासिल है क्योंकि आप एक पार्टी के लीडर हैं, आप हमारी तरह तो नहीं हैं कि इधर इतने भाई बैठे हैं, जिनके बीच हमको कभी-कभी मौका मिलता है, आपको हर दम मौका मिलता रहता है। तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारे विरोधी दल के नेता अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

*श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। मैं सत्तारूढ़ दल को बता देना चाहता हूं कि इस प्रांत के अन्दर प्रत्येक वर्ग में आज सत्तारूढ़ पार्टी से असंतोष है। चाहे वह किसान वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे अध्यापक वर्ग हो, सभी में एक असंतोष का वातावरण फैला हुआ है। अध्यापकों के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि यही सत्तारूढ़ दल वाले चाहते हैं कि अध्यापकों से वह चुनाव में काम लें, नगरपालिका के चुनाव में, विधान सभा के चुनाव में या मतगणना हो तो उसमें उनसे काम लें लेकिन जब वह भूखे और नंगे अध्यापक अपने पेट के लिये रोटी और तन के लिये कपड़ा मांगते हैं तो उनकी उचित मांगों को ठुकरा देते हैं। यही नहीं मान्यवर, जिला परिषद् के अध्यक्ष उनसे जिला कांग्रेस कमेटी का मेम्बर बनवाते हैं, और-और काम उनसे लेते हैं, लेकिन उस भूखे नंगे अध्यापक की सहायता नहीं करते। आज आप चाहते हैं कि मीठे-मीठे वचनों और गोलमोल शब्दों से उनको अपने कब्जे में रखें, लेकिन वह अध्यापक जो हमको और आपको पढ़ाकर बहुत दूर तक पहुंचा सकता है, उसको अब आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। वह समझदार है, बुद्धिमान है, उसको आप अब किसी तरह से गिरा नहीं सकते है। उनकी मांगें उचित हैं। जब आप मानते हैं कि उनकी मांगें उचित हैं तो क्यों नहीं उनको मानते हैं?

यही नहीं, मान्यवर, यह सरकार इस देश की भुखमरी को नहीं मिटा सकी है। सात करोड़ जनता भूखों मर गई। यह कहते हैं कि हमने बड़े बड़े प्रयत्न किये, बड़े-बड़े साधन जुटाये लेकिन देहात के गरीब किसानों के बच्चे भूखे बिलखते सो गये और उनके मां बाप बैठे देखते रह गये। अपने सारे जेवर उन्होंने बेंच डाले, गृहस्थी बेंच डाली मगर फिर भी अपने भूखे परिवार को भोजन वह न दे सके। इधर हमारी सरकार आराम करती रही और स्टेटमेंट देती रही कि फलां जगह से गेहूं मंगा रहे हैं, फलां जगह से चावल मंगा रहे हैं। परन्तु न जाने वह गेहूं और चावल कहां चला गया? गरीब जनता तक वह नहीं पहुंच सका। आज भी यह सरकार राशन नहीं दे पा रही है। १५ दिन के लिए डेढ़ किलो राशन आज यह दे रही है। उससे एक आदमी कितने दिन तक जीवित रह सकता है? चोरबाजारी और ब्लैक मारकेटिंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार खुल्लमखुल्ला देख रही है कि चोरबाजारी हो रही है, लेकिन कुछ भी नहीं करती। इस पर भी वह कहती है कि हम सफल हो रहे हैं। यह सफल होने की नीति नहीं है। आप सफल कभी नहीं हो सकते हैं। बड़ी-बड़ी योजनायें आप बनाते हैं, क्या वह योजनायें आपकी सफल होती हैं? योजना बनाने के पहले क्या कभी आप खयाल करते हैं कि जो योजना आप बनाने जा रहे हैं उसके लिये सामान भी आपने मुहैया किया है? बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स आपने बना दीं। आगरे में बड़ी भारी इंडस्ट्रियल स्टेट आपने कायम की, लेकिन सामान आज तक नहीं पहुंच सका है, बड़ी-बड़ी बिल्डिगें बनी पड़ी हैं। वह बेचारे अपनी पूंजी लगाकर कंगाल की हालत में बैठ गये हैं। तो आपकी सारी योजनायें कागज पर हैं। हो सकता है कि एक दो योजनायें सफल हो गई हों, लेकिन वह भी एक तरफ से सफल होती हैं और दूसरी तरफ बरबाद होती जा रही हैं। हरिजनों की बात यह सरकार बहुत करती है लेकिन उनके लिये करती क्या है? मैं आज सत्तारूढ़ दल को बतला देना चाहता हूं कि हरिजन जिस स्थान पर थे उससे भी पीछे चले गये हैं, उनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है। जमींदारी एबालिशन के बाद गरीब हरिजनों से जमींदारों ने जबरदस्ती जमीन छीन ली जिससे वे भूमिहीन हो गये और इस लायक भी नहीं रहे कि मुकदमेबाजी कर सकें। वे हर तरह से परेशान व भीख मांगने वाले हो गये।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को बतला दूं कि वह जनसंघ की बड़ी बुराई करती है और कहती है कि हरिजन उनके साथ नहीं है। लेकिन मैं आप देखें कि पार्टी की संख्या को देखते हुये पार्टी में आज भी ९ हरिजन सदस्य हैं और हरिजन उनके साथ हैं। आज सरकार हरिजनों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुखलाल (लखनऊ)]

के सहारे पर ही जीत कर यहां आती है, लेकिन उनके साथ जो वह कर रही है वह न के बराबर है । उनको सरकारी नौकरियों में भी १८ प्रतिशत संरक्षण देने की बात की जाती है लेकिन देखा जाय तो उनका प्रतिशत २ भी नहीं आयेगा । आप हरिजनों को बड़े-बड़े अनुदान देने की बात कहते हैं लेकिन आप ये अनुदान ब्लाक्स द्वारा देते हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाते । अगर कोई गरीब हरिजन अपना प्रार्थना-पत्र देता है तो उसके लिये ग्राम सेवक पहले ही ५० रुपये मांगता है । यदि प्रार्थी ने ५० रु० दे दिया तब तो प्रार्थनापत्र सही स्थान पर पहुंच जाता है वरना वह प्रार्थना-पत्र सही स्थान तक पहुंचता ही नहीं । जो अनुदान आपकी तरफ से दिया जाता है वह इसी कारण से समाप्त नहीं हो पाता । यह आपकी माया है जो हरिजनों के साथ बरती जा रही है । यही नहीं इसके अलावा और भी तमाम तरीके अपनाये जाते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । सरकार ने वायदा किया था कि वह भ्रष्टाचार, चोरबाजारी और पुलिस के दमन को दूर करेगी, लेकिन आज वह पहले से भी दुगना हो गया है । देश और प्रदेश की जनता, देहात की जनता आज पुलिस के अत्याचार से त्रस्त है । किसी का कोई ठिकाना नहीं कि किस वक्त उसके ऊपर कोई आफत टूट पड़े ।

मैं अपने जिले के पुलिस इन्सपेक्टर की बात बतलाता हूं कि अक्सर लोगों को पकड़ कर किसी न किसी बहाने दफा १०९ में या चोरी में बन्द कर दिया जाता है । जब इसके लिये दौड़ धूप होती है कि उसे छोड़ दिया जाय तो वे कहते हैं कि अमुक व्यक्ति से टेलिफोन करवा दो तो मैं छोड़ दूंगा । इस तरह से पुलिस का आतंक चारों तरफ व्याप्त है, ऐसी हालत में इस सरकार में जनता का विश्वास कैसे हो ? ये चाहे जितना कहें कि जनता का उनके अन्दर विश्वास है इसीलिये जीत कर आते हैं लेकिन असलियत यह है कि पुराने होने की वजह से इनके जितने हथकंडे हैं उनको हम लोग समझ नहीं पाते और भोली भाली जनता भी नहीं समझ पाती जिससे धोखाधड़ी व फरेब करके ये जीत जाते हैं। इनको बड़ा अरमान है कि जनता का इनके उपर विश्वास है, लेकिन वास्तव में ये जनता का विश्वास खो चुके हैं और जनता इस समय आपसे बहुत परेशान व पीड़ित है ।

श्रीमन्, मैं अपने क्षेत्र मड़ियाहूं के चिनहट गांव के एक व्यक्ति के साथ हुए व्यवहार का जिक्र कर दूं जो पुलिस द्वारा किया गया है । उसके ऊपर धारा ५५१ की कार्यवाही की गयी और उस व्यक्ति को पता तक नहीं चला और धारा ८७-८८ के अन्तर्गत उसके भाई का माल कुर्क कर लिया गया । जब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं तो अपने भाई से अलग हूं तो उससे कहा गया कि १०० रु० दे दो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा । जब उसने कहा कि मैं १०० रु० देने लायक नहीं हूं तो उससे कहा गया कि तुम १०० रु० यहां नहीं देकर १५० रु० वहां ही दोगे । इस तरह से तमाम तरह से जनता को परेशान किया जाता है । जिसे सरकार भी जानती है, लेकिन जानबूझ कर वह इस पर कोई ध्यान नहीं देती । यह अविश्वास का प्रस्ताव इस सरकार को रसातल में पहुंचा देगा । इन शब्दों के साथ मैं विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, आज की जो बहस है वह मुख्य रूप से तीन विषयों पर रही है । इन तीन विषयों में से दो पर मैं चर्चा करना नहीं चाहूंगा । एक विषय तो हिन्दी उर्दू का रहा और दूसरा विषय अध्यापकों की नीति के संबंध में रहा । इन २ विषयों पर काफी गौर व विचार यहां हुआ है इसलिये मैं उन दोनों विषयों को छोड़कर केवल भ्रष्टाचार के ही संबंध में थोड़ा कहूंगा जो विषय यहां अधिक चर्चित रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आमतौर से विरोधी दल के सदस्यों की यह शिकायत रही है कि सरकार के ऊपर ब्यूरोक्रेसी हावी है और अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और वे भ्रष्टाचारी हैं । मैं सदन के सम्मुख दो तीन उदाहरण प्रस्तुत करूंगा । एक माननीय सज्जन जो विरोधी दल के बहुत प्रमुख सदस्य हैं और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सहारनपुर से चुन कर आये हैं उनकी दो तीन मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं कि वह आमतौर पर इस विषय को यहां क्यों छेड़ते हैं और उसका कारण क्या है ? आज के भाषण से पहले उन्होंने जितने भी भाषण यहां दिये हैं उनमें उन्होंने मुख्य रूप से नगरपालिका सहारनपुर के चेयरमैन को ही अपना मुख्य विषय बनाया है और अब चूंकि यही फिर दोबारा वहां के चेयरमैन चुने गये हैं और वहां की जनता ने उन पर अपना विश्वास प्रकट कर दिया है इसलिये अब उन का वह विषय छूट गया । अब वहां के सरकारी अधिकारियों को और दूसरे विषय को उन्होंने चुना है । मैं अब उनकी बात ही बताता हूं ।

एक बार ऐसा हुआ कि पुलिस कप्तान को उन्होंने फोन किया कि क्वालिटी डायर्स ऐंड ड्राईक्लीनर्स की दूकान में ३ कत्ल हो चुके हैं, आप उनके आदमियों को पकड़िये । इस पर वहां के पुलिस कप्तान ने फौरन ३–४ इन्सपेक्टर और १५–२० सिपाहियों के एक स्क्वेड को भेजा और उस भले आदमी के घर की तलाशी हुई । वहां न कोई कत्ल हुआ था, न डकैती और न कोई परेशानी की बात थी । बाद में मालुम हुआ कि उस के मालिक से माननीय सदस्य की शिकायत यह थी कि उन्होंने उनके चुनाव में उनका विरोध किया था । केवल इसीलिये इस तरह से उन के घर की सर्च कराई गई । इस पर लांडरी के मालिक ने एस०पी० से कहा कि अगर हमारी शिकायत हो जाय तो आप उस पर क्या ऐक्शन लेंगे ? इसको छोड़कर अब मैं एक दूसरा उदाहरण और देता हूं ।

उनकी दूकान की बराबर में एक सरदार खालसा टी स्टाल है । उस का दूध का सेम्पिल भरा गया और चालान हुआ । उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने भ्रष्टाचार और गुटबन्दी की चर्चा की उन्होंने ही नेताओं से सिफारिश की कि किसी तरह से उसका सैम्पिल बदलवा दिया जाय । हमने कहा कि यह काम हमारा नहीं है, हम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते । जो कि बराबर दोहाई देते हैं कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिये और ब्यूरोक्रेसी पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिये उनका एक उदाहरण मैं और दूंगा । एक बार सहारनपुर में एक कंट्री लिकर या शराब की दूकान खुलने वाली थी । उसके लिये उन्होंने कोशिश की कि पंजाब की एक पार्टी, जो उनकी रिश्तेदार और संबंधी थी, उसको मिल जाय । लेकिन वह जिलाधीश ने दूसरे आदमी को ही दी जिसके लिये कि वहां की लाइसेंस कमेटी और बोर्ड की सिफारिश थी । इस पर उनकी नाराजगी हो गई । इस तरह के उदाहरण उनके हमारे सामने हैं । इसी तरह से अगर हम विरोधी दल के अन्य नेताओं के कार्यकलाप देखेंगे तो बहुत से इस तरह के उदाहरण मिलेंगे । वही लोग रोज सरकारी अधिकारियों और सरकार पर लांछन लगाते हैं कि उस पर ब्यूरोक्रेसी छाई हुई है और सरकारी अधिकारी हावी हैं । मैं समझता हूं कि वह ऐसे इल्जाम इसीलिये लगाते हैं कि उन के द्वारा ऐसे लोगों के गलत काम पूरे नहीं किये जाते और मेरे खयाल से यह बहुत शर्म की बात है ।

इस बात की भी बड़ी दुहाई दी गयी कि कांग्रेस में गुटबाजी है और जिले में भी गुटबाजी के आधार पर काम किये जाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जब उन माननीय सदस्य का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है तो फिर कई सौ रुपये का पैट्रोल कांग्रेस की आपसी बातों में क्यों खर्च करते हैं ? उनकी दिलचस्पी किसी व्यक्ति विशेष से है इसीलिये वे ऐसी बातें कहते हैं और लांछन लगाते हैं । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, अगर स्वयं वह अपने गरेबां में हाथ डाल कर देखें तो मालूम होगा कि वह कहां खड़े होते हैं । तब संभवत: उनकी हिम्मत नहीं होगी कि किसी की आलोचना कर सकें । जिस प्रकार से सरकारी अफसरों पर या सरकार पर लांछन लगाया जाता है, वह पहले जरा अपने बारे में भी तो सोच लिया करें । समाजवाद की बहुत दुहाई दी जाती है, जो बहुत बड़े समाजवादी बनने की कोशिश करते हैं, मेरे जिले में उन्हीं के गांव में अगर ५०० बीघे

[श्री रामसिंह (सहारनपुर)]

जमीन है तो दूसरे के पास झोपड़ी भी नहीं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उसके लिये कुछ किया है ? कभी नहीं कुछ किया । यहां ऐसे सदस्य होंगे जिनके पास सम्पत्ति है और जो समाजवाद का दावा करते हैं, लेकिन अपने करीब में ही अगर कोई गरीब आदमी है जिसके पास खाना, कपड़ा नहीं है तो क्या उन्होंने कभी अपने में से बचाकर उस गरीब को दिया ? तो चैरिटी बिगिन्स ऐट होम, देने की शुरुआत घर से होती है । अगर आदमी खुद कुरबानी करे तो ठीक रहता है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(एक आवाज--बैठो ।)

श्री चन्द्रबलीसिंह--

बैठो कहोगे तो ठीक नहीं रहेगा । माननीय सदस्य ने कहा कि गरीबी है, और अमीरी है, तो वह तो हमारी ही बात का समर्थन कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)---

मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूं जो लोग समाजवाद का बहुत दावा करते हैं, मैं मानता हूं कि जो योजनायें सरकार चलाती है उनमें कुछ कमियां, खामियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम समाजवाद के रास्ते को छोड़ दें । मेरा विश्वास है कि कांग्रेस ही समाजवाद ला सकती है, और कोई पार्टी नहीं । क्योंकि आप लोग तो वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से बातें करते है । इस तरह से समाजवाद नहीं आ सकता । आपको रचनात्मक तरीके से सोचना चाहिये ताकि सरकार के सामने मिसाल हो । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कांस्टीट्यूशन को तहत में माइनारिटीज को फ्रीडम आफ स्पीच के लिये हक दिया हुआ है । बाहर तो फ्रीडम है, लेकिन हाउस में हमारा गला घोटा जाता है । ४३० सदस्यों में से मैं एक जमात का अकेला आदमी हूं, कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं और इसके लिये कई मर्तबा उठ-बैठ चुका हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष---

आपका गला नहीं घोटा जायगा ।

श्री एस० जी० दत्त--

मैं व्यवस्था चाहता हूं,कि कांस्टीट्यूयशन की तहत में माइनारिटी को फ्रीडम आफ स्पीच है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

माइनारिटी का सवाल नहीं है । यहां सब मेजारिटी में हैं । आप बैठ जायं ।

श्री एस० जी० दत्त--

आपको मुझे समय देना होगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल के अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, आज अविश्वास का प्रस्ताव आया और उस अविश्वास के प्रस्ताव पर बातें आरम्भ हुईं, सरकार के कार्यों की आलोचना आरम्भ हुई, आप विश्वास कीजिये, मैं नहीं कह सकता शायद आपकी निगाह भी दौड़ी हो, ४--५ मंत्री बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, उनका मनोरंजन हो रहा था । ऐसा लगा कि उनके घर में मनौती के लड़के पैदा हुए हों और अब वे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं । शान्तिप्रपन्न जी तो निश्चित ही और सबसे अधिक प्रसन्न मुद्रा में थे, मैं यह राष्ट्रपति की सौगन्ध से कहता हूं । यदि हमारा आक्षेप गलत था तो उन्हें क्षोभ होना चाहिये था हमारी नासमझी पर और यदि हमारा आक्षेप सही था तो उन्हें लजाना चाहिये था, क्योंकि ये राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की दुहाई देकर आज भी शासन का काम कर रहे हैं । अविश्वास के प्रस्ताव पर जाने अनजाने में कांग्रेस पक्ष ने बहुमत की बात जरूर कही है । श्रीमन्, एक तो उनका बहुमत ४४ प्रतिशत का है । सेकिन्ड क्लास का नतीजा है । दूसरे उनको भी अनुभव होगा, और श्रीमन्, आपको भी अनुभव होगा कि ऐन चुनाव के मौके पर एक कांग्रेस उम्मीदवार अफसरों को धांधली से २ १/२, ३ हजार निश्चित रूप से वोट अतिरिक्त रूप से पाता है । अपनी-अपनी साइकिलों पर हम दौड़-धूप करके जो चुनाव की खेती तैयार करते हैं, और यह कांग्रेस की बैलों की जोड़ी उस दिन हमारी उस खेती को जैसे सांड़ बनाकर बरबाद कर डालती है ।

श्री अध्यक्ष--

यह अविश्वास का प्रस्ताव कांग्रेस पर नहीं सरकार पर है । तो आप सरकार की ही बात कीजिये ।

श्री रघुनाथसिंह---

श्रीमन्, कांग्रेस के नेताओं ने जो बात कही है उसका मैं पर्दाफाश कर रहा हूं । हमारे राजस्व मंत्री एक बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं । चाहे जैसा संकट हो, हंस कर सदन के मनोरंजन करने की गलती करते रहते हैं । यह अत्यन्त शर्मनाक बात है । आपने कहा था कि अगर टेप रेकार्डर यहां पर होता तो हम बताते कि विरोधी पक्ष के लोग एक ही घिसी-पिटी बात हर मौके पर कहते रहते हैं । लेकिन अगर आज यहां फोटो और एक्सरे का कैमरा होता तो हम देखते कि आपके नेताओं में कहां क्या परिवर्तन है । दार्शनिकों का मत है कि तथ्यों के प्रकाशन में उदाहरण कभी-कभी गलतफहमी पैदा करते हैं । हम टेप रेकार्डर की बोली में पकड़ में आने वाले एकही जबान बोलने वाले हैं । लेकिन जैसे टेप रेकार्डर बना हुआ है वैसे ही फोटो, और एक्सरे भी बना हुआ है । सन् ४७ से अगर आपका फोटो और एक्सरे लिया गया होता तो यह उदाहरण जा कर कहां बैठेगा ? उनके कथनानुसार हमारी तो जबान एक ही है पर हमारी फोटो में उनकी क्षय रोग से ग्रहित मरणशील काया विद्यमान है, जिसकी लाश पता नहीं कब उठनी है । इस राज्य की दुर्दशा के लिये राज्य के दुर्भाग्य से वे जो कुछ कर रहे हैं वह तो कर ही रहे हैं लेकिन मुझे सबसे अधिक नफरत तब होती है जब वह अपने को समाजवादी कहते हैं । यह आत्म प्रवंचनाका पाप, उनके साथ बैठने का कुसंगत का पाप हमारे ऊपर भी पड़ रहा है और यह पाप इस राज्य के डोंगे को ले देकर डूबने वाला है । अगर बचा रही है तो रूस और अमेरिका की शक्ति, संतुलन की चिन्ता । समाजवाद कोई मजाक है ? यह एक दर्शन है । समाज-

[श्री रघुनाथसिंह]

वाद लाने केलिये आपको नंगा हो जाना पड़ेगा, कुर्सियों के लिये लत्ती–जूता नहीं करते रहना पड़ेगा। समाजवाद जिन्होंने लाया है उनको बड़ी तपस्या करनी पड़ी है। दूसरे देशों में भी समाजवाद आया है। हमको समझ में नहीं आता कि या तो वे इतने मूर्ख हैं कि समाजवाद की इतनी चर्चा है, पुस्तकों में इतना आलोचन विवेचन उसका हुआ है जिसमें पढ़ नहीं पाये हैं या इतने धूर्त हैं कि मारे बेहयाई के समाजवाद की वास्तविक कल्पना नहीं करते। मैं बापू की शपथ खा कर कहता हूं कि मैं अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलता नहीं आज जबकि मंत्रिमंडल की बागडोर भारत की उस सपूत बेटी के नेतृत्व में है जो देश की इनी गिनी ४, ६ सपूत बेटियों में है। लेकिन समाजवाद का नाम ले कर भ्रष्टाचार का शासन चलाते आपको लज्जा चाहे न आये लेकिन हमको आज जरूर जनता के बीच में लजवा रहे हैं अपने को समाजवादी कहने में। अगर ६७ तक ऐसी ही बदइन्तजामी रही तो जिस प्रकार दीवालिया बाप मर जाता है और उसका लड़का सपूत होते हुये भी अपने बाप के दीवालियेपन को मिटा नहीं पाता है उसी प्रकार हम भी शासन तो क्या करेंगे उल्टे उस दीवालियेपन को मिटाने में ही मिट जायेंगे।

अध्यापकों के विषय में बड़ी ऊल जलूल बातें कहीं गयीं। मैं स्वयं भी अध्यापक हूं। एक ध्वनि बराबर आई भाषणों से जैसे कि विरोधी दल के लोग अध्यापकों को बहका रहे हैं। अध्यापक आपसे ज्यादा समझदार हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। आप ऐसा कह कर उनका अपमान भी कर रहे हैं। आप उनको भूखों मार रहे हैं और उल्टे उनका अपमान भी कर रहे हैं। कालेजों, यूनिवर्सिटी में शिक्षा देने वाले अध्यापक हमारे बहकावे में आ जायेंगे? परसाल अध्यापकों का यहां जुलूस निकला। इस वर्ष जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में निकला, अनशन हुए सामूहिक रूप से और सामूहिक रूप से प्रदर्शन हुए, तो क्या उस समय हमने उन्हें बहकाया था? उनको भूखों मारिये और समान काम के लिये समान वेतन मत दीजिये और ऊपर से दोष दीजिये उसको कि लड़कों की परीक्षाओं के साथ, उनकी प्रक्रिया के साथ अध्यापक खिलवाड़ न करें, यह कहां तक उचित है? (व्यवधान) मैं आपको पढ़ा सकता हूं। आप जैसा मूर्ख नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष––

अब आपका समय समाप्त।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो इस सदन का एक सदस्य होने के नाते अभी जो एक सदस्य बोले थे उसके लिये मैं आपसे माफी मांगता हूं। धूर्त और मूर्ख जो भाषा का प्रयोग हुआ है उसके लिये मैं महात्मा तुलसी दास ने जो चौपाई कही है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं "तुलसी बुरा न मानिये जो गंवार कहि जायं।" मैं माननीय मुख्य मंत्री से और उनकी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की भाषा पर वे तवज्जह नहीं करेंगी।

सुबह से अब तक एक ही प्रश्न पर बहस हुई और वह प्रश्न है खाद्यान्न। माननीय विरोधी दल के नेताओं ने और सदस्यों ने इसी प्रश्न पर पूरी तरह से आलोचना की। मैं आपका ध्यान सन् ६१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश में खाद्यान्न की कितनी अच्छी उस समय स्थिति थी? ६२ में समस्थिति रही। ६३ में मैं उसी माननीय नेता विरोधी दलों से तथा सदस्यों से पूछना चाहता हूं क्या यह बात सही नहीं है कि ३० लाख हेक्टर्स के ऊपर खरीफ की फसल सैलाब से बरबाद हुई, और सवा करोड़ एकड़ के करीब रबी की फसल पाला में मारी गयी? जुलाई, अगस्त, और सितम्बर, ६४ तक तीन बार सैलाब आये और २० लाख हेक्टर्स खरीफ मारी गई। तीन फसलें इस प्रदेश की प्राकृतिक प्रकोपों के कारण तबाह हुईं। करोड़ों रुपये सिचाई, सहकारिता तथा कृषि विभाग के जरिये खर्च किये गये लेकिन किसानों में फिर भी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने में के लिये दम नहीं था। इसको मैं मानता हूं कि जब इस देश में अन्न संकट पैदा हुआ तो महंगाई आई, मूल्य वृद्धि हुई और सारी मूल्य

वृद्धि गेहूं के भाव पर निर्भर है। काश्तकार जिस तरह पिछले दो वर्ष से प्राकृतिक संकटों का शिकार हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है और अगर ये शब्द असंसदीय न हों तो मैं कहना चाहता हूं कि यह राजनीतिक एय्याशी है अविश्वास का प्रस्ताव रोजाना लाना विरोधी दल के सदस्यों तथा माननीय नेताओं के द्वारा। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के ७० लाख से ज्यादा खेतिहर मजदूर हैं, और गरीब हैं। करोड़ों किसान हैं, उनकी फसलें मारी गई हैं, उनके मुताल्लिक इस सदन में विरोधी दलों के नेताओं ने तथा सदस्यों ने एक लफ्ज भी नहीं कहा (शोर) इनको उभाड़ने का प्रयत्न है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, जो बातें सदन में कही गई हैं वे प्रोसीडिंग्स से पढ़ लें।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, सरकारी कर्मचारियों को उभाड़ा जा रहा है। किसानों की गर्दन के ऊपर विरोधी दल के सदस्य कुल्हाड़ा रखना चाहते हैं और कोई रास्ता नहीं है। पैसा कहां से आयेगा? उनका मतलब यह है कि इस तरह से इनको उभाड़ कर काश्तकार की गर्दन के ऊपर लगान बढ़ाया जाय। यह इनकी नीयत है। (तालियां) ये लोग चाहते हैं कि सरकार के सामने इतने मतालबे पेश कर दिये जांय जिनका अंत न हो। यह बदनीयती विरोधी दल के सदस्यों की है और ये लोग काश्तकार की गर्दन में फंदा डालना चाहते हैं। जनसंघ, एस० एस० पी० के उग्रसेन जी, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री काशीनाथ मिश्र बड़ी लम्बी बातों की डींग हांकते हैं। बड़ा शोर सुनते थे, हाथी की दुम है लेकिन दुम उठाई तो बालिश्त भर रस्सी का टुकड़ा निकला। इनकी गलत नीतियों की हालत क्या है? आज राजनारायण जी प्राइम मिनिस्टर को तार दे रहे हैं कि डाक्टर लोहिया की जान बचाइये, यह उनकी नीति है। उनकी जिन्दगी की खैरियतें श्रीमती सुचेता कृतालानी और माननीय लालबहादुर शास्त्री करें। (व्यवधान) इनके नारे देखिये, जरा अंदाज कीजिये। जिस पार्टी की सांठ गांठ जनसंघ के ताल्लुकेदारों—कुंवर श्रीपालसिंह, राजा यादवेन्द्रदत्त, कृष्णपालसिंह जी से हो वह अपने को समाजवादी कहे, यह इनका समाजवाद है। उनको कहने में शर्म नहीं आती। (व्यवधान) श्रीमन्, ब्यूरोक्रेसी खराब है, हमने किसी ब्यूरोक्रेट को बरखास्त किया तो इन्होंने दीपक पकड़ा दिया। हम के० के० दास जी को बरखास्त करें या रिटायर करें तो श्री रामसुन्दर पांडेय झोंपड़ी दिखा देंगे। यह अपने खान्दान में ब्यूरोक्रेसी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। श्रीमन्, ठाकुर हरगोविन्दसिंह जी का बड़ा स्वागत हुआ। इसकी बजह आप समझेंगे। इन्होंने भड़काया लोगों को कि अन्न की कीमत बढ़ रही है, बाजार लूट लिये जायं लेकिन लुटे कोई नहीं। ठाकुर हरगोविन्दसिंह जी का डंडा मजाबूत रहा और उसके सामने एस० एस० पी०, जनसंघ और उधर का सारा विरोधी दल फेल हो गया। इसलिये उनकी झुंझलाहट, उनकी परेशानी और नाकामयाबी शोर मचा रही है....

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन, मुझे २ मिनट का समय और दे दें, मैं खत्म ही कर रहा हूं। यह शोर मच रहा है कि नाकामयाबियां, नाकामयाबियां। यह उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जिसको यह धोखे से ठाकुर शारदाभक्तसिंह जी समझ बैठे हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार यह कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं और मैं सरकार को चार्ज करता हूं कि ७५-७५ हजार रुपया यह लोग डकार गये, १२-१२ हजार रुपये के वोट बिक गये, उनकी आपने कोई जांच की? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, सड़कों पर भ्रष्टाचार, सब जगह भ्रष्टाचार। ठाकुर साहब.....

(व्यवधान)

आप अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों को बरगलाना चाहते हैं और इस बहाने अपना फायदा उठाना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, इस समय संकट है, काश्तकार बहुत

[श्री जे० पी० मिश्र]

बड़ी मुसीबत में है, तीन तीन, चार चार फसलें उसकी मर गई हैं, उस पर खाद, तकावी, बीज का करोड़ों रुपया बकाया है, करोड़ों रुपये का कर्ज उस पर लदा हुआ है। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और उनका भत्ता बढ़ाने के पहले आपको काश्तकारों का करोड़ों रुपया माफ करना होगा। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से कि उनको खाद, बीज, तकावी का सारा बकाया माफ किया जाये और कोई चाहे कितना चिल्लाये उन पर एक पैसा लगान न बढ़ाया जाये, न बढ़ाया जाये।

*श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अध्यक्ष महोदय, शायद १० घंटे की बहस है, सुनते सुनते काफी दिमाग चकराने लगा है। मगर जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने पिक्चर्स लैंग्वेज में कहा, जो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं उतनी अच्छी हिन्दी नहीं बोल सकती। यह समझा जाता था कि बहुत बड़ी चीज आने वाली है, लेकिन निकली बहुत छोटी चीज। इस बारे में मैं सबको धन्यवाद देती हूं कि आज के अविश्वास के प्रस्ताव की बहस में दोनों तरफ से एक सद्भावना का वातावरण बना रहा। बिटरनेस का कभी-कभी थोड़ा-सा वातावरण आया, लेकिन उसे इस प्रकार से लिया गया जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा कि कोई सीरियस मामला नहीं है, लेकिन बहस करनी थी सो अविश्वास का प्रस्ताव ले आये। मैं कुछ जवाब भी दे दूं। अभी अभी बहस हो चुकी है, उधर के माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसके बाद इधर से उसका जवाब दिया जा चुका है। इसलिये सरकार की तरफ से जो कुछ कहा जाना चाहिये था वह कहा जा चुका है। अब मेरे यों तो कोई जवाब देने की खास जरूरत नहीं है, अब मैं दोहरा ही सकती हूं। इसके अतिरिक्त चूंकि बजट में बहस हो चुकी है, उसमें जो कुछ भी सरकार की तरफ से कहना था मैंने कहा है। अब मैं कुछ थोड़ी चीजों की तरफ फिर से ध्यान दिलाऊंगी।

जो बातें आज उठीं, उनमें सबसे बड़ी बात जो उठी, टीचरों की समस्या के ऊपर उठी। फिर उठी ऐडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल डिटोरियोरेट कर रहा है। और हमारे कम्युनिस्ट भाई साहब श्री चन्द्रजीत यादव साहब ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने उन्हें कांफीडेंस में लेकर बताया है कि यहां की सरकार बिलकुल नाकामयाब हुई है। फिर यह बतलाया गया कि बेचारी कृपालानी तो बिलकुल बेवकूफ जाहिल औरत हैं, उनको यह अफसर जैसा चाहते हैं वैसा बताते हैं और उनसे रबड़ का स्टाम्प लगवा लेते हैं और यह सुचेता तो सिर्फ स्टाम्प लगाने वाली हैं। उसके बाद यह कहा गया कि कांग्रेस जो, सोशलिस्ट और सोशलिज्म की दुहाई देती है, उसका नारा लगाती है, लेकिन वह बिलकुल धोखा है, सच्चे सोशलिस्ट तो हम हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सी बातें कही गईं और दुःख तो इस बात का है कि जो कुछ व्यक्तिगत आक्रमण हुए हैं, चाहे मन्त्रियों पर हुये हों या चाहे मेम्बरों पर हुये हों, वह बहुत ही अनडिजायरेबुल चीज थी। और आप तब उस समय नहीं थे। इस तरह से अगर चलें तो हम अपनी पब्लिक लाइफ में कोई मिनिमम स्टैंडर्ड कायम नहीं कर पायेंगे। यह सारी बातें अभी हुईं। यादवेन्द्र-दत्त दुबे जी ने सिक्योरिटी के बारे में बहुत सी बातें कहीं। जो बातें उन्होंने उठाईं वह केन्द्रीय सरकार से संबंधित हैं मगर उसके बारे में मैं बाद में कहूंगी। भाषा के बारे में कुछ बातें कही गयीं और-और बातें कही गयीं। अब मैं एक-एक विषयों को लेकर रोशनी डालूंगी और उनके बारे में जो मेरे खयालात हैं, बताऊंगी।

टीचर्स के बारे में कहा गया। कल ही कैलाशप्रकाश जी ने सरकार की तरफ से जो कुछ कहना है वह प्रेस कांफ्रेंस में कह दिया है। मुझे कोई नयी बात नहीं कहनी है। मैं यह कहती हूं कि यह जरूर आप लोगों को देखना है कि इस सरकार ने जिसकी आमदनी कोई ज्यादा नहीं है पैसा निकाल कर टीचर्स की हालत सुधारने का प्रसाय किया है। टीचर्स की तन्ख्वाह बहुत कम थी, वह भी धीरे-धीरे बदलती गयी। हाल ही में १ करोड़ ५६ लाख रुपये उनकी बेहतरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये दी थी चाहे तनख्वाह बढ़ाने के लिये, चाहे ग्रेचुइटी के रूप में, चाहे ट्रिपिल बेनिफिट स्कीम का कार्यान्वित कराने में दिया गया। हमने गत वर्ष यह किया कि वह तो चलेगा ही, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से २ करोड़ रुपया और लिया और अगले साल भी इसी प्रकार हुआ हो तो ५ करोड़ रुपये टीचरों के लिये निकाला गया। मैं पूछना चाहती हूं कि टीचरों के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दुखी तबका नहीं है और कोई कष्ट वाला तबका नहीं है? मैं मानती हूं कि महंगाई ज्यादा है और ५०० रुपये से कम पाने वालों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इन लोगों को जिनको मैंने बताया था उनको अभी महंगाई के लिये दिया गया है। कुछ पहले दिया गया था। जो छूटे थे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स उनको भी दिया गया। यह देने के बाद भी गवर्नमेंट का यह रवइया नहीं है कि हमारा दरवाजा बन्द है, या कोई हमने अनरीजनेबिल ऐटीट्यूड अख्तियार किया है। हमारा कोई भी ऐटीट्यूड अनरीजनेबिल नहीं है। हम यह कहते हैं कि उनकी मांग जायज है और हरएक की मांग जायज है। जिनकी आमदनी स्टैंडर्ड से नीचे है उनकी मांग सही है। जो मांग टीचरों ने रखी है उनकी मांग हम गलत नहीं मानते हैं। मैं खुद भी टीचर रह चुकी हूं। मैं ऐसी जगह टीचर रह चुकी हूं कि जहां पर टीचरों के साथ बड़ी बेइन्साफी होती थी मगर हम अपने टीचिंग के प्रोफेशन में इस तरह से ट्रेड यूनियनिज्म लाना या इस तरह से प्रदर्शन करना कोई डिगनिटी की बात नहीं समझते थे या इस तरह से स्ट्राइक की बात नहीं सोचते थे। कारखाने के मजदूरों का यह एक ए्पे्टेड तरीका था कि वह स्ट्राइक से नेगोशियेट करते हैं। मगर आज टीचर स्ट्राइक करें, कल यूनिवर्सिटी के टीचर स्ट्राइक करें, परसों को स्टुडेंट्स स्ट्राइक करें और फिर असेम्बली के सदस्य स्ट्राइक करें तो फिर इस सामाजिक जीवन को या गवर्नमेंट को कैसे चलाया जायगा? आज मैं यह समझती हूं कि हिन्दुस्तान में अपोजीशन में ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं है जो इस मुल्क की जिम्मेदारी को सम्भाल सके या जो मुल्क की जिम्मेदारी को लेने के लिये तैयार हो। लेकिन उनको आज नहीं तो कल इस मुल्क की जिम्मेदारी सम्भालना है तो जिम्मेदारी के साथ बात करनी पड़ेगी। मैं अपोजीशन से यह पूछना चाहती हूं कि आज कांग्रेस की सरकार न हो, कोई दूसरी सरकार हो तो क्या तब भी यह बात सही होगी कि टीचर स्ट्राइक करें या स्टूडेंट्स स्ट्राइक करें या सरकार के अफसरों को स्ट्राइक करने के लिये यहां पर प्रोत्साहन दिया जाय? इस तरह की बातें कहकर आप कयास लाना चाहते हैं, तो क्या इस कयास से यह कांग्रेस सरकार चली जायगी? कांग्रेस सरकार चली भी जाय हमको इसकी परवाह नहीं है, लेकिन देश और प्रदेश नहीं जायगा। मैं यह जरूर कहूंगी कि जो लोग यहां पर कयास पैदा करना चाहते हैं, मुल्क में अनार्की की कंडीशन लाने की तैयार करना चाहते हैं वह लोग यह जानें कि वे देश में बहुत बड़ा खतरा पैदा करना चाहते हैं। टीचरों की मांग के बारे में कहती हूं कि उन लोगों की मांग को सारे वक्त हमने विचार किया है और दो साल से हमने बराबर गौर किया है और इन दो साल में हमने उनके लिये ५ करोड़ रुपया निकाल कर दिया है। तो आज किस तरीके से यह कहा जा सकता है कि हमने उनकी मांग पर गौर नहीं किया? इस वजह से जो रास्ता उन लोगों ने अख्तियार किया है वह मैं बिलकुल उचित नहीं समझती और उस रास्ते को हर तरीके से कंडेम करना चाहिये। यह टीचरों का रास्ता नहीं है। उनको यह समझना चाहिये कि उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। गार्जियन्स ने ऐसे वक्त में हजारों रुपया खर्च करके उनको पढ़ाने के लिये भेजा है। मां बाप बच्चों को बड़ी तकलीफ से पढ़ाते हैं। अगर ऐसे समय में इम्तहान के वक्त में टीचर्स यह कहते हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे तो इस तरह की धमकी से हम डरते नहीं हैं और न ऐसी धमकी से हम दबेंगे। मैं कहती हूं कि इम्तहान होगा और हम इम्तहान लेंगे। आज हमारी कांग्रेस पार्टी की पार्टी मीटिंग हुई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे सारे मेम्बरों ने अपने को वालन्टरी आफर किया है कि हम इन्विजिलेशन के लिये तैयार हैं। हम कहते हैं कि टीचर्स अपनी मांग जरूर रखें मगर वह एक डिगनिटी का रास्ता होना चाहिये। यह जो टीचरों ने स्ट्राइक का तरीका अख्तियार किया है और इस तरीके को अख्तियार करके अगर वह गवर्नमेंट को इन्टिमिडेट करना चाहते हैं तो यह गवर्नमेंट इस तरह से दबने वाली नहीं है .....

श्री उग्रसेन—

यह आप धमकी दे रही हैं । आप उत्तर प्रदेश की मुख्य मन्त्री हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं धमकी हरगिज नहीं दे रही हूं । (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

आप नहीं बैठा सकते हैं । ९ तारीख को पता लग जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन जब बोल रहे हों तो सभ्यता का तकाजा है कि आप खामोशी से सुनें । हो सकता है कि आप उनसे असहमत हों । आप बैठिये ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत उग्रसेन जी से कहना चाहती हूं, मैं उनको धमकी नहीं दे रही हूं । मैंने इतना ही कहा है कि उनकी धमकी से हम दबेंगे नहीं । हम उनकी रीजनेबिल डिमांड्स को दस दफा कंसीडर करने के लिये तैयार हैं, हमारी ताकत हो तो हम उनको देने के लिये तैयार हैं, लेकिन हम उनकी धमकी से नहीं दबने वाले हैं ।

एक बात कही गयी और उसे बहुत उछाला गया । केन्द्रीय सरकार पर हर बात के लिये दोष लगाया जाता है । इस इंसीडेंट में हम लोगों ने केन्द्रीय सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा । छागला साहब आये थे, उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम । पेपर में जो रिपोर्ट थी उसमें कहा जाता है कि छागला साहब ने कहा कि २५ फीसदी अगर यह दें तो हम २५ फीसदी दे सकते हैं और २५ रुपया उनका बढ़ सकता है । हम लोगों ने केन्द्रीय सरकार को लिखा । २० रुपया तो हम आलरेडी दे चुके हैं, केन्द्रीय सरकार को मदद करना है तो २० रुपया और दे दे । उनको ४० रुपया मिल जायगा । इसके अलावा भी हम लोगों ने लिखा और उसका जवाब मिल चुका है । हम लोग जब प्लान पर डिस्कशन करने गये थे तो कहा गया था कि एक पाई भी प्लान के बाहर किसी काम के लिये नहीं दिया जायगा । छागला साहब के पास हम लोगों ने बहुत मिन्नत की कि यह स्टेट एजूकेशनली बैकवर्ड है, इसे स्पेशल एड दे कर आप मदद दीजिये । वह हमदर्दी दिखा कर गये । सेंटर का फाइनेंस पोर्टफोलियो उनके हाथ में नहीं है । हो सकता है कि वह उनके दिमाग में हो, लेकिन कई दिन पहले पार्लियामेंट में जो जवाब दिया गया है वह हमारे सिलसिले में नहीं था दूसरे स्टेट के सिलसिले में था, लेकिन था यही कि प्लान के बाहर हम एक पैसा भी नहीं दे सकते । अगर केन्द्रीय सरकार पैसा देने के लिये तैयार है तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम लोगों के पास उनका कोई एश्योरेंस नहीं है, बल्कि इन्कार है । हम लोगों ने अपनी गुंजायश दिया है । ५ करोड़ रुपया जो टीचरों को दिया गया है वह किसी भी तबके को समझना चाहिये कि हमने बड़ी मुश्किल से निकाला है । अब भी हम लोग कंटीनुअसली उनकी कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन किसी के दबाव से हम दबने वाले नहीं हैं । हम धमकी नहीं देना चाहते, लेकिन दिस वाज नाट एक्सपेक्टेड आफ दिस क्लास आफ पीपुल । ऐसी कार्यवाही की हमने उनसे उम्मीद नहीं की थी । मैं इसको फिर से कहती हूं कि यह चीज उन्होंने गलत की है ।

यह कहा गया कि आज ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब है । बहुत सी बातें उठायी गयीं । कहा गया कि पुलिस का ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब है, इस मिनिस्टर ने यह किया, उसने वह किया । एक मिनिस्टर साहब ने जवाब भी दे दिया, बाकी सब लोग अपने अनुदान पर जवाब देंगे । लेकिन बतलाया गया कि पुलिस का ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब है । भारतवर्ष का सब से बड़ा यह प्रान्त है । ५४ जिले हैं । इस प्रान्त में ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाना कोई आसान काम

नहीं है, एक मुश्किल काम है। बंगाल में १३ जिले हैं। इस इतने बड़े प्रान्त में किस्म-किस्म की समस्यायें हैं। सरकार को बहुत सड़ी-गली कहा गया। जिस समय पाकिस्तान से और बंगाल से रिफ्यूजी आ रहे थे उस समय बिहार और मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। क्या यहां लोग नहीं थे जो उसका ऐडवांटेज ले कर यहां का अमन चैन बिगाड़ने को तैयार हों ? यहां अगर किसी का बाल बांका नहीं हुआ तो वह हम लोगों की वजह से। क्योंकि हम लोगों को इन्सट्रक्शंस थीं कि कोई गड़बड़ी न होने पाये, स्थिति पर हमारा काबू था, पुलिस हमारी सतर्क थी। कोई गड़बड़ी हमारे यहां पुलिस की उचित व्यवस्था के कारण नहीं होने पायी। हमारा सरहदी इलाका है, मुसलमान भी गड़बड़ी कर सकते थे, और लोग भी गड़बड़ी कर सकते थे, कम्युनल वातावरण भी कुछ लोगों ने पैदा कर रखा था, लेकिन हम लोग उन सब से चौकन्ने थे, हमारी पुलिस एलर्ट थी, और कोई स्थिति खराब नहीं होने पायी। उसके लिये हमें पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिये, उनको धन्यवाद देना चाहिये। यादव जी ने बार-बार प्रशंसा की कि जिस ढंग से हम लोगों ने लॉ एंड आर्डर को मेन्टेन रखा उसके लिये हम लोग प्रसंशा के पात्र हैं। शायद ही किसी चीफ मिनिस्टर का जमाना ऐसा गुजरा हो जिस में इतनी मुश्किलात सामने आयी हों जितनी कि मेरे समय में आईं। खाद्य की एक विकट स्थिति आयी और वह सबको विदित है। मर्चेन्ट्स फायदा उठाना चाहते थे स्थिति का, स्केयरसिटी की हालत थी, वातावरण स्केयरसिटी के नाम से खराब किया जा रहा था, दूकानें लूटने के लिये लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, ऐसे समय में हमारी पुलिस ने चप्पे-चप्पे पर पहरा रखा और स्थिति को खराब नहीं होने दिया। इसके लिये उन लोगों की तारीफ करना चाहिये। स्टेट की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, मैं जानती हूं किस तरह से हमारी पुलिस ने काम किया है। जब इस स्टेट की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयी, उस समय स्टूडेन्ट्स का भी आन्दोलन चल रहा था। हमने किस तरह से उस पर कन्ट्रोल किया, सबको मालूम है। हमने रात दिन एक कर के काम किया है और हम लोग पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इस पर भी आप लोग जो इल्जाम लगाते हैं मैं उसे वापस करती हूं, स्वीकार नहीं करती। मद्रास में स्टूडेन्ट्स आन्दोलन हाथ से बाहर हो गया, लेकिन हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं होने पायी।

छोटी-छोटी और बातें कही गयीं, यह नहीं किया गया, वह नहीं किया गया। श्रीमती सुचेता कृपालानी कठपुतली हैं उनके हाथों में आदि आदि बातें कही गयीं जिनको सुन-सुन कर मेरा कलेजा पक गया। इतना बड़ा प्रदेश है, इतने जिले हैं, कहीं भी किसी डी० एम० ने या किसी अधिकारी ने किसी की बात नहीं सुनी, मेरे पास शिकायत लेकर माननीय सदस्य आते हैं, तबादले की बात करते हैं। सब पार्टियों का मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। मैं लिबरल व्यूज रखती हूं, अपोजीशन के लोग भी आकर बदलने को कहते हैं, तो मैं ख्याल करती हूं। बहुत दफा बदल भी देती हूं, उसका ऐडवांटेज लिया जाता है। मैं आप से बताती हूं, मेरे पास मिनिस्टर्स तक आये हैं और मैंने नहीं सुना है, वह लोग नाराज हुए हैं, मेरे पास हमारी पार्टी के अपने लोग आये हैं, मैंने नहीं किया है, मैं भी चाहती हूं कि आफिसर्स भी काम करते हैं, उनको भी समय चाहिये, बाल-बच्चे वह भी रखते हैं, परिवर्तन उस समय किया जाय, जिस समय वह जा सकते हैं। हां, ऐसी बहुत खुराफात किसी ने की हो कि जिसके लिये फौरन सजा मिलनी चाहिये, तो वह बात दूसरी है, लेकिन एक कायदे से काम होना चाहिए। एक साहब ने कहा फलां जगह एस० पी० को नहीं हटाया या डी० एम० को नहीं हटाया, मैं कहना चाहती हूं कि एस० पी० और डी० एस० पी० जिसको मैंने जहां से हटाना ठीक समझा उसको हटाया, और जिसको रखना सही समझा उसको रखा। पोस्टिंग के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन किसी को देने के लिये तैयार नहीं हूं। हां, अगर कोई आदमी खराब काम करे, तो बेशक उसको हटाया जा सकता है। एक साहब ने कहा फलां जगह को कम्युनल स्थिति खराब है, आपने डी० एम० की रिपोर्ट को सुना। मुरादाबाद का जिक्र था। तो डी० एम० की रिपोर्ट मैं नहीं सुनूंगी, तो किसकी सुनूंगी ? गवर्नमेंट जब चलाई जाती है, तो उसका एक तरीका होता है, यह बात सही है कि हम एक पार्टी को बिलांग करती हैं, पार्टी के लोगों को भी सुना जाता है, पोलिटिकल लाइफ में हैं, पोलिटिकल लाइफ की बातों को भी सुना जाता है, मगर अन्तिम अवस्था में अपने सी० आई० डी० पुलिस और डी० एम० की रिपोर्ट को

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

ही तो सुनेंगे, क्योंकि तरह तरह की रिपोर्ट हमारे पास आती हैं. . . (व्यवधान) । हां ब्यूरोक्रट्स तो वे जरूर हैं, हम उनके द्वारा शासन करते हैं, वह हमारे हाथ पैर हैं, उनसे ही हम सब काम करवाते हैं। यह भी होता है कि कोई अगर शक हुआ तो हम उसकी जांच करा लेते हैं। तो अगर डी० एम० से टेस्ट कराने के बाद हमें मालूम हुआ कि एक जिला है जहां हिन्दू मुसलमान बंटे हुए हैं, और वहां एलेक्शन में खतरा है, तो उसके बारे में तो हम कार्यवाही करेंगे ।

फिर मुझसे कहा गया कि सोशलिज्म कांग्रेस नहीं अपना रही है, और पूंजी परस्ती कर रही है, और पूंजी परस्ती के कुछ छोटे मोटे उदाहरण दिये। जिनका जवाब में उस दिन दे चुकी हूं। हम लोग कांग्रेस की तरफ से एक सोशलिस्ट पालिसी अपनाये हुए हैं। इससे बड़े-बड़े जो मेन टेस्ट्स होते हैं उनको देख लीजिये, उन टेस्ट्स के अनुसार हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं। बैंक्स का नेशन लाइजेशन, लाइफ इन्श्योरेंस का नेशनालाइजेशन, हैवी टेक्सेज आन हाई इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बड़े-बड़े कारखानों का पब्लिक सेक्टर में होना, इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में बढ़ना यह सारी बातें क्या बता रही हैं कि हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं या सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं? हां, यह बात सही है, हम लोगों ने यह कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी स्थान हमारी इकोनामी में होगा, कुछ दिन के लिये, क्योंकि अभी गरीब मुल्क है, सबको रोटी देनी है। सबसे पहले हमें यहां इकोनामिक स्थिति सुधारनी है, उसके लिये थोड़े दिन के लिये हमें ऐडजस्ट करना है। प्राइवेट सेक्टर को भी हमें रखना है। यह किसी से छिपी बात नहीं है, यह हमने डिक्लेयर करके किया है। सोशलिस्ट आबजेक्टिव की तरफ हम धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं, और सोशलिस्ट सोसाइटी लाने के लिए यह हमारी मेजर पालिसी है। मगर अभी हमारी मिक्स्ड इकोनामी है, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी रखेंगे और रखे हुए हैं। हटायेंगे, मगर थोड़े दिन बाद ।

फिर लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें कही गईं। मैं धन्यवाद देती हूं, जिन लोगों ने मेरे ऊपर थोड़ा-सा भरोसा रखा और कहा कि मैंने हिन्दी का काज थोड़ा-सा प्लीड किया। चन्द्रजीत यादव साहब ने बड़ी होशियारी से भाषण दिया और थोड़ी यह झलक लाने की कोशिश की कि मिसेज कृपालानी तो यू० पी० की नहीं हैं, वह यू० पी० की बात कैसे समझें ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैंने यह चार्ज नहीं लगाया ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सही है कि मैं बंगाल की हूं, और मुझे फख्र है कि मैं बंगाल की हूं, मैं बंगाली परिवार की हूं, यह कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में सन् ३१ से आकर रह रही हूं और कोई आकर के मैंने किसी की खुशामद नहीं की थी कि मुझे यहां मिनिस्टर बनाओ, मुझे उसके लिए इनवाइट किया गया, और लीडर भी आप लोगों ने चुना . . . (व्यवधान) कांग्रेस ने चुना, उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुना। जब उन्होंने चुना तो उनको थोड़ा बहुत भरोसा था कि मिसेज कृपालानी बंगाली खानदान की होने के बावजूद भी इतने लिबरल व्यूज रखती हैं कि उत्तर प्रदेश के इन्टरेस्ट को सेफगार्ड कर सकेंगी। मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहती, मगर दिल्ली में भाषा का जो कुछ डिस्कशन चल रहा था, उसमें हिन्दी भाषी अगर कोई जाता तो मुझसे ज्यादा न लड़ सकता, मुझसे ज्यादा आपके इन्टरेस्ट को और आपके काज को कोई प्लीड न कर सकता, क्योंकि हिन्दी भाषी अगर अपनी भाषा के लिए लड़ता, तो उसके ऊपर इल्जाम लगता। मैं बंगला भाषी हूं। तो मैं ज्यादा जोर से आपकी तरफ से बोल सकी, पैरोकियलिज्म का चार्ज मेरे ऊपर नहीं आता, इसीलिए मैं बोल सकी और दूसरों को थोड़ा दबना पड़ा ।

यादव जी ने कहा कि सरकारी सर्विसेज में कोटा सिस्टम का विरोध करके मैंने उत्तर प्रदेश के इन्टरेस्ट को खराब किया। मैं कहना चाहती हूं, यह मेरे अपने स्वभाव की बात है कि जिस चीज

को बुनियादी तरीके से मैं गलत समझती हूं, उसको किसी के लिए मैं सपोर्ट नहीं कर सकती और इन बातों से उत्तर प्रदेश का कोई इन्टरेस्ट सर्व नहीं होता कि कोटा सिस्टम मैं मानती, जिन्होंने यह कोटा सिस्टम का प्रोपोजल रखा था, मैं समझती हूं, उन्होंने कांस्टीट्यूशन का अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि यह एकदम कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के जो दो सेक्शन्स हैं १४ और १६ उसके यह खिलाफ है, तो मैं इतनी अपढ़ नहीं हूं कि मैं जाकर एक ऐसा प्रोपोजल रखती या मान लेती, जो कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि हम लोग प्रान्त में बंटे हुए जरूर हैं, परन्तु हम यह नहीं भूल गये कि भारत एक है और हम यह नहीं चाहते कि भारत का बंटवारा हो जाय, हम चाहते हैं कि भारत एक रहे। पिछले सालों में इन्टीग्रेशन का बहुत वातावरण बनाया गया था, जजेज की अदला बदली की, और बहुत-सी बातें की गई थीं, इस उद्देश्य से कि भारत में एक जगह से दूसरी जगह आदान-प्रदान होता रहे और अलग-अलग दीवारें बनाकर या कुएं बनाकर न बैठ जायें। तो मैं उसी आइडियालोजी में विश्वास करती हूं। मैंने कहा कि यह गलत चीज है, इससे भारत का इन्टीग्रेशन टूटेगा और भारत विभक्त हो जायगा, इसलिए मैं यह नहीं चाहती। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का कोई इन्टरेस्ट भी उससे सर्व नहीं होता, वह भी मैंने देख लिया था, क्योंकि मैं भी कामनसेन्स रखती हूं। हमने देखा कि हम लोग १६ प्रतिशत हैं, पापुलेशन में और उससे ज्यादा हमको सर्विसेज मिली हुई हैं। अब अगर कोटा मैं मानती तो कुछ घाटे ही में हम लोग रहते, और उसूलन भी यह बात गलत थी। उत्तर प्रदेश का कोई इन्टरेस्ट भी इससे सर्व नहीं हो रहा था, तो हम ऐसी छोटी बातों में क्यों पड़ें? पहले दिन पार्लियामेंट के मेम्बर जो थे, वे भी बड़े नाराज हुये थे इस बात से कि मिसेज कृपालानी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन दूसरे दिन जब उन्हें पूरी रिपोर्ट मिली और सारे आंकड़े मिले, तो वह मेरी तारीफ करने लगे। मैं बंगाली हूं और बंगाली भाषा के ऊपर मुझे बड़ा नाज है। हम लोग इमोशनली इन्वाल्व्ड हैं अपनी भाषा के साथ और उसी लिए हम मातृ-भाषा की इज्जत समझते हैं, हिन्दी को हम लोगों ने अपनी भाषा कांस्टीट्यूशन में करार दिया। कांस्टीट्यूशन में जब इसकी बहस हो रही थी, और यह प्रश्न आया था, तो ६ महीने बाद यह निर्णय लिया गया, उस ६ महीने में हमने काफी कोशिश की थी कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो, हम थे और कुछ हमारे साथ और लोग थे, हम लोग ऐसे थे, जो हिन्दी भाषा-भाषी नहीं थे, मगर गांधी जी की वह आइडियोलाजी हमको मंजूर थी, और हम चाहते थे कि हमारी अपनी भाषा बने। इसलिये हमारा विश्वास था और यह पोजीशन बरदाश्त के काबिल नहीं है कि हम एक विदेशी भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा मानें। कांग्रेस के ऊपर भी कुछ भाषा सम्बन्धी बौछार की गई। कांग्रेस का कोई व्यक्ति, इन्क्लूडिंग कामराज—किसी ने एक सेकिंड के लिये भी यह नहीं कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। किसी ने एक दफा भी नहीं कहा कि कांस्टीट्यूशन अमेंड हो या हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा न रहे। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा हमने स्वीकार की है और वह राष्ट्रभाषा रहेगी। केवल उनका यह कहना था कि १५ साल में जो कदम उठाने चाहिये थे वह न केन्द्र ने किया और न स्टेटों ने किया, इस कारण हम हिन्दी में काम करने के काबिल नहीं हैं। दक्षिण भारत में कांग्रेस के खिलाफ इस बात का कैपिटल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाषा विधेयक में कुछ सुधार किया जाय। कोई भी कांग्रेस का आदमी, चाहे वह तमिलनाड का हो या आंध्र का हो या मालावार का हो, हिन्दी के खिलाफ नहीं है। थोड़ा उन्होंने समय मांगा है कि हम हिन्दी भाषा सीख लें। मैं तो इसके खिलाफ थी, मगर इसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री उग्रसेन—

कामराज ने मद्रास में कहा कि हिन्दी की चिट्ठी फाड़ दो।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

खुशकिस्मती से मैं मद्रास में उस मीटिंग में मौजूद थी। २४ तारीख को मद्रास में मैं टूर कर रही थी। उस मीटिंग में बड़ा भारी मजमा था। लोगों में भाषा का जोश बहुत था। उस मीटिंग में कामराज ने शुरू किया यह कह कर कि क्या तुम लोगों को कोई जबरदस्ती

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

हिन्दी पढ़ावेगा ? अगर हिन्दी में चिट्ठी आती है तो उसे अलग रख दो, उसे फेंक दो। उन्होंने कहा कि २,३ भाषा, और हिन्दी हमारे बच्चे सीखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अन्त में उन्होंने यह प्लीड किया कि तुम हिन्दी सीखो, यह हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन रिपोर्टिंग में सारी चीज को भूल गये और हिन्दी को लेकर हाई-लाइट कर दिया। प्रेस हिन्दी के खिलाफ है, तो उसने भी बढ़कर लिखा। कांग्रेस स्टैन्ड्स फर्मली बाई हिन्दी।

मुझे दुख है कि हमारे दो भाई ने कहा कि उर्दू को हम कुचल रहे हैं, या जो भी हो। हम हिन्दी उर्दू सब सुनते हैं और हम भी कोई शब्द उर्दू का बोलते हैं तो हिन्दी व उर्दू में चालू भाषा खास अन्तर नहीं है, केवल लिपि का अन्तर है। जब से थ्री लैंगुएज फारमूला हमने मंजूर किया है, २,००० लैंगुएज टीचर रखे हैं जिनमें ५७५ उर्दू के हैं। अगर कहीं ५ बच्चे चाहते हैं कि हम उर्दू पढ़े तो हम फौरन टीचर देते हैं। हम खुद चाहते हैं कि उर्दू भी बढ़े। उर्दू एक सुन्दर भाषा है। उर्दू जबान यहीं की है। कोई बाहरी जबान नहीं है। हम लोगों की तरफ से उर्दू के पनपाने का कोई विरोध नहीं है।

माननीय यादवेन्द्र दत्त जी ने सिक्योरिटी के बारे में कहा। हम लोग राष्ट्र के बचाव के लिये कुछ नहीं करते हैं। वह भाषण अगर पार्लियामेंट में वे करते तो अच्छा होता। मैंने सुना है अगले चुनाव में वे पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वहां उस भाषण को दें तो ज्यादा ठीक होगा। क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की है। कोई एटम बम चलाये या और कुछ चलाये, माननीय लालबहादुर शास्त्री उसको देखेंगे। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि हम लोगों पर केवल यह जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षा में उनकी मदद करें। उसमें हम लोग कोताही नहीं कर रहे हैं। सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स और इन्टेलीजेंस, यह हम लोगों के हाथ में हैं। सिविल डिफेंस में ९ जगहों पर हम लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं ६ हजार वार्डन सर्विस में है, ६ हजार रेवेन्यू सर्विस में हैं साढ़े नौ हजार फायर फाइटिंग सर्विस में और साढ़े पांच हजार कम्युनिकेशन सर्विस में हम लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं, और अभी ट्रेंड किये जा रहे हैं। होम गार्ड्स में एक लाख साढ़े बत्तीस हजार का एनरोलमेंट हो चुका है जिसमें से करीब ४० हजार ट्रेंड हो चुके हैं। इसके अलावा पी० ए० सी० भी हमारी काफी तादाद में है और उसके पास काफी अच्छा इक्विपमेंट है। यह नहीं कहा जा सकता कि हम पूरे चौकन्ने होकर काम नहीं कर रहे हैं। उनको बड़ा मजबूत बना कर वहां रखा हुआ है और बड़ी भारी मुसीबत में वे वहां काम कर रहे हैं। हर तरह की उनको सहायता दी जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड एरिया में सिविल डिफेंस का भी हम काम कर रहे हैं। मैं उसकी यहां डिटेल तो नहीं बताना चाहती, लेकिन वहां पर भी हमने पूरा प्रबंध किया है। सुरक्षा लाइन का जो भी प्रबन्ध किया जा सकता है, वह वहां किया गया है। वहां पर हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हां, यह हमारी कमी जरूर है कि हम यह नहीं बता पाते हैं कि हमने यह प्रगति की है। होम गार्ड्स की एक रैली में मैं कानपुर गयी थी। वहां पर दो हजार पुरुष और ३०० लड़कियां तैयार खड़ी थीं। उन्होंने जिस तरह का मार्च किया उसको देखकर मैं हैरान हो गयी। उन्होंने जिस उत्साह से ट्रेनिंग पायी है, मुझे खुद अन्दाजा नहीं था कि हमने इस दिशा में इतनी प्रगति की है। हमारे नौजवानों में उत्साह है। वे ट्रेनिंग ले रहे हैं। यद्यपि हमारी पब्लिसिटी कम है, लेकिन हम काम बहुत पुख्ता कर रहे हैं।

आपने बताया कि गवर्नमेंट ने कोई प्रगति नहीं की है। आप अगर चाहें तो आपको फिर से आंकड़े गिना दूं। मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि हम इस प्लान में टारगेट से आगे जा रहे हैं, इस साल में ही टारगेट से आगे पहुंच गये हैं। बिजली के लिये तो हमारे पास पैसा नहीं है। इसके लिये २० करोड़ रुपया हमने सेंटर से मांगा। यह क्या बताता है ? क्या यह बताता है कि हम गैरजिम्मेदारी से काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट खराब है? गवर्नमेंट खराब है, मिसेज कृपालानी का कोई कन्ट्रोल नहीं है, मंत्री लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मगर टारगेट अचीव हो रहे हैं। सेक्रेटेरियट का काम स्ट्रीम लाइन हो गया है, क्या यह मजाक में हो गया है ? इसलिये विरोधी पक्ष के इस आरोप को मैं कम्पलीटली रेप्यूडियेट करती हूं। हां, यह बात ठीक है कि हमारे में

आपसी झगड़ा है, लेकिन वह हमारी घरेलू बात है। लेकिन फिर यह झगड़ा है तो खेद की बात है और ऐसी-ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये। लेकिन इतनी बात आपको जान लेनी चाहिये कि कांग्रेस में इतनी परम्परा की झलक बाकी है कि जब जरूरत पड़ेगी तो वे सब एक साथ पाये जायंगे। आज भी देख लीजिये कि सब लोग यहां बैठे हुए हैं और एक साथ हैं और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि वे हरगिज इस गवर्नमेंट का बाल बांका नहीं होने देंगे। मुझे दुख है कि माननीय काशीनाथ जी ने माननीय गेंदासिंह व माननीय रामायणराय जी पर हमला किया। आप हमला करें, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि वे लोग काफी मजबूत हैं इसका जवाब देने के लिये। मगर इस तरह का हमला कि मिनिस्टरी की लालच में या कमेटी के चेयरमैन होने की लालच में इधर चले आये, यह बात गलत है। अगर माननीय गेंदासिंह उधर भी बैठते होते तो मैं उनको कमेटी का चेयरमैन अवश्य बनाती। माननीय गेंदासिंह तथा दूसरे सज्जन उधर फ्रंट बेंच पर बैठते थे जबकि वे इधर के बैंक पर बैठते हैं, इस तरह से उनको इधर आने से कोई फायदा नहीं हुआ है पोजीशन के प्वाइंट आफ वियू से। मैं भी कभी पी०एस०पी० में थी, लेकिन कांग्रेस में क्यों आयी? क्योंकि केवल फ्रूटलेस क्रिटिसिज्म और भाषणों से कभी कभी लोगों का जी ऊब जाता है। हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। हम अपने यहां के लाखों आदमियों को यहां की आर्थिक तरक्की के लिये जुटाना है। जिसके दिल से देश में प्रेम होता है वह सोचता है कि चलो सरकार की समालोचना बहुत कर ली, अब उसके कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ें, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें। पी० एस० पी०, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस की आइडियोलाजी करीब-करीब एक ही है।

श्री उग्रसेन—

सोशिलस्ट पार्टी की आइडियोलाजी वह नहीं है जो कांग्रेस की है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

खैर, पी० एस० पी० और कांग्रेस की आइडियोलाजी एक समान है। तो बजाय इसके कि हम दो ग्रुप में बैठ कर एक दूसरे की काट करें, अच्छा यही है कि हम सब आपस में मिल कर देश को सोशलिज्म की तरफ आगे बढ़ावें। मैं किसी पार्टी की बात में नहीं जाना चाहती, लेकिन माननीय काशीनाथ जी ने इन दो महानुभावों के खिलाफ जो बातें कहीं, उसकी मैं काफी निन्दा करती हूं।

माननीय काशीनाथ जी ने एक बात यह कही कि यहां टीचर्स और सरकारी कर्मचारी मिल कर मद्रास की तरह से पोलिटिकल टर्पोच्यूड करेंगे और यहां आन्दोलन करेंगे। मैं समझती हूं कि इस तरह से पोलिटिकल टर्पिच्यूड की चिनगारी भड़काने तथा आग लगाने आदि की कार्यवाही को मैं कोई बहुत अच्छा नहीं समझती। इससे देश का हित नहीं होगा, बल्कि देश का नुकसान होगा और टीचरों का भी नुकसान होगा। टीचरों तथा देश के हित को देखते हुये यह शोभा नहीं देता कि इस तरह का आन्दोलन यहां किया जाय।

माननीय राधेश्याम शर्मा ने कई बातें सुनायीं कि फलां ने फलां कहा, फलां ने फलां कहा। मैं उनसे बिलकुल सहमत हूं कि पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट तभी अच्छी तरह से चल सकती है जबकि अपोजीशन सरकार के आमने सामने बैठा हो जो समय आने पर गवर्नमेंट बनाने की रिस्पांसिबलिटी अपने ऊपर ले सके। मगर गवर्नमेंट बनाने की रिस्पांसिबलिटी किसी की चिरौरी करने से या किसी को गाली देकर और कोई बात कर के नहीं आती। गवर्नमेंट बनाने की ताकत कोई किसी को देता नहीं है बल्कि इसे लिया जाता है। मैं बड़ी खुश हूंगी अगर आपोजीशन पार्टी आकर इस गवर्नमेंट को सम्भाल ले। क्योंकि कांग्रेस को भी शासन करते हुए १७ साल हो गये और हम इस जिम्मेदारी को और नहीं लेना चाहते। हम भी चाहते हैं कि कोई प्रोग्रेसिव बात हो तो अच्छा है, और कोई ऐसी आपोजीशन पार्टी बने जिसके हाथ में इस शासन को सुपुर्द कर के हम भी ५ साल तक आपोजीशन

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

बेंच पर बैठ कर देख सकें कि आज जो हमारे कामों में इतने सारे नुक्स निकालते हैं वे भी इस कुर्सी पर बैठ कर जरा महसूस कर सकें कि गवर्नमेंट को चलाना कितना मुश्किल है।

*श्री शारदाभक्तसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं अपने उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं शासन पक्ष का भी आभारी इसलिये हूं कि लगभग जिस तरह की समस्याओं का मैंने जिक्र किया उन्होंने इसको स्वीकार किया। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि समस्यायें हैं और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विरोधी दल के लोगों ने यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा है तो उन्होंने इन समस्याओं की गम्भीरता और उनसे उत्पन्न प्रतिक्रिया और क्षोभ जो आज जनता में व्याप्त है उस सबका अनुभव करके उसे प्रस्तुत किया है। हम कहते हैं कि यह चीजें आप के सामने आयें।

अभी जो बातें कही गईं मैं समझता था कि माननीया मुख्य मंत्री उन समस्याओं का कोई न कोई हल निकालें होंगी। आज इस प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता इस बात से आन्दोलित है कि टीचर्स का जो संघर्ष चल रहा है उसका परिणाम क्या होगा। सब ओर के सदस्यों के यहां भाषण हुये। हमें यह आशा थी कि वह अपने पद की गम्भीरता को समझते हुये इस प्रदेश के हित में कोई न कोई हल निकालें होंगी ताकि यहां की आन्दोलित जनता को कुछ राहत मिले, लेकिन वही सारे तर्क कि मैं भी टीचर थी आदि--दिये गये। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप टीचर थीं तब ऐसी ः हंगाई नहीं थी और यह अभिशाप जो आप की सरकार लायी है वह उस समय नहीं आया था। टीचर के सामने उस समय खाने की समस्या नहीं थी। आज उनके सामने यह नई समस्या है। आज मंहगाई से सभी लोग पीड़ित हैं वह महंगाई कौन लाया? इसकी जिम्मेदारी किस की है? इस प्रदेश की करोड़ों जनता जानना चाहती है कि १७ साल के नियोजन के बाद, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद यह महंगाई का अभिशाप कैसे खड़ा हुआ? और अगर यह जिम्मेदारी आप नहीं लेना चाहते तो मैं कहना चाहता हूं कि यह राजनीतिक ईमानदारी नहीं है। अगर आप महंगाई लाये हैं, सारी योजनाओं की असफलता के फलस्वरूप तो आप को उस से उत्पन्न परिस्थिति का भी हल ढूंढ़ना होगा। यह कह कर कि पैसा नहीं है आप भूखे लोगों को मार नहीं सकते। मुझे याद आता है कि श्रद्धेय आचार्य कृपालानी ने कहा था कि "प्लानिंग के कनपयूजन से यह समस्यायें पैदा हो रही हैं" तो मैं कहूंगा कि अगर आप की गलत नीतियों के कारण, आप के भ्रष्ट प्रशासन के कारण, आपकी अदूरदर्शिता के कारण यह महंगाई इस हद तक पहुंची है कि आज टीचर्स का जीवन चलाना मुश्किल है तो आप भाषण देकर आज उनका पेट नहीं भर सकते। आपको इस समस्या का कोई न कोई हल ढूंढ़ना होगा और विरोधी दल ने जो चुनौती दी है कि लगभग २१ करोड़ रुपया जो बड़े सरमायेदारों पर बाकी है उस के लिये आप विरोधी दल को ताकत दें तो एक सप्ताह के अन्दर उसका चौगुना वसूल हो जायगा और टीचर्स की समस्या उससे हल हो जायगी। क्या रामरतन गुप्ता से पैसा वसूल नहीं हो सकता? एक घंटे में वह वसूल हो सकता है और अगर वह ईमानदारी से टीचर्स की रक्षा करना चाहें, तो जिनके घरों में लाखों करोड़ों रुपया भरा पड़ा है, जिनके बड़े-बड़े कारखाने हैं और जो सारे प्रान्त का धन अपने यहां समेट कर रखे हैं उनसे वह मोहब्बत करके भूखे टीचर्स को उपदेश दे रही हैं। इससे उनको राहत नहीं मिलेगी। सरकार की ओर से यह कहा गया कि परिस्थिति ऐसी भयंकर हो रही है कि टीचर्स के लिये क्या यह उचित है कि वह हड़ताल करें और क्या टीचर्स को यह मार्ग अपनाना चाहिये? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ‹या यह सरकार के लिये शोभनीय है कि टीचर्स के लिये ऐसी स्थिति पैदा की जाय कि उन्हें यह सब करना पड़े? क्या एक दिन में खड़े होकर अध्यापकों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने यह सब कुछ करना शुरू कर दिया ? पिछले दो सालों से अपनी करुण कहानी कहते-कहते वह थक गये और जब उसके लिये जीना मुश्किल हो गया तब उस को यह करना पड़ा। एक कहावत है कि जिनसे पैर में बिवाई नहीं फटती वह दूसरे के दुख को समझ नहीं सकता। मिनिस्टरों के बंगलों में बैठ कर, मोटर में चलने के बाद, जनता से दूर रह कर आप उन की व्यथा नहीं समझ सकते जिनके बच्चे उनके सामने भूखे मरने की नौबत को पहुंच गये हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं—विरोधी दल की ओर से यह बात कही गयी, और मैं सरकार पर चार्ज लगाता हूं कि उसने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि जो अशोभनीय काम नहीं होना चाहिये उसको करने के लिये आदमी मजबूर हो रहा है। तो क्या उसका उत्तरदायित्व लेने के लिए आप तैयार नहीं है ? अगर आप की नीतियों के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है, अध्यापकों की समस्या पैदा हुई है तो उसका हल विरोधी दल ढूंढ़े क्या यह राजनीतिक ईमानदारी है ? आपने धमकी दी है, मैं कहना चाहता हूं कि हजारों अध्यापक आपके सामने यह कह रहे हैं कि हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल है, तो आप कहती हैं आप गलत रास्ते पर हैं। तुम्हारी धमकी से नहीं डरेंगे। हम कहते हैं कि यह अध्यापकों की धमकी नहीं है, धमकी आप दे रही हैं। आपको मद्रास में नहीं झुकना चाहिये था, वहां दो मिनट में झुक गये। जिस बात के सामने सरकार झुकी है उससे कोई हिन्दुस्तानी आदमी गर्व नहीं कर सकता है। आप अपनी गलत नीतियों से यहां बरबादी पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस का आरोप दूसरे पर लगाते हैं कि तुमने चिनगारी लगायी है। जहां आपकी सही नीति थी वहां अगर आप नहीं झुकते तो हम सब को गर्व होता। देश के मान्य नेता तथा संविधान कहता है कि हिन्दी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिये और है, लेकिन उसके विरोध में अगर राष्ट्रीय शक्तियां गड़बड़ करती हैं तो उसको आप को मना करना चाहिये। लेकिन ऐसा न करके आप वहां झुक गये। तो परिणाम यह निकला कि जहां धमकी सचमुच में सरकार को दी जाती है वहीं सरकार झुक जाती है। लेकिन अध्यापक वर्ग आप से लड़ना नहीं चाहता, इसलिये यह कहना कि उनको धमकी है, यह सर्वथा गलत है। अध्यापक तो आपकी कृपा पर निर्भर है, लेकिन अगर आप यह समझें कि आप धमकी देकर उसको बहुत दिन तक दबाये रख सकते हैं, तो मैं आगाह करना चाहता हूं कि यह आपकी भूल होगी। अगर १०–५ हजार अध्यापकों को आप दबायेंगे, उनको डी० आई० आर० में बन्द करेंगे, और उनके भूखे पेट को गोली देंगे तो यह प्रदेश इसको सहन नहीं करेगा। मैं आपको आगाह किये देता हूं कि आप बड़ी भारी गलती करेंगे। आप हमको भले ही कहें कि हम भड़काने वाले हैं लेकिन ईमानदारी से विरोधी दल के लोग कहते हैं कि अगर आप अध्यापकों को इस तरह से अपनी गलत नीतियों तथा हठवादिता से विनाश की ओर ले जाते हुए उन्हें डंडे के बल पर कब्जे में करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह आप की भूल है, अदूरदर्शिता है। अब वह समय है कि जब सहानुभूति के साथ उनके साथ बैठ कर हल निकाला जाय। अगर आप चाहें तो कल हल निकल सकता है। मैं निकाल सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि विरोधी दल उधर होता तो ऐसी समस्या पैदा ही नहीं होने देता। इसलिये जो प्रश्न मैंने रखा है उसको आप बहुत छोटा न करें। यह न कहें कि छोटी सी अध्यापकों की समस्या है।

माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे माननीय सदस्य जाकर इनविजिलेशन करेंगे। क्या आपकी यह धारणा है कि आपने बहुत काम कर दिया है प्रदेश का और देश का और प्रदेश देश में बहुत आगे बढ़ गया है। आर्थिक प्रगति में सारे देश से आगे है और अब कोई समस्या नहीं है, इसलिये अब यही काम रह गया कि इनविजिलेशन जाकर करें। शायद आप यह भी कहने लगें कि कापियों भी जांच देंगे। माननीया मुख्य मंत्री पीछे को देख कर चुप हो गयीं, यह समझ कर कि बहुतों को तो पढ़ना भी नहीं आयेगा। और यही होगा कि ५ लाख लड़के और लड़कियों का भाग्य उस नौकरशाही के हाथ में चला जायगा। मेरी प्रार्थना है कि उन्हें उनके हाथ में न छोड़ें। यहां यह वातावरण न बनाइये कि हम लोग धमकी दे रहे हैं, ये बेचारे अध्यापक धमकी दे रहे हैं, उनकी समस्या का समझौता करके हल करना चाहिए। मैंने इसीलिए इस प्रश्न को उपस्थित किया क्योंकि प्रदेश के भविष्य के सम्बन्ध

[श्री शारदाभक्त सिंह]

में हमें बड़ी आशंका है। आपने कहा कि आप तो चिनगारी लगाते हैं पर स्मरण रहे कि अगर हम विद्यार्थियों में चिनगारी लगाते तो आप से न कहने आते।

अध्यक्ष महोदय, हम प्रदेश में आग लगाना नहीं चाहते, पर आने वाले भविष्य के खतरे को आप के सामने जरूर रखना चाहते हैं। श्रीमन्, ऐसे संकेत आ रहे हैं कि परिस्थिति और गम्भीर हो जायगी। हम लोग इस परेशानी में हैं कि सोचें क्योंकि हम भी इसी प्रदेश में रहते हैं, हमारे भी लड़के और लड़कियां कालिजों में पढ़ती हैं। हजारों बालक इधर बैठने वालों के भी आज विभिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस प्रश्न को दलगत स्वार्थों के आधार पर न सोचें। हम आपसे बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि यह आपकी और हमारी, दोनों की समस्या है। अगर आपने अपनी प्रतिष्ठा के नाम पर सरकार की बहादुरी के नाम पर इस समस्या को पैदा कर दिया तो हमारी दूसरी समस्यायें भी अधूरी रह जायंगी। क्या यही सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण है कि हम दबते नहीं? हमने आप की बहादुरी को देखा है। इस बहादुरी से आज कर्मचारियों और अध्यापकों का सामना न किया जाय, ऐसी मेरी आप से प्रार्थना है।

अभी तक आप भी कहते हैं कि हमारी नौकरशाही बहुत अच्छा काम कर रही है। सब लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं पर अच्छे से बुरा होगा अगर आप के मतलब की बात न कही। यह राजनीतिक ईमानदारी नहीं है। इसलिये, श्रीमन्, आप के द्वारा मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के सामने जो समस्या है, उसे हल किया जाय। आज प्रदेश में बड़ी विस्फोटक समस्या खाद्य की बन गयी है और आप कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं बताये देता हूं कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों नर नारियां ऐसी विकट परिस्थिति से गुजर रही हैं कि उन को भर पेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि सब लोग परेशान हैं, अध्यापकों की मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार कीजिए। आज अध्यापक बड़ी शांति के साथ अपनी मांगें रख रहे हैं। उन की मांगों पर विचार न करके यह कहना कि हम बड़े बहादुर हैं, इससे समस्या बढ़ेगी ही, कम न होगी। अगर आप अध्यापक को नौकरशाही द्वारा दबा देने का प्रयत्न करेंगे तो मैं कहता हूं कि इसके भीषण परिणाम होंगे और लाखों नर नारी जिनकी सहानुभूति अध्यापकों केसाथ है, वे उनका साथ देंगे। मैंने भी देखा कि अभी मैनेजरों को आदेश हुए हैं कि जिस प्रकार से भी हो अपने कर्मचारियों से कहें कि वे अपने कर्तव्यों को ठीक से निभायें, पर क्या इससे भी समस्या हल होने वाली है? आप कुछ देंगे भी नहीं और चाहते भी हैं कि समस्या हल हो जाय। समस्या बहुत साधारण है। अगर आप चाहते हैं कि सामान कार्य करने वाले को समान वेतन मिले तो मैं कहता हूं कि उनकी मांगों पर आप विचार करें और कहें कि इतना नहीं इतना दे सकते हैं, कुछ तरीका आप निकालिये। लेकिन आप कहते हैं कि टीचर्स ने गलत रवैया अखतियार किया है। इससे काम चलने वाला नहीं है। जिन लोगों ने जो बातें कहीं हैं मुझे आश्चर्य हुआ कि वे जनता के बीच में बैठते हैं और ऐसी बातें कहते हैं। टीचर्स ने बड़ी गलती की हम उनको कंडेम करते हैं। आज अध्यापक कहते हैं कि हमें रोटी दो। आपके कंडेम करने से काम नहीं चलेगा। उन को तो रोटी मिलनी ही चाहिये। (व्यवधान)

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य--

आप की पार्टी के लोगों ने गांधी जी का मर्डर किया था। वह भारत के इतिहास में एक धब्बा है जो कभी मिट नहीं सकता। अगर इस अविश्वास के प्रस्ताव को किसी पोलिटिकल पार्टी ने पेश किया होता तो इसकी सुन्दरता कुछ और होती। मैं जनसंघ को पोलिटिकल पार्टी नहीं मानता हूं बल्कि रिलीजस पार्टी मानता हूं।

श्री शारदाभक्तसिंह---

मैं कहता हूं कि मुझे बड़ा दुख है कि आप ने सदन में गैर जिम्मेदारी की बात कही है जो मैं पढ़े लिखे आदमी से उम्मीद नहीं करता । मुझे अफसोस है··· (व्यवधान)

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य---

आप क्या समझते हैं अपने आप को....

श्री अध्यक्ष---

माननीय बैजनाथ जी...

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

आप सुबह से शाम तक गैर जिम्मेदारी की बात कहते हैं। आपका भाषण गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं।

श्री शारदा भक्त सिंह---

मुझे मालूम है कि उधर गर्मी अधिक है। उनमें शासन की गर्मी है और होनी चाहिये। अगर मिनिस्टरों से भी उनमें ज्यादा गर्मी आ जाय तो हमें आपत्ति नहीं है। हम लोगों की तरफ से माननीय रामायणराय और गेंदासिंह जी के लिये कुछ बातें कही गईं। माननीया मुख्य मन्त्री ने कहा कि मैं भी उधर से कांग्रेस में आई थी। ठीक है। आपका यदि उसकी नीति में विश्वास है तो जरूर जाइये। हमारी इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि उधर दो चार आदमी जाकर बैठ गये, बल्कि शिकायत इस बात की है कि जब आपने सदाचार समिति बनाई है और नियम बनाये हैं तो उनका पालन होना चाहिये। जब आपने कोड आफ कंडक्ट बनाया है तो पहले रिजाइन करें और तब जायं। आप परम्परा बिगाड़ रहे हैं। आप ने जब कोड आफ कंडक्ट बनाया है तो आप अपनी बात को भंग न करें। हमारी तरफ से यही कहा गया कि जब कोड आप कंडक्ट बना हुआ है तो आप को रिजाइन करके उधर जाना चाहिये था। इसलिये यह गलती हुई।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि समस्या हमारे प्रदेश की बहुत गम्भीर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

कृपा करके जरा शान्त रहिये।

श्री शारदा भक्त सिंह---

अन्त में मैं श्रीमन्, बड़े ठंडे दिल से माननीया मुख्य मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की हुकूमत में आप महिला हैं, आपके हृदय में ज्यादा उदारता है, इसलिये आप इन अध्यापकों के बारे में ज्यादा सहानुभति कर सकती हैं। आप यह इतिहास न बनने दें कि आप के मंत्रित्वकाल में अध्यापकों के ऊपर इतने बड़े अत्याचार हुये। लेकिन यह चीज मैं नहीं चाहता हूं, इसलिये मैं उनसे अपील करता हूं विरोधी दल की ओर से कि हम लोगों की भावना है कि हर तरीके से सहयोग देकर इस समस्या को निपटाना चाहते हैं और आप भी यह समझ कर कि हमारी समस्या है, प्रतिष्ठा को छोड़ कर, हल निकालिये। यह निश्चय करके जब आप बैठेंगी तो हल अवश्य निकलेगा और यदि हल निकल जाता है तो समस्या सुलझ जायगी। हमारे प्रदेश में बहुत सी समस्यायें हैं, उनका हल सब लोग मिल कर एक जगह बैठकर निकाल सकते हैं। आपकी नौकरशाही जो उनके विरोध में तर्क उठा रही है वह

[श्री शारदाभक्त सिंह]

समस्या का हल नहीं निकाल सकती है। इस समस्या का हल निकालना चाहिये। इसके लिये मैं सभी लोगों से अपील करता हूं और आशा करता हूं कि आप समस्या को और अधिक गम्भीर नहीं होने देंगो। अगर हुई तो इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी। विरोधी दलों ने कहा कि हम अध्यापकों को विनाश की ओर नहीं जाने देंगे और जो रुख अपनाया गया है उसको हम सहन नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जरा शान्त रहिये। अब मैं आपके सामने जो अविश्वास का प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल का पेश है वह रख रहा हूं--

प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घण्टी बजाई गई।)

श्री अध्यक्ष--

जब तक यह कार्यवाही समाप्त न होगी सदन बैठा रहेगा।

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में .. १०४,
विपक्ष में .. २४३)।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ८ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
४ मार्च, १९६५।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२३८ एल० ए०—१९६५—८६२।